

लाक अदालत

संगठन एवं कार्य-पद्धति का अध्ययन

डा० अवध प्रसाद
योजना निदेशक

कुमारपा गाँव स्वराज्य संस्थात, जयपुर



स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्रा० लि०

ए बी/9 सफरजग इनक्वेव, नई दिल्ली 110016

यह पुस्तक भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई० सी० एस० एस० आर०), नई दिल्ली के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित की गयी है। इसमें दिये गये तथ्य, विचार एवं निष्कर्ष के लिए पूणतया लेखक जिम्मेदार है न कि भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद।

कुमारप्पा ग्रामस्वराज्य संस्थान
बो-190 यूनिवर्सिटी मार्ग, बापू नगर
जयपुर-302004

प्रशासनिक निदेशक
योजना निदेशक
सहयोगी
आमुख
भूमिका

जवाहिरलाल जैन
डा० अवध प्रसाद
गोपीनाथ गुप्त। पी०के० सवानी
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी
डा० उपेन्द्र बक्स

लोक अदालत संगठन एवं कार्य पद्धति का अध्ययन
© 1978 इस पुस्तक का सर्वाधिकार कुमारप्पा ग्रामस्वराज्य संस्थान जयपुर द्वारा सुरक्षित है।

सुरिन्दर कुमार घई, मनजिग डॉक्टर स्टैनिस पतिष्ठा शा लि० नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एवं स्टैनिस प्रिंट्स एल 11 चीन पाथ एक्सटर्न नई दिल्ली से मद्रित।

Lok Adalat Sangathan Awam Karyapadhati Ka Addhyayan
मूल्य 50 रुपये

आमुख

डा अरवि प्रसाद और उनके दो सहयोगियों ने अपनी ओर से एक ऐसा रोचक, जीवन्त और विचारोत्तेजक विषय चुना है कि जिसकी अंतरंग सम्बन्ध भारतीय लोकजीवन के मर्म और यथार्थ से है।

मूलतः जनतान्त्रिक राज्य प्रणाली स्थानीय स्वायत्तशासन का ही एक विराट् राष्ट्रीय स्वरूप और संस्करण है। इस दृष्टि से हमारी राष्ट्रीय मसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर मसदीय पंचायत प्रणाली की सफलता के लिए यह अनिवार्य है कि हम गांव के स्तर पर तहसील या तालुक के स्तर पर, जिला कस्बा और शहर के स्तर पर स्वायत्तशासन की स्थापना में प्राण प्रतिष्ठा करें स्वावलम्बी जनतान्त्रिक परम्पराओं का निर्माण करें, लोकशक्ति में सक्रियता को सुदृढ़ और संगठित करें। अर्थात् आशा है कि हमारा मसदीय परिवेश केवल बाहरी दिखावा और झाड़ुबूझ ही रह जायगा। कहना न होगा कि सिर्फ ऊपरी सतह का अभिजात लोकतन्त्र कभी स्थायी नहीं हो सकता क्योंकि उसके साथ जनजीवन की जीवनदायिनी जड़ें जुड़ नहीं सकती। मेरा यह विनीत मत है कि इस आधारभूत प्रस्थापना की उपेक्षा करना हमारे देश में जनतन्त्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना होगा।

मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे संविधान का प्रारूप बनाते समय संविधान सभा एक प्रारूप समिति ने स्वायत्तशासन की इस मूल प्रस्थापना के महत्त्व को पूर्णतः नहीं समझा। इस भूलचूक का कारण अनेक थे। कांग्रेस संगठन और देश की राजनीति का अधिक प्रभावशाली मध्यवर्ति नेतृत्व गांधीजी की नैतिक आध्यात्मिक तेजस्विता और लोकछवि के समक्ष विनत नतमस्तक अवस्था थी कि नु उसने गांधीवादी दशन विचारधारा

और मूल्यों का हृदयगम नहीं किया था। ग्राह्य समिति के अध्यक्ष डा भीमराव अम्बेडकर भारतीय पंचायत प्रणाली व परंपरागत सामाजिक व्यवस्था की आशंकाओं के कारण नवारात्मक दृष्टिकोण के व्यापकता बन गए थे। संविधान सभा के प्रमुख सांविधानिक सलाहकार श्री बनीमल नरसिंह राऊ की निजी पृष्ठभूमि में कानून और प्रशासन ही मुख्य थे जनजीवन और राजनीति से उनका सम्पर्क नहीं था। ग्राह्य समिति के सदस्यों की भी स्थिति यही थी कि उनमें से कई अपने विषय के विशेषज्ञ बानूँ के, उदाहरण विद्वान अवश्य थे कि तु ग्राम्य जीवन की परम्पराओं और सभासनाओं का साक्षात्कार उन्हें नहीं था। संविधान सभा स्वयम् व्यवस्था मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई थी यद्यपि उसमें व्यापक राष्ट्रीय सहमति का समावेश अवश्य था।

संविधान निर्माण में पंचायत संस्थानों की उपस्था का सबसे मूलभूत कारण यह था कि उस समय हमारे देश में पारम्पर्य बानूँ और सांविधानिक परम्पराओं के विषय में, ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली और संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान के विषय में और ब्रिटेन की देख रेख में बनाए गए भारतीय और दूसरे डोमिनियन देशों के संविधानों और सामन प्रणालियों के विषय में अपेक्षाकृत कहीं अधिक चिंतन साहित्य और जानकारी उपलब्ध थी। भारतीय राजनीति शास्त्र एवं आधुनिक अनुसंधान हमारे संविधान निर्माण के समय बहुत कुछ अविकसित थे और आज भी अधविकसित ही हैं। पंचायत व्यवस्था की सभासनाएं अनचीनी और अज्ञात थीं। पंचायतों को लेकर एक ओर किसी सुदूर पुरातन स्वर्ण युग की सुरम्य कल्पनाओं को आहूत किया जाता था तो दूसरी ओर हमारे दीन दलित, निरक्षर, सुमुक्त ग्राम्य जीवन की लोकात्मिक सामर्थ्य शकास्पद मानी जाती थी। ऐसी स्थिति में मौलिक सांविधानिक चिंतन एवं पंचायती संस्थाओं के यावहारिक अनुभव के अभाव में पंचायती संविधान की संकल्पना करना दुबल दुस्तर और दुस्साहसपूर्ण होता।

राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांतों में सम्मिलित अनुच्छेद 40 की पृष्ठभूमि में संविधान सभा के समक्ष समस्याभाव के अतिरिक्त दो विरोधी विचारधाराओं के बीच एक अंतरिम कामचलाऊ समझौते का महत्वपूर्ण स्थिति है। संविधान बनाते समय अनुच्छेद 40 में पंचायती व्यवस्था के विकास का आश्वासन देकर हमारी संविधान सभा ने पंचायती संस्थाओं की सांविधानिक सावजनिक भूमिका पर राष्ट्रीय बहस का केवल कुछ समय के लिए स्थगित किया था। आज उस बहस के मूल प्रश्नों को फिर उठाया

जाना आवश्यक है उन प्रश्नों पर गहराई से विचार करना अपेक्षित है।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 40 के द्वारा पंचायती राज के उत्तरोत्तर विकास का जो मयत और विनम्र आश्वासन दिया और दुहराया गया था उसे पूरा कराने के लिए समुचित सत्रिय प्रयत्न नहीं हो पाया। जो प्रयत्न बड़ी घूमघाम से प्रारम्भ हुए उन्मत्त राष्ट्रीय राजनैतिक मन्त्रालय सदाशयता और साधना का अभाव रहा। पञ्चत पंचायत व्यवस्था की उज्ज्वल संभावनाएँ अधिकांशतः अग्रगण्य और अग्रणी रही और अन्त में ही वह व्यवस्था विविध व्याधियों से ग्रस्त और दुबल हो गई। पंचायत व्यवस्था की दुबलता के कारण जानना और उनकी व्याधियों का उपचार करना एक आधारभूत राष्ट्रीय महत्त्व का विषय है। जब तक हम अपने राष्ट्रीय स्वभाव का नहीं पहचान पाएंगे राष्ट्र का स्वास्थ्य गति स्फूर्ति तथा गति रत संचार से वंचित रहेगा। पंचायत व्यवस्था की सम्पूर्ण दिन-परा देण की आधि-व्याधि विवृतियों के लिए मध्यम और उपयोगी प्रावृत्तिक चिकित्सा मिष्ट हो सकती है, एसा मेरा मतव्य और विश्वास है। किन्तु यह भी सम्भव है कि जब हम ताननिष्ठ और राष्ट्रीय मन्त्रालय के साथ, दूरदर्शी तन्त्रि और विनम्र विवेक के साथ सामाजिक न्याय और सचदन की सजीवनी प्रेरणा नकर मकीर्ण दलगत स्वाधियों के ऊपर उठकर राष्ट्रीय सहमति के व्यापक आधार पर पंचायत व्यवस्था को संविधान और सावजनिक जीवन की प्रक्रिया में सुप्रतिष्ठित करें और उसे केवल शब्दों का अर्थ ही न द वल्लि उसे साधक बनाने में प्राणवण से जुट जाए। यह लक्ष्य और वायन्त्रम सुगम नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर श्रम, सकल्प दृष्टि, साधन और सहमति के समवेत समन्वय के बिना इस लक्ष्य और वायन्त्रम का सफल होना सम्भव नहीं है। मेरी यह भावना है कि जिस दिन यह लक्ष्य और वायन्त्रम हमारे देश में सही माँने में मूलरूपा लेने लगेगा, उस दिन हम एक नव विश्वास के साथ कह सकेंगे कि अब भारत में लोकतन्त्र और स्वतन्त्रता संरक्षित है कि भारत में अन्तःस्वातन्त्र्य और लोकतन्त्र की धरती की तह में अपनी जड़ें जमा चुका है।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायत व्यवस्था का कोई सुनिश्चित स्वरूप निर्धारित नहीं किया गया है। मुख्यतया और मूलतः उस प्रावधान में दान और दिशा का संकेत है, किसी सुस्पष्ट और व्योरेवार योजना का आदेश नहीं है। अनुच्छेद 40 का आधार और आग्रह 'स्वायत्त शासन' के निमित्त है और उस लक्ष्य के लिए अनुच्छेद 40 केवल ग्राम पंचायतों को सम्मानात्मक आयुध और उपकरण के रूप में अभिहित और मनोनीत करता

है। ग्राम पंचायत या लोकप्रदानत का कोई दान्तिव उत्तरण संविधान में नहीं मिलता। इस दृष्टि में यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि हमारा संविधान द्वारा ग्रान्टि राज्य नीति व निष्ठात्मक सिद्धांत में ग्राम पंचायतों की स्थापना भी सम्मिलित है या नहीं ?

संविधान में ग्राम पंचायत की कल्पना स्वायत्तता का कोई रूप में की गई है किंतु इसका यह अन्विष्ट अर्थ नहीं है कि ग्राम पंचायत या स्वायत्तशासन का कोई दान्तिव पक्ष और पहलू नहीं हो सकता, न यह कहा जा सकता है कि ग्राम पंचायत और स्वायत्तशासन का संगठन केवल निर्वाचन की राजनीति का या समक्षीय पद्धति का अंग मात्र हो सकता है। मूलभूत सैद्धांतिक प्रश्न यह है कि क्या गांव, तहसील और जिला के स्तर पर ग्राम प्रशासन का कोई वास्तविक ग्राम पंचायत को सौंपा जा सकता है या नहीं और यदि ऐसा किया जाता है तो परिणामतः क्या विधायिका कायपालिका और ग्रामपालिका के क्षेत्राधिकार आपस में उलझ नहीं जाते ? उत्तर में यह कहा जा सकता है कि हमारी सांविधानिक प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह राज्य शक्ति व सम्पूर्ण विभाजन के सिद्धांत पर आधारित नहीं है और वस्तुतः संयुक्त राज्य अमेरिका में भी राज्य शक्ति के विभाजन का सिद्धांत त्रिधा विभक्त नहीं होता। किंतु यह उत्तर संतोषजनक नहीं है। ब्रिटेन की संसदीय पद्धति में विधायिका और कायपालिका के बीच सीमा रेखा अवश्य है किंतु विभाजन नहीं है। क्योंकि मंत्रिपरिषद् एक तरह से मन्त्र की समिति है और सांविधानिक सिद्धांत की दृष्टि से संसद के प्रति उत्तरदायी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस (विधायिका) और राष्ट्रपति (कायपालिका) अलग अलग हैं और राष्ट्रपति या उसकी वाशिना के सदस्या का अपन पदों पर रहना कांग्रेस के सार्विक समर्थन पर निर्भर नहीं करता। किंतु ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में ग्रामपालिका विधायिका और कायपालिका अलग और स्वतंत्र है। जिस प्रकार की शक्ति और क्षेत्राधिकार ग्रामपालिका में निहित होते हैं उनके लिए ग्रामपालिका का विधायिका और कायपालिका से अलग और स्वतंत्र होना अनिवार्य भी है। तब प्रश्न यह उठता है कि ग्राम पंचायत में राज्य शक्ति का यह विभाजन किस प्रकार संयोजित हो किस प्रकार ग्राम पंचायत या लोकप्रदानत पंचायत व्यवस्था की विधायिका और कायपालिका से संवत्थ पृथक् स्वतंत्र और सुरक्षित रखी जाय ?

यह उल्लेखनीय है कि पुरातन समाज में ग्रामपालिका विधायिका और कायपालिका के बीच की सीमा रेखाएं स्पष्ट नहीं थी और ग्राह्य इसीलिए

पचायत व्यवस्था में इन तीनों पक्षों का एक विलक्षण सम्मिश्रण सम्पन्न हुआ। उस सम्मिश्रण के बावजूद भी पचायत व्यवस्था के 'यायिक पक्ष' की विशिष्ट अपक्षाओं को विस्मृत या उपक्षित नहीं किया जाता था। 'याय' की प्रक्रिया में पंच परमेश्वर की दुहाई दी जाती रही है। इसकी तह में मूल प्रस्थापना यह है कि 'याय' निष्पक्ष, निश्छल, निर्भीक, निष्कलुष हो, कि 'याय' मतुलित, सहृदय और सकरुण हो, कि 'याय' युक्तियुक्त, तत्संगत और स्थापित मानका पर आधारित हो, कि 'याय' समाजाभुव हो और समाज के प्रति दायित्वपूर्ण हो। क्या 'याय' पचायत की व्यवस्था आज इन आदर्शों को मूर्त रूप दे सकती है ?

समकालीन समाज के सन्तर्भ में 'याय' पचायत को लेकर कई ज्वलत प्रश्न उठते हैं—क्या बहुमत के मुख्यापेक्षी निर्वाचित पंच स्थानीय सामूहिक विवाद का निष्पक्ष नजर से देख सकते हैं ? क्या वे समय के—वातावरण के—वर्ग भावों में वह नहीं जायेंगे ? क्या भुपर या प्रबल भीड़ का भय उनकी अंतरात्मा को आच्छादित नहीं करेगा ? क्या प्रभावशाली समुदाय 'याय' पचायत के मध्य को अपने स्थापित स्वार्थों का शरत और माध्यम नहीं बना देंगे ? इन प्रश्नों का कोई सीधा सपाट उत्तर संभव नहीं है। स्पष्ट है कि इन प्रश्नों का नकारने से या उनसे पलायन करने की प्रवृत्ति से काम नहीं चल सकता। हम सैद्धांतिक और व्यावहारिक, दोनों स्तर पर विचार करना होगा और उपयुक्त कदम उठाने होंगे।

विवादों के नियंत्रण और समाधान में परम्परा से सभी देशों में रीति रिवाज, लोचनमत और सामाजिक समाज की यूनाधिक भागीदारी रही है। एक हद तक, सामाजिक नागरिक दीवानी विवाद का निणायक या दण्डनायक हो सकता है। दीवानी तथा फौजदारी मामलों में जूरी की प्रथा इसी भागीदारी का एक स्वरूप है। हमारे अपने देश में पचायतों का 'यायिक' पक्ष सदैव मुख्य रहा है। इस दृष्टि से 'याय-पचायत' या लोकअदालत इस देश के लिए कोई अनन्य अज्ञाना एवं अपरिचित विचार नहीं है। किंतु आधुनिक समकालीन संदर्भ में यह विचार कितना खप सकता है, कितना कारगर हो सकता है यह प्रश्न अवश्य उठता है। यह प्रश्न भी उभरता है कि शायद स्थानीय पचायती 'याय' सब प्रकार के विवादग्रस्त मामलों के लिए समुचित उपयुक्त और पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। उलझे हुए आधुनिक कानूनी विवादों के लिए विशेषज्ञों के 'यायालय' शायद अधिक सक्षम और स्वीकार्य हों इस तथ्य से भी इकार नहीं किया जा सकता। जहाँ निजी वैयक्तिक मूलभूत अधिकारों का प्रश्न है वहाँ भी पचायती 'याय' का नियंत्रण आवश्यक

होगा, यह भी मेरी राय में निर्विवाद है। ये प्रश्न 'याय पचायत' की मर्यादाओं के प्रश्न हैं जिसे कानून के मनुलित और दूरदर्शी प्रारूप से सुलझाया जा सकता है। जहाँ तक याय पचायती की निष्पक्षता का प्रश्न है, उस लक्ष्य के लिए हम याय पचायती की एक संस्कृति का निर्माण करना होगा, विश्वमनीय निष्पक्षता के मूल्यों को लोकशिक्षण एवं प्रशिक्षण द्वारा जनता और जनता के पक्षों तक पहुँचाना होगा। यह कार्य व्ययसाध्य है श्रमसाध्य है, निष्ठासाध्य है अत्यंत कठिन है किंतु अशभव नहीं है। यदि हम 'याय-पचायत' की निष्पक्षता और सामाजिक संवेदन की उत्तरदायी याय प्रक्रिया की नींव डालना चाहते हैं तो लोक शिक्षण लोकमत, विधि और परिपाटी के सम वय से याय की एक नई लोक संस्कृति का निर्माण करना चाहिए। हमारे ग्राम्य अचला में 'याय पचायत' का संस्थान उस नई 'याय प्रणाली' एवं याय संस्कृति का द्योतक, पोषक और सहायक बन सकता है, स्थानीय स्तर पर लोकप्रदालत के रूप में होते हुए भी उसे हमारी 'यायपालिका' से जोड़ा जा सकता है और एक यायक परिप्रेक्ष्य में हमारी 'याय पचायतें' हमारे प्रति दिन के लोक जीवन में याय की आदतों को सजीव, सुघड और सुदृढ बनाने में योगदान दे सकती हैं।

स्वर्गीय श्री मोतीलाल सीतलवाड की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग ने अपनी चौदहवीं रपट में पचायती अदालतों की उपयोगी संभावनाओं पर बात दिया था। तदनंतर केन्द्रीय सरकार ने विधि आयोग के सदस्य श्री जी आर राजगोपाल की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल गठित किया था। उस अध्ययन दल की रपट पचायती अदालतों के विषय में एक प्रामाणिक, विश्लेषणात्मक और रचनात्मक दस्तावेज है। राजगोपाल अध्ययन-दल की सिफारिशों और उनके सुझाव क्रियावित करने की दिशा में कोई संकल्पनीय प्रयत्न नहीं हुआ। उस रपट के अतिरिक्त यायमूर्ति श्री प्रफुल्ल भगवती की अध्यक्षता में गुजरात कानूनी सहायता समिति ने और यायमूर्ति श्री कृष्ण अय्यर की अध्यक्षता में केन्द्रीय सरकार की विधेयन समिति ने भी पचायती अदालतों को पूरी सहानुभूति के साथ स्वीकार करने के लिए बहुत जोर दिया। केन्द्रीय सरकार की कानूनी सहायता विधेयन समिति (जिसका मैं सदस्य रहा) ने अपनी 1973 की रपट ('जनता की प्रक्रियात्मक याय') में पचायती 'याय और कानूनी सहायता पर एक पूरा अध्याय' लिखा है और याय पचायती को देश के बहुमर्यादक निधन 'उन के लिए कानूनी सहायता की एक सार्वजनिक विधा और प्रकार' माना है। हमारी 1973 की रपट में यह मसौदा अक्षरबद्ध रूप में

प्रकट हुआ है कि आधुनिक 'याय' के दुसह व्यय, दुनिवार विलम्ब, दुसाध्य उलझी हुई प्रक्रियाएँ और उनसे उत्पन्न अविश्वास और अलगव की पीडा-दायक प्रतीतियाँ एक सीधा सरल उपाय और एक सुलझा हुआ समाधान मांगती है। 'याय-पचायत' वह समाधान हो सकती है। याय पचायतें हमारी अधिकांश आबादी के लिए दिन प्रतिदिन की सामान्य विवाद समस्याओं को सुलझाने में, मध्यस्थता कराने में, भेल और समझौता कराने में और सर्वमान्य निर्णय देने में एक विराट और व्यापक योगदान दे सकती है। न केवल ग्रामीण अचला स बल्कि शहरी विवादों में भी इस प्रकार की 'याय-पचायत' की उपयोगी भूमिका हो सकती है। किंतु इन सभावनाओं को सकारात्मक और मूल रूप देने के लिए गहराई तक स्वस्थ लोकमत बनाना होगा मर्यादाएँ और सामाजिक परिपाटियाँ स्थिर करनी होंगी, कानूनी सुरक्षाओं के विधि विधान निर्मित करने होंगे, मिल कर विचार-विनिमय से विवेक के आधार पर 'सपञ्छध्व मजानी' के आदेश पर चलने की सांस्कृतिक आदत डालनी होगी दलगत और निजी स्वार्थों में ऊपर उठ कर सामाजिक 'याय' लेने और देने की क्षमता का निर्माण और विकास करना होगा, हर समस्या के परस्पर विरोधी पहलुओं को समझने और उनमें सतुलन-मम वय स्थापित करने का स्वभाव बनाना होगा, यायपचा और जनता को पचायत 'याय' के दशन और शैली में शिक्षा दीक्षा देनी होगी। इसमें कोई मदेह नहीं कि यह आदर्श बहुत दुगम और दुस्तर है, अत्यंत महत्वाकांक्षी है यह भी स्पष्ट है कि यह आदेश राष्ट्रीय सहमति, निष्ठा साधन और श्रम का मुग्धापक्षी है। किंतु इस आदेश के अतिरिक्त भारतीय जीवन के स दम में और कोई समथ विकल्प भी नहीं है। इस सबंध में अत तक चलती आ रही उपेक्षा उदासीनता और पलायनवादी अकर्मण्यता कोई विकल्प या समाधान नहीं है बल्कि दष्टिरहित सवेदनहीनता का और कबीक विवगता के परिचायक मात्र है। हमें नया समाज बनाने और नया दौर लाने के लिए इस सवेदनहीनता और उदामीनता को तिलाजनि देनी होगी श्रेष्ठ परंपराओं से प्रेरणा लेते हुए नये परीक्षणों और प्रयोगों के प्रति आशावान और निष्ठावान होना होगा, अनागत, अज्ञात भविष्य का मागना करने के लिए अतीत की उपलब्धियाँ और वर्तमान की अपेक्षाओं को जाड़ कर नई सामर्थ्य और नये मन्त्रों का सचय समन्वय और मयोजन करना होगा। यह स्वप्न का आवाहन भी है और यथाय का आदेश भी।

प्रस्तुत पुस्तक का एक स्वप्निल ययाय की तीर्थयात्रा बहू तो अनियोजित नहीं होगी। इस पुस्तक में डॉ अरवि प्रसाद एवं उनके दा सहयोगियों ने

रगपुर में श्री हरिवल्लभ भाई वारीय द्वारा स्थापित लोकप्रदात का अध्ययन किया है। मैं रगपुर आश्रम को एक अनोखा परीक्षण मानता हूँ। मैंने स्वयं इस मस्थान का साक्षात्कार किया है। कुछ वर्ष पूर्व मैं स्वयं जिनासा कुतूहल और आकर्षण से संप्रेरित हुआ और बड़ोदा जिला के उस दुर्गम वनप्रांता में गया था और अपने साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि सहायक प्रमुख डा. उपेन्द्र बक्स को ले गया था ताकि हम दोनों इस परीक्षण पर कुछ सामग्री संकलित करें उसका विश्लेषण और मूल्यांकन करें। सब मिलकर रगपुर की मरी यात्रा बहुत सावधान और सफल रही। रगपुर परीक्षण की अपनी कुछेक कमियाँ और कमजोरियाँ हैं किन्तु उसकी अपनी अद्वितीय और उत्प्रेरक शक्ति भी है। वह उपलब्धियाँ और वे कमियाँ और कमजोरियाँ समाज-वैज्ञानिकों के लिए बहुत मूल्यवान हैं। प्रस्तुत पुस्तक इस दृष्टि में विशेष महत्त्व रखती है। जिस अनुसंधान काय और मूल्यांकन की कल्पना मैं और श्री उपेन्द्र बक्स ने की थी और जिसका श्रीगणेश हमने रगपुर जाकर किया था यह पुस्तक उस काय की एक सजीव कड़ी है। मैं डा. अवधप्रसाद श्री गोपीनाथ गुप्ता एवं श्री पी. के. सवानी को बधाई देता हूँ और कुमारप्पा ग्राम स्वराज मस्थान एवं उसका मुख्य मन्त्रिण मन्त्रिण श्री जवाहरलाल नेहरू का साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने रगपुर की लोकप्रदात का एक समाज-वैज्ञानिक नमूना प्राप्त किया है, जिसे अनुसंधान की लीक से हटाकर हमारे राष्ट्रीय जीवन के मर्याद और मर्म को प्रवर्धन के घरातल पर देगन समझने और भाषने का एक रचनात्मक और अध्ययनशील प्रयत्न किया है। मुझे आशा है कि यह पुस्तक पचासवीं शताब्दी के कठिन और बेबीदा सवाला और समस्याओं पर राष्ट्रीय चिंतन के लिए तथ्य और विवरण ही नहीं बल्कि विश्लेषण दृष्टि और अनुमति भी जुटाएगी एवं विवाद समाधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय नीति निर्माण का माग प्रसस्त और आलोचन करेगी।

—डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी,

वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय,
मानद वार्षिक मासिक एवं समीप अध्ययन मस्थान

30, लातो एस्टेट
नई दिल्ली
1 मई, 1978

भूमिका

समाज में विवादों का निपटारा करने वाली संस्थाओं का अध्ययन विधि की समाजशास्त्रीय सूची का एक मुख्य विषय रहा था एवं है। राजकीय विधि प्रणालियों में ही अत्यधिक उलझे रहने के कारण याय (विवादों का निपटारा) से जिनका गहरा सम्बन्ध रहा है उनमें सामान्यतः यह धारणा बन गयी है कि सरकारी न्यायालयों के अतिरिक्त विवादों का निपटारा करने वाली अन्य संस्थाएँ समाज में विधि के अध्ययन की दृष्टि से अत्यन्त कम महत्व की अथवा रान्ते के इतर उधर की स्मारक चिह्न मात्र हैं। वास्तव में सामान्य प्रवृत्ति यह रही है कि विवादों का निपटारा करने में प्रवृत्त गैर सरकारी संस्थाओं का अध्ययन 'सांस्कृतिक या विधि नृत्तस्वविज्ञान के अन्तर्गत आने वाला अध्ययन मान लिया जाय जो कुछ इन गिने विशेषज्ञों तक सीमित मूल विषय में परे का क्षेत्र है और अस्त-यायाधीश, वकील या विधायक की दृष्टि से इसका कोई तात्कालिक तथा प्रामाणिक महत्व नहीं है।

भारत में 'विधि' नृत्तस्वविज्ञान का भी संपूर्ण शास्त्रीय अनुशासन के रूप में अभी तक मायता प्राप्त नहीं हुई है। नवशशास्त्रीय विवरणा में भी विवादों का निपटारा करने वाली संस्थाओं और उनके द्वारा प्रन्याया के यदा कदा प्रासागिक उल्लेख ही हैं लकिन जहा तक उनके सामाजिक स्थायित्व एवं परिवर्तन के दिशा-निर्देशन के मूल्यांकन का प्रश्न है, वह कभी कभी ही अगीकार किया गया है। आदिवासी नवशशास्त्र में भी विवादों का निपटारा करने वाली संस्थाओं और उनके द्वारा व्यवहृत प्रन्याया के महत्व की ग्राम तौर पर अवहलना की गयी है। (अवलोकन करें—भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्—1972, 31-133, 258 61 बीणादास 1973) जहा वहीं विवादों का निपटारा करने वाली इन संस्थाओं की उपाययता दृष्टि गाचर हो भी रही है, वहा भी व्यवस्थित अनुसंधान के अवमरा का परित्याग कर दिया गया लगता है (वक्मी—1973)। आदिवासी जातीय समुदायों में सामाजिक नियंत्रण और याय परम्पराओं से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन क्रिस्टोफ वान फ्यूरर हैयरडोफ के 'मोरल्स एण्ड मेरिटम (1967) और प्रोफेसर नायक द्वारा किये गये अध्ययन (भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद् 1973 258) तक ही सीमित है।

‘विधि’ नृत्तविविधान के अध्ययन की दृष्टि से भी ग्रामसन होरेल (1954), मकम ब्लूमेन (1967, 1965), पालवोहनन (1957) ए एल एस्टोन (1964) जम उच्च कोटि के अध्ययन भारत में नहीं किये गये हैं। तथ्य तो यह है कि भारत के प्रमुख विद्वद्विद्यालय विधि के स्नातकोत्तर अध्ययन के निये सर हैनरी मैर की पुरानी पुस्तक पर आश्रित है और यह केवल इस बात का ही परिचायक नहीं है कि हमारे विधि पाठ्यक्रम अप्रचलित और असंगत हैं बल्कि इस क्षेत्र में इस ज्ञान की जा दयनीय स्थिति है उस पर दुःखद टिप्पणी भी है।

लम्बे समय से एकत्र होती जान वाली इस बर्मी की सुधारन की आवश्यकता बहुत तीव्र है। इस सन्दर्भ में रंगपुर स्थित लोकप्रदात में बार में किया गया वर्तमान अध्ययन इस क्षेत्र में उपलब्ध अत्यंत सीमित साहित्य में एक ठोस अभिवृद्धि माना जायेगा। प्रमुख सर्वोदयनता श्री हरिवल्लभ परीय, (जि ह लोग स्नेह पूर्वक भाई के प्रिय नाम से संबोधित करते हैं) के द्वारा प्रारम्भ की गयी यह लोकप्रदात अब चौपाई सदी से अधिक पुराना सम्था हो गयी है। इस संस्था ने (1946-71) की पच्चीस वर्षीय अवधि में कुल 17,254 विवादों का निपटारा किया है जिनमें 10615 पारिवारिक एवं विवाह सम्बन्धी, अशांति तथा चतह के 3215 भूमि सम्बन्धी विवाद 2225, मारपीट एवं हिंसा के 816 एवं कुछ हत्या एवं हत्या के पयातो से सम्बन्धित रहे हैं। इस दीर्घ अवधि में इस संस्था ने, जो प्रथमतः विवादों का निपटारा करने वाली संस्था के रूप में प्रारम्भ हुई थी, इस क्षेत्र में विविध प्रकार की सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों की प्रक्रिया का सिलसिला जारी कर दिया है। इस क्षेत्र में लगभग 402 ग्रामदानी गांव हैं जिनमें एक लारा से अधिक लोग निवास करते हैं और लगभग 7,500 एकड़ भूमि है। रंगपुर का यह आश्रम, जिसके अब भी केन्द्र और है, इस संपूर्ण क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाने के कार्यों में सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। उसकी मुख्य उपलब्धिया है—भूमि मुक्ति (लास तीर से साहूकारों के कुगुल से भूमि का छुटकारा) शराब मुक्ति (नशे के व्यसन से मुक्ति) कृषि यंत्रीकरण और सिंचाई पशुपालन में उन्नत तरीकों का प्रयोग जीवन-मालाघो (जीवन की स्वावलंबी एवं सुखमय बनाने का भाग दिखाने वाली पाठशाला) के माध्यम से प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, प्रौढ़ निम्न कक्षेत्रों और सहकारी समितियाँ और बका के माध्यम से ऋण एवं एकीकृत वित्तीय आवश्यकताओं की आपूर्ति जो संभवतः अल्पकालीन कार्यक्रमों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस प्रकार विवादों का निपटारा करने के सामाजिक

सेवा कार्यों के बिंदु से प्रारंभ कर के रंगपुर ग्राम्य क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की महत्वपूर्ण घुरी बन गया है। वास्तव में ग्राम्य और उसका नेतृत्व बहुत बड़ी सीमा तक एक प्रकार से इस क्षेत्र की सरकार बन गया है।

ग्रामदान एवं भूदान आंदोलन तथा ऊपर वर्णित अथ सेवा कार्यों के कारण लोकअदालत के एक प्रकार के 'सघीय' संगठन के स्वरूप का धीरे-धीरे विकास होता जा रहा है। कम से कम ग्रामदानी गांवों में तो ग्राम सभाओं ने स्थानीय जनता की अदालतों का रूप ग्रहण कर लिया है। वे अपने क्षेत्र के अनेक विवादों का अपने स्तर पर निपटारा कर देती हैं। स्थानीय स्तर पर निर्णित न होनेवाले विवाद यदाकदा निम्नोच्च रंगपुर स्थित लोक अदालत के समक्ष ले जाय जाते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि लोकअदालत प्रणाली में विवादों का निपटारा करनेवाली संस्थाओं का एक समूह ग्राम्य के तत्वावधान में संगठित हो गया है। यह सही है कि कुछ हद तक इसे प्रणाली कहने की बात की पूर्णतः संपुष्टि नहीं की जा सकती। वस लोकअदालत प्रणाली में भाई की जा भूमिका है, उसको भी भुलाया नहीं जा सकता। लोकअदालत भाई की कृति है। उनके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में इसका जन्म एवं विकास हुआ है, इसलिये जब हम लोकअदालत के संगठन की विवेचना करें तो उसका सही विवेचन करने का एक मात्र तरीका यह है कि हम मात्र लोकअदालत के बजाय लोकअदालत में भाई इस मुद्दे का प्रयोग करें (बकसी 1975)।

जो कुछ हो तथ्य यह है कि लोकअदालत ने अपना स्थानीय प्रतिरूप खड़ा कर दिया है और लोकअदालत का कोई भी अध्ययन उस समय तक पूरा नहीं माना जायेगा जब तक साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर विवादों का निपटारा करने में प्रवृत्त इन संस्थाओं का भी गहरा अध्ययन न किया जाये। इस दृष्टि से वर्तमान अध्ययन भी इसी प्रकार अधूरा है जिस प्रकार हम लोग द्वारा किया गया पूर्व अध्ययन लेकिन 'केन्द्रीय' लोकअदालत में अध्ययन की दिशा में निश्चय ही यह एक महत्वपूर्ण तथा आवश्यक प्रारंभ है। रंगपुर की लोकअदालत एक ऐतिहासिक प्रारंभ बिंदु तथा सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के सतत केन्द्र बिंदु तथा सामाजिक दृष्टिकोणों में एक अनूठी संस्था है।

लोकअदालत प्रणाली ने विवादों का निपटारा करनेवाली संस्थाओं की एक ऐसी श्रृंखला विवर्धित की है जो न तो परम्परागत ही है और न 'आधुनिक' ही। लोकअदालत प्रणाली प्राचीन परम्परा से नहीं निवृत्ती है।

वास्तव में सर्वोच्च विचारधारा के मद्देनवाहको के संस्कारों में से इसका जन्म हुआ है। दूसरी ओर यह प्रणाली अपने मगठन, काम पद्धति और संस्कृति की दृष्टि से भी न पचायता के मूल्यवान् लक्षणों पर फनीफूली है।

लोकप्रदात प्रणाली दूसरी दृष्टि से भी झनूठी है। यह केवल विवादों का निपटारा करने वाली मस्या ही नहीं है, बल्कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का भी एक साधन है। यह निर्विवाद है (यद्यपि बहुधा इसकी सराहना नहीं की जाती) कि विवादों का निपटारा करनेवाली सभी संस्थाएँ, चाहे वे सरकारी अथवा प्रणाली से संबंधित हों या सामुदायिक या यवस्था से किसी न किसी रूप में सामाजिक परिवर्तन के हेतु लोक शिक्षण काय संपन्न करती हैं। सरकारी याय प्रणाली, जो यद्यपि विरासत में मिली 'कामन ला' की संस्कृति से ओतप्रोत है अपनी यायिक संस्थाओं के माध्यम से उच्च शिक्षादायक भूमिका का निर्वाह करती है। (चाहे वह विवाद की सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान ही अथवा अपील के स्तर पर।) हा, यह भूमिका न तो सद्धातिक दृष्टि से माय हाती है और न माय की जा सकती है जैसी कि अथ विवि प्रणालियों में, उदाहरणार्थ सोवियत मिषि प्रणाली में इस शिक्षात्मक भूमिका पर स्पष्ट तीर पर ही अधिक बल रहता है। हरिवल्लभ पारीख लोकप्रदात प्रणाली की हर प्रक्रिया का विवाद प्राप्त होन एव उसकी सुनवाई की प्रक्रिया प्रारंभ होने के समय से लेकर अंतिम निर्णय की स्थिति तक और यदि आवश्यक दिमाई दे तो निणय की क्रिया वलि तक का लोक-शिक्षण के रूप में उपयोग करते हैं। हम कह सकते हैं कि याय की इन प्रक्रियाओं एव वास्तविक निणय के दौरान अनेक विषयों पर जस परिवार नियोजन गराव के अत्यधिक सवन से होने वाले दुष्परिणाम लन लन के मामलों में ईमानदारी, महिलाओं के लिय समानता की स्थिति कृपि में उत्तम तरीका का प्रयोग स्वास्थ्य और स्वच्छता स्थापन और मानव गरिमा का महत्व आदि पर व अपनी उपदशात्मक सीधी कायवाही जागरूक ढंग में जारी रगत है और अनेक अवसरों पर लोकप्रदात की बैठकें प्रोत्तिगण कार्यक्रम का माध्यम ही बन जाती हैं। इनमें हरिवल्लभ पारीख बैठकें में उपस्थित लोगों की अपनी दिल्ली और अहमदाबाद की यात्राओं में अनुभव मुनात है और सुदूर विदंगा में रहन वाले लोगों का रहन सहन और कायकलापा एवं समस्याओं के बारे में उनकी जानकारी बढ़न करत है। मेरी दृष्टि में यह लोकप्रदात प्रणाली का 'विकास संबंधी भाय' है। (वर्ष 1975) वर्तमान अध्ययन ने नवें परिच्छेद में इस पर विंग प्रकाश डाला गया है। हम लोकप्रदात प्रणाली के उपदशात्मक तत्व में उत्पन्न

तथा सम्बन्धित विशिष्ट सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों को स्पष्ट किया गया है।

जहां तक सरकारी विधि प्रणाली एवं लोकमदालत प्रणाली के पारस्परिक सम्बन्ध का प्रश्न है, लोकमदालत प्रणाली की अपनी कुछ अनूठी विशेषताएं हैं। समय पाकर लोकमदालत न 'यूनाधिक' रूप में सरकारी विधि प्रणाली की भूमिका को अधिकांश मामलों में पूर्णतः आत्मसात् कर लिया है। न केवल इस क्षेत्र के घटन से निवासी सरकारी विधि प्रणाली का प्रभय नहीं लेने हैं बल्कि जब सरकारी विधि प्रणाली में प्रवृत्त अधिकारियों की यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि उनके सम्मुख प्रस्तुत विवाद की लोकमदालत में सुनवाई चला है या चल रही है तो वे अक्सर अपने सम्मुख प्रस्तुत सुनवाई का स्थगित कर देते हैं ताकि वादी प्रतिवादी का लोकमदालत के माध्यम से अपने विवाद का निपटारा करने का अवसर उपलब्ध हो सके। दूसरे शब्दों में, चाहे यह विरोधाभास लगे इस प्रकार सरकारी विधिप्रणाली में प्रवृत्त अधिकारियों की यह कार्यवाही लोकमदालत की वैधता एवं युक्तता को समर्थन देती है और इस हद तक लोकमदालत प्रणाली सरकारी विधि प्रणाली के ऊपर छा जाने वाली प्रक्रिया है।

लोकमदालत प्रणाली की यह छा जाने वाली प्रवृत्ति प्रतिवादियों का सूचना देने की प्रक्रिया में ही स्पष्टतः दृष्टिगोचर हो जाती है। सरकारी विधिप्रणाली में प्रयुक्त तौर-तरीकों के समान ही लोकमदालत द्वारा भी प्रतिवादी का एक बचन य द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि वह लोकमदालत की कार्यवाहियों में उपस्थित हो अथवा मकदमेबाजी प्रारम्भ हा सकती है जिसका सम्बन्ध में उसे आगाही की जाती है कि "वह हम गरीब किसानों के हित में नहीं है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सरकारी याचिका-प्रणाली की दुर्गुहता और महंगेपन की ही लोकमदालत की कार्यवाहियों में भाग लेने की आवश्यकता का आधार बना दिया गया है। इस प्रकार सामुदायिक आधार पर विवादों का निपटारा करने वाली मस्या द्वारा सरकारी विधि प्रणाली को अपने कार्य के लिए वैधता के रूप में उपयोग करने का ऐसा अनूठा तरीका अब तब अथवा हमारे देश में नहीं पाया है।

यह सही है कि लोकमदालत प्रणाली और सरकारी विधिप्रणाली के एक दूसरे पर छा जाने वाले अथवा विरोधी भूनाव परस्पर सम्बन्धों का केवल एक पहलू है। दाना ही प्रणालियाँ में पारस्परिक पूरकता और पर्याप्तता सम्बन्धों में तत्त्व मौजूद हैं। पारस्परिक पूरकता सम्बन्धी स्थिति का नस्ब विचारधारा

और काय दोनों ही स्तरों पर मौजूद है। विचारधारा व स्तर पर लोक-अदालत प्रणाली शराब मुक्ति भूमिमुक्ति डायना आदि के अवविश्वासा के निराकरण स्त्री पुरुष की समानता आदि में सरकारी प्रयासों की अनुपूरक है। काय सम्बन्धी पारम्परिक पूरकता के स्तर पर लोकअदालत प्रणाली द्वारा बिनादा का निपटारा करने की दिशा में अपनाई गयी भूमिका उस सीमा तक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है जिस सीमा तक इसका निर्णयों से सामाजिक स्थायिक को पापण मिलता है और भारतीय संविधान के अनुसार वांछित समाज व्यवस्था के हेतु व सामाजिक परिवर्तन में सहायक हान है। (अध्ययन के परिच्छेद 8 9 और 10 का अवलोकन करें साथ ही देखें बबसी, 1975)। जहाँ तक रोजमर्रा के पारस्परिक पूरकता सम्बन्धी कार्यों का सवाल है लोकअदालत प्रणाली द्वारा उपलब्ध लाकपाल सम्बन्धी तत्व कानूनी सहायता और सेवा सार्वजनिक रूप से रखे गये रेकाड और वैवाहिक आदि मामला में सलाह देने के कार्य उल्लेखनीय रूप से राज्य के विकास तथा आधुनिकीकरण सम्बन्धी प्रयासों में सहायक होते हैं।

जहाँ तक दोनों प्रणालियाँ में पथकता के प्रश्नों की मौजूदगी का सवाल है, स्थिति कुछ पचीदा है। सामान्यतः गंभीर कौजदारी मामल जस मानव हत्या लोकअदालत सरकारी विधिप्रणाली के लिये छोड़ देती है। लोक-अदालत के प्रारम्भिक जीवन काल में उसके द्वारा ऐसे कुछ मामलों पर अपना निर्णय दिया गये जिनके अनुसार एक मामल में पञ्चायाप करने वाले अपराधी हत्यार को यह दण्ड दिया गया था कि वह समाज की निगरानी में निश्चित अवधि तक मनन के उत्पीडित परिवार की भूमि जोतकर उस पेत में होने वाली पैदावार मतक की विधवा एवं बच्चों का दे और उसका रक्षण का धायित्व वहन करे। सरकारी विधि प्रणाली के अन्तर्गत जो दण्ड-उन परिवारों पर प्रतिकूल असर पड़ता जबकि लोकअदालत की दण्ड प्रक्रिया में उत्पीडित परिवारों के पुनर्वास पर अधिक जोर दिया गया। निश्चय ही पीडित को राहत दिलाते की यह व्यवस्था अधिक उन्नत मानी जानी चाहिए लेकिन लोकअदालत द्वारा निर्णित इस प्रकार के मामले अब अतीत की बातें मात्र रह गयी हैं। हमारे सर्वेक्षण के दौरान आश्रम के पास नदी में बहती हुई एक ताल का मामला हमारे सामने आया जिसमें उस ताल का जाल के नियम तत्काल पुनर्निर्माण के लिए किया गया था।

मगर कुछ मामलों में लोकअदालत प्रणाली और सरकारी विधिप्रणाली दोनों न एक रूप हाकर एक प्रकार से महमत् बढ़ा उठा है। जैसे जीजा

भाई रेवती और बेहला भाई के मामले। (विशेष विवरण देखें—परीख 1973) यहाँ दानो प्रणालियाँ म पारम्परिक प्रतियोगिता की स्थिति रही। इस सन्दर्भ में सरकारी विधि प्रणाली की कायवाही के प्रति आदरभाव का दर्शन होता है। उदाहरण के लिये जब बेहलाभाई मन्त्र धा विवाद के मामले में श्री हरिवल्लभ परीख को गिरफ्तार किया गया और बाद में गमानगर छोड़ा गया तो उन्होंने तमाम दबाव के बावजूद लोकप्रदालत में उस विवाद की सुनवाई उस समय तक नहीं होने दी जब तक सरकारी विधिप्रणाली के अंतर्गत उस विवाद की सुनवाई की कायवाही पूरी नहीं हो गयी। रेवती के जटिल मामले में जिस कुशलता के साथ समझौता प्रचार सीधी कायवाही एवं समाचार पत्रों के सम्मिलित माध्यमों का उपयोग किया गया वह लोकप्रदालत प्रणाली की 'छा जाने वाली भावना का सज्जक है। यही प्रवृत्ति, जैसा कि पहले कहा गया है प्रतिबान्नी की लोकप्रदानत के समक्ष बुलाने के नियम प्रयुक्त तौर-तरीके में भी परिलक्षित होती है, जिसमें लोकप्रदानत की कायवाही में प्रतिबान्नी को भागीदार बनाने हेतु सरकारी विधि प्रणाली के तत्त एव प्रकार की अनुज्ञा के रूप में उपयोग किया जाता है।

लोकप्रदानत प्रणाली को किन कारणों से यह सफलता प्राप्त हुई, इसका विश्लेषण करें तो एक कारण तो हमें यह दृष्टिगोचर हुआ है कि इस क्षेत्र में सरकारी विधि प्रणाली की उपस्थिति अत्यंत अल्प है। सरकारी विधि प्रणाली के अंतर्गत बाधरत प्रशासनिक व्यवस्थाएँ भी इस क्षेत्र से बहुत दूरी पर स्थित हैं। यातायात एवं संचार के पयाप्त साधनों का अभाव इस क्षेत्र के लोगों को इस प्रणाली से पयव रखे हुए है। (देखें अध्याय 4)। तीसरा कारण यह है कि लोकप्रदानत द्वारा किये गये विवादों के निणयो से प्रभावित होकर क्षेत्र के अधिकांश निवासी यह महसूस करने लगे हैं कि लोकप्रदानत प्रणाली द्वारा निष्पादित पाय गुणात्मक दृष्टि से सरकारी विधि प्रणाली के अंतर्गत उपनब्ध न्याय से कहीं अधिक 'सतोपयुक्त' है। आमाम पटुच तत्परता और कम खर्चों के अलावा इन कारणों का भी अपना महत्व है— लोकप्रदानत प्रणाली की सफलता का एक आधारभूत कारण यह प्रतीत होता है कि विवाद का निपटारा करने के नियम प्रयुक्त इसकी काय पद्धति अत्यंत जनताग्रिक है। (देखें अध्याय 10 और 11) लोकप्रदानत द्वारा विवादों के निपटारा के लिये महत्वपूर्ण आधारभूत मूल्य के रूप में समुदाय को भागीदार बनाने की जा नीति अपनाई जाती है और उस प्रक्रिया एवं काय विधि एा जिस ढंग से गठन किया गया है, उनमें सामुदायिक भागीदारी के मूल्य की अधिकतम उपनब्धि हुई है। जनसमुदाय की इस ढंग की श्रेष्ठ

भागीदारी न इस संस्था एवं इसकी कायप्रणाली की सामाजिक दृष्टि से अधिक स्पष्ट और उत्तरदायी बना दिया है। इसी व प्रतीक स्वरूप यह भागीदारी लोकप्रदात तथा इसका नेता की वैधता का निरंतर नवीनीकरण करती रहती है और इसका निणया की सामुदायिक इच्छा या समाज से जनमत की अनुज्ञा का स्वरूप प्रदान करती रहती है।

यह जानी मानी सिवायत है कि जनतांत्रिक जिंदाई देन वाल तरीके या कायविधिया भी प्रायः निर्णायक शक्ति के क्षेत्रों का मुहोटा लगाय रहती है। प्रायः जनसाधारण की सहमति से किय जाने वाल निर्णय थोड़े से लोगों द्वारा कमरा में लिये गये निर्णय का औपचारिक समर्थन मात्र होते हैं। किंतु प्रस्तुत अध्ययन यह विश्वास करने का व्यावहारिक आधार प्रदान करता है कि विवादा का निपटारा करने के लिय प्रयुक्त लोकप्रणालत की काय प्रणाली में जनसाधारण की भागीदारी केवल दिखावटी प्रयवा प्रतीकात्मक चेष्टा नहीं है। (हमने अपने प्रारम्भिक अध्ययन में भी इस तथ्य को व्यावहारिक रूप में स्वीकार किया था) इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि लोकप्रदात प्रणाली की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण इसका प्रयुक्त कायविधि एवं प्रक्रिया का उच्च जनतांत्रिक स्वरूप है।

तथापि लोकप्रदात प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त 'याय' की गुणात्मकता सम्बन्धी प्रश्न तो रह ही जात है। इस अध्ययन में ये प्रश्न स्पष्ट भाषा में मुखरित होकर सीधे सामने नहीं आये हैं बल्कि लोकप्रदात के भविष्य के प्रति सदेहात्मकता का रूप में प्रस्तुत किये गये हैं। लेखकगण महसूस करते हैं कि लोकप्रदात प्रणाली का भविष्य सदेहात्मक प्रयवा समझाया जा सकता है क्योंकि यह प्रणाली एक व्यक्ति पर आधारित हो गयी है। श्री हरिवल्लभ भाई के समर्पित जीवन, जादू भरे आकाशक व्यक्तित्व और श्री हरिवल्लभ भाई के कारण लोकप्रदात को इसके मौजूदा स्वरूप की प्राप्ति हुई है। नेता एवं गायकर्ता दोनों रूपों में उनकी शक्ति एवं प्रतिष्ठा अद्वितीय है लेकिन एक व्यक्ति के नेतृत्व पर अत्यधिक आश्रित रखने की इस परिस्थिति में अधिनायकवाद की प्रबल प्रवृत्ति अनिवार्यत उत्पन्न हो जाती है। यह प्रवृत्ति याय उपलब्धि में किस सीमा तक सहायक सिद्ध हुई है यह एक विचारणीय विषय है। निस्संदेह लोकप्रदात काय प्रणाली बहुत जनतांत्रिक है और इसका निणय तुरंत काय रूप में परिणित कराये जाते हैं। (हम इस प्रति की मनोवैज्ञानिकता कहेंगे) लेकिन जब सम्पूर्ण कायविधि एक व्यक्ति के ह्द गिर धूमती रहती है तो उसमें न केवल निरंतरता के लक्षण खतरे में पड़ जाते हैं बल्कि समकारीन एवं भावी नेतृत्व व विकास

की सम्भावनाएँ भी सीमित हो जाती हैं। साथ ही ऐसी अपेक्षा भी वास्तव में नहीं रखी जा सकती कि जनसमुदाय प्रत्येक निर्णय का उसके वास्तविक 'यायपरक्ता' के गुणों के कारण आदर करता है। हम बहिष्कार यह स्वीकार करना चाहिए कि कुछ निर्णय यायकर्त्ता की विवेक बुद्धि पर आधारित, मनमान (इस अर्थ में कि दो समान परिस्थितियों में विभिन्न निर्णय हो जाते हैं) और कभी-कभी तुलनात्मक रूप से पक्षपात युक्त भी हो सकते हैं (पक्षपात युक्त इस अर्थ में कि वे सिद्धांत या नियम पर आधारित होने के बजाय अवसर या परिस्थिति पर आधारित हो जाते हैं या वे अथ सामाजिक तथा विधि के क्षेत्र के बाहर के विवादों में 'यायकर्त्ताओं' तक 'वादों' प्रतिवादी की अपेक्षाकृत 'यूनाधिक' पहुँच के कारण प्रभावित हो जाते हैं) इस प्रकार की परिस्थितियाँ रंगपुर स्थित गोकर्णदानत एवं ग्रामदानी गाँवों की ग्रामसभाओं के सघात्मक सम्बन्धों में विशेष रूप से अभिव्यक्त हो सकती हैं, क्योंकि ग्रामदानी गाँवों की ग्रामसभाओं के कार्यकर्त्ता विचारधारा और व्यवहार दोनों दृष्टियों से श्री हरिवल्लभ भाई के प्रति समर्पित हैं।

इसके साथ ही यह भी समझना होगा कि चाहे सवधानिक दृष्टि इस स्वच्छ दत्ता पक्षपात, अवसरवादिता, अग्रगण्य और अधिनायकता के विपरीत हो, पर सरकारी विधिप्रणाली और प्रशासनिक श्रेणियों के प्रतिनिधि भी यूनाधिक रूप में अपने निर्णयों में इसी बुराईयाँ की अभिव्यक्ति करते रहते हैं लेकिन लोकअदालत प्रणाली इस अर्थ में उक्त प्रणाली से भिन्न है कि कार्य प्रणाली की रुढ़ता एवं अफसरशाही की अवश्यभावी प्रवृत्ति के बावजूद अंतिम अधिकार एक व्यक्ति में केन्द्रित है। इसके विपरीत औपचारिक राज्य पद्धति, मार दुर्गुणों के बावजूद, ऊपर से नीचे तक क्रमिक उत्तरदायित्व भावना से ओतप्रोत है, चाहे फिर इस प्रकार की जवाबदेही में सर्व सामान्य की पहुँच की कितनी ही सीमाएँ क्या न हों। श्री हरिवल्लभ परीत के अलावा क्रमिक नियंत्रण की कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं है। नियंत्रण की औपचारिक यंत्र रचना शक्तिधारक और उस शक्ति का मायता देकर शक्तिधारकों के आदेशों निर्देशों को मानने वाले शक्तिदाताओं की पारम्परिक सम्बन्ध स्थिति—अवश्य मौजूद है और हर प्रकार के शक्ति ढाँचे में यह स्थिति अवश्यम्भावी है। अंतिम तौर पर विश्लेषण प्रस्तुत करें, तो यह सब शक्ति सम्बन्धों में समता और विशिष्टता का ही प्रतीक है।

इस का यह तात्पर्य नहीं है कि अधिनायकवाद की ओर उन्मुख यह प्रवृत्ति सभी मदों में आवश्यक तौर पर हितकर हो लेकिन लम्बो अवधि में यह प्रवृत्ति ऐसी सिद्ध हो सकती है क्योंकि इससे लोकअदालत प्रणाली का एक

विशिष्ट प्रकार की सीमा मर्यादा प्राप्त हो सक्ती है जो समय की परिधि में वास्तव में सभी सामाजिक प्रणालियों का एक सामान्य नक्षण रहा है।

यस्तुतः लाकडासले प्रणाली सामुदायिक विवाद निणय प्रणाली का एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करती है जो कुछ बातों में राज्य की विधि प्रणाली में श्रृंखला है। लेकिन इस प्रणाली में निहित गुणों की मर्यादा करने का यह अवश्य-भावी अर्थ भी नहीं कि सरकारी विधिप्रणाली संपूर्णतः दोषयुक्त ही है। इस अध्ययन में मुख्यतया इसके अतिरिक्त अध्यायो में, पाठकों का ऐसा महसूस हो सकता है कि इस का लक्ष्य मर्यादित भुक्त सरकारी विधिप्रणाली में विच्छेद है। यह भुक्त वास्तव में दृढ़ता से ग्रहित मान्यताओं की अभिव्यक्ति हो सकता है जो नैतिक की ग्राम मर्यादा में बौद्धिक और सामाजिक मूल निष्ठा से उत्पन्न है। भुक्त तथा मान्यता के बीच सीमा रखा नहीं भी हो यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत अध्ययन के लेखकों की सरकारी विधिप्रणाली में बहुत कम आस्था है। उनका कथन है कि सरकारी विधिप्रणाली के अतःगत कार्यरत यायालयों का लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन लाना है ही नहीं। "याय प्रदान करने में जनसाधारण की उन तक पहुँच नहीं है और न उनमें गतिशीलता है, न उनमें खर्च की सीमा है और न उनमें जनताप्रियता का तत्त्व है। उक्त दोनों कथनों में सत्य का अंश तो है पर पूरा सच्चाई नहीं है। कुछ यायाधीश इस अर्थ में सत्रियावादी होते हैं कि उनका भुक्त गविवधान में अतिनिहित या कानून द्वारा अप्रक्षित सामाजिक परिवर्तन का समयन देने के उद्देश्य से विधि के सारे उपकरणों के उपयोग की आरंभ होता है। इतिहास ने बार बार इस तथ्य को प्रकट किया है कि परिवर्तन की ओर उन्मुख यायाधीश प्रभावपूर्ण ढंग से कानून का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यह भी सही है कि ऐसे यायाधीशों की संख्या या उनके काम के प्रभाव का दिग्दर्शन कराने वाले कोई अध्ययन उपलब्ध नहीं है (यद्यपि ऐसे अध्ययनों की अत्यंत आवश्यकता है) लेकिन यहाँ मौजूदा सम्भ्रम में इस पहलू पर इतना जोर दे देना ही पर्याप्त होगा।

सरकारी विधि प्रणाली की याय सम्बन्धी गुणात्मकता के प्रति दोषारोपण का निराकरण करना थोड़ा कठिन है। एक तो यह कि सरकारी विधि-प्रणाली के अतःगत किये जाने वाले याय के जो भवेत्क माने गये हैं अर्थात् त्वरा व्यय और पहुँच— इनके सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय आँकड़े ही नहीं। हाँ विवादों के निपटारा में होने वाला विलम्ब के सम्बन्ध में स्थूल आँकड़े अवश्य प्राप्त हैं, पर उनसे कुछ अर्थ नहीं निकलता।

विधि का जिस ढंग का भारीभरकम ढाँचा बना हुआ है उसका कारण

स्पष्ट हो 'याय प्रक्रिया' में 'विलम्ब' (अति महत्वपूर्ण विवादों में होने वाले कुछ अतीव विलम्ब के मामलों के अलावा) कानून के अंतर्गत गठित सामान्य प्रक्रिया की एक व्यवस्था हो बन जाता है। निर्णय की शीघ्रता अपने आपमें कोई मूल्य नहीं है और न यह होना ही चाहिए। लोकप्रदानत में भी यह कोई बड़ा मूल्य नहीं है। इसके अतिरिक्त 'यामातया' में विनम्ब सम्बन्धी नियम अधिकांश मामलों में मूल्य सम्बन्धी नियमों के समान ही होते हैं। दूसरे शब्दों में यह भी स्पष्ट नहीं है कि विनम्ब के सम्बन्ध में नियमों के तहत समय हमारे दिमाग में कोई ऐसा भावबोध मौजूद है कि, जिस मामले में कितना समय लगना उचित है, यह बतला सके। यह प्रश्न न भी उठाया जाये तो जब हम सरकारी विधिप्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध नियमों में होने वाले विलम्ब का जिक्र करें तो उसकी पुष्टि के लिए हमारे पास अनुभवों एवं जानकारी विधि-वेत्ताओं द्वारा एकत्रित प्रमाणित तथ्यों का संग्रह होना चाहिए। सरकारी विधि प्रक्रिया के सामान्य स्वरूप के कारण विवादों के प्रस्तुतीकरण में समय लगेगा ही। यह भी कहना बठिन है कि किस समय बिंदु के आग और किस प्रकार के मामलों में कब विलम्ब या समय लगने की भयावहता का उल्लेख प्रारम्भ हो जाता है। जानकारी और सदाशयी लोग, जब वे कानून के विलम्बों की चर्चा करते हैं तो वे इस प्रश्न का उठाते भी नहीं, उत्तर देने की बात तो भूल ही जाते हैं।

उक्त सन्दर्भ में विधि प्रक्रिया के बारे में अतन्त्र से दिये गये नियमों का अपना स्थान है और वे सही हो सकते हैं लेकिन वही स्थिति वैज्ञानिक आधार पर दिये जाने वाले नियमों के बारे में भी है। पूर्ववर्ती प्रकार के नियमों का बाहुल्य है, तो परवर्ती प्रकार के निर्णय कम हैं।

सरकारी विधि प्रणाली के बारे में यह दोष दर्शन कि वह पुरानी अथवा जनसाधारण की पहुँच से परे है बहुत सामान्य बात हो गयी है और इसमें सामान्यतया सच्चाई भी है। सबको समान ढंग से याय उपलब्ध कराने की समस्याओं का समाधान कानूनी सहायता तथा सेवा उपलब्ध के कार्यक्रमों और कानून के सुधार से कुछ हद तक हो सकता है। लेकिन अतन्त्रता (जिसमें जन के अनुभव से सिद्ध है) ऐसे कार्यक्रमों केवल अल्पकालीन राहत दे सकते हैं वे समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। यह बात कानून सुधार कार्यक्रमों की तुलना में कानूनी सहायता एवं सेवा कार्यक्रमों के बारे में अधिक सही हो सकती है। लेकिन कानूनी सुधारों को भी विधि प्रणाली के मूलभूत ढाँचे का समादर करना ही पड़ता है। लोकप्रदानत जैसी समस्याओं का अध्ययन वर्तमान विधि प्रणाली के विवरणों के द्वारा में (इस सम्बन्ध में मैं इस दृष्टि में बहुत कम

रचनात्मक चिंतन हुआ है) आधारभूत प्रश्न गड़ा करता है। निश्चय ही किसी भी देश की विधि प्रणाली उस देश की राजनैतिक प्रणाली के अंग के रूप में कार्य करती है लेकिन प्रायः उस विधि प्रणाली की अपनी निजी स्वायत्तता होती है। जसा कि राबर्ट अगर् न हाल ही में दुहराया है कि 'इस स्वायत्तता के चार पहलू हैं—(1) पक्ष सत्ता सम्बंधी (2) संस्थागत, (3) कार्य विधि सम्बंधी और (4) व्यवसायात्मक' (अगर् 1976 52-54)। इसलिये इस बात की पर्याप्त गूँजाइश है कि स्वायत्तता की इन सीमाओं के भीतर विधि एक कार्य विधि के वैकल्पिक नमूने प्रस्तुत करने की कोशिश एक हद तक की जा सकती है।

अतः मैं यह तो मानना ही होगा कि मौजूदा राजकीय न्यायालय प्रणाली जनसाधारण की भागीदारी का एक मूल्य का रूप में स्वीकार नहीं करती। जूरी प्रणाली इसका एक उदाहरण है। कुछ और भी ऐसे परबन्धन महत्वपूर्ण उदाहरण रहे हैं (देखें—जैन, 1976 134) लेकिन यहाँ वह वस्तुतः समाप्त प्रायः है। न्याय और उसमें जनसाधारण की न्यायक भागीदारी का पारस्परिक सम्बंध—हमेशा ही कार्य-कारण रूप में नहीं ठहराया जा सकता। कुछ स्थितियों में ऐसा संभव है (जैसे कि मजबूत लोकप्रदात में)। लेकिन अनेक मामलों में इससे भिन्न स्थिति भी हो सकती है—उदाहरण के लिये क्रूर न्याय (Lynch Justice)। उमादप्रस्त भीड़ द्वारा लिये गये निर्णयों में जनसाधारण की न्यायक भागीदारी तो होती है लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उसका निर्णय आवश्यक रूप से न्यायपूर्ण ही हो। यहाँ तक कि जूरी प्रणाली में जूरीगण भी अपनी वानून विरोधी हरकतों के लिये दुरुप्राप्त हैं (उदाहरणार्थ कडीश एम और और कडीश एस एच एच 1971 199)। यहाँ इस विषय में चर्चा बटाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी यह कहना पर्याप्त होगा कि विवादों का निपटारा करने वाली संस्थाओं में निर्णय देने की प्रक्रिया में जन भागीदारी का सम्बंध एक खराब प्रश्न ही रहना चाहिये।

इस प्रकार के अध्ययनों की शायद यह दुर्भाग्यपूर्ण उपलब्धि है कि वे बहुत से मूलभूत प्रकार के जटिल प्रश्न गड़े कर देते हैं। वर्तमान अध्ययन भी अपनी दोनों प्रकार की सीमाओं—सद्धातिक एवं प्रयोगिक—में बिल्कुल इस प्रकार के चिंतन का आवाहन करता है। यह इसका बहुमूल्य योगदान है। लोकप्रदात स्वतः ही समाज निमाताओं की वर्तमान भारत में एक उपयुक्त विधि प्रणाली और सामाजिक व्यवस्था के निमाण के लिये नये सिरे से चिंतन करने की सगर्ब प्रेरणा प्रदान करता है।

उपेन्द्र बक्सो (सकायाध्यक्ष)

विधि सकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्रारम्भिक

गुजरात के बड़ोदा जिले में आनंद निकेतन आश्रम के माध्यम से आस पास के ग्रामीण क्षेत्र में महात्मा गांधी की प्रेरणा के अनुरूप सघन रचनात्मक कार्यक्रम गत पच्चीस वर्ष से चल रहा है, जिसका संचालन प्रारम्भ से ही आश्रम के संस्थापक-अध्यक्ष श्री हरिवल्लभ परोख द्वारा किया जा रहा है। वे लोकप्रदालत के नाम से जन-यायालय का एक अभिनव सामाजिक प्रयोग कर रहे हैं, जिसके द्वारा अब तक लगभग बीस हजार मामलों का फैसला और समाधान हो चुका है। इस प्रयोग का कुछ परिचय श्री हरिवल्लभ परोख ने 'नाति का अरुणोदय' नामक पुस्तिका में दिया और इसका संक्षिप्त अध्ययन डा लक्ष्मीलाल सिंघवी और डा उपद्र बक्सी ने किया। कुमारप्पा ग्रामस्वराज्य संस्थान ने इस सामाजिक प्रयोग का थोड़ा विस्तार और गहराई से अध्ययन करने का निश्चय किया और तदनुसार इसकी एक योजना भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली को प्रेषित की। सतोप की बात है कि परिषद् ने इस योजना को अपनी स्वीकृति प्रदान की और इसकी आवश्यक आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया।

इस अध्ययन का प्रारम्भ 1 अप्रैल 1975 से किया गया। योजना की सलाहकार समिति का इस कार्य में पूरा सहयोग मिला। समिति की बैठकें आनंद निकेतन आश्रम, रणपुर तथा जयपुर में बुलाई गईं। हरिवल्लभ परोख और उनके साथी कार्यक्रमियों ने इस अध्ययन में बहुत रुचि ली और सारी जानकारी जो लिखित और मौखिक उनके पास थी, सबसे हमें अवगत किया। लोकप्रदालत के अध्येक्षकों में हम स्वयं शामिल हुए आसपास के गांवों में घूमे, लोगों से प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त किया और बातचीत की। डा विजयशंकर व्यास, डा उपद्र बक्सी का पूरा सहयोग और भागदान इस अध्ययन को प्राप्त हुआ। डा एस पी वर्मा ने भी अध्ययन में बहुत रुचि दिखाई और समय-समय पर आवश्यक सुझाव दिये।

योजना निर्देशक डा अवधप्रसाद ने इस योजना का संचालन किया। उनके सहायक श्री गोपीनाथ गुप्त और श्री पी के सवानी ने उस सारे कार्य को पूरा करने में बहुत परिश्रम किया है। राजस्थान विश्वविद्यालय, ज

म समाजसाक्ष्य विभाग के अध्ययन के नरेन्द्र सिन्धी का प्रारम्भ से ही इस अध्ययन में पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन मिला। उन्होंने परिश्रमपूर्वक अध्ययन को अंतिम रूप देने में मन्द की।

संस्थान भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् के सदस्य मन्त्रि श्री जे. पी. नायक, निर्देशक डा. नरुना तथा अथ उच्चाधिकारियों का विनाशकारी है जिनके प्रोत्साहन के बिना इस योजना का प्रारम्भ और पूर्ति नहीं हो सकती थी। योजना 30 नवम्बर तक पूरी हो जानी थी पर कुछ कारणों से दो माह की अवधि और बढ़ानी पड़ी। जनवरी के अंत में यह अध्ययन परिषद् को प्रेषित कर दिया गया था।

परिषद् ने इस अध्ययन को अपनी भाषा प्रदान की और इस के प्रकाशन के लिए भी कुछ आर्थिक सहायता स्वीकृत की। इसे प्रकाशित करने का उत्तरदायित्व स्टैनग पब्लिशर्स दिल्ली ने स्वीकार किया। संस्थान इन दोनों का बहुत आभारी है।

इस प्रकार के अर्थ प्रयोग भी इस देश के विभिन्न भागों में चलते हैं और कुछ अब भी चल रहे हैं। इनका अध्ययन किया जाना भी हमारे विचार से उपयोगी होगा।

कुमारप्पा ग्रामस्वराज्य संस्थान,

जयपुर।

2-4-77

जवाहिरलाल जैन

मंत्री निर्देशक

विषय-सूची

ग्राममुख	v
भूमिका	XIII
प्रारम्भिक	XXV
अध्ययन की पष्ठभूमि	1
भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति	18
परम्परागत आदिवासी समाज में 'याय' व्यवस्था	31
ग्राम की सामाजिक संरचना	44
लोकअदालत का संगठन	56
लोकअदालत की कार्य पद्धति	67
निर्णय की पूर्ति	85
निर्णय की प्रक्रिया और भावना	92
लोकअदालत और सामाजिक	
आर्थिक परिवर्तन	100
'यायालय' और लोकअदालत	113
लोक जागृति और 'याय' में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना	126
उपसंहार	137
परिशिष्ट	153
(क) लोकअदालत में निर्णित विवादों के नमूने	154
(ख) सरकारी 'यायालयों' में प्रस्तुत विवादों के नमूने	165
(ग) लोकअदालत और समस्याओं के समाधान का प्रयास	167
(घ) करारवत के नमूने	195
अनुमोचिका	202
संदर्भ ग्रंथ	216
विषयानुक्रमिका	219

1

अध्ययन की पृष्ठभूमि

मानव समाज के विकास के साथ उसके सामाजिक जीवन को संगठित एवं नियंत्रित करने वाली अनेक संस्थाओं एवं व्यवस्थाओं का भी क्रमिक विकास हुआ। इन संस्थाओं में मुख्य है—विवाह, परिवार, धर्म, राज्य आदि। ये संस्थाएँ सार्वभौमिक रही हैं चाहे देश, काल एवं श्रम के अनुसार उनके स्वरूप में यूनाधिक भिन्नताएँ दृष्टिगोचर होती रही हों। सामुदायिक जीवन में आने वाले व्यक्ति के पारस्परिक सम्बन्धों एवं आचरणों का नियमबद्ध करने वाली व्यवस्थाओं में न्यायिक संस्था का मुख्य स्थान रहा है और उसकी सार्वभौमिकता भी सर्वविदित है। 'याय' व्यवस्था के संचालन के लिए प्रादिकाल से ही मानव समाज ने याय के कुछ नियमों का सहारा लिया है। विभिन्न देशों की भौगोलिक परिस्थितियों एवं उनके फलस्वरूप विकसित सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन की भिन्नताओं के कारण नियमों में अंतर भले ही हो रहा हो लेकिन आधारभूत नियमों में सभी जगह सादृश्य देखा जा सकता है। इन आधारभूत नियमों में मुख्य ये माने जा सकते हैं जैसे, (क) अपराधी को दंड मिले, (ख) ऐसे व्यक्ति को दंड न मिले जो निर्दोष हों (ग) यायालय के सम्मुख सब समान हैं, आदि। कानून एवं याय सामाजिक जीवन के अभिन्न भग हैं। समाज में कानून का निर्माण नैतिकता के पोषण के लिए होता है और इस प्रकार दोनों का निकट सम्बन्ध है। जिस समाज में जितनी अधिक नैतिकता होगी वहाँ कानून का पालन उतना ही अधिक होगा। यह दखने में आया है कि सामान्यतया परम्परागत नियम नैतिकता की भित्ति पर आधारित रहे हैं।

किसी देश की यायिक संस्था के विकास का सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए क्योंकि उसका विकास उसी परिप्रेक्ष्य में होता है। यायिक संस्था की संरचना, याय प्रक्रिया, न्यायिक मूल्य एवं दंड आदि

मे सामाजिक एव सांस्कृतिक भिन्नता के कारण अंतर पाया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से 'याय' व्यवस्था पर विचार करें तो यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि प्रायः सभी देशों में 'याय' का अंतिम अधिकार राज्य में निहित रहा है। राजतंत्रीय शासनपद्धति में यह व्यवस्था स्वभावतः राजा के हाथों में केन्द्रित होती है। भारतीय इतिहास से इस बात की भी पुष्टि होती है कि यहाँ 'याय' व्यवस्था मुख्यतः दो भागों में विभक्त थी (1) 'याय' का नाय राज्य के हाथों में था और उसका निष्पत्ति अंतिम होता था, यद्यपि वह अपनी सहायता के लिये इस कार्य में अन्य लोगों को सगाने का अधिकार रखता था। (2) स्थानीय स्तर पर पचायती व्यवस्था थी। यहाँ प्राचीन काल से ही ग्रामस्तर पर पचायती 'याय' प्रणाली की ठोस परम्परा रही। इस व्यवस्था में गाव के पचा द्वारा जिनकी सख्या ग्रामतौर पर पाँच होती है विवादों को सुलझाया जाता रहा। गादिवासी समाज में यह परम्परा आज भी देखी जा सकती है।¹

भारत में ब्रिटिश शासनपद्धति के जरिये पाश्चात्य ढंग की 'याय' प्रणाली का विकास हुआ। आज जो कानूनसम्मत 'याय' व्यवस्था भारत में प्रचलित है उसका आधार पाश्चात्य 'याय' व्यवस्था है। कानून भारतीय समस्याओं को दृष्टिगत रखकर भल ही बनाये गये हो, परन्तु विवादों को सुलझाने के लिये जो पद्धति जारी की गई है, वह ब्रिटिश साम्राज्य की देन है। ब्रिटिश साम्राज्य ने विभिन्न स्तर के 'याय'ालयों की स्थापना की और अपनी आवश्यकतानुसार क्रमशः उन्हें मजबूत करता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने भी उसी 'याय' व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। यहाँ यह स्वीकार किया जाना चाहिये कि हमारे देश का संविधान भी पाश्चात्य देशों के संविधानों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया एव इस व्यवस्था के अनुसार विधायिका, नायपालिका एव 'याय'पालिका के बीच सम-वय-ात्मक सम्बन्ध रखते हुए सबका समक्ष एव अधिकार क्षेत्र अलग-अलग निर्धारित किया गया। संविधान की मूल भावना यह रही कि सबको निष्पक्ष 'याय' मिले।

भारतीय संविधान में पचायतीराज की व्यवस्था को लागू करने का भी प्रावधान है। भारत में लोकतांत्रिक समाज की जड़ें मजबूत करने के लिये पचायतीराज को आवश्यक माना गया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सन् 1959 में देश में पचायतीराज को प्रारम्भ किया गया और आज पूरा देश पचायतीराज की परिधि में आ गया है। पचायतीराज की व्यवस्था में याय पचायत का मुख्य स्थान है। 'याय'पचायत की स्थापना के पीछे यह भावना थी कि जन साधारण को स्थानीय स्तर पर सहज-सरल 'याय' प्राप्त हो

और सामान्य मामलों के लिये दूर के न्यायालयों में जाने की परेशानी एवं खर्च से बचा जा सके। इसके साथ साथ विवेचित समाज रचना की दृष्टि से न्याय कार्य को विवेचित करने की दिशा में इसे एक कदम माना गया।¹ न्यायपचायतों किस सीमा तक इस उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर सकी है यह अलग प्रश्न है और यहाँ इस प्रश्न पर विचार करना संभव भी नहीं। फिर भी यह एक तथ्य है कि न्यायपचायतों के माध्यम से विवेचित आधार पर न्याय कार्य की व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया गया है।

यह व्यवस्था एक सीमा तक गांधीजी द्वारा प्रतिपादित पचायतीराज की कल्पना का एक हल्का-सा रूप है। गांधीजी ने न्याय कार्य को ग्रामस्वराज्य का एक अंग माना था लेकिन उनकी कल्पना का ग्रामस्वराज्य अभी मूर्त रूप नहीं ले पाया है।² आज की न्यायपचायतें स्थानीय स्तर पर एक सीमा तक ही न्याय की सुविधा प्रदान करती हैं जबकि गांधीजी ग्राम सम्बंधी सभी विवाद ग्रामपचायता द्वारा सुलझाये जाने की आकांक्षा रखते थे।

वर्तमान न्यायव्यवस्था में न्याय सर्व सुलभ नहीं हो पाता है और दूर गांव में रहने वाला सामान्य नागरिक अपने को इस स्थिति में नहीं पाता कि गांव से दूर जा कर न्याय प्राप्त कर सके। सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अशिक्षित व्यक्ति न्यायालय में अपने को असहाय महसूस करता है। वह इस आर्थिक स्थिति में भी नहीं होता कि न्यायालय तक जा सके और न्याय प्राप्त कर सके। पचायतीराज की न्यायपचायतें इस कमी को एक सीमा तक तो पूरी करती हैं लेकिन उनका कार्यक्षेत्र काफी सीमित है। सरकारी न्यायालय में जाने में गांव के सामान्य लोगों को अनेक प्रकार की कठिनाइयां होती हैं जैसे

- (1) समय ज्यादा लगता,
- (2) अधिक खर्च
- (3) कानूनी उलझनें जिनके कारण वकील की मदद लेना आवश्यक होता है,
- (4) जटिल पद्धति।

गांव के लोगों के लिये न्यायालय की दौड़ परेशानी में डालने वाली भी होती है। वहाँ के कानूनी दावपेंच, गवाही, पेन्गी खर्च का बोझ, आदि के कारण जो परिस्थिति बनती है, उसमें उसके लिए न्याय पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। न्यायव्यवस्था की इन परेशानियों से देहात में रहने वाले जन-साधारण का मुक्ति प्रदान करने के लिये ही गांधीजी ने पचायतीराज की

कल्पना प्रस्तुत की थी और कहा था—‘जब पचायतीराज बनेगा तब लोकमत सब कुछ करवा लगा।’ गांव का शासन चलाने के लिये हर साल गांव के पांच आदमियों की एक पचायत चुनी जाएगी। इसके लिये नियमानुसार एक खास निर्धारित योग्यता वाले गांव के बालिंग स्त्री पुरुषों को अधिकार होगा कि वे अपने पंच चुन लें। इन पचायतों को सब प्रकार की आवश्यक सत्ता और अधिकार रहेंगे।⁴

पचायत की इस व्यवस्था के पीछे भारतीय ग्राम्य समाज की प्रकृति के अनुरूप ‘यायप्रणाली’ विकसित करने का लक्ष्य रहा है। गांव के लोगों को ग्राम स्तर पर ही शोध, सत्ता एवं सरल ‘याय’ मिले, यह गांधीजी का मूल उद्देश्य था।

गांधीजी ने परम्परागत यायालय के स्थान पर जिस प्रकार के पचायती याय की बात कही, उसकी मुख्य विशेषताओं को हम इस रूप में गिना सकते हैं —

- (1) इसका कार्यक्षेत्र ग्राम स्तर पर होता है।
- (2) इसमें पंच गांव के लोग ही होते हैं जिन्हें गांव की एक विवाद की पूरी जानकारी होती है।
- (3) ‘याय-नाय’ खेल रूप में होता है।
- (4) इसमें स्वशासन की भावना होती है।
- (5) इसमें दबाव का स्थान नहीं होता है।

लोकअदालत-स्थापना की परिस्थिति

गांधीजी ने ग्रामसेवक की निस्वार्थ हाकर ग्रामसेवा काय करने की बात कही थी। इस प्रकार की निस्वार्थ सेवा से ही ग्राम स्वराज्य की स्थापना होगी और सच्चा स्वराज्य प्राप्त हो सकेगा यह उनकी दृढ़ धारणा थी। वे कहते थे कि ग्रामसेवक गांव के ऊपर बोझ बनने के बजाय मेहनत की कमाई खायगा और स्वयं को आदश के रूप में प्रस्तुत करेगा। उसका प्रभाव ग्राम समाज पर पड़ेगा। गांव के लोग उसकी क्रियाओं में प्रेरणा लेंगे। इस प्रकार सच्चा ग्रामसेवक गांव को आदश बनने के लिये प्रेरणा देगा।⁵

भारत में अनेक लोगो ने गांधीजी द्वारा बताये गये रास्ते पर ग्राम पुनर्निर्माण का काम प्रारम्भ किया था। इसी प्रकार का एक कार्यक्रम 1949 में रायपुर (छत्तीसगढ़) में चालू हुआ। उस समय इस क्षेत्र का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन अत्यंत पिछड़ा हुआ था।⁶ आदिवासी क्षेत्र होने के

कारण प्राथमिक विद्यार्थी व माध्यमिक माध्यमिक प्रथममानता की जड़े भी काफी गहरी थीं। जीवन व सभी क्षेत्रों में साम्यवाद विद्यमान था। इस परिस्थिति में मुक्ति का प्रयास भी इस माध्यमिक व मूलभूत एवं प्रगतिशील श्री हरिबल्लभ परीक्षा व प्रारम्भ बिना और साम्यवाद मुक्ति व साम्यवाद का प्रमुख धर्म बताया। महाजन जगत व कमजोरी पुनर्गठन एवं बड़े किसानों द्वारा जीवन की परिस्थितियाँ न इस क्षेत्र के प्राथमिकता का मरवाती साम्यवाद में जान की मजबूर कर रहा था एवं साम्यवादी समाज के परिवारिक एवं विवाह संबंधी विचार भी साम्यवाद में जान लग गया था। साम्यवाद की शुरुआत न केवल जीवन का प्राथमिक एवं साम्यवादी दृष्टि से साम्यवाद विद्यमान एवं बलवत्तम बना दिया था और उस स्थिति में मुक्ति व नये साम्यवाद का कि सभी प्रकार के विचारों व स्थानीय स्तर पर विप्लव का बाई व बाईसगाँव और मरन रास्ता दिखाना जाय और क्षेत्र व समाज का गैर प्राथमिकता का प्राथमिकता से मुक्ति दिलाई जाए। इस क्षेत्र में यह साम्यवाद प्रारम्भ थी कि साम्यवाद की मुक्ति एवं बाहरी तटस्थ भवन से दूर इस क्षेत्र में बाहरी का हर व्यक्ति केवल साम्यवाद स्थापना साम्यवाद व नये समाज है यथा, महाजन व्यापार व नये, ठेकाई जगत उजाड़न व नये, सर्वजन विज्ञान जमीन उन व नये मरवाती कमजोरी पैसा वमान व नये और पुनर्गठन विचारों को बढ़ाने के लिये। इस स्थिति को सुधारन में श्री परीक्षा की काफी परिश्रम करना पड़ा।

मानव विकास आश्रम, रंगपुर एवं साम्यवादी सेवा संस्था है जो इस क्षेत्र में समाज-साथ में सलग्न है। बड़ीदास 120 कि०मी० दूर और साम्यवाद की मुक्ति की सभी के कारण यह क्षेत्र एवं समय धरती विच्छिन्न हुआ था। यहाँ की परिस्थिति को देखते हुए आश्रम न नीचे लिखे कार्यों को प्राथमिकता दी —

- (1) लोकप्रदायक—इसके माध्यम से विवादा की सुलभता, गलत माध्यमों का समाप्त करन एवं साम्यवाद की दिशा में भागे बढ़ने की प्रेरणा देने का प्रयास किया जाता है।
- (2) कृषि विकास—इसमें सिंचाई के साधन उपलब्ध करन के साथ-साथ कृषि की नयी पद्धति का शिक्षण भी दिया जाता है।
- (3) सहकारी समितियाँ—इसके द्वारा कमजोर वर्ग की प्राथमिक स्थिति सुधारने का प्रयास किया जाता है।
- (4) प्रौढ़ शिक्षा।

- (5) शोषणमुक्ति—बहुमध्यम गरीब जनसमुदाय को महाजन, बड़े किसान एवं अधिकारियों के शोषण से मुक्त करने का प्रयास किया जाता है।
- (6) समग्र शिक्षा—ग्राम-निर्देशन कार्यक्रम में जीवन-शाला के नाम से एक प्रवृत्ति चलती है जिसमें इस प्रकार की व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है जिसे प्राप्त कर व्यक्ति स्वावलम्बी जीवन व्यतीत कर सके। यहाँ मुख्यतः कृषि, कृषि तकनीक, ग्रामीण मशीन आदि का प्रशिक्षण सामान्य शिक्षा के साथ साथ दिया जाता है।

उपरोक्त कार्यक्रमों में लोकप्रदालत इन भवका बे-द्र बिन्दु रही है। यह एक प्रकार की घुरी है जिसके चारों ओर अन्य कार्यक्रम चलते हैं। लोकप्रदालत के माध्यम से ही ग्रामों के पुनर्निर्माण का कार्यक्रम हुआ और साथ ही ग्राम कार्यो का भी विकास हुआ।¹ प्रारम्भ (1949) से ही लोकप्रदालत यहाँ का प्रमुख कार्यक्रम रहा है और पिछले 27 वर्षों में लोकप्रदालत में अनेक प्रकार के हजारों विवाद निपटाये गये हैं।

लोकप्रदालत उद्देश्य एवं परिभाषा

लोकप्रदालत सरकारी न्यायालय एवं ग्राम पंचायत दोनों से भिन्न न्यायिक संगठन है। यह भिन्नता ही इसकी विशेषता है।² जैसा कि ऊपर कहा गया है, इसका विकास समस्याओं के समाधान की खोज के प्रयास के क्रम में स्वतः हुआ है। प्रारम्भ में इसकी व्यवस्था, कार्य पद्धति आदि के कोई बने बनावे नियम नहीं थे। आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे व्यवस्था का विकास स्वतः होता गया। यही कारण है कि यहाँ के नियम अत्यंत सरल हैं एवं कागजी बाधाही नाममात्र की है। लोकप्रदालत का स्वाभाविक विकास होने के कारण इसे बड़े बंधाएँ नियमों की परिभाषा में परिभाषित करना कठिन है। हमारी दृष्टि में लोकप्रदालत के निम्नलिखित उद्देश्य हैं

- 1 गाँव के लोगों में स्वशासन की भावना का विकास एवं उसका प्रयास।
- 2 समाज के सभी वर्गों के लिये ऐसी न्याय व्यवस्था का निर्माण करना जिससे उन्हें सस्ता तथा जल्दी न्याय मिल सके।

अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिये लोकप्रदालत ने जो स्वरूप विकसित किया है, उससे आधार पर इसकी विशेषताओं की खोज करने का प्रयास किया

गया है। मामा'य तौर पर लोकमदालत की नींव सिंगी विनियमायें मानी जा सकती है।

- 1 इसकी सभी कामवाही गुरु रूप में जाती है। इसीलिए इस मूल्य प्रदानत (open court) भी कहा गया है।
- 2 विरिद्धा ररकर—यह ग्राम स्तर तक फैला हुआ है। यह वर्तमान व्यवस्था में अधिकांश विवादों का निपटारा व द्वितीय लोकमदालत में जा रगपुर आश्रम में स्थित है। किया जाता है फिर भी ग्रामस्तर पर निपटाया जात बात विवादों की मर्याद गण्य नहीं है।
- 3 'याय प्रक्रिया में लोकतांत्रिकता—मकानों अपनी राय व्यक्त करत का अधिकार,
- 4 निर्णय की स्वच्छता व स्वीकार करना
- 5 कानूनी (राज्य का) धर्मन का ग हाता,
- 6 शारीरिक दण्ड का न हाना,
- 7 तीव्र एवं सरलता 'याय,
- 8 ग्याय प्रक्रिया की सरलता
- 9 स्वशासन का अध्याग (विवाद निपटान की प्रक्रिया में पचा का समावेश एवं नेतृत्व के विकास का प्रयास),
- 10 तथ्यों के आधार पर 'याय देने का प्रयास,
- 11 नये मूल्यों की स्थापना का प्रयास जिसमें सामुदायिकता, नैतिकता, मानवीयता आदि मुख्य हैं।

उपरोक्त बातें बमोवेश लोकमदालत में पायी जाती हैं। लोकमदालत में बकील जैसे मध्यस्थ एजेंट की आवश्यकता नहीं होती। वादी प्रतिवादी उपस्थित समुदाय के सामने निर्भीक होकर अपनी अपनी बात कहत है और अध्यक्ष एवं अन्य पक्षों के सवालियों का जबाब देते हैं। इन्ही विशेषताओं के कारण गांव के लोग इसे पसंद करते हैं। इस समय लोकमदालत दो रूपों में चलती है।

(क) एक निश्चित स्थान पर (आनंद निवेदन आश्रम में खुले चबूतरे पर) लोक मदालत की बैठकें होती हैं,

(ख) ग्राम स्तर की लोक न्यायालय का विस्तार हो, इस दृष्टि से ग्राम स्तर पर उसकी बैठकें होती हैं जिसमें गांव के बालीग लोग उपस्थित रहते हैं।

प्रस्तुत अध्ययन की उपयोगिता

प्रस्तुत अध्ययन में लोकन्यायालय के संगठन एवं कार्य-पद्धति का सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है। लोकन्यायालय ने परम्परागत न्याय पद्धति को नये परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ग्रामीणों पर न्याय की जो व्यवस्था है, उससे भिन्न यहाँ की लोकन्यायालय न्याय के क्षेत्र में नयी दिशा प्रस्तुत करती है। इसके विविध पक्षों पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। लोकन्यायालय का यह अध्ययन न्यायव्यवस्था की विविध समस्याओं का समाधान खोजने में सहायक हो सकता है। इस अध्ययन की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए कुछ बातें इस रूप में कही जा सकती हैं

(क) ग्रामीण भारत की जिस प्रकार की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति है, उसमें इस प्रकार के प्रयास का अपना महत्व है। मुख्य बात यह है कि न्याय क्षेत्र उपलब्ध किया जाय एवं न्याय प्राप्ति में खर्च कम हो। प्रायः यह देखा जाता है कि न्याय प्राप्ति में वृद्धि लग जाते हैं और विलम्ब के कारण न्याय का महत्व एवं उपादेयता निरर्थक हो जाती है। लोकन्यायालय तात्कालिक एवं सस्ते न्याय का भाग बताती है। यदि इसकी व्यवस्था एवं कार्य-पद्धति के बारे में विस्तृत एवं प्रामाणिक जानकारी मिले, तो इसे न्याय क्षेत्र में स्वीकार किया जा सकता है। इसका सबसे अधिक लाभ समाज के उस कमजोर वर्ग को होगा जो आर्थिक परेशानियों एवं अन्याय के कारण न्याय प्राप्त करने में अपने आपको सदैव विफल एवं असहाय महसूस करता है।

न्याय-क्षेत्र में देरी आज की न्याय व्यवस्था की एक प्रमुख समस्या है और न्यायविद् इस खोज में हैं कि क्षेत्र न्याय के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाय। यह अध्ययन इस खोज में मददगार हो सकता है।

(ख) न्याय सत्य पर आधारित होता है। सत्य की खोज के उद्देश्य से मौजूदा न्याय व्यवस्था में अनेक कानून कायदे बने हुए हैं। लेकिन यह पद्धति इतनी पक्कीदा हो गई है कि इस काम में वकीलों की मदद

अनिवार्यता आवश्यक हो गयी है। तथ्या की प्रस्तुत करने एवं सत्य की खोज के प्रयास में वकीला का घ-घा जिस रूप में फैला है, वह सामाज्यजन की पकड़ के बाहर है। व्यवहार में विवाद के प्रस्तुतीकरण और उस विवाद के सम्बन्ध में प्रतिवादी का पक्ष प्रस्तुत करने में वकील ही प्रमुख होता है। 'याय' व्यवस्था पेचीदा होने के साथ साथ उसमें ब-घाव (closed system) भी है। खुलापन नहीं है। इससे विपरीत लोकअदालत पूर्णतः खुली हुई है, 'खुलापन' (openness) इसकी विशेषता है। इसकी खुली 'यायपद्धति' (open justice) का विश्लेषण 'याय' पद्धति के सम्यक् विकास में योग दे सकता है और उससे सामाज्यजन को भी 'याय' कार्य में भागीदार बनने का अवसर उपलब्ध हो सकता है। इसके साथ साथ वकील जैसे मध्यस्थ की आवश्यकता भी कम हो सकती है।

(ग) 'याय' के विकेंद्रीकरण के प्रयास में यह अध्ययन उपयोगी सिद्ध होगा। ग्राम या ग्रामसमूह स्तर पर स्व-न्याय' (self justice) की व्यवस्था की सफलता में यह अध्ययन महत्व रखता है। 'याय' पंचायत के सरकारी प्रयास को शक्ति प्रदान करने में भी लोकअदालत के अनुभव का उपयोग किया जा सकता है।

(घ) अधिकांश गांवों में आज भी पुरानी रूढ़ियाँ एवं अ-धविश्वासों का बोलबाला है और परम्परागत जाति पंचायतें इनका पोषण करती हैं।⁹ आवश्यकता इस बात की है कि 'याय' प्रक्रिया में बाधक ऐसी रूढ़ियों एवं अ-धविश्वासों से ग्राम्य समाज को मुक्त कराया जाये। लोक-अदालतें अपने कार्य के माध्यम से लोकशिक्षण का कार्य भी करती हैं, यायकाय के साथ लोकशिक्षण एवं समाज परिवर्तन की प्रक्रियाओं को किस प्रकार जोड़ा जा सकता है, अध्ययन का यह पक्ष प्रगतिशील ग्रामीण व्यवस्था के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

(ङ) प्रस्तुत अध्ययन का एक महत्व यह भी है कि लोकअदालतें ने 'याय' एवं दंड के सिद्धांत एवं व्यवहार पक्ष को नई दिशा दी है। शारीरिक दंड देकर अपराधी को घट्टा एवं अन्यस्त अपराधी बनाने के स्थान पर उसके अंतर्मुख में प्रायश्चित्त की भावना जागृत करके उसकी अपराध वृत्ति का क्षमन करना इस 'याय'प्रक्रिया का एक प्रमुख अंग है। साथ ही लोकअदालत की 'याय'प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण अंग यह भी है कि विवादग्रस्त पक्षों के आपसी तनाव को हमेशा के लिए

समाप्त किये जाने पर विशेष जोर देता है, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहने वाला वैमनस्य समाप्त हो और आज के विवादी या दुश्मन भ्रान्ते वाले कल के मित्र एवं भण्डे पड़ोसी बन जायें।

अध्ययन का विषय

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया है

- 1 भौगोलिक परिस्थिति और लोकअदालत पर उसका प्रभाव,
- 2 सामाजिक संरचना और लोकअदालत के विकास एवं संगठन में उसका योग,
- 3 लोकअदालत का संगठन और 'याय' पद्धति
- 4 निर्णय की नियामित्व,
- 5 निणय की प्रतिक्रिया
- 6 लोकअदालत द्वारा किये गये निर्णयों का अध्ययन,
- 7 कानूनी 'याय' व्यवस्था के साथ लोकअदालत का सम्बन्ध और लोकअदालत पर उसका प्रभाव।

इसके प्रतिरिक्त इस अध्ययन में लोकअदालत सम्बन्धी अन्य पहलुओं पर भी विचार किया गया है। अध्ययन में शामिल प्रश्न इस प्रकार हैं

- 1 लोकअदालत में और सरकारी 'यायालयों' में जाने वाले विवादों के प्रकार में क्या भिन्नता है ?
- 2 तुलनात्मक दृष्टि से लोकअदालत और सरकारी 'यायालयों' की निणय प्रक्रिया में किस प्रकार की भिन्नता है ?
- 3 ऐसे कौन से तत्व हैं जो लोकअदालत के सफल संचालन में प्रभावी हैं और इन तत्वों की तुलना सरकारी यायालय 'याय' प्रणाली और ग्राम सभा के कार्य में प्रभावी तत्वों से किस सीमा तक की जा सकती है ?
- 4 इस क्षेत्र के लोगों का लोकअदालत के साथ किस प्रकार का व्यवहार है और वे लोकअदालत की सफलता में किस सीमा तक मददगार हैं ?
- 5 लोकअदालत एवं सरकारी यायालयों के सम्बन्ध किस रूप में विद्यमान हैं ?

6 लोकप्रदालत में विवाह और जमीन सम्बन्धी विवादों के अधिक सरया में आने का क्या कारण है ? क्या यह स्थिति समाज में स्त्रियों के स्थान या भूमि व्यवस्था में कमजोरी के कारण है ?

अध्ययन में नीचे लिखी प्राक्ल्पनाओं को जाचने का भी प्रयास किया गया है

1 इस क्षेत्र के लोगों की सामाजिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक वातावरण, आर्थिक विषमता एवं प्रचलित पेचीदा तथा महंगी 'यायव्यवस्था' लोक-प्रदालत की स्थापना का कारण है ।

2 लोकप्रदालत की सफलता का कारण नि स्वार्थ और सतत कार्यशील नेतृत्व एवं क्षेत्र में विद्यमान सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ रही हैं ।

3 इस क्षेत्र में भूमि एवं विवाह सम्बन्धी विवाद पारस्परिक तनाव के मुख्य कारण रहे हैं ।

4 सहज, सरल एवं सीधी कानूनी प्रक्रिया विवादग्रस्त पक्षों को अधिक प्रभावी ढंग से सतोष प्रदान करती हैं ।

5 समझौता भावना लोकप्रदालत में प्रस्तुत विवादों के निपटारे का मुख्य घग रही है ।

6 लोकप्रदालत विवादग्रस्त पक्षों की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए समाधान करती हैं ।

क्षेत्र एवं पद्धति

भानूद निकेतन आश्रम का सघन कार्य क्षेत्र करीब 100 गावों का माना जाता है । इस अध्ययन में 10 गावों (कुल का दस प्रतिशत) को शामिल किया गया है । इन गावों के अतिरिक्त पाँच ऐसे गावों से भी तथ्यों का संग्रह किया गया है जहाँ के लोग अपने विवादों को सरकारी यायालयों में ले गये हैं । इस प्रकार के पाँच गावों को इस लिये चुना गया है कि लोक-प्रदालत एवं सरकारी 'यायालयों में जाने वाले मामलों के बीच तुलना की जाय । लोकप्रदालत से प्रभावित दस गावों से व्यापक रूप में तथ्यों का संग्रह किया गया है जब कि अन्य पाँच गावा से केवल सरकारी 'यायालयों में जाने वाले विवादों की जानकारी ही एकत्र की गयी है ।

इन 10 गावों में 15 प्रतिशत मतदाताओं से साक्षात्कार किया गया है । इस साक्षात्कार में ऐसे लोग शामिल हैं जिनके विवाद लोकप्रदालत में

गये हैं। साक्षात्कारियों में से 80 साक्षात्कार ऐसे हैं जिनके विवाद लोकप्रदानत में गये हैं। दोष साक्षात्कारियों में निम्न प्रकार के लोग शामिल हैं—(1) गांव के मुखिया (2) लोक अदालत में जूरी के रूप में भाग लेने वाले (3) गवाह के रूप में या पक्ष विपक्ष में भाग लेने वाले और (4) सामान्य जन।

इसके अतिरिक्त क्षेत्र के अन्य लोगों से भी साक्षात्कार किया गया है जिनमें मुख्य हैं गैर आदिवासी नागरिक, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी एवं वकील।

गांव का चुनाव एवं उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति

जिन दस गांवों में सर्वेक्षण काय किया गया है और जिन लोगों से साक्षात्कार किया गया है, उनके बारे में सामान्य जानकारी इस प्रकार है

तालिका सरया-1

सर्वेक्षित ग्राम की प्रकृति

क्रमांक	गांव का नाम	मतदाता संख्या	मतदाता संख्या का 15 प्र.श. जिनका साक्षात्कार किया गया है।	गांव की प्रकृति
1	रगपुर	287	43	आदिवासी
2	मोटावाटा	381	57	"
3	खेरवा	436	65	,
4	जाम्वा	271	40	,
5	गजनावाट	82	12	,
6	कपराईली (रतनपुर)	159	23	मिश्रित
7	गोमावाट	396	59	,
8	मकोडी	637	95	आदिवासी
9	मेखडिया	205	30	,
10	बिजली	137	20	

उपरोक्त गांवों के अतिरिक्त क्षेत्र के जिन पांच गांवों से सरकारी न्यायालय में जाने वाले विवादों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की गयी है उनके नाम हैं—(1) साटियावाट (2) भरवाई (3) भूडामोर (4) चिपाण और

(5) नलवाट। इनकी आश्रम से दूरी क्रमशः 3, 2, 4, 2, 5 कि० मी० है। क्षेत्र में किये गए साक्षात्कार को नीचे लिखे वर्गों में विभाजित किया गया है—

- 1 सामान्य साक्षात्कार (क) उपरोक्त दस गांवों के 15 प्रतिशत मत दाताओं से साक्षात्कार किया गया जिसकी कुल संख्या 435 है।¹⁰
 (ख) उक्त संख्या में से 80 साक्षात्कार ऐसे हैं जो वादी या प्रतिवादी के रूप में लोकप्रदासत में गये हैं।
 (ग) साक्षात्कारियों में से 9 से सम्बंधित विवाद ऐसे हैं जो लोक प्रदासत के निर्णय के पहले सरकारी न्यायालय में भी जा चुके थे।
- 2 अध्ययन क्षेत्र के कुछ विशेष लोगों से भी साक्षात्कार किया गया है जिसे विशेष साक्षात्कार कहा गया है। क्षेत्रीय बाजार (कवाट), कस्बा (छोटा उदयपुर) एवं जिला मुख्यालय (बड़ोदा) के महाजन शिक्षक वकील तथा अन्य बुद्धिजीवियों को इस साक्षात्कार में शामिल किया गया है। रैंडम सैंपल के अनुसार इस साक्षात्कार में कुल 31 व्यक्तियों को शामिल किया गया है।
- 3 सरकारी न्यायालय में जाने वाला से साक्षात्कार—सामान्य साक्षात्कार के प्रतिरिक्त इसी क्षेत्र के पांच अन्य गांवों (ऊपर लिखे) के ऐसे विवादों से सम्बंध नगो से भी साक्षात्कार किया गया जो सीधे सरकारी न्यायालय में गये थे। इनकी संख्या 23 है। सीधे सरकारी न्यायालय में जाने वाला से साक्षात्कार से भी कुछ तुलनात्मक तथ्य प्राप्त हुए हैं।

सामान्य (न० 1) और विशेष (न० 2) साक्षात्कारियाँ की सामाजिक स्थिति इस प्रकार की पायी गयी

8966

तालिका सरया—2

उत्तरदाताओ का जातिवार विभाजन

क्र०	नाम जाति	सामान्य साक्षात्कार		विशेष	साक्षात्कार
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	राठवा	378	86—89	00	00
2	भील	39	8—97	1	3—23
3	नायका	11	2—53	00	00—00
4	हरिजन	3	0—69	00	00—00
5	सवण हिंदू	4	0—92	27	87—09
6	मुसलमान	00	00—00	1	3—23
7	जाति न बताने वाले	00	00—00	2	6—45
योग		435	100—00	31	100—00

उम्र की दृष्टि से उपरोक्त उत्तरदाताओ का वर्गीकरण इस प्रकार है

तालिका संख्या—3

उत्तरदाताओ का उम्र के अनुसार वर्गीकरण

क्र०	उम्र समूह (वय मे)	सामान्य साक्षात्कार		विशेष	साक्षात्कार
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	20 से 35	152	34 94	4	12—90
2	36 से 50	169	38 85	3	9—68
3	51 से 65	87	20 00	0	00—00
4	66 से 80	9	2 07	0	00—00
5	80 से अधिक	18	4 14	0	00—00
6	उम्र न बताने वाले	00	00 00	24	77—42

उत्तरदाताओं के घ-घे की स्थिति निम्न प्रकार है। इससे इनकी आर्थिक स्थिति का पता लगता है

तालिका सख्या-4
उत्तरदाताओं का घन्धा

क्र०	घ-घा	सामान्य सख्या	साक्षात्कार प्रतिशत	विशेष सख्या	साक्षात्कार प्रतिशत
1	कृषि	389	89—42	1	3—22
2	मजदूरी	31	7—13	0	0—00
3	नौकरी	14	3—22	16	51—62
4	व्यवसाय	00	0—00	10	32—26
5	अन्य	1	0—23	2	6—45
6	उत्तर नहीं देने वाले	00	0—00	2	6—45
योग		435	100—00	31	100—00

ऊपर की तालिकाओं के अनुसार सामान्य उत्तरदाताओं एवं विशेष उत्तरदाताओं के बारे में कह सकते हैं कि सामान्य उत्तरदाताओं में आदिवासी मुख्य हैं और उनका मुख्य घ-घा कृषि है। विशेष उत्तरदाताओं में सबन हिंदुओं की सख्या अधिक है और उनका मुख्य घ-घा नौकरी एवं व्यवसाय है।

जिन 80 बादियों एवं प्रतिवादियों से उनके विवादों के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी है, उनकी आर्थिक स्थिति इस प्रकार है

तालिका सख्या-5
विवाद से सम्बद्ध उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति
सख्या 80

क्र०	घ-घा	बादी प्रतिवादी	वार्षिक पारिवारिक		मास स्तर (रुपये में)		1501 पाग 2000
			100	500	501-1000	1001 1500	
1	घेती	बादी	22	15	00	2	39
		प्रतिवादी	20	11	1	2	34
2	मजदूरी	बादी	5	00	00	0	5
		प्रतिवादी	1	00	00	0	1
3	अन्य	बादी	00	00	00	0	00
		प्रतिवादी	1	00	00	0	1

अध्ययन में द्वितीयक सामग्री का पर्याप्त उपयोग किया गया है। लोक अदालत कार्यालय में प्राप्त फाइलो एवं अन्य प्रकार के विवरणों का अध्ययन करके विवादों के बारे में तीव्र व्यापक जानकारी प्राप्त की ही गयी है, साथ ही परम्परागत आदिवासी समाज में प्रचलित ग्राह्यव्यवस्था सम्बन्धी साहित्य का भी उपयोग किया गया है और इस अध्ययन से सम्बन्धित विषयों के बारे में प्रकाशित अन्य सामग्री को भी देखा गया है।

लोकअदालत की वायपद्धति के बारे में तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से लोकअदालत की बैठकों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया गया है। अध्ययनदल लोकअदालत का छ बैठका में उपस्थित रहा है।

अध्ययन की सीमाएँ एवं समस्याएँ

प्रस्तुत अध्ययन की कुछ सीमाएँ हैं। लोकअदालत जिस क्षेत्र में चल रही है वह आदिवासी क्षेत्र है। सर्वेक्षण में प्राप्त तथ्यों से इस बात की पुष्टि होती है कि लोकअदालत में आये विवादों में लगभग सभी आदिवासियों के विवाद हैं। गैर आदिवासी समाज के विवादों की संख्या बहुत कम है। इस प्रकार लोकअदालत का प्रभाव क्षेत्र आदिवासी समाज तक ही सीमित मान सकते हैं। प्रभाव क्षेत्र की यह सीमा प्रस्तुत अध्ययन की सीमा को भी दर्शाती है। आदिवासी समाज में जातिगत ग्राह्य की जो परम्परा रही है उसके कारण लोकअदालत को अनुकूल वातावरण मिला है। इसमें जातिगत ग्राह्य की परम्परा एवं स्वयं के अनुभवों के आधार पर विकसित ग्राह्य-पद्धति दोनों का समन्वय पाया जाता है। अतः लोकअदालत के अध्ययन में परम्परागत ग्राह्य व्यवस्था के सदर्भ में लोकअदालत द्वारा प्रयुक्त ग्राह्यप्रणाली अन्य क्षेत्रों में लागू करने की दृष्टि से सीमा रेखा की समस्या भी आती है। दोनों के पारस्परिक समन्वयात्मक स्वरूप को देखते हुए इसे अन्य क्षेत्रों में लागू करने की दृष्टि से प्रयोग की कमी खटकती है। यह हमारे अध्ययन की भी एक सीमा हो जाती है कि हम लोकअदालत के विस्तार के बारे में इस दृष्टि से प्रमाणिक तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। लोकअदालत राज्य द्वारा बने कानून की सीमा में नहीं आती है। इसके नियम प्रचलित कानून के अन्तर्गत नहीं दिये जाते। अतः कानूनसम्मत ग्राह्य एवं उसके नियम के साथ इसकी तुलना की समस्या भी आती है। लोकअदालत द्वारा दिये गये नियम दोनों पक्षों और ग्रामीण जनसमुदाय द्वारा तो मान्य होते हैं, परंतु राज्य के कानून के साथ उनका सम्बन्ध न होने के कारण सरकारी ग्राह्यालयों में लोकअदालत के नियमों का महत्त्व नहीं होता।

लोकअदालत जिस क्षेत्र में चलती है, वह सामाजिक आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा हुआ है। यहाँ शिक्षा का प्रसार नाममात्र का है। इस प्रकार की समाजव्यवस्था में साक्षात्कार अत्यंत कठिन कार्य हो जाता है। सभी प्रश्नों को समझाने एवं उत्तर प्राप्त करने में कठिनाई तो होती ही है इसके साथ साथ सही उत्तर प्राप्त करना भी एक समस्या है।

लोकअदालत में आये कई वष पुराने विवादों की जानकारी प्राप्त करने में भी कठिनाई हुई। लोकअदालत के कार्यालय में लिखित रूप में विवादों के बारे में अत्यंत सीमित जानकारी प्राप्त हो सकी है। प्रारम्भ में तो विवादों का विवरण रखा ही नहीं जाता था। बाद में 1960 से विवादों का 'यूनाधिक' विवरण रखा जाने लगा है। फिर भी जो विवरण प्राप्त हुए हैं, उन्हें पर्याप्त नहीं माना जा सकता। इसकी पूर्ति हमने एक सीमा तक साक्षात्कार से करने का प्रयास किया है।

संदर्भ

- 1 देखें अध्याय तीन।
- 2 देखें श्री नागेश्वर प्रसाद 'डा सेट्टालाइजेशन इन यूगोस्लाविया एण्ड इंडिया'।
- 3 देखें गांधीजी 'हरिजन सेवक' 16 1947।
- 4 गांधीजी 'हरिजन सेवक' 28 7 1946।
- 5 देखें गांधीजी 'हमारे गाँव का पुनर्निर्माण' नवजीवन प्रकाशन भदिर भद्रमदाबाद।
- 6 देखें अध्याय दो एवं तीन।
- 7 देखें 'स्वप्न हुए साकार' सोसाइटी फार डेवलपिंग ग्रामदान नई दिल्ली।
- 8 तुलना के लिये देखें अध्याय दस।
- 9 देखें अध्याय तीन।
- 10 15 प्रतिशत के अनुसार यह संख्या 444 होती है। कतिपय कारणों से जाँचों की आवश्यकता करना पड़ा है।

भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति

भौगोलिक पर्यावरण

बडोदा गुजरात का ऐसा जिला है जिसमें विविध जाति एवं धर्म के लोग रहते हैं। यहां की भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति में भी विविधता है। एक ओर बडोदा शहर है जिसके आस पास औद्योगिक प्रतिष्ठानों का बाहुल्य है तो दूसरी ओर ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां विकास की किरणें अभी तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकी हैं। भौगोलिक एवं भूमि संरचना की दृष्टि से देखें तो एक ओर समतल और उपजाऊ जमीन है तो दूसरी ओर घनघोर जंगल एवं ऐसी पथरीली जमीन है जहां कठिन परिश्रम के बाद भी नाम मात्र का ही उत्पादन हो पाता है। सामाजिक संरचना की दृष्टि से देखें तो यहां हिंदू, मुसलमान तथा अन्य धर्मावलम्बियों के साथ-साथ आदिवासियों की समस्या भी पर्याप्त है। छोटा उदयपुर एवं उसबाड़ी आदि ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पचास प्रतिशत से अधिक संख्या आदिवासियों की हो है। जिले की पूर्वी सीमा मध्यप्रदेश से जुड़ी हुई है। उत्तरी सीमा पंचमहाल जिले से लगी हुई है। उत्तर-पश्चिम में खेडा जिला है। जिले की दक्षिणी सीमा भडोच जिले से मिलती है। माही नदी बडोदा जिले को खेडा से अलग करती है, तो नर्मदा भडोच से। औद्योगिक दृष्टि से यह गुजरात राज्य में सबसे विकसित जिलों में से है। भौगोलिक एवं भूमि संरचना की दृष्टि से इस जिले को मुख्यतः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं—(1) समतल मरदाना क्षेत्र, जहां शहरीकरण एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों का पूरा विकास हुआ है। यह क्षेत्र बडोदा शहर के आस पास और खेडा से मिलने वाला सीमा पर है। (2) ऐसा क्षेत्र जहां आदिवासियों का बाहुल्य है और जहां कुछ दशक पूर्व घनघोर जंगल था। यह क्षेत्र मध्यप्रदेश पंचमहाल एवं भडोच जिले की सीमा से मिलता है।

बडौदा जिले की मिट्टी की मुख्य दो किस्में हैं। कुछ क्षेत्रों में बलुई दोमट मिट्टी है तो कुछ क्षेत्रों में काली मिट्टी। पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्र में काली मिट्टी का बाहुल्य है। छोटा उदयपुर एवं नसवाड़ी में काली एवं बलुई दोमट दाना प्रकार की मिट्टी है। इस क्षेत्र में प्रायः सभी किस्म की फसलें उगायी जाती हैं। काली मिट्टी के क्षेत्र में नकाम प्रमुख व्यापारिक फसल (cash crop) है। यहाँ वर्षा अच्छी होती है। परन्तु जब धीरे धीरे जंगल कटने के कारण वर्षा की कमी महसूस की जाने लगी है। जिन की कुल जनसंख्या का 23.89 प्रतिशत भाग आदिवासियों का है। आदिवासियों का घनत्व जिले के छोटा उदयपुर एवं नसवाड़ी क्षेत्र में अधिक है।¹

बडौदा जिले के विभिन्न ताल्लुकों में आदिवासी आबादी की संख्या एवं कुल आबादी का प्रतिशत इस प्रकार है

सारणी संख्या— 6

बडौदा जिले के विभिन्न ताल्लुकों में आदिवासी

क्र०	ताल्लुका	आदिवासी आबादी संख्या	कुल आबादी में प्रतिशत
1	छोटा उदयपुर	83,247	57.35
2	जबुगाव	46,543	41.07
3	नसवाड़ी	38,992	68.46
4	सखरा	16,642	31.71
5	बभोई	26,975	47.34

ऊपर की सारणी में केवल पाँच ताल्लुका में निवास करने वाले आदिवासियों की संख्या ही दी गई है क्योंकि उपरोक्त ताल्लुकों में ही आदिवासियों की संख्या अधिक है। वस जिले के अन्य क्षेत्रों में भी कभी-कभी आदिवासी आबादी है। एक समय था जबकि यह क्षेत्र आवागमन एवं अन्य सुविधाओं की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ था लेकिन जंगल कटने एवं अन्य सुविधाओं के बढ़ने के साथ-साथ यहाँ के लोगों का जीवन भी बदला है। आदिवासी-प्रधान इस क्षेत्र में आदिवासियों की कुल 18 जातियाँ हैं। बडौदा जिले की इन आदिवासी जातियों की ग्रामीण एवं शहरी आबादी की जानकारी सारणी 7 में मिलेगी—

सारणी सख्या—7

बडोदा जिले की आदिवासी जातियाँ एवं उनकी आबादी

क्र०	जाति	ग्रामीण आबादी	ग्रामीण आबादी	कुल
1	भोल	1 13,890	4,946	1,18 836
2	बरडा	4	—	4
3	बावचा	26	857	883
4	चौधरी	3	28	31
5	घानका	59 657	4 601	64 258
6	घोडिया	79	89	168
7	डुबला	20 144	717	20 861
8	गामीत	1	46	47
9	गार	—	12	12
10	गावण	3	35	38
11	दोर नौली	64	81	145
12	नायका	10 466	245	10 711
13	पारधी	—	1	1
14	पटेलिया	25	16	41
15	पोमता	8	39	47
16	राठवा	1,06,289	13	1 06 302
17	विटेलिया	40	2	42
18	अन्य	5 565	—	5,565
कुल योग		3 16 264	11 728	3 27 992

उपरोक्त सारणी के अनुसार कुछ आदिवासी जातियों की आबादी नाम मात्र की है। सख्या की दृष्टि से भोल, घानका, डुबला नायका राठवा आदिवासियों की सख्या अधिक है।

आदिवासी परिभाषा एवं प्रजाति

देश की कुल आबादी का करीब 7 प्रतिशत भाग आदिवासियों का है। सामान्य बोल चाल की भाषा में सुदूर जंगल में रहने वाली जातियों को आदिवासी कहा जाता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि जंगलों में रहने

वाली सभी जातियाँ को आदिवासी कह। शाब्दिक दृष्टि देखें तो आदिवाल से रहने वाली जातियों को आदिवासी कह सकते हैं। आदिवासी किसे कहा जाय या आदिवासिया की क्या परिभाषा की जाय, इस पर विद्वानों में मतभेद नहीं है। श्री एल एम श्रीवास्तव के अनुसार आदिवासी समाज को समय समय पर विविध नामों से सम्बोधित किया जाता रहा है। जैसे—भरण्यक, वनवासी, व य जाति रानीपरज, आदिवासी आदि। इन्हें किसी सर्वमान्य परिभाषा में बाधना कठिन है। फिर भी श्री हुटर की परिभाषा के अनुसार आदिवासी वगैरह एक सुमिश्रित सामाजिक संरचना में समुदाय के रूप में ऐसा समुदाय है जो एक खास प्रकार के भौगोलिक पर्यावरण में रहता है।⁴ समाज शास्त्री श्री गिलिन ने अपनी रचना 'कल्चरल एंथ्रोपोलाजी' में जनजाति की परिभाषा इस रूप में की है—'स्थानीय जनजातीय समूहों का ऐसा समन्वय जनजाति कहा जाता है जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता है, एक सामान्य भाषा का प्रयोग करता है तथा जिसकी एक सामान्य संस्कृति है।' इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएँ दी हैं। परिभाषाओं की विविधता को देखते हुए आदिवासी समुदाय के प्रमुख लक्षणों से इनकी विशेषता को आकर अधिक उपयोगी होगा। प्रो ए. आर. देसाई ने कुछ ऐसे लक्षण गिनाये हैं जो प्रायः सभी आदिवासियों में पाये जाते रहे हैं। ये सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं।⁵

- (1) वे सभ्य जगत से दूर पर्वतों तथा जंगलों में दुर्गम स्थानों में निवास करते हैं।
- (2) वे निग्रिटोज, ऑस्ट्रोलाइड अथवा मंगोलाइड में एक प्रजातीय समूह से सम्बंधित हैं।
- (3) वे जनजातीय भाषा का प्रयोग करते हैं।
- (4) वे आदिम धर्म को मानते हैं जो कि सर्वजीववाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और जिसमें भूतों तथा आत्माओं की पूजा का महत्त्वपूर्ण स्थान है।
- (5) वे जनजातीय व्यवस्था का अपनाते हैं, जैसे उपयोगी प्राकृतिक वस्तुओं का संग्रह शिकार, वन में उत्पन्न वस्तुओं का संग्रह करना आदि।
- (6) वे अधिकांशतया भासाहारी हैं।
- (7) उनकी सानाबदोशी आदतें हैं तथा भदिरा एवं नृत्य के प्रति उनकी विशेष रुचि है।

(8) आदिवासी महिलायें विवाह, तलाक आदि मामलों में अधिक सुदृढ़ स्थिति में हैं।

प्रो. देसाई के अनुसार जनजातीय जनसंख्या के केवल 1/5 भाग में ही अब उपरोक्त लक्षण पाये जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि अब आदिवासी समाज धीरे-धीरे अपनी मूल संस्कृति को छोड़ता या कम करता जा रहा है और दूसरी संस्कृति के रीति रिवाज, परम्पराएँ एवं जीवन पद्धति को स्वीकार करता जा रहा है।

भारत के मध्य भाग के आदिवासियों में आस्ट्रोलाइट जाति तत्व हैं। काफी गाढ़े रंग की शरीर की चमड़ी छोटा कद, लम्बा सिर और काफी चिपटी नाक—ये उनके विशिष्ट लक्षण हैं। उनके चेहरे और शरीर पर बहुत बाल नहीं होते हैं। गुजरात के आदिवासी मध्य भारतीय भाग के आदिवासियों में आते हैं और उनमें विशेषतया आस्ट्रोलाइट जाति तत्व हैं। लेकिन धीरे धीरे आदिवासी जातियाँ भी शेष जातियों के साथ थोड़े बहुत सम्पर्क में आ रही हैं इसलिए यह जाति तत्व भी मूल स्वरूप में अब देखने को मिलें, यह सम्भव नहीं है।

गुजरात की आदिवासी जातियाँ पहले कहा से आयी, इसकी खोज करने में ऐसा मान्य होता है कि वे उत्तर से, पूर्व से और दक्षिण से आयी हैं। उनकी भाषा नाम और रीति रिवाजों के अध्ययन में ज्ञात हुआ है कि ये जातियाँ अलग अलग समय पर अलग अलग कारणों से गुजरात में आकर बस गयीं। बाद में उत्तर से आयी हुए गुजर, राजपूत, ब्राह्मण कोली आदि ने उन्हें मैदानों से पूर्व सीमा पर स्थित जंगलों और पहाड़ी प्रदेशों में भगा दिया था। इस तरह अपने मूल स्थान को छोड़कर उन्हीं जंगल और पहाड़ों में घुस जाना पड़ा और बाहर की दुनिया से उनका सम्पर्क प्रायः समाप्त हो गया। समय बिसाल से अलग पड़ जाने के कारण ही उनका जो स्वाभाविक विकास होता चाहिए था, वह नहीं हुआ। परिणामस्वरूप वे गरीबी और अज्ञानता के चंगुल में फँस गये। उनकी बोलियाँ गुजराती भाषा में अलग हैं फिर भी जहाँ जहाँ ये गुजराती भाषा भाषियों के सम्पर्क में आयी, वहाँ उन पर वहाँ की भाषा का असर साफ़ नज़र आता है।

गुजरात की आदिवासी जातियों की भौगोलिक दृष्टि से मुख्यतया तीन भागों में बाँटा जा सकता है

1 उत्तर गुजरात के भील तथा उनकी उपजातियाँ, जिनका राजस्थान के भीला के साथ निकट का सम्पर्क है।

2 पथमहाल, बड़ोदा और महोच्च जिले के भील—राठवा, घानवा, पटेलिया

तथा नायका जिनका मध्यप्रदेश की आदिवासी जातियों के साथ निकट का सम्पर्क है।

- 3 दक्षिण गुजरात के आदिवासी जिनमें मुख्यतया घोटिया पोधरी, ग्रामीत, बावणा दुमला, भील नायका, बारसी, कोटवालिया, डोर, कोली वगैरह आते हैं और उनका महाराष्ट्र की आदिवासी जातियों के साथ निकट का सम्पर्क है।⁶

गुजरात में बसने वाली विविध आदिवासी जातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन में विभिन्नता देखी जा सकती है। यह भिन्नता काफी मूल्य स्तर की है। ऊपरी दृष्टि से देखने पर विभिन्न आदिवासी जातियों की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, रीति रिवाज तथा परम्परा में काफी हद तक साम्य देखा जा सकता है। यहां के आदिवासियों में समान तत्व का खोज करने पर धनक बिशेषताएँ देखने में आती हैं जो कि समावेश प्राय सभी आदिवासी जातियों में पायी जाती हैं। ये समान तत्व इस प्रकार हैं

- 1 एक ही स्थान पर गोट बस्ती निश्चित करके बसने के बजाय वे खेतों में भ्रमण भ्रमण घर बनाकर रहने हैं। ज्यादा से ज्यादा हुआ तो बिल्कुल भ्रमण बसने के बजाय दस पन्द्रह घरों का टोला बनाकर एक साथ रहते हैं। लेकिन इन टोलों में भी इतनी दूरी होती है कि जिससे उनके गांव का विस्तार काफी बड़ा हो जाता है। आदिवासी गांव प्राय तीन चार भील के विस्तार में फैला हुआ होता है।

- 2 वे घर स्वयं ही अथवा बहुत हुआ तो कुटुम्बियों की सहायता लेकर स्थानिक साधना से बना लेते हैं और इस तरह के घर बाधते हैं कि उसके बनाने में एक दो दिन से अधिक समय नहीं लगता। मृत्यु के कारण अथवा अथवा वहमा के कारण पुराने घर को तोड़कर नया बनाने में देर नहीं लगती। ऐसे घर बनाये जाते हैं, जिन पर उन्हें कुछ नकद खर्च या तो करना ही नहीं पड़ता अथवा करना पड़ता है तो बहुत कम।

- 3 आहार में मात्र अनाज पर निर्भर नहीं करते बल्कि शिकार से प्राप्त पक्षी या जंगली जानवर, जंगल से इकट्ठा किया हुआ आहार, नदी या तलाब से पकड़ी मछलियां घर के आगन में पाले हुए भूँ बस्तख आदि का उपयोग करते हैं। आसाहार का निषेध नहीं है। खेती काम होने के कारण मात्र खेती पर आश्रित रहना उनके लिए संभव भी नहीं। खेती के

साथ साथ जंगल पर उनकी निर्भरता अभी बनी हुई है।

4 वस्त्र जहा तक हो, कम उपयोग में लेते हैं। स्त्री-पुरुष दोनों सिर्फ गुप्तांग ढकने की दृष्टि से ही आवश्यक पोशाक पहनते हैं।

5 व्यसनो को दृष्टि से जरूरी शराब व शराबबंदी से पहले, अपने आप महुए से बना लेते थे। वे तम्बाकू बाड़े में उगा लेते हैं। इसलिये उस पर भी नबंद खच कम होता है। जरूरी सब्जी भी वे बाड़े में पैदा कर लेते हैं। इनके अलावा उनकी दूसरी जरूरतें बहुत कम हैं। दवा का उपयोग वे बहुत कम करते हैं इस सम्बन्ध में वे भोझा, भगत पर विशेष भुकाव रखते हैं, इसलिये उसमें उहे कम खच होता है।

इस तरह उनका जीवन बहुत कम जरूरतों पर और इनमें से अधिकतर स्वयं स्थानीय आधार पर पूरी कर लेने के नियम पर अवलम्बित है।

6 सामाजिक व्यवहार में काफी सौचनीयता देखने को मिलती है, फिर भी जो व्यवहार तय है, उनका चुस्ती से पालन होता है। वर को खुद पसंद करने की छूट, तलाक, पुनर्विवाह की छूट, सामान्य न हो तब मात्र सगाई करके ही विधिपूर्वक घादी किये बिना गृहस्थी आरम्भ करने की छूट प्रयत्न घर-जवाई रहने की छूट इत्यादि के कारण उनके सामाजिक जीवन में बहुत कम घुटन मालूम होती है तथा स्त्री और पुरुष में समानता की भूमिका पर सम्बन्ध बनते हैं।

सामाजिक सम्बन्धों के कारण स्त्री को पुरुष के दबाव में नहीं रहना पड़ता, ऐसा हाते हुए भी उसमें स्वच्छन्दता के लिये स्थान नहीं है। जाति के कानूनों को जो भी भंग करता है उसे जाति पंच के समक्ष हाजिर होना पड़ता है और उसका फैसला मानना पड़ता है। पटेल, कारभारी और पंच मिलकर बने हुए जाति पंच तथा एक स अधिक गांवों के लिए चौरा पंच सब जातियों में दफ्तन को मिलते हैं। ये पंच उनके सब सामाजिक व्यवहारों का चुस्ती से निपटन करते हैं।

7 सब सामाजिक प्रयोग अत्यंत सादगी से मनाय जाते हैं और इन्हें मनाते में नृत्य को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है।

8 वे किसी भी रूढ़ धर्म का पालन न करके प्रगम्य शक्तियों में आस्था रखते हैं और उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं। इसमें भी सरलता और सादगी दिखाई देती है। वे काम करते अपने पूर्वजों की आत्मा को सन्तुष्ट रखने की सबसे अधिक चिन्ता रखते हैं।

9 प्रगम्य शक्तियों में विद्वानों के कारण और जीवन सम्बन्धों कोई योगमय दान नहीं अपनाया जाने के कारण उनका जीवन वहम और प्रयत्नवादायी से

भरा होता है। इसलिए ओझा और सयाने का सब जातियो में भाँदर होता है।

10 वे माल की खरीद बिन्ही के लिये हाट प्रथा पर आधारित रहते हैं।

11 बालक का नामकरण पशु पक्षी वृत्त या दिन के आधार पर करते हैं।

12 उनकी स्वतः बोली है परंतु लिपि नहीं है।

13 अलग अलग धंधों का विकास नहीं हो सका। शिक्षा का भी पर्याप्त विकास नहीं हुआ। खेती, जंगल और मजदूरी इन तीन पर उनका आर्थिक जीवन निर्भर रहता है। जंगल का काम कम हुआ है और जंगल सम्बन्धी कानूनों के बड़े बन्दन से उस काम में पहले जैसी सुविधा अब नहीं रही। खेती के लिए पर्याप्त जमीन नहीं मिलती इसलिए अधिकांश को मजदूरी पर निर्भर रहना पड़ता है।

गुजरात की सब आदिवासी जातियाँ में उक्त तत्त्व विद्यमान हैं। सम्पक की वजह से एक जाति दूसरी जाति की अपेक्षा किसी बात में आगे बढ़ गयी हो, ऐसा संभव है। बाह्य सम्पक के कारण इनमें परिवर्तन आ रहा है। फिर भी उपर्युक्त तत्त्व समावेश सभी जातियों में पाये जाते हैं।'

आदिवासी—आर्थिक परिस्थिति

आदिवासी समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति इस प्रकार की है कि गैर-आदिवासी समाज द्वारा उनका भरपूर शोषण किया जाता है तथा अज्ञान, अशिक्षा, रुढ़िग्रस्तता, अंधविश्वास आदि ऐसे कारण हैं जिनसे उनका जीवन कष्टमय बना हुआ है। एक समय था जबकि वे जंगलों में स्वच्छंद रूप में रहते थे और उनका जंगलों पर एक प्रकार से एकाधिकार था। इससे उनका आर्थिक जीवन सहज रूप में चलता रहता था। बाद में जंगलों के कटने, नये कानून बनने, महाजन एवं सरकारी कमचारियों का प्रवेश और ठेकेदारों के हस्तक्षेप आदि के कारण उनकी आर्थिक स्थिति उत्तरोत्तर दयनीय होती गयी। आज की परिस्थिति में सामान्य आदिवासी का आर्थिक जीवन काफी कष्टमय हो गया है। आदिवासी समाज का एक हिस्सा अवश्य समृद्ध हुआ है लेकिन वह दूसरे आदिवासियों का शोषक भी बन गया है। ऐसे आदिवासियों की जो शिक्षित हो गये हैं और जिनका सम्पक बाहरी समाज से हो गया है वह जो होने परम्परागत धंधों के साथ साथ या तो नये धंधों अपना लिये हैं या आय के अन्ध स्रोत खोज लिये हैं आर्थिक स्थिति सुधर गयी है। सामाजिक क्षेत्र में भी रुढ़ि एवं अंधविश्वासों के कारण उनका जीवन दुःखदायी हो जाता है। राजनीतिक चेतना के नाम पर उनके

मतों का स्वार्थपूर्ण उपयोग करने की परम्परा बन गयी है ।

परम्परागत आर्थिक परिस्थिति के अनुसार आदिवासी समाज को कई श्रेणियों में विभाजित किया गया है । डा. हट्टन ने भारतीय जनजातियों को तीन समूहों में विभाजित किया है (1) वे जनजातियाँ जो वनों से साध सामग्रियों एकत्रित करती हैं (2) वे जनजातियाँ जो चारागाही व्यवस्था में हैं (3) वे जनजातियाँ जो कृषि काय शिकार मछली मारना तथा उद्योगों पर जीवन यापन करती हैं ।^{१०}

गुजरात का आदिवासी समुदाय मुख्यतः कृषि और मजदूरी पर निर्भर रहता है । ये लोग प्रायः एक स्थान पर रह कर खेती करते हैं । आज की परिस्थिति में स्थानांतरित खेती संभव भी नहीं है । एक समय था जब जंगली चीजों से इनको अच्छी आय होती थी और जंगलों की जमीन पर उनका अधिकार था । लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के दिनों में लगान वृद्धि के कारण आदिवासियों की जमीन सीमित होने लगी और उनके स्थान पर गर-आदिवासियों ने जंगल की जमीन खरीदनी प्रारम्भ कर दी । जंगल के क्षेत्र में गर-आदिवासियों का प्रवेश हुआ तो इसका प्रभाव आदिवासियों के जीवन पर भी पड़ा । एक तरफ आदिवासियों की जमीन छिनने लगी और दूसरी तरफ गर-आदिवासियों के द्वारा शोषण के विविध तरीकों सामने आने लगे । जिन क्षेत्रों में आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा कानून द्वारा नहीं की गयी थी वहाँ वे आदिवासियों के हाथ से जमीन निकलती गयी । आदिवासी किसान के स्थान पर भूमिहीन श्रमिक की श्रेणी में आने लगे । जंगली फल सब्जी और पशु आदिवासियों की जीविका के आधार थे लेकिन राज्य की ओर से जंगलों की सुरक्षित करन के बानूना के लागू होने के बाद वे इनसे भी वंचित होने लगे । आजादी के बाद भी आदिवासियों द्वारा जंगल का उपयोग किया जाने का अधिकार काफी सीमित किया गया है और अब वे जंगलों से वे लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं जो पहले प्राप्त करते थे ।^{११} जंगलों की सुरक्षा के साथ-साथ जंगल के कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि हुई । इस प्रकार हम देखते हैं कि गर-आदिवासियों का जंगल में आकर बसना, जंगल की सुरक्षा के बानून सरकारी कर्मचारी महाजन एवं ठेकेदारों का उनका आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप आदि ऐसे कारण हैं जिनमें उनका आर्थिक जीवन पहले से अधिक बाधित हुआ गया ।

यह आम धारणा है और यह सही भी है कि आदिवासी समाज अपने अस्तित्व का बनाय रखन के लिये बज्र सत्ता है । यह बात इस क्षेत्र के आदिवासियों पर भी लागू होती है । ये पीछी दर पीछी बज्र के शिकार रहते

है। बठिन आर्थिक परिस्थितियों में बर्ज हो इनका एक मात्र सहारा रहता है। यद्यपि इनकी आवश्यकताएँ अत्यंत सीमित हैं और उनमें से अधिकांश की ये श्रम के श्रम से ही पूरा करत हैं फिर भी ये बर्ज में डूबे रहते हैं। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि इनका आर्थिक स्तर काफी गिरा हुआ है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया की भारत में आन्वित्तियता के बर्ज व वार में जो सर्वेक्षण किया गया है उसमें कहा गया है कि गुजरात में 667 प्रतिशत आन्वित्तियता परिवार परम्परागत ढंग के बर्ज में डूबे हुए हैं। औसत प्रति परिवार बर्ज का भार 355) रुपये पाया गया। ये लोग बर्ज का बड़ा भाग महाजना से बहुत ऊँची ब्याज की दर पर प्राप्त करत हैं। महकरी समितियों एवं अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा बर्ज की मुविधा प्रदान करने के बावजूद 63 प्रतिशत बर्ज महाजनो में लिया जाता पाया गया।¹⁰ ग्रामतीर पर फमल बोनो के समय भी उनके पहले रह बर्ज की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक गस्कार के अवसर पर भी बड़ी मात्रा में बर्ज लिया जाता है। फमल लोभ होने पर बर्ज का भार बढ़ जाता है। ये लोग जो कुछ पैदा करत हैं या जंगल से प्राप्त करत हैं उस सम्पत्ती कीमत पर बेचना पड़ता है और जल्दतर पहन पर वे ही वस्तुएँ अधिक कीमत पर खरीदती होती है। यह भी दया गया है कि बर्ज की स्थिति में आदिवासी की पूरी की पूरी फमल बर्ज के भुगतान में खली जाती है। आदिवासियों की जमीन की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगने के बाद बर्ज में जमीन छूटना कम हुआ है, परन्तु यह रास्त दिखने है। आदिवासियों में बर्ज की जो स्थिति है उसमें गोपण के अनेक रूप छिपे हैं जिनका उल्लेख करना यहाँ सम्भव नहीं है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि बठिन आर्थिक परिस्थितियों में बर्जदारी इनके जीवन का अतिवाय अंग बन गयी है। फलतः महाजन दुबानदार और बड़े किसानों से अमानुषिक क्षतों पर ये लोग बर्ज प्राप्त करत हैं और गोपण के गिकार होत हैं। इस परिस्थिति को समाप्त करने के लिये सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है। लोकप्रदालन के माध्यम से भी इस क्षेत्र में बर्ज से सम्बन्धित विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ बर्ज लन-दन में होने वाला गोपण का अंश कम करने का भी प्रयास किया जा रहा है। यह भी एक तथ्य है कि आदिवासी समाज श्रमिक बंधक (bonded labour) के रूप में काम करता है लेकिन अब श्रमिक बंधक बनने की स्थिति नये कानून के प्रचलन के कारण समाप्त होने की आशा बधी है। जमीन की बिक्री पर प्रतिबंध होने के बावजूद उसकी जमीन का उपयोग महाजन या किसान करता पाया जाता है।¹¹

सर्वेक्षित क्षेत्र छोटा उदयपुर, एव नसवाडी ताल्लुको म आदिवासियों का बाहुल्य है। जैसा कि कहा जा चुका है, कुल आवादी का आधे से अधिक भाग आदिवासियों का है। शेष में सबण हिंदू जातियाँ, हरिजन, मुसलमान तथा अन्य धर्मों के लोग हैं। आमतौर पर यह देखने में आया है कि गैर आदिवासी सर्वर्ण जातियाँ बाजारों में ज्यादा हैं और कई गाँव ऐसे भी हैं जहाँ सर्वर्ण हिंदू जातियों का बाहुल्य है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि ये लोग प्रारम्भ में जमीन प्राप्त करने के लोभ में जंगल की ओर बढ़े, लेकिन बाद में वही बस गये। आदिवासियों से इन्हें कई प्रकार का लाभ मिला और वह लाभ आज भी मिल रहा है जैसे सस्ती जमीन, सस्ता धर्म, शोषण की सुविधा आदि। सुरक्षित क्षेत्र होते हुए भी इस क्षेत्र की राजनीति पर गैर आदिवासियों का प्रभाव देखा जा सकता है। दूरस्थ गाँवों में आदिवासियों के बीच गिने चुने परिवार गैर आदिवासियों के भी मिलेंगे। ये गैर आदिवासी इनके बीच शोषक के रूप में रहते हैं। गैर आदिवासियों का बसने का जो ढंग है उसे तीन रूपों में देख सकते हैं (1) बाजारनुमा गाँवों में बसना जैसे कवाट, कोसिद्रा, नसवाडी, छोटा उदयपुर आदि। (2) गैर आदिवासी प्रधान गाँव जिनमें सबण हिंदू, मुसलमान एवं हरिजन आदि हैं। इस प्रकार के गाँवों में श्रमिक किस्म के आदिवासी भी मिलेंगे। इन्हें आदिवासी क्षेत्रों में गैर आदिवासी गाँव कह सकते हैं। (3) तीसरी श्रेणी आदिवासी प्रधान गाँव जिनमें गिने चुने गैर आदिवासी परिवार जैसे दुकानदार या घरेलू उद्योग करने वाले बसे हुए हैं।

सारांश

1. ग्राम द निवेदन आश्रम रंगपुर स्थित लोकअदालत ने उपरोक्त भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में काम करना आरम्भ किया और इस क्षेत्र की समस्याओं एवं विवादों को सुलझाने की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया जिससे समाज की बुराईयाँ दूर हों और सामाजिक सम्बन्धों को एक नयी दिशा मिले। यह क्षेत्र विविध प्रकार की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं से ग्रसित था। आदिवासी परम्परा एवं संस्कृति की दृष्टि से यहाँ सामाजिक समस्याओं और आपसी विवादों को सुलझाने की एक परम्परा रही है और यह परम्परा आदिवासी-याय व्यवस्था के अनुसार है। आदिवासी समाज में जातिगत संगठन, सामाजिक संरचना एवं याय की ठोस व्यवस्था रही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत नातन्त्री की समस्या, जातिगत विवाद एवं तलाक के विवाद भूतप्रेत सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने की जातिगत व्यवस्था देखने

को मिलती है। आदिवासी समाज में कई प्रकार के अंधविश्वास हैं। इसलिए परम्परागत याय व्यवस्था में रूढ़ियों एवं अंध विश्वासों का पूरा स्थान है। आदिवासी समाज के जातिगत मगठन में जिस प्रकार की न्याय-व्यवस्था प्रचलित है, उसमें पारिवारिक, जातिगत एवं अंध प्रकार की आपसी समस्याएँ काफी हद तक सुलझाने का प्रयास रहता है। परन्तु इसकी एक सीमा है और उस सीमा के अतः ही आदिवासियों को याय मिलता है। लोक अदालत ने आदिवासी समाज की याय व्यवस्था को परिष्कृत करने का प्रयास किया है। आदिवासी समाज में अंधविश्वास, भूतप्रेत सम्बन्धी धारणा, स्त्रियों के प्रति मायता, विवाह का अस्थायित्व आदि बुराईयाँ को समाप्त करने का प्रयास भी लोकअदालत ने किया है। अपनी समस्याओं एवं आपसी विवादों को पंच निर्माण द्वारा खुले रूप में सुलझाया जाय, इस नीति को लोकअदालत ने स्वीकार किया है और यह नीति किसी न किसी रूप में आदिवासी समाज की याय व्यवस्था में विद्यमान है।¹

2 इस क्षेत्र की विविध प्रकार की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के कारण आदिवासी समाज में ही आपसी विवाद नहीं होते, समाज के अंध वर्गों से भी आदिवासियों के विवाद चलत रहते हैं यथा—(1) महाजन के साथ लेन देन (2) कज सम्बन्धी विवाद (3) जमीन के विवाद (4) जंगल के कमचारियों के साथ विवाद (5) पुलिस एवं अंध कमचारियों के साथ विवाद और गैर आदिवासी के साथ अंध विवाद आदि। इन विवादों को आदिवासी यायव्यवस्था के अतः ही निपटाया जा सकता है, इन्हें सुलझाने के लिये सरकारी यायालय में भी जाना पड़ता है, लेकिन लोकअदालत इन विवादों को सुलझाने का प्रयास करती है।

3 इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकअदालत न एक ओर तो आदिवासी समाज की परम्परागत यायव्यवस्था के स्वरूप को अपनाया है। उस पर आदिवासी यायव्यवस्था का यह प्रभाव देखा जा सकता है। तो दूसरी ओर आदिवासी यायव्यवस्था की बुराईयाँ को दूर करने का भी प्रयास किया गया है एवं अपने कार्यक्षेत्र को व्यापक भी बनाया है। इस प्रकार इसको गुणात्मक एवं विस्तारात्मक दोनों दृष्टियों से व्यापक बनाया गया है।

सदभ

- 1 जनगणना रिपोट बडोदा जिला (गुजरात) 1960
- 2 विमलशाह गुजरात के आदिवासी पृष्ठ 10 गुजरात विद्यापीठ महमदाबाद
- 3 विमलशाह उपरोक्त पृष्ठ 62
- 4 उद्धत श्री एल० एम० श्रीवास्त द्राइबल सोविनिगर प०—13, भारतीय आदिम जाति सेवक सघ नई दिल्ली
- 5 ए० आर० देसाई एरल इडिया इन ट्राजिशन, प० 51
- 6 विमलशाह पूर्वोक्त प० 32 महमदाबाद
- 7 विमलशाह, पूर्वोक्त पृष्ठ 39 40
- 8 हरिश्चन्द्र उपरतो भारतीय जनजातिगर, पृष्ठ 12 राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर 1970
- 9 स्टपन फूच द एबोर्जनल द्राइस आफ इडिया पृष्ठ 137 138 मकमिलन नई दिल्ली 1973
- 10 श्री० एन० श्रीवास्तव एक्सप्लायटेशन इन द्राइबल एरिया पृष्ठ 5 भारतीय आदिमजाति सेवक सघ नई दिल्ली—1968,
- 11 उपरोक्त पृष्ठ 17 18
- 12 आदिवासी 'याय'यवस्था के लिए अगला अध्याय देख

परम्परागत आदिवासी समाज में न्यायव्यवस्था

आदिम समाज में न्याय और नेतृत्व

परम्परागत समाज व्यवस्था में न्याय की खास पद्धति रही है। आदिकाल से मनुष्य समूह में रहता रहा है और उसके सामुदायिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिये नियमों का निर्माण किया गया है। आदिम समाज में इन नियमों पर धर्म जादू-टाना अलौकिक शक्तियों आदि मान्यताओं का अधिक प्रभाव था। इन नियमों के अतः सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिये परिवार और समूह के नेता या मुखिया को प्रमुख स्थान दिया गया। आदिम समाज का मूल रूप गुजरात के आदिवासियों में भले ही दखन की न मित्रों पर तु उसका सूक्ष्म रूप अवश्य देखने को मिलेगा।

आदिम समाज में व्यक्ति सदा समूह झुंड (horde) कुल (class) या कबीले (tribe) द्वारा सम्पूर्ण रूप से प्रभावित रहता है। वह अपने समुदाय तथा उसकी परम्पराओं, लोकमत, आज्ञावक्तियाँ (decrees) के आदेशों का पालन आज्ञाकारिता के साथ करता है।¹ स्पष्ट है कि आदिवासी समाज में समूह तत्त्व की प्रधानता है और ये लोग नियम का पालन निष्ठा पूर्वक करते हैं। प्रा. हॉबहाउस यह मत व्यक्त करते हैं कि ऐसे समाज में वस्तुतः उनकी अपनी प्रथाएँ होती हैं जिन्हें उसके सन्स्थ अस्तित्व रूप से बचनकारी अनुभव करते हैं। कुछ विद्वानों की राय में आदिवासी समाज के नियम एवं परम्पराएँ उनके ऊपर जबरन दबाव नहीं है, बचन नहीं है बल्कि यह स्वेच्छापूर्वक, समाज का व्यवस्थित करने के लिये बनाये गये नियम हैं। इस तथ्य को यहाँ की आदिवासी समाजव्यवस्था के अनुकूल

मान सकते हैं। आदिवासी समाज में 'याय और दण्ड' उनके द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार्य होते हैं। वे इसे सुव्यवस्थित समाज के लिये उपयोगी मानते हैं। विद्वान डॉ लोवी (Dr Lowie) ने इसे इस रूप में व्यक्त किया है 'सामान्य रूप से रूढ़िजय प्रथा (customary usage) के अलिखित नियम लिखित नियमों की तुलना में कहीं अधिक स्वेच्छापूर्वक मान जाते हैं और उनका पालन स्वयंप्रेरित होता है। वस्तुतः कोई समाज तब तक कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता जब तक उसके नियम स्वेच्छापूर्वक और स्वयं प्रेरणा से न माने जाय'।¹

भारतीय आदिवासी समाज में 'यायव्यवस्था' के माध्यम से इसकी सामाजिक संरचना में नियंत्रण आता है। विभिन्न आदिवासी जातियों में 'यायव्यवस्था' के भिन्न भिन्न स्वरूप प्रचलित हैं लेकिन सभी आदिवासियों में यह एक रूपता देखने में आती है कि उनमें ग्राम एवं जाति के मुखिया का प्रमुख स्थान होता है।

आदिवासी यायव्यवस्था

देश के प्रमुख आदिवासी समाजों जैसे सथाल, भील, दुबला, हो, मुंडा आदि में 'याय' कार्य करने वाले प्रमुख को विभिन्न मामलों से सम्बोधित किया जाता है। सथाल आदिवासी समाज की प्रमुख जाति है। छोटा नागपुर एवं बस्तर क्षेत्र सथाल आदिवासियों में मुखिया को माभी कहा जाता है। वह जाति का प्रमुख होता है। वैसे ग्राम, क्षेत्र एवं जिला स्तर पर भी पंचायत का संगठन होता है और परगना माभी मुखिया, पटेल आदि इनके जातिगत अधिकारी होते हैं। परगना माभी क्षेत्रीय पंचायत के प्रमुख की भूमिका निभाता है।²

माभी नागरिक व्यवस्था का संचालन अपने सहयोगियों की मदद से करता है। गांव में 'याय' व्यवस्था के लिये पंचायत होती है जिसमें पांच से लेकर ग्यारह संस्य तक होते हैं। मथालों में दस ग्यारह गांव समूह-स्तर पर भी पंचायत की व्यवस्था पायी जाती है जिसे स्थानीय भाषा में परगना कहते हैं। इसे गांव के लोग चुनते हैं। गांव की व्यवस्था में माभी के सहयोगी के रूप में परमानिक तथा चपरासी के रूप में भोदेत होता है। अनेक गांवों के बीच परगनन नामक मुखिया होता है। परगनेत के सहायक के रूप में देश माभी नामक सहयोगी रहता है। मथाला में संघीय परिषद (फंडरल काऊंसिल) की भी व्यवस्था है जिसका मुख्य कार्य 'यायव्यवस्था' देखना है।

सघीय परिषद

प्रशासनिक उद्देश्य में कुछ गाँवों का एक सघ बनाया जाता है। ऐसे सघ को बंग्लो (Bungalow) कहा जाता है। प्रत्येक बंग्लो में दो बाउसिल होती हैं। अथवा बाउसिल पचायत का उच्चस्थ अधिकारी बंग्लो का परगनत होता है। गाँव के मुखिया उक्त पचायत के सदस्य होते हैं। यह पचायत जटिल तथा पचीदे मामलों पर विचार करती है।

कुली द्रुप (Kuli Drup)

इस निचली सभा कहा जाता है जो बंगला की छुमरी सभा के रूप में कार्य करती है। कुलीद्रुप में प्रत्येक परिवार का मुखिया परिवार का प्रतिनिधित्व करता है तथा गाँव का मुखिया इस सदन की अध्यक्षता करता है। गाँव के अन्य अधिकारी इस सदन के पदेन सदस्य होते हैं। छोटे मोटे झगड़ों का निबटारा यह सदन करता है लेकिन बड़े मामलों पर उच्च सदन (पचायत) को ही नियंत्रण करने का अधिकार है।¹⁵

उराव जनजाति में न्याय

सुंदरवन की उराव जनजाति में पहले ग्राम पचायत तथा परहा पचायत दाना थी। परंतु परहा पचायत का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है।¹⁶ ग्राम पचायत छोटे छोटे सामिक एवं सामाजिक विवादों को निपटाती थी तथा परहा पचायत जो कि कई ग्रामों को मिलाकर बनती थी, दो गाँवों के बीच विवादों का निपटाती थी। एक समय था जबकि ग्राम पचायत का अधिकार क्षेत्र काफी व्यापक था तथा उसके निष्णयो का पालन कठोरता से किया जाता था। परंतु अब इसका महत्त्व कम होता जा रहा है और कोट में जान की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

उराव पचायत का गठन इस प्रकार होता है

- 1 राजमीरल - मुखिया (एक)
- 2 मंत्री - राजमीरल का परामर्शदाता (एक)
- 3 सदस्यगण (भरवा निश्चित नहीं है)
- 4 चौकीदार (एक)

पंचायत का मुखिया आमतौर पर वंशानुगत होता है और उसकी मृत्यु के बाद उसका सबसे बड़ा लड़का राजमौरत बनता है। राजमौरत मंत्री की नियुक्ति करता है तथा वह गांव के मुख्य लोगों एवं मंत्री की सलाह से सदस्यों का चुनाव करता है। चौकीदार का चुनाव पंचायत करती है। चुनाव के बाद पंचायत का अधिकारी ईश्वर के नाम पर समस्त प्रभावशाली लोगों के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। ग्राम पंचायत मुख्यतया निम्नलिखित विषयों से सम्बंधित झगड़ों को निपटान का कार्य करती है

- 1 मारपीट
- 2 जमीन के मामले
- 3 प्रेम से सम्बंधित मामले
- 4 सामाजिक नियमों एवं परम्पराओं के उल्लंघन के मामले।

कोल आदिवासी

मध्य भारत में काल आदिवासी समाज में भी जातीय पंचायत की व्यवस्था दमन की मिलती है। इस समाज में ग्रामप्रमुख होता है, परन्तु पाय बाय अंततः पंचायत में निहित होता है। इस समाज में पंच की अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। इसके निर्णय की अवहलना संभव नहीं होती। यहाँ पंच का तात्पर्य पाँच व्यक्ति में न होकर ग्राम समुदाय के सभी योग्य एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के समूह में है। यह एक प्रकार की ग्राम सभा होती है जिसका प्रधान गांव का परम्परागत मुखिया होता है। निर्णय सबकी राय से किया जाता है। इस समाज में सामाजिक बहिष्कार दबाव का प्रमुख अस्त्र है।

काल जन जाति पंचायत में अनेक प्रकार के विवादों को निपटाया जाता है। कोल पंचायत द्वारा निपटाए जाने वाले विवादों को इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं —

- 1 इतर जाति के साथ भोजन एवं गाराव यौन की गिरावट पर विचार करना।
- 2 कोल जाति द्वारा अमान्य यौन सम्बंध।
- 3 विवाह सम्बंधी विवाद जिसमें इससे सम्बंधित लन देन भी शामिल है।
- 4 सत्ता एवं वंश के सम्बंध में।

- 5 पारिवारिक विवाद ।
- 6 वज्र एवं मारपीट ।
- 7 पशु से सम्बन्धित विवाद ।
- 8 बोल जाति में असामाजिक घोषित कार्य करना ।
- 9 सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद ।⁹

इस आदिम जाति में न्यायव्यवस्था अधिक मजबूत देखने में आती है । न्याय कार्यक्षेत्र भी व्यापक है । मात्र सामाजिक क्षेत्र तक सीमित न होकर अधिक क्षेत्र को भी इनकी जाति पचायत से प्रभावित करती है ।

बिम्बवार

मध्य प्रदेश में बिम्बवार नाम की एक आदिम जाति है । यह आदिम जाति छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पायी जाती है । बिम्बवार जाति के लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास का ही एक अंग है । उनका घनक राजाओं के साथ जो सम्बन्ध था, उसका उल्लेख उनकी दत्त कथाओं में मिलता है ।⁹ इस आदिम जाति में परम्परा से किसी प्रकार की न्याय पचायत की व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता । डा० टी०बी० नायक के अनुसार सन 1955 तक बिम्बवारा में जातीय संगठन के आधार पर कोई विशेष महासंगठन या पचायत नाम की चीज नहीं थी । पर जय मह जाति दूसरी जातियों के द्वारा सतायी जाने लगी एवं पुलिस कमचारी इस बिना अपराध परेशान करने लगे तब 1955 में इस जाति में जागृति उत्पन्न हुई एवं इस जनजाति ने प्रथम बार पूर्ण जातीय संगठन के रूप में एक महासभा का निर्माण किया । इस महासभा में सम्पूर्ण बिम्बवार जातीय क्षेत्र की दो सौ क्षेत्रों में बांटा गया । प्रत्येक क्षेत्र से तीन मुखिया चुन जाते हैं जिन्हें गोठिया कहा जाता है तथा प्रत्येक ग्राम या दो ग्राम समूह से दो दो उपमुखिया चुने जाते हैं जिन्हें 'पंच' कहा जाता है ।¹⁰ गोठिया सामान्यतया निम्नलिखित कार्यों को पूरा करता है

- 1 जातीय चर्चा एकत्र करना ।
- 2 जातीय झगड़ों का निपटारा करना ।
- 3 पारिवारिक बंटवारे में भूमि का बंटवारा करना ।
- 4 जाति में व्याभिचार आदि होने से रोकना ।
- 5 महासभा द्वारा मान्य किये गये समाज सुधार सम्बन्धी नियमों की

सोगो को जानवारी कराना ।

6 चंदा तथा दण्ड की रकम का लेना-जोना रखना ।

याय-नाय गोठिया तथा पंच मिलकर करत हैं । यह मस्या मात्र याय कार्य करवे जाति कल्याण का काय भी सम्पन्न करती है । यदि कोई जटिल जातीय मामला गोठिया और पंच से गही सुलभ पाता है तो धन गाठिया की मदद से उसे सुलभाने की कोशिश की जाती है । यदि वे सब भी विफल हो जाते हैं तो जनवरी माह में होने वाली महासभा में सभी गाठियों तथा पंचों की राय से फैसला सुनाया जाता है ।¹¹ इस प्रकार बिम्बवार जाति में जातिगत पंचायत की व्यवस्था काफी मजबूत है । ग्राम स्तर पर यह पंचायत अपनी समस्याओं एवं विवादों की सुलभाने का भरसक प्रयास करती है ।

भील

भील समाज की संगठित करने के लिये जातीय स्तर पर अनवर प्रकार के जातीय नियम हैं जिनसे उनके जीवन का व्यवहार संचालित होता है और जिनसे उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक कार्यों में मदद मिलती है तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिकार एवं कर्तव्य का सम्यक ढंग से पालन होता है । सामाजिक व्यवहार, विवाह मृत्यु त्योहार आदि के बारे में निश्चित नियम हैं और यदि उन नियमों का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन करने वाले को दण्ड का भागीदार होना पड़ता है । जीवन का प्रत्येक क्षेत्र सन्तुलित रहे, इसके लिये याय की समुचित व्यवस्था है । जीवन के व्यवहार को नियमित रखने के जो नियम हैं वे भील के दैनिक कायकलाओं में देखे जा सकते हैं ।¹²

भील जाति में, खासकर भील प्रधान गांव में जातीय संगठन मजबूत होता है । इस जाति में याय व्यवस्था में खुलापन एवं पंच निणय की पुरानी परंपरा है जिसमें गांव के प्रमुख लोग एकत्र होकर विवादों की सुलभाने हैं । वैसे ग्राम संगठन की दृष्टि से गांव में एक परम्परागत प्रधान होता है जिसे स्थानीय बोलचाल की भाषा में वसवो (Vasawo) कहते हैं । यह गांव का मुखिया होता है तथा गांव में परिवार या ग्राम स्तर पर होने वाले सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में अग्रगण्य भी होता है । विवाह त्योहार मृत्यु आदि में इसकी प्रमुख भूमिका होती है । यायनाय में भी इसकी उपस्थिति आवश्यक होती है । सामान्यतया ग्राम प्रमुख का पद वंशानुगत होता है ।¹³

भील समाज में गांव के मुखिया को पटेल या तडवी कहते हैं । वह हर

गाव का मुखिया होता है और इस प्रकार पचायत की शक्तिया भी उसमें निहित होती है। आमतौर पर वह गाव के पचा की राय से याय काय करता है।¹⁴

इस जनजाति में पचायत की व्यवस्था है जो जाति स्तर पर 'याय का काय' करती है। गाव के बुजुर्ग एवं प्रमुख लोग इस पचायत के सदस्य होते हैं। पचायत का कोई लिखित विधान न होकर इसकी अपनी परम्परा एवं परम्परागत नियम हैं। समायतया गाव के बुजुर्ग एवं प्रमुख लोग एक स्थान पर एकत्र होते हैं और विवाद का सुलझाते हैं। यह पचायत कई प्रकार की समस्याएँ एवं विवादों को सुलझाती है, जस—प्रेम सम्बंध, विवाह एवं तलाक से सम्बंधित विवाद पशु का लेकर उठन वाले विवाद जबरन बेगार से सम्बंधित विवाद आदि। विवाद को सुलझाने के लिय बुलायी गयी पचायत में सभी उपस्थित सदस्य एक स्थान पर बैठते हैं। इस बैठक में अध्यक्ष या प्रमुख की भूमिका गाव का बुजुर्ग, गाव का अधिक सम्भवार-बुद्धिमान व्यक्ति या जातिगत प्रमुख बसबी (Vasawo) में से कोई एक निभाता है। यह व्यक्ति विवाद को सुलझाने में अग्रगण्य करता है। इस बात का पूरा प्रयास किया जाता है कि नियम सर्वसम्मति से किया जाय। सर्वसम्मति के प्रयास में विवाद की गहराई में जान का प्रयास किया जाता है ताकि सत्य की जानकारी हो सके। पचायत द्वारा जो भी नियम लिया जाता है, उसका अच्छी तरह पालन किया जाता है। अतः जनमत एवं नियम का आदर करने की कठोर परम्परा इस समाज में पायी जाती है। इस बारे में टलर ने कहा है कि इस प्रकार के आदिम समाज में समाज को नियंत्रित करने की कठोर परम्परा है तथा यहाँ जनमत की शक्ति काफी मजबूत है¹⁵ अर्थात् पचायत एक मजबूत सामाजिक संस्था है।

आदिवासी समाज में विवाह सम्बंधी विवाद प्राये दिन होते रहते हैं। लोकप्रदालत में भी विवाह सम्बंधी विवादों की संख्या अधिक है। विवाह की स्वतंत्रता एवं समाज में स्त्रियों का समान स्थान आदि ऐसे कारण हैं जिनसे विवाह सम्बंधी विवाद अधिक होते हैं। विवाह सम्बंधी कई प्रकार के विवादों का पचायत द्वारा सुलझाया जाता है जैसे जब अविवाहित लड़की को कोई व्यक्ति भगा ले जाये अथवा विवाह के पूर्व कोई लड़की गर्भवती हो जाये अथवा जब कोई विवाहित महिला दूसरे गाव के किसी व्यक्ति के पास चली जाय आदि।¹⁶

भीत सत्य बालने के अभ्यासों होते हैं। सत्य नैतिकता एवं अपनी बात पर दब रहना उनकी विनियमता है। यही कारण है कि चोरी जैसे मामले

वाफी कम आत है। फिर भी कई मामले उस घात हैं जिनसे लोग बान को छिपाने का प्रयास करत है। जैसा कि लोकअदालत में भी देखन में आया, विवाह तलाक आदि के मामले में महिलायें प्रारम्भ में सही बात स्वीकार नहीं करती या यदि अपनी गलती है तो उम छिपाने का प्रयास करती हैं। यही बात कमोबश अ य प्रकार के विवादा पर भी लागू होती है।

परम्परागत भील पचायत में सत्य को सामने मान क लिय शपथ दिनायी जाती है। यह शपथ इस प्रकार की पायी जाती है जस 'यदि मैं सत्य नहीं बोलू तो मुझे नेर ला जाय मेरा पुत्र मर जाय, मुझे डाकन परेशान करें' आदि। इसी प्रकार यह राजा सूर्य, अग्नि, जल आदि को साक्षी लेकर भी सत्य बोलने की शपथ लेता है।¹⁷ इस प्रकार की शपथ लेने के बाद व्यक्ति सत्य बात कहता है। यह अपेक्षा भी रखी जाती है कि जो व्यक्ति पच के सामने इस प्रकार की शपथ ग्रहण करेगा, वह सत्य कहेगा ही।

इस प्रकार भील जाति में (1) 'याय' का बिस्तार जातिगत स्तर पर सामाजिक धार्मिक समस्याओं को सुलझाने तक है। (2) इसके साथ साथ इसकी निणय प्रक्रिया में काफी हद तक लोकतांत्रिकता है। (3) निणय सामायतया सर्वसम्मति से किया जाता है। (4) निणय का पालन निष्ठापूर्वक किया जाता है। (5) पचायत में गांव के बुजुर्ग, सम्भार एव बुद्धिमान व्यक्ति भाग लेते हैं। (6) इसके नियम परम्परागत हैं। (7) पचायत का प्रमुख स्थायी न होकर प्रत्येक बैठक में प्रायः भलग भलग होता है। यह प्रमुख गांव का प्रतिष्ठित, योग्य व्यक्ति होता है। (8) सत्य पर पहुचने के लिये (क) शपथ दिलायी जाती है और (ख) मामले पर गहराई से विचार किया जाता है।

दुबला समाज में न्याय

अय आदिम जातियों की भांति दुबला समाज में भी जाति स्तर पर याय व्यवस्था विद्यमान है। दुबला जाति में तीन¹⁸ स्तर की 'याय' व्यवस्था पायी जाती है

(क) राज्य कानून के अंतर्गत गठित पचायत।

(ख) जाति स्तर पर संगठित ग्राम या गली (फालिया) स्तर की जाति पचायत जो उनके दैनिक विवादों को सुलझाती है।

(ग) सम्पूर्ण जानीय स्तर की जाति पचायत। यह पचायत जिला या उससे भी बड़े क्षेत्र की संगठित जातीय पचायत है। इसमें सभी

प्रकार की जातीय समस्याओं को सुलझाया जाता है।

दुबला पचायत के प्रमुख का पटल कहा जाता है। पटल का चुनाव गाव में रहने वाले बालिगों द्वारा किया जाता है। पटल के चुनाव में उम्र एवं अनुभव के साथ-साथ प्रभाव को भी महत्त्व दिया जाता है। इस प्रकार गाव का प्रौढ़ अनुभवहीन एवं प्रभावशाली व्यक्ति पचायत का पटल चुना जाता है। पटल पूरे गाव का मुखिया होता है। वह गाव की समस्याओं एवं विवादों को निपटाने में प्रमुख भूमिका निभाता है।

दुबला पचायत का गठन एवं कार्य पद्धति—इस पचायत का जो प्रमुख चुना जाता है वह पूरे गाव में एक ही होता है लेकिन इसके सहयोगी के रूप में गाव के प्रत्येक फलिये (वाड) से एक प्रतिनिधि पचायत में जाता है। यह प्रतिनिधि अपने वाड का प्रतिनिधित्व करता है। पचायत का प्रमुख प्रतिनिधियों में से एक को अमलदार नियुक्त करता है। अमलदार की जिम्मेदारी होती है कि सभा की बैठक की सूचना सबको दे।

दुबला पचायत गाव एवं जाति से सम्बंधित व्यक्तिगत पारिवारिक ववाहिक तथा अन्य सामाजिक विवादों को सुलझाती है। पचायत दोषी पाये गये पक्ष के ऊपर आर्थिक दंड भी करती है। ग्रामतीर पर विवाद एवं उसके फैसले के बारे में किसी प्रकार का लिखित विवरण रखने की परम्परा नहीं है। इसका मुख्य कारण शिक्षा का अभाव है। पिछले कुछ दिनों से इस समाज में शिक्षा का प्रचार बढ़ा है और कुछ लोग न लिखना पढ़ना भी सीखा है। शिथिल गावों में तलाक सम्बंधी विवादों का विवरण रखने का प्रयास किया जाता है। स्थानीय भाषा में इसे फारगती नामा कहा जाता है।¹⁸ इस प्रकार के फारगती नामे में तलाक का प्रश्न एवं निणय लिखा जाता है। इस पर पक्ष एवं दोनों पक्षों—वादी एवं प्रतिवादी के हस्ताक्षर होते हैं।

आदिवासी समाज में ग्रामप्रमुख की जो भूमिका है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह गाव का सामाजिक राजनतिक एवं नतिक प्रमुख भी होता है। अफ्रीकी समाज के अध्ययन में कहा गया है कि गाव का मुखिया गाव के सामाजिक सम्बन्धों में एकरूपता स्थापित करता है। इस काम में वह याय काय का भी प्रमुख होता है। वह व्यक्ति पारिवारिक एवं अन्य सामाजिक सम्बन्धों को सामान्य एवं शुद्ध बनाता है।¹⁹ अफ्रीकी समाज में ग्रामप्रमुख ग्रामीण विवादों को सुलझाता है। दक्षिण अफ्रीका के 'यो' समाज का ग्रामप्रमुख गाव में अच्छे सम्बन्धों के लिये जिम्मेदार होता है साथ ही साथ उनके विवादों को भी सुलझाता है। वह दोनों पक्षों को सुनकर याय देता है। इस प्रकार छोटे-छोटे ग्राम समुदाय में

मर्यादा की भूमिका निभाता है ।

सारांश

1 परम्परागत धार्मिकी या व्यवस्था के बारे में मर्यादा में विचार रिया गया है । हमने देखा है कि विभिन्न धार्मिकी रीतियों में याद की परम्परा भिन्न भिन्न है और प्रायः सभी धार्मिकी रीतियाँ ॥ व्यवस्था में कई मामूली एवं भी हैं । कुछ बातें सभी धार्मिकी रीतियों की जानी-पूजी हैं मर्यादा पर लागू होती हैं तो कुछ बातें में भिन्नता है । यदि व्यवस्था की रीतें हैं तो मर्यादा बातों का हिसाब ॥ गिना गकत है

(क) पंच नियम ।

(ग) नियम में मान्यताओं के मूल्य का मूल्यांकन रिया जाना ।

(ग) कुछ अपवादों को छोड़कर पचायत प्रमुख का अनिवार्य रूप से चुना जाना ।

(घ) परम्परा में निर्वाह ।

(ङ) पंच नियम का बढोस्ता में पालन करना ।

(च) अतिरिक्त नियम ।

(छ) जादू टोन में विश्वास ।

(ज) पचायत का जाति तक सीमित होना ।

(झ) पचायत का सघन कार्य क्षेत्र विवाह परिवार, यौन सम्बंध सामाजिक (जातिगत) विवाद तक सीमित है ।

2 धार्मिकी या व्यवस्था का जो स्वरूप है उससे स्पष्ट हो जाना है कि जीवन की कई समस्याएँ उसकी सीमा में नहीं आती हैं । उनमें मुख्य में हैं

(क) महाजनों के साथ लन देन का मामला ।

(ख) दूसरी जातियों के साथ विवाद ।

(ग) जंगल के कर्मचारियों के साथ विवाद ।

(घ) पुलिस एवं अन्य कर्मचारियों के साथ विवाद ।

(ङ) मारपीट के मामले ।

(च) जमीन व भूगड आदि ।

उक्त मामले आदिवासी पचायत द्वारा सामायतया नही निपटाये जात है । इसके लिये उह सरकारी अदालत मे जाना पडता है । जातिगत पचायत के प्रति उदासीनता के कारण यह भी देखने मे आता है कि जो मामले परम्परागत रूप से जातीय पचायत म जाते रहे हैं, वे भी अब सरकारी अदालत मे जाने लगे हैं । इससे स्पष्ट है कि जातीय पचायत का काय धीरे धीरे कम होता जा रहा है ।

3 आदिवासी पचायत मे दंड की जो व्यवस्था है वह भी सामाय स भित है और उसे केवल उसी जाति के लोगो तक सीमित किया जा सकता है । जैसे आदिवासिया मे डायन (witches) एव ओभा भगत की परम्परा है । इसमे शारीरिक कष्ट दिया जाता है । किसी व्यक्ति को एसकर महिला को डायन करार देने पर उसे शारीरिक कष्ट दिया जाता है । कभी कभी तो इस परिस्थिति मे मौत भी हो जाती है । इसी प्रकार भूत प्रेत के विश्वास म ओभा भगत द्वारा कष्ट दूर करने के नाम पर ददनाक शारीरिक कष्ट दिया जाता है । अफ्रीका के आदिवासिया मे डायन के मन्थ ध मे जो अध्ययन हुए हैं, उससे एस बात की पुष्टि होती है कि आदिम समाज मे अधिश्वास की जडें काफी गहरी है और प्राय विश्व के सभी भागो म इस समाज म इसे देखा जा सकता है । प्रा० माकम ग्लूकमैन ने अफ्रीकी समाज में डायन के भय एव मुक्ति का अध्ययन प्रस्तुत किया है । वैसे अफ्रीकी आदिम समाज में इससे मुक्ति (anti-witchcraft movement) के लिय आ दालन भी चले ह जिसका अच्छा प्रभाव पडा है ।³

4 अपराधी अपना अपराध स्वीकार करे, या सत्य बात कह इसके निये भी कई प्रकार के कठोर कदम उठाये जाते है—जसे(क) पच द्वारा अपराधी को गरम सोहा हाथ म लेने के लिये कहा जाता है । माना यह जाता है कि यदि वह निर्दोष है तो उसका हाथ नही जलेगा और दोषी होने पर जलेगा ।

(ख) एक बर्तन मे घी को खूब गरम किया जाता है और उसम दो सिक्के डाल जात है । अपराधी को उसम हाथ डालकर इह निकालने को कहा जाता है । माना जाता है की यदि वह निर्दोष है तो उसका हाथ नही जलेगा ।⁴ इस प्रकार की गलत मायताआ पर आधारित दण्ड के नियम का आज के समाज द्वारा स्वीकार नही किया जा सकता ।

5 आदिवासी समाज म जिस प्रकार के विवादा के निपटारे की परम्परा गत व्यवस्था मौजूद थी, वे तो लोकअदालत द्वारा निपटाय ही जात हैं

लेकिन लोकअदालत ने अथ विवादा को भी यथा आदिवासियों एवं गर आदिवासियों के आपसी विवाद, भूमि सम्बन्धी विवाद, पौजदारी कानून के अंतर्गत आने वाले कई प्रकार के विवाद आदि सुलझाने की दिशा में प्रयास किया है। इस प्रकार उसने परम्परागत न्याय क्षेत्र का विस्तार किया है।

आदिवासी समाज की परम्परागत न्याय व्यवस्थाएँ अंधविश्वास, रूढ़ियों एवं अवैज्ञानिक गलत धारणाओं और मायताओं का बोल बाला रहता था जिसके कारण निर्दोष व्यक्तियाँ यथा, तथाकथित जायन आदि को अमानुषिक प्रणालियों एवं दंड भोगने पड़ते थे। लोकअदालत ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसने न केवल उनकी अत धारणाओं को बल कर उनके विवेक भाव को जागृत करने का प्रयास किया है बल्कि शारीरिक दंड-प्रणाली को अस्वीकार करने दोषी व्यक्ति के प्रति माननीय दृष्टिकोण अपनाये जाने की भावना सुदृढ़ की है। अंधविश्वास या रूढ़िगत माय-ताओं के कारण किसी निर्दोष को दंड मिल जाये, यह लोकअदालत की कल्पना क्षति के परे की बात है और इसका दशन लोकअदालत द्वारा दिये गये विभिन्न निर्णयों से हो सकता है।

संदर्भ

1. पी० मोलनोवस्की नय समाज में अपराध और पना (Crimes and Customs in Savage Society) पृष्ठ 3 म० प्र हिन्दी अथ अकादमी भोपाल 1971
2. उद्यत उपरीक्त पृष्ठ 9
3. उपरीक्त पृष्ठ 10
4. स्टफन फच (Stephen fuchs) द एबोरिजिनल ट्राइब्स आफ इंडिया पृष्ठ 152 मेकमिलन नई दिल्ली 1973
5. पी० सी विश्वास सभासद आफ द सवाल परगना पृष्ठ 149 अध्याय ६
6. अनिल कुमार दास द अररस आफ सुंदर बन पृष्ठ 227 1963
7. हरिचन्द्र उग्रेशी भारतीय जनजातिया पृष्ठ 117 119 राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर—1970
8. वास्टर जी प्रीफियास द कौल ट्राइब्स आफ सेटल इंडिया पृष्ठ 48 द रायल

एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल कलकत्ता 1946

- 9 डा० नी० बी० नायक वारह भाई बिजवार पृष्ठ 1 मध्य प्रश्न हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल 1972
- 10 डा० टी० बी० नायक वारह भाई बिजवार पृ० 58 सन 1972
- 11 उपरोक्त पृष्ठ 68
- 12 उपरोक्त
- 13 डा० टी० बी० नायक द भीक्स ए स्टडी पृष्ठ 223 27 भारतीय आन्तिम जाति सेवक सघ दिल्ली 1956
- 14 दब जी० एस० छुरिय द गिडयूल टाइस पृष्ठ 232
- 15 The controlling forces of society are at work when among those savages only in more rudimentary ways than among ourselves public opinion is already a great power E D Taylor Anthropolgy Vol (II) (Thinkers Library Watts & Co London 1949) page 136
- 16 डा० टी० बी० नायक उपरोक्त पृष्ठ 53
- 17 उपरोक्त पृष्ठ 233
- 18 पी० जी० शाह द दुबला आफ गुजरात पृष्ठ 46 भारतीय आन्तिम जाति सेवक सघ, दिल्ली 1958
- 19 पी० जी० शाह उपरोक्त पृष्ठ 50
- 20 दब माक्स ग्लूक मन, 'आडर एण्ड रिबेलियन इन टाइबल अफ्रीका' पृष्ठ 151 52 द फ्री प्रेस आफ स्टेनको 'यूवाक'—1963
- 21 दब जे० सी० माइकल आडर एण्ड रिबेलियन इन टाइबल अफ्रीका पृष्ठ 152
- 22 देखें टी० बी० नायक, उपरोक्त पृष्ठ 234 35
- 23 देखें माक्स ग्लूकमन आडर एण्ड रिबेलियन इन टाइबल अफ्रीका पृष्ठ 143 द फ्री प्रेस आफ स्टेनको 'यूवाक' 1963
- 24 देख टी० बी० नायक उपरोक्त पृष्ठ 234 35

ग्राम की सामाजिक संरचना

गाव और मुख्यालय

जिन दस गावा का अध्ययन में शामिल किया गया है वे सभी बड़ौदा जिले की दो तहसीला में स्थित हैं। कुछ गाव छोटा उदयपुर तहसील के हैं तो कुछ नसवाड़ी तहसील के। विकास की दृष्टि से भी ये गाव इन्हीं दोनों प्रखण्डों से जुड़े हुए हैं। आनन्द निवेतन आश्रम जहाँ लोकप्रदात का केन्द्रीय कार्यालय है लगभग मध्य में है। आश्रम से नसवाड़ी एवं छोटा उदयपुर दोनों स्थानों की दूरी प्रायः समान है। सरकारी कार्यालयों एवं आवागमन की दृष्टि से यह क्षेत्र एक समय अत्यन्त असुविधाजनक स्थिति में था लेकिन आजकल यह क्षेत्र सड़क मार्ग से जुड़ गया है। फिर भी अनेक गावा की स्थिति इस दृष्टि से आज भी ज्यादा अच्छी नहीं मानी जा सकती। सरकारी कार्यालयों से सर्वेक्षित गावा की दूरी नीचे निम्नी तालिका में देख सकते हैं।

पंचायती राज की स्थापना के बाद ग्रामस्तर पर प्रशासन एवं विकास की एजेंसी के रूप में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई है लेकिन ग्राम पंचायत शासन की कोई विशेष अधिकार प्राप्त इकाई नहीं है। वह प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे निचली इकाई है जिससे ग्राम को कुछ मामूली सी सुविधायें उपलब्ध हो गई हैं और ग्राम की दृष्टि से भी इसे सीमित अधिकार हैं तथा वह ग्राम पंचायतों के माध्यम से गाव में होने वाले छोटे छोटे विवादों को सुलझाती भी है। पंचायत कार्यालय में सभी सर्वेक्षित गावों की दूरी 2 किलोमीटर से कम है। इसलिए इन गावा के लोगों को पंचायती राज से सम्बंधित सामान्य कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ता परन्तु इसके ऊपर की

तानिका मन्गा-8

गाव में स्थानीय मुख्यालयों की दूरी

दि० मा०

क्र०	गाव का नाम	पुलिस	पंचायत	प्रखण्ड कार्यालय	जिला मुख्यालय
(1)	रन्पुर	17	0	30	125
(2)	मन्गावांग	16	0	29	124
(3)	गरगा	15	2	24	128
(4)	भागडा	13	2	26	122
(5)	मन्गावांग	17	0	30	119
(6)	बनराहली (रन्पुर)	14	1	28	143
(7)	गावावाट	16	0	24	139
(8)	मकोडा	14	0	23	129
(9)	मण्डिया	14	2	27	121
(10)	बिजला	12	2	25	121

दुवाई के बारे में यह स्थिति नहीं है। विकास की प्रमुख दुवाई प्रखण्ड कार्यालय है जिसमें 4 गावा की दूरी 21 से 25 किलोमीटर के बीच है और 6 गावा की दूरी 26 से 30 किलोमीटर। पंचायती राज की मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत प्रायः प्रत्येक आवश्यक कार्य के लिये प्रखण्ड कार्यालय तक जाना पड़ता है। इसलिए दूरी की दृष्टि से प्रखण्ड कार्यालय की स्थिति असुविधाजनक मान सकता है। गाव से इतनी दूर जाकर काम करना इनके लिए कठिन हो जाता है और आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण यह दूरी उनका आर्थिक बोझ बढ़ाती है। पुलिस चौकी से गाव की दूरी अपेक्षाकृत कम है। 6 गावा से पुलिस चौकी की दूरी 11 से 15 किलोमीटर है जबकि 4 गावों में 16 से 20 किलोमीटर के बीच। पुलिस चौकी बाकी पुरानी है जबकि प्रखण्ड कार्यालय नियोजित अव्यवस्था का परिणाम है। क्षेत्र में घूमन और चर्चा करने से इस बात की पुष्टि हुई कि इस क्षेत्र में आपसी झगडा की जो स्थिति थी, उसमें पुलिस की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती थी। करीब दो दशक पूर्व यहाँ के आदिवासी छोटे छोटे मामला में भी लड़ाई झगडा कर बैठते थे और भार पोट ग्राम बात थी। उस समय पुलिस चौकी ही प्रशासन की सबसे निकट की दुवाई थी। जिला

काफी दूर है। यद्यपि जिला मुख्यालय तक जाने के लिये बस की सामान्य सुविधा उपलब्ध है फिर भी अधिक दूर होने के कारण सामान्य नागरिक अपनी आवश्यकता स्थानीय स्तर पर ही पूरा करता है और बहुत आवश्यक कार्य होने पर ही जिला मुख्यालय तक जाता है।

आवागमन की सुविधा

ग्राम्य सामान्य सुविधाओं के लिये गांव के लोगों को कितनी दूर जाना पड़ता है यह जानना भी उपयोगी रहेगा। इस क्षेत्र का आर्थिक व्यवहार कुछ बाजारों तक ही सीमित है। आश्रम के आस पास के गांवों के लिये मुख्य बाजार कवाट है। नसवाड़ी एवं छोटा उदयपुर से भी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। पिछले दशकों में सड़कों का पर्याप्त विकास हुआ है और स्थानीय सड़कें प्रायः सभी क्षेत्रों में अवस्थित हैं। गांव के लोगों की सीमित आवश्यकताओं को देखते हुए उन्हें आवागमन की दूरी कम चलनी है। तालिका 9 (पृष्ठ 47) से विभिन्न उपयोगी केन्द्रों के गांव की दूरी की जानकारी उपलब्ध हो सकती है।

सुविधा की दृष्टि से चिकित्सा तारघर एवं बिजली की सुविधा आज भी कई गांवों का उपलब्ध नहीं है। रेलवे स्टेशन भी दूर है, यद्यपि सड़क से आवागमन की सामान्य सुविधा सुलभ हो जाती है। माल की खरीद बिक्री के लिये प्रायः सभी गांवों के लोगों को दूरस्थ बाजार में जाना पड़ता है। लोकप्रदालत की दूरी कुछ गांवों से कम है तो कुछ गांवों से ज्यादा। इससे स्पष्ट होता है कि लोकप्रदालत का कार्य क्षेत्र दूर के गांवों तक फैला हुआ है और दूरस्थ गांवों के लोग भी विवादों को सुलझाने के लिये यहां आते हैं।

भूमि और उसका वितरण

सर्वोक्षित गांवों में जमीन एवं उसके उपयोग की स्थिति से वहां की आर्थिक स्थिति का अंदाज लगा सकता हैं। भूमि सम्बन्धी दो प्रकार के प्रावधान दिए जा रहे हैं जिनसे उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति का दर्शन हो सकता है—

- (1) गांव में कुल जमीन एवं उसका विस्म के अनुसार उपयोग, और
- (2) भूमि वितरण की स्थिति। जितनी जमीन में सुविधापूर्वक खेती की जा सकती है उस पर खेती होती है और शेष भाग जंगलों के नीचे एवं बेकार रहता है। जनसंख्या की वृद्धि एवं कृषि का गान बढ़ने के साथ-साथ वज्र भूमि को भी खेती योग्य बनाने का सतत प्रयास किया जाता रहा है। सर्वोक्षित गांवों में कुल जमीन की स्थिति तालिका 10 (पृष्ठ 48) के अनुसार है।

Dr. Hiepke A. B. Jansen

1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 26

[illegible]

तालिका सरया-10

भूमि का प्रकार एवं उपयोग

क्र०	गाव का नाम	वृषि होती है	मकाना में प्रयुक्त	बजर	कुल क्षेत्रफल एकर म
(1)	रगपुर	600	15	239	854
(2)	मोटावाटा	753	20	138	911
(3)	घरवा	1000	50	92	1142
(4)	जाम्बा	800	10	205	1015
(5)	गजलावाट	195	5	00	200
(6)	कपराइली (रतनपुर)	280	10	65	345
(7)	गोयावाट	300	20	380	700
(8)	मकोडी	1580	20	190	1790
(9)	मेखडिया	652	5	00	657
(10)	विजली	332	5	10	347

अधिकांश गावों में जितनी जमीन खेती लायक है उस सब पर खेती होती है। बजर भूमि की जा स्थिति है, उसमें सामान्यतः खेती होना संभव नहीं। विशेष योजना द्वारा उसे खेती योग्य बनाया जा सकता है। गजलावाट एवं मेखडिया में तो जमीन काफी सीमित है और यहाँ बजर भूमि भी नहीं है। कुछ गावों में मकान काफी कम जमीन पर स्थित हैं।

गाव की आर्थिक स्थिति का अंदाज लगाने के लिये भूमि वितरण की स्थिति को भी देखना आवश्यक है। आदिवासी गाव में मकान के लिये जमीन सभी के पास है। लेकिन खेती की जमीन सब परिवारों के पास नहीं है। कुछ भूमिहीन परिवार भी हैं। आमतौर पर आदिवासी परिवार के पास कुछ न कुछ खेती की जमीन होती है। परंतु फिर भी कि हो कारणों से कुछ परिवार भूमिहीन हो गये हैं। उनकी भूमिहीनता का कारण जानने के प्रयास में निम्न तथ्य सामने आये —

(क) बज्रों में फसल के कारण उनकी जमीन हाथ से निकल गयी और वे भूमिहीन की स्थिति में आ गये। जैसे विवाह मृत्यु या अन्य कठिन

परिस्थितियों में कर्ज लेने पर जमीन दूसरे के हाथ में चली गयी।

- (ख) कुछ परिवारों ने अपना मूल गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाकर भोपडी बना ली। ऐसी स्थिति में नये गांव में वे भूमिहीन हो गए।
- (ग) गैर आदिवासी लोग धांचे की तलाश में आये और गांव में भोपडी बना ली। कुम्हार, खाती, नाई या अन्य मजदूर स्तर की जातियों के ऐसे लोग भूमिहीन की श्रेणी में स्वतः आ गये क्योंकि बाहर से आने के कारण उनके पास भूमि होना संभव नहीं था।

पृष्ठ 50 में तालिका 11 से विभिन्न गांवों में भूमि वितरण की स्थिति देखी जा सकती है।

यस क्षेत्र में भूमि वितरण की स्थिति को देखते हुए कृषि विकास की संभावना उत्साहवर्धक है। हालांकि परम्परागत कृषि-पद्धति पिछड़ी हुई एवं वर्षा पर निर्भर होने के कारण उत्पादन अत्यंत कम है। फिर भी पिछले एक दशक में उन्नत कृषि के तरीकों के प्रसार के कारण यहां कृषि विकास देखने में आया है। गांव के लोगों ने इस बात की पुष्टि भी की कि हमने पिछले दस वर्षों में कृषि की अच्छी पद्धति सीखी है और हमें सिंचाई की सुविधा भी मिली है और इन दोनों सुविधाओं के कारण उत्पादन में दो से लेकर सात-आठ गुणा तक बढ़ि हुई है। पूरे क्षेत्र में भूमिगत (अंडर ग्राउंड) पाइप लाइन देखने का मिलती है। उन्नत कृषि के प्रशिक्षण एवं सिंचाई सुविधा के विस्तार से कम जमीन में अधिक पैदावार करने का अवसर मिला है। कुछ वर्ष पूर्व गांव में कुआ का अभाव था। लेकिन आज प्रायः सभी गांवों में सिंचाई के लिये कुए हैं। गजनावाट, रामपुर, जाम्बा मोटावाटा आदि गांवों में शक्तिशाली पम्पिंग सेट से गांव के लोगों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और सिंचाई की सामूहिक व्यवस्था का विकास हुआ है।

जाति और ग्रामसभा

सामाजिक व्यवस्था में जाति सबसे अधिक प्रभावी तत्व है। आदिवासी प्रधान गांवों में अनेक आदिवासी उपजातियां हैं। इन उपजातियों की अपनी अपनी परम्पराएं हैं। इन परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभाओं में अनेक विवादों को सुलझाया है। इन गांवों का जातीय ढांचा एवं विवाद सुलझाने की स्थिति तालिका-12 पृष्ठ 51 में दर्शाई गयी है।

इन गांवों की सामाजिक संरचना को देखते हुए यह कहना उचित होगा कि इन गांवों के मूल निवासी आदिवासी हैं। हरिजन या संवर्ण हिंदू यहां

तालिका सत्या-11

गाव मे मूमि स्वामित्व की स्थिति एव कयि साधन

क्र०	गांव वा नाम	भूमि वितरण (परिवार सख्या)					इदि साधन	
		भूमिहीन 5 एकड़ 11	6 स 10 एकड़ सक	11 से 20 एकड़ सक	20 एकड़ से अधिक	कुमा	पम्पिंग सेट	
(1)	रणपुर	3	54	17	5	00	12	4
(2)	मोटाबांदा	1	59	56	9	00	13	6
(3)	छरगा	1	30	115	20	10	30	6
(4)	जाम्ना	1	84	10	5	00	25	7
(5)	पञ्जसाबाट	0	1	18	0	1	7	1
(6)	पपरारसी (रतनपुर)	11	15	18	7	0	3	1
(7)	मोयाबांट	0	89	40	14	2	11	8
(8)	मदोही	4	10	83	50	4	30	12
(9)	मेयडिया	1	60	8	6	00	9	2
(10)	बिजनी	1	24	4	00	3	4	00

बाद में आये हैं। आदिवासी जातियाँ में राठवा, भील एवं नायका हैं। वस ये सभी आदिवासी कह जाते हैं, परन्तु ये उपजातियाँ में बट हुए हैं और आपस में भेदभाव भी करते हैं। राठवा एवं भील अपने को उच्च मानते हैं। परन्तु यह भेदभाव उतना कठोर नहीं है जितना हिंदू सवर्ण एवं हरिजन के बीच है। ग्राम स्तर पर सभी आदिवासी हैं और आदिवासी के नाते एक सूत्र में बंधे हुए हैं। जातीय संगठन का प्रभाव क्षेत्र, परम्परा रीति रिवाज एवं नस्लगत तंत्र सीमित है। विवाह, मृत्यु आदि मस्कारों में अन्तर है।

ग्रामसभा द्वारा विवाहों को सुलझाने की जो स्थिति देखने में आई है उस पर से यह कहना चाहेंगे कि अभी तक यह बात जड़ नहीं पकड़ सकी या ऐसी व्यवस्था विकसित नहीं हो पायी है कि ग्रामस्तर पर लोकप्रदात मुद्रा रूप से चल सके। जो गांव उसाही है उनमें तो ग्रामस्तर पर लोकप्रदात का काम चलता पाया जाता है परन्तु सामान्य स्थिति में लोग आश्रम की लोकप्रदात में ही जाने के अभ्यस्त हैं।

उन गावों में लोग का शैक्षणिक स्तर काफी गिरा हुआ है। आश्रम स्थापना के पूर्व तो इस क्षेत्र में साक्षर व्यक्ति नहीं थे बराबर थे। शिक्षा का विस्तार एवं रुचि जागृत करने का श्रेय आश्रम को दिया जाना चाहिये। आरम्भ में प्रौढ शिक्षा का कार्यक्रम आश्रम की ओर से शुरू किया गया था। बाद में क्षेत्र में विद्यालयों की स्थापना हुई। आज विभिन्न सर्वेक्षित गावों में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है

तालिका संख्या—13

गावों में शिक्षा का स्तर

क्र०	गाव का नाम	अक्षरज्ञान	प्राथमिक शिक्षा	उ० प्राथमिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा	कालेज शिक्षा	योग
(1)	रगपुर	75	40	11	2	00	128
(2)	भोटावाटा	170	125	9	3	1	308
(3)	खरका	25	150	9	7	1	192
(4)	जाम्बा	38	35	00	0	00	73
(5)	गजलावाट	7	8	00	0	00	15
(6)	कपराइली (रतन पुर)	25	25	00	4	00	54
(7)	गोयावाट	35	125	20	3	00	183
(8)	मन्डोडी	30	124	26	7	00	187
(9)	भर्याडिया	7	30	00	3	00	40
(10)	बिजली	10	50	00	0	1	61

शिक्षा के प्रति गांव के लोगों की रुचि आमतौर पर कम है। ये बच्चा की पढ़ाई में रुचि नहीं दिखाते और उनके बच्चे घर के काम काज में लगे रहते हैं। यही कारण है कि उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों की संख्या अत्यंत कम है। आश्रम की धोर से एक विद्यालय चलता है, जहां आस-पड़ोस के गांवों के विद्यार्थियों के लिये स्वावलम्बी शिक्षा की व्यवस्था है। इस 'जीवनशाला'¹¹ नाम दिया गया है। यहां कम उम्र के बच्चे आते हैं और उन्हें सामान्य शिक्षा के साथ-साथ कृषि तकनीकी तथा अन्य जीवनोपयोगी विषयों का शिक्षण दिया जाता है। यहां से निकले हुए विद्यार्थी घर पर जाकर अच्छी खेती करते हैं और गांव की तकनीकी आवश्यकता को भी पूर्ति करते हैं। आश्रम की 'जीवनशाला' शिक्षा के क्षेत्र में एक आक्षेपक प्रयोग है जहां स्वावलम्बी शिक्षण की प्रेरणा मिलती है।

लोकप्रदालत और ग्राम पंचायत

लोकप्रदालत और ग्राम पंचायत के बीच तनाव देखने में नहीं आया। ग्रामदानी गांव और ग्राम पंचायतों के बीच भी तनाव की स्थिति नहीं है। सैद्धांतिक दृष्टि से ग्रामदान का विचार व्यापक है और इसमें स्वशासन की भावना निहित है। इस कारण ग्रामदानी गांव के विवाद ग्राम पंचायत में न जाने की स्थिति में किसी प्रकार के तनाव की बात नहीं होती। इसी प्रकार सामान्य गांवों से भी जब विवाद ग्राम पंचायत में न जाकर लोकप्रदालत में जाता है तो तनाव की संभावना नहीं रहती क्योंकि लोकप्रदालत में विवाद स्वच्छा से धारा जाता है। लोकप्रदालत, ग्रामदानी गांव और ग्राम पंचायत के बीच सद्भाव रखने वाले निम्न तत्त्व देखने में आये

- (1) कुशल नेतृत्व—श्री हरिबल्लभ परीव के नेतृत्व के कारण उक्त समस्याओं में सद्भाव कायम रहता है।
- (2) लक्ष्य की एकता—लोकप्रदालत ग्राम पंचायत या ग्रामदानी गांवों की समस्याओं, इन सबके लक्ष्यों में विरोधाभास नहीं है। हां, उनमें सैद्धांतिक एवं कार्य पक्ष में कभी हो सकती है।
- (3) जैसा ऊपर कहा गया है लोकप्रदालत या ग्रामदानी गांवों की ग्राम सभाओं और ग्राम सभाओं (ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत) के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती बल्कि उनके साथ सहयोगात्मक सम्बंध रखने का प्रयास करती है।

सारांश

- (क) लोकअदालत गावों में रहने वाले विभिन्न जातियों के लोगों की एक सूत्र में आबद्ध करने के लिए प्रयत्नशील रही है। आदिवासियों एवं गर आदिवासियों—सभी को लोकअदालत में जाने एवं वहाँ के अनुभवा से एकता की सीख मिलती है। गावों के लोग यह महसूस करने लगे हैं कि ग्राम एकता कायम करने में लोकअदालत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
- (ख) विवादों को सुलझाने में जातीय पंचायत की परम्परागत बुराइयों को कम करने में लोकअदालत का प्रभाव उल्लेखनीय है। बातचीत के दौरान प्रायः सभी गावों के लोगो ने स्वीकार किया कि उद्दे अंधविश्वास, भूत प्रेत एवं अंध गलत परम्पराओं को समाप्त करने की प्रेरणा लोकअदालत से मिली है और अब भी बराबर मिल रही है।
- (ग) जातीय विवाद व्यवस्था का कार्य क्षेत्र सीमित था और कोट में जाने की प्रवृत्ति में वृद्धि होने के कारण जातीय पंचायत का महत्व उत्तरोत्तर कम होता जा रहा था। लोकअदालत ने इस विचार को मजबूत किया है कि स्थानीय स्तर पर विवादों को सुलझाना अधिक लाभकर है। यही कारण है कि गावों के लोग जातीय सीमा से हटकर लोकअदालत एवं ग्राम सभाओं के माध्यम से विवादों को सुलझाने का प्रयास करने लगे हैं।
- (घ) गजलावाट रंगपुर जाम्बा आदि गावों के लोग इस बात का विशेष प्रयास करते पाये गये कि आसपास के गावों के लोग भी अपने विवाद लोकअदालत के माध्यम से सुलझाएँ तो उनके लिए ज्यादा हितकर होगा। ऐसे अनेक उदाहरण मिले हैं जिनमें गजलावाट, रंगपुर जाम्बा आदि गाव के लोगो ने पास के गाव के लोगो के विवाद को सुलझाने में अपनी ओर से हर सम्भव मदद की² और जो विवाद वे नहीं सुलझा सके उन्हें लोकअदालत के सहयोग से सुलझाने का प्रयास किया।
- (च) ग्रामवासियों को महाजनो पुलिस या अन्य सरकारी कर्मचारियों एवं बड़े किसानों आदि के शोषण एवं अत्याचार का मुकाबला करने की प्रेरणा लोकअदालत से मिलती है और उन्हें अपनी संगठन शक्ति का भान करने का अवसर मिला है।³

सदभ

- 1 देखें 'स्वप्न हुए साकार प० स० 79, सोसायटी फार डेवलपिंग ग्रामदान नई दिल्ली—1972 ।
- 2 देखें श्री हरिबल्लभ परीख क्रान्ति का मरुणोदय, सब सेवा सघ प्रकाशन वाराणसी 1973 ।
- 3 देखें श्री हरिबल्लभ परीख की उक्त पुस्तक एवं प्रस्तुत अध्ययन का परिशिष्ट ।

लोकअदालत का संगठन

संगठन

लोकअदालत का विकास क्रमशः हुआ है इस कारण इसके संगठनात्मक स्वरूप को बने बनाय ढांचे में बिठाना सम्भव नहीं है। लोकअदालत के प्रारम्भकर्ता एवं उसमें लगे लोगो ने भी उसके संगठनात्मक स्वरूप पर कम ध्यान दिया है। प्रारम्भ में तो यह पूर्णतया विश्वास पर आधारित मौखिक याचक व्यवस्था थी और संगठन के नाम पर प्रायः कुछ भी नहीं था। जातीय पक्षपात से भिन्न होने के कारण इसमें जातीय पक्षपात जैसी परम्परागत व्यवस्था का भी अभाव था। प्रारम्भ में श्री हरिबल्लभ परीय स्वयं ही सारा काम देखते थे एवं संगठन उन तक ही सीमित था। अतः संगठन के बारे में विस्तार से कुछ कहना अभी भी सम्भव नहीं हो पा रहा है। फिर भी अध्ययन के दौरान जो तथ्य सामने आये हैं उन पर हम इस अध्याय में विचार करना चाहेंगे।

लोकअदालत के संगठन के सम्बन्ध में कालक्रम के अनुसार विचार करना उपयोगी होगा क्योंकि संगठन में स्पष्टता एवं मजबूती भी उसी के अनुसार देखने में आती है। लोकअदालत के संगठन को इस क्रम में देख सकते हैं —

1. घल लोकअदालत (Mobile Lok Adalat)
2. केन्द्रीय लोकअदालत का विकास
3. लोकअदालत का मौजूदा संगठन

जैसा कि ऊपर बताया गया है इसके संगठनात्मक स्वरूप के बारे में निश्चित ढांचा प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है और इस बारे में जानकारी का भी अभाव रहा है इसलिए इसके संगठनात्मक पक्ष पर विचार करते समय प्रत्येक अंग पर उसके तीन मुद्दों को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे

1 संगठन का रूप एवं पदाधिकारी

2 कार्य एवं अधिकार क्षेत्र

(1) प्रारम्भिक संगठन—चल लोकप्रदालत (Mobile Lok Adalat)

लोकप्रदालत की प्रारम्भिक अवस्था में संगठन का खास स्वरूप नहीं था। सन 1950 में 55 तक यह कार्य व्यक्तिगत स्तर पर होता रहा। इस में लोकप्रदालत का कार्य अथवा कार्यों से जुड़ा हुआ था। जसा कि पहले उल्लेख कर चुके हैं श्री हरिवल्लभ परीख इस क्षेत्र में गांधीवादी विचार के अनुसार समाज सेवा के काम में लगे हुए थे और प्रारम्भिक दिना में ही उनके सामने मुख्य सवाल यहाँ के विवादों को सुलझाने का आ गया था। उन दिना गांव गांव में व्यक्तिगत और पारिवारिक विवादों के साथ महाजन, पुलिस एवं अथवा कर्मचारियों के सम्बन्धित विवाद भी उनके सामने आते थे। क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने एवं उनमें पारस्परिक सौहार्द पदा करने की दृष्टि से उन विवादों को सुलझाना जरूरी था। उपरोक्त अवधि में व्यक्तिगत एवं सामूहिक पदयात्राओं का कार्यक्रम व्यापक रूप से चला जिससे सम्पर्क एवं कार्य की भूमिका बनी। जहाँ जो विवाद उनके सामने स्वभावतः आये वे उन्हें सुलझाने का प्रयास करने लगे और यही प्रयास धीरे-धीरे लोकप्रदालत की प्रारम्भिक भूमिका के रूप में मूल्यमान हा गये। इस प्रारम्भिक अवस्था के संगठन का केन्द्र बिन्दु व्यक्ति ही था।

उस समय विवाद सुलझाने में जो प्रक्रिया अपनायी जाती थी उसकी दो भागों में बाँट सकते हैं —

(क) श्री हरिवल्लभ परीख द्वारा विवाद सुलझाने की स्थिति में संगठन।

(ख) आश्रम के अथवा व्यक्तियों द्वारा पदयात्रा के दौरान विवाद सुलझाने में संगठनात्मक स्वरूप।

जिस गांव में श्री हरिवल्लभ परीख मौजूद रहते थे, वहाँ लोकप्रदालत के संगठन के केन्द्र बिन्दु वे स्वयं होते थे। इस प्रकार की चल लोकप्रदालत (Mobile Lok Adalat) में उन्हें एक गांव में एक से अधिक दिनो तक भी रुकना पड़ता था। समय विवाद की संख्या एवं प्रकृति (number and nature of cases) पर निर्भर करता था। इनकी उपस्थिति में संगठनात्मक स्वरूप, संगठनात्मक रूप, स्वरूप, स्वरूप था—(क) प्रारम्भिक

(रा) पंच (ग) उपस्थित समुदाय । विवाद प्रस्तुतकर्ता एवं दूसरा पक्ष अपनी बात रखता और अन्त्य श्री हरिजननम परीग इन बार में पूरी जानकारी प्राप्त करत । पंच की नियुक्ति भी उतनी व्यग्रस्थित रूप से नहीं होती थी जितनी आज होती है । सामान्यतः गाव के प्रमुख लोग पंच का काम कर देते थे और पंच भी राय पर अग्र्यक्ष विवाद सुलझा देत थे । उपस्थित जन समुदाय की राय भी ली जाती थी तबिन कुन मिनाजर स्थिति यह थी कि अग्र्यक्ष साक्षात् काम स्वयं की जिम्मेदारी पर करके विवादप्रस्त पक्षों में समझौता करा देता था । उस समय विवादों का किसी प्रकार का विवरण नहीं रखा जाता था और न यह मभव ही था । यही कारण है कि उन स्थिति के निर्णित किये गये विवादों की प्रामाणिक जानकारी प्राप्त नहीं है ।

आश्रम के अध्यक्ष व्यक्ति जब गावा में जात थे तो वे भी विवादों को सुलझाने का प्रयास करत थे । उनकी नीति भी विवाद सुलझाने में समझौते का मार्ग अपनाने तक ही सीमित रहती थी । सगठनात्मक दृष्टि से थोड़ी भिन्नता यह रहती थी कि यहाँ अग्र्यक्ष उतना प्रभाव नहीं होता था जितना पहली स्थिति में होता था । यहाँ गाव के प्रमुख को इस काम में पहल करने का प्रयास करना पड़ता था और आश्रम के कार्यकर्ता इस काम में मदद करत थे । यहाँ यह स्वीकार करना चाहिये कि इन स्थिति में सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया अधिक मजबूत थी । ऐसे विवादों में उस समय नहीं सुलझ पात थे, उन पर विचार करने के लिये आश्रम में निश्चित तारीख को उन्हें सुलझाने का प्रयास किया जाता था और तब अग्र्यक्ष की भूमिका पुनः उतनी ही प्रभावी एवं महत्वपूर्ण बन जाती थी ।

लोकप्रदालत के प्रारम्भिक सगठनात्मक स्वरूप की प्रमुख बातों के बारे में कह सकते हैं कि (क) इस अवस्था में सगठन व्यक्ति-प्रधान था । (ख) परम्परागत जातीय पक्ष को खास महत्व प्राप्त था । (ग) सामूहिक निर्णय पर जोर दिया जाता था । (घ) विवाद सम्बन्धी लिखित विवरण का अभाव था । (ङ) अनिर्णित विवाद सुलझाने के लिये आश्रम में बैठकें होती थी ।

(2) सगठन का विकास

धूम धूमकर विवादों का सुलझाने का यह क्रम चलता रहा और विवादों की संख्या को देखते हुए यह एक व्यापक कार्य हो गया । प्रारम्भ से ही इस बात पर बल दिया जाता रहा कि ऐसी शक्ति विकसित हो जिसके आश्रम पर गाव के विवाद गाव में ही सुलझाये जाय । जब आश्रम के कार्य का विस्तार हुआ और काम का ढाँचा भी बदला तो विवादों को सुलझाने के लिए

प्राथम्य में आने वाली की संख्या भी बढ़ने लगी। स्वभावतः लोकप्रदालत की बैठकें गावों के स्थान पर आथम्य में होने लगीं। इस दौरान सत्त पद-यात्रा का क्रम भी कम हुआ। इन दिनों लोकप्रदालत सम्बन्धी व्यवस्था में एक प्रमुख परिवर्तन और भी हुआ और वह यह कि पडोस के लोग अपने विवाद आथम्य में लाने लगे और विवादों की संख्या बढ़ने के कारण यह आवश्यक हो गया कि लोकप्रदालत के काम को थोड़ा बहुत व्यवस्थित किया जाय। सन् 1955 से 65 की अवधि में लोकप्रदालत का केन्द्र मजबूत हुआ और सगठनात्मक स्वरूप भी थोड़ा निखरा। लेकिन फिर भी सगठन को किसी बने बनाय ढांचे में नहीं बांधा गया, बल्कि इसका खुला रूप ही कायम रहा। लोग विवाद लाते और अध्यक्ष द्वारा उन विवादों के बारे में प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त करके उन्हें लोकप्रदालत की प्रगली बैठक की तारीख बता दी जाती एवं निश्चित तारीख को विवाद सुलझाने का प्रयास किया जाता। इस संदर्भ वर्ष में सगठनात्मक स्वरूप इस प्रकार से रहा

- (क) अध्यक्ष विवादों की प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त करके बैठक की तारीख बताता था।
- (ख) विवाद सम्बन्धी सामान्य जानकारी नोट कर ली जाती थी। यह काम आश्रम का कोई कार्यकर्ता या अध्यक्ष स्वयं करता था।
- (ग) विवाद की सुनवाई के समय प्रमुख भूमिका अध्यक्ष की होती थी। वह स्वयं दोनों पक्षों की बात सुनता था और उपस्थित लोगों की राय जानकर निर्णय देता था तथा ग्रामतों पर उस निर्णय को स्वीकार कर लिया जाता था।
- (घ) विवाद को गांव के लोग स्वयं सुलझाये इस दिशा में प्रयास सन् 1960 के आस पास ही आरम्भ किया गया और सक्रिय एवं ग्राम दानी गांवों में ग्राम सभाओं की स्थापना की गयी। हर ग्राम सभा का एक अध्यक्ष होता था जो ग्रामस्तर पर लोकअदालत की बैठक बुलाता, विवादों का सुलझाने के लिये पक्षों की नियुक्ति की जाती एवं पक्षों की राय से ग्राम सभा द्वारा विवाद सुलझाने का प्रयास किया जाता था।

इस अवधि में लोकअदालत की स्थिति यह रही —

केन्द्रीय लोकअदालत का संगठन मजबूत हुआ—

(क) विवादो की जानकारी मक्षेप म रये जाने की प्रक्रिया का प्रारम्भ हुआ ।

(ख) अध्यक्ष का प्रभात अधिक मजबूत हुआ ।

(ग) ग्रामस्तर पर लोकअदालत का नाम फैलना प्रारम्भ हुआ ।

(3) मौजूदा मगठन

इस समय लोकअदालत का दो स्तर का मगठनीत्मक स्वरूप है

केन्द्रीय लोकअनालत और

ग्राम लोकअनालत

केन्द्रीय लोकअदालत

केन्द्रीय लोकअदालत म निम्नलिखित मय है

(क) अध्यक्ष—केन्द्रीय लोकअदालत के स्थायी अध्यक्ष श्री हरिवल्लभ परीक्ष है । प्राय सभी बैठका म वे उपस्थित रहत हैं । लोकअदालत की बैठका म इनके नेतृत्व का प्रभाव दला जा सकता है । अध्यक्ष को व्यापक अधिकार प्राप्त है । उनका यह प्रयास रहता है कि लोकअदालत का काम स्थानीय लाग स्वय करें और यही कारण है कि वे अपने आप को माग दशन तक ही सीमित रखन का प्रयास करत हैं । फिर भी निणय प्रक्रिया मे इनकी भूमिका प्रमुख रहती है ।¹ अध्यक्ष को निम्न काम करत दला गया

(अ) विवादो को स्पष्ट करना ।

(आ) सत्य जानकारी प्राप्त करने म सक्रिय रूप मे मदद करना ।

(इ) निणय के समय आयी गुथिया सुलभाना ।

(ई) करार खत तयार करना ।

(उ) मय आवश्यक मागदान करना ।

इसके अतिरिक्त विवाद की प्रारम्भिक कामवाही म भी अध्यक्ष मदद करता है । ग्रामस्तर पर विवाद के रजिस्ट्रेशन के समय वह स्वय विवाद की सामा य जानकारी प्राप्त करता है ।

(ख) मंत्री—लोकअदालत का एक मंत्री होता है । यह मंत्री आश्रम का स्थायी कामकर्ता होता है । अभी तक जो व्यक्ति मंत्री के रूप मे कार्य करत रहे हैं वे आश्रम के स्थानीय कामकर्ता नहीं हैं । वे गैर आदिवासी भी हैं । इस प्रकार अध्यक्ष एवं मंत्री दोनों गैर आदिवासी रहे है परंतु यहां के

लोगो का इन पर पूरा विश्वास देखा गया है।

मन्त्री आमतौर पर निम्नलिखित कार्य करता है —

- (अ) विवाद का रजिस्ट्रेशन।
- (आ) विवाद की सामान्य जानकारी प्राप्त कर उसे लिखना।
- (इ) पत्र व्यवहार।
- (ई) लोकप्रदालत के कार्यालय को देखना।
- (उ) बैठक के समय विवाद को प्रस्तुत करना तथा काय में अध्यक्ष की मदद करना।

इसके अतिरिक्त मन्त्री अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकप्रदालत की अन्य काय चाहो भी देखता है। जैसा कि डा० उपेन्द्र बक्षी ने कहा है, 'अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वह लोकप्रदालत में आये कुछ विवादों को सुलझाता है'। लेकिन हम यहां यह भी कहना चाहेंगे कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकप्रदालत के काम में लोग कठिनाई महसूस करते हैं।

मन्त्री आश्रम का कायक्ता होने के कारण उसका आर्थिक भार आश्रम पर हाता है। कार्यालय सम्बन्धी अन्य खर्च भी आश्रम वहन करता है। लोकप्रदालत में किसी प्रकार की फीस नहीं है। संगठन एवं व्यवस्था सम्बन्धी सभी गन्ध आश्रम ही उठाता है।

(ग) जूरी — विवाद का सुलझाने में जूरी की भूमिका प्रमुख है। जूरी की व्यवस्था 1966 से प्रारम्भ हुई। इस व्यवस्था के विकास के पीछे मूल भावना यह रही कि स्थानीय लोग स्वयं इस काम का करें ताकि इससे काय में स्थायित्व आये। वर्तमान व्यवस्था में प्रत्येक विवाद के लिये अलग अलग जूरी नियुक्त किये जाते हैं। दोनों पक्षों की ओर से जूरी के लिये नाम मांगे जाते हैं और सभा की राय से अध्यक्ष द्वारा जूरी की नियुक्ति की जाती है।

जूरी का मुख्य काय विवाद के विविध पक्षों पर विचार करके निणय देना है। जूरी की संख्या आमतौर पर चार—दोनों पक्षों से दो-दो होती है। जूरी सभा से अलग जाकर दोनों पक्षों की बात सुनते हैं और पारस्परिक विचार विमर्श करके अपना निणय देते हैं। विवाद सुलझाने के बाद करारखत पर जूरी के हस्ताक्षर होते हैं। करारखत पर उनके अतिरिक्त दोनों पक्षों एवं अध्यक्ष के भी हस्ताक्षर होते हैं। जूरी की नतिक जिम्मेदारी यह भी दबो गयी कि वह इस बात का भी प्रयास करें कि दोनों पक्ष केवल निणय को

स्वीकार ही नहीं करें बल्कि उस पर अमल भी करें।

जुरी को किसी प्रकार का आनरेरियम नहीं दिया जाता। यह पद पूणतया आनरेरी है। जुरी की योग्यता के बारे में कोई ठोस नियम नहीं है पर वह स्वस्थ मन एवं मस्तिष्क रखने वाला जिम्मेदार नागरिक हो। इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाता है।

कार्यालय में उपलब्ध रजिस्ट्रो एवं फाइल आदि से जो जानकारी, आवेदों एवं सामग्री प्राप्त हो सके, उसका आधार पर यह कहना चाहेंगे कि पहले विवाद सम्बन्धी नाम मात्र की जानकारी रखी जाती थी। यह नहीं कहा जा सकता कि अब भी कार्यालय पूणतः व्यवस्थित है और सभी धिवरण पर्याप्त मात्रा में एवं सत्तापजनक ढंग से रखे जाते हैं। कार्यालय पर तो इतना कमजोर देखने में आया कि निम्न विवादों के पूरे करारखत भी प्राप्त नहीं हो सके। पिछले चार वर्षों के उपलब्ध करारखतों की स्थिति नीचे की तालिका में देव सकते हैं

तालिका मर्या-14

विवाद की सुनवाई एवं करारखत की स्थिति

वर्ष	लोकप्रदासत की बैठकों की संख्या	सुनवाई हेतु प्रस्तुत विवाद (संख्या)	प्राप्त करारखत (संख्या)	प्राप्त करार खतों का प्रतिशत
1972	13	577	33	5—72
1973*	15	574	21	3—66
1974	17	340	39	11—47
1975 (नवम्बर तक)	15	324	57	17—59

* करारखतों की पूरी फाइल नहीं प्राप्त हो सकी।

उपरोक्त तालिका के आधार पर यह तो कह सकते हैं कि पहले से अधिक संख्या में करारखत रखे जाते हैं और लोकप्रदासत की बैठकों की संख्या के बारे में भी जानकारी मिलती है। लेकिन जो विवाद निगयाय प्रस्तुत किये गये और जिनके करारखत मौजूद हैं उनमें काफी फर्क है। इस फर्क के बारे में निम्न बातें सामने आयी

(क) कार्यालय व्यवस्थित न होने के कारण पूरे करारखत नहीं रखे जा सके।

वई विवादा के निर्णय लिखित रूप म न किये जाकर मौखिक रूप से ही दे दिय गये । जैम पति-पत्नी के बीच मतभेद के मामला मे दोना पक्ष की सहमति हो जाने पर निणय मे लेने ँने सम्ब धी खास बात न होने पर दोना पक्ष गुड वितरण के बाद भागे से प्रेम पूवक रहने की प्रतिज्ञा करके घर चले जात पाये गये । इस प्रकार के सामा य विवादो के निणय के करारखत नही रखे गय । इसी प्रकार लेन देन सम्ब धी सामा य विवाद भी मौखिक रूप स ही सुलझा दिये गये उनके कोई विवरण उपलब्ध नही हुए ।

(ख) यह भी दखन म आया कि विवाद लोकप्रदात म पजीकृत कराया गया परंतु एक पक्ष के नही उपस्थित होने या अ य कारणो स उसका निर्णय लोकप्रदात म न होकर ग्राम स्तर पर या आपसी समझौत द्वारा हा गया । इस स्थिति म भी करारखत नही रखा जाता । इही कारणो स करारखता की सत्पा काफी कम है । करारखत की उक्न परिस्थिति के कारण जानकारी-प्राप्ति की यह कठिनाई भी आयी कि इससे यह स्पष्ट नही हो सका कि लोक-प्रदात की बैठक म प्रस्तुत विवादा म से वास्तव म कितन विवादा का निणय हुमा । स 1971 की फाइल मे यह स्पष्ट जिक्र है कि इस बप कुल 17 बैठकें हुइ जिसमे 98 विवादा का निणय हुमा पर तु उक्त फाइल ॥ भी केवल 35 करारखत मौजूद मिल । गैप निणयो के करारखत नही प्राप्त हो सक ।

(ग) उक्त तथ्यो के आधार पर हम यह कहना चाहये कि लोकप्रदात के संगठन पक्ष को अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि विवाद एव उमके निणय सम्ब धी पूरी जानकारी उपलब्ध रह सके ।

(घ) सभा—लोकप्रदात की बैठक के समय उपस्थित जन समुदाय सभा का रूप ग्रहण कर लत है । यह खुली सभा है इस कारण सभा म उपस्थिति के लिय किसी प्रकार का बंधन नही है । सभा का हर मदम्य निणय म मदद करने का अधिकार रखता है और सभा म उपस्थित सदस्या में ॥ ही जूरी भी नियुक्त होत है ।

(च) बागजात—लोकप्रदात बागालय में नीचे निम्न विवरण रखा जाता है —

(अ) रजिस्ट्रेशन रजिस्टर

(आ) विवाद विवरण फाइल

(इ) करारखत फाइल

- (ई) पत्र व्यवहार फाइल
- (उ) रजिस्ट्रेशन फाइल
- (ऊ) प्रतिवादी के लिये निमंत्रण पत्र

ग्राम लोकअदालत

(क) लोकअदालत के काम को स्थायित्व देने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि उसे ग्राम स्तर पर विकसित किया जाय और हर गाँव में 'स्पनिश' की क्षमता का विकास हो। लोकअदालत किसी प्रकार का प्रतिद्वन्द्वी संगठन नहीं है।

ग्रामस्तर पर लोकअदालत के संगठनारम्भ स्वरूप का विकास अभी प्रारम्भिक स्थिति में देखने का मिलता है। इस संगठन में भी एक अध्यक्ष होता है जो ग्राम लोकअदालत की बैठक की अध्यक्षता करता है। ग्रामस्तर पर ग्राम का प्रमुख व्यक्ति जो ग्रामसभा का भी अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष होता है और वह विवादों को सुलझाने में हर सम्भव मदद करता है।

(ख) मंत्री—ग्रामसभा का मंत्री ग्राम लोकअदालत का काम देखता है। विवाद से संबंधित कागजात रखने की जिम्मेदारी उसकी होती है।

(ग) पंच—विवाद को सुलझाने के लिये उसी प्रकार पंच नियुक्ति की व्यवस्था होती है जमी कि केन्द्रीय लोकअदालत में है। कई ग्राम सभाओं में स्थायी पंचों की भी व्यवस्था है जो विवाद सुलझाने में मदद करते हैं। पंचों का काम विवाद के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके निणय देना एवं उसकी पूर्ति का प्रयास करना होता है।

(घ) सभा—गाँव के सभी बालिग स्त्री पुरुष ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम स्तर की सभा प्रायः वे ही काम करती है जो कि केन्द्रीय लोकअदालत की सभा करती है।

विवाद का केन्द्रीय लोकअदालत में भेजा जाना

यदि ग्राम लोकअदालत में विवाद नहीं सुलझ पाता तो (अ) ग्राम लोकअदालत अपनी ओर से विवाद को केन्द्रीय लोकअदालत में भेज देता है या (आ) वादी प्रतिवादी में से कोई एक या दोनों ही स्वयं विवाद को केन्द्रीय लोकअदालत में ले जाते हैं।

सारांश

- (क) केन्द्रीय लोकन्यायालय आनन्द निवेदन आश्रम में चलती है।
- (ख) केन्द्रीय लोकन्यायालय का प्रमुख अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष सामान्यतया मार्गदर्शन का काम करता है और विवाद सुलझाने में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। सत्य तब पहुँचने एवं गुप्तियों को सुलझाने में भी इसकी प्रमुख भूमिका रहती है।
- (ग) एक मंत्री होता है जो अध्यक्ष की मदद करता है। मंत्री कार्यालय को सभालने के साथ-साथ विवाद सम्बन्धी जानकारी भी रखता है।
- (घ) विवादों को सुलझाने के लिये प्रत्येक विवाद के लिये जूरी की नियुक्ति होती है। वादी प्रतिवादी द्वारा दिये गये नामों में से चार व्यक्तियों को अध्यक्ष सभा की सहमति से जूरी नियुक्त करता है। जूरी दोनों पक्षाओं की राय से विवाद सुलझाने का प्रयास करता है एवं अपना निर्णय देता है। सभा में उपस्थित कोई भी सतुलित मानस का व्यक्ति जूरी के रूप में काम कर सकता है।
- (च) लोकन्यायालय में काम करने वाले सभी व्यक्ति आनन्देरी रूप में काम करते हैं। अध्यक्ष एवं मंत्री का आर्थिक सबब आश्रम से रहता है।
- (छ) ग्राम लोकन्यायालय का विकास करके लोकन्यायालय के कार्य को स्थायित्व देने एवं उसे विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्राम लोकन्यायालय में अध्यक्ष, मंत्री एवं पंचगण इस काम को सभालते हैं। कार्यपद्धति केन्द्रीय लोकन्यायालय से मिलनी जुलती है।
- (ज) लोकन्यायालय के संगठन का कोई बना बनाया ढाँचा नहीं है। इसका विकास समय हुआ है और इस प्रकार इसमें परम्परा का प्रमुख स्थान है।
- (झ) लोकन्यायालय का सभी स्थायित्व प्राप्त हो सकता है जब कि उसका मर्यादात्मक ढाँचा मजबूत हो। मौजूदा संगठनात्मक ढाँचे का देखते हुए यह स्थिति देखने में आती कि संगठन में एक व्यक्ति के नेतृत्व का प्रभुत्व है। इस बात की पुष्टि साक्षात्कार के दौरान भी हुई। ग्रामस्तर पर सुलझाये जाने वाले विवादों की सत्यापन के देपने पर भी यह बात प्रगट होती है हालाँकि उत्तरदाताओं ने यह सभावना व्यक्त की है कि मौजूदा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में भी लोकन्यायालय सफलतापूर्वक चल सकेगी, परंतु यह सभावना ही है—वस्तुस्थिति

नही। इन बातों पर विचार करने पर सगठनात्मक पक्ष पर एक व्यक्ति के नृत्त्व के कारण इसके सस्यात्मक स्वरूप के विकास में कमी देने को मिलती है। यह कमी इसके सगठनात्मक स्थायित्व के बारे में भी शका को जन्म देती है।

संदर्भ

1. दण्ड निगम प्रणिया का अध्याय।
2. डा० उपेन्द्र कर्मा सीव भदास एट रमपुर ए प्रिन्सिपलरी स्टडी — 1974।

लोक अदालत की कार्य पद्धति

प्राचीन समाज में विवाद सीमित थे और विवादों का फैसला ग्रामतौर पर ग्रामन्तर पर होता था। लेकिन आज विवादों का दायरा काफी व्यापक हो गया है और उनके समाधान के लिये नए कानूनों की सहायता भी बहुत अधिक हो गई है। कानून और विवाद की इस गुंथी को सुलझाना ग्राम आदमी के बस की बात नहीं है। इसके लिये वकील व्यवस्था का प्रारम्भ और विस्तार हुआ है और मौजूदा 'याय' व्यवस्था में विवाद को सुलझाने में वकीलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोकअदालत में स्थिति बिल्कुल भिन्न है। यहाँ प्रत्यक्ष विचार-विनिमय और सरल निर्णय-प्रक्रिया होने के कारण मध्यस्थ की भूमिका नगण्य होती है।

सामान्यतया व्यक्ति इस बात का प्रयास करता है कि विवाद न हो। विवाद हो ही नहीं यह उत्तम स्थिति है, परन्तु यदि वह हो जाय तो श्रेयस्कर यही है कि विवाद इस प्रकार सुलझाया जाय कि विवादग्रस्त पक्षों के पारस्परिक सम्बन्ध में वह स्थिति बनी रह जाय जैसी विवाद न होने या प्रारम्भ होने की स्थिति में थी। लोकअदालत विवाद सुलझाने में ऐसी प्रक्रिया अपनाने का प्रयास करती है जिससे पारस्परिक सम्बन्धों में तनाव की स्थिति न रहे और सम्बन्ध सुधर जायें।

वर्तमान 'यायालय' कानूनों दृष्टि से 'याय' देता है परन्तु लोकअदालत न्याय का सामाजिक पक्ष भी प्रस्तुत करती है। 'याय'लय का कार्य मात्र दोषी व्यक्ति का दोष सिद्ध करना एवं उसे दंड देना ही नहीं होना चाहिये बल्कि उसके साथ दो बातें और भी जुड़ी हैं (क) वह आगे इस प्रकार का कार्य न करे एवं उसका सुधार हो और (ख) पारस्परिक सम्बन्धों में सुधार हो क्योंकि विवाद का प्रभाव स्व (self) के साथ साथ समाज (society)

पर भी पड़ता है और इस प्रकार विवाद से सामाजिक परिवेश भी प्रभावित होता है। इसलिए 'याय' प्राप्ति के बाद विवाद का प्रभाव दोनों स्तर पर समाप्त हो सके, इसका लोक अदालत की वाय पद्धति में विशेष महत्व है। इन बातों को मूर्त रूप देने की 'याय' प्रक्रिया की गोज करने का प्रयास लोक अदालत करती है।

विवाद होने के क्रम में अनेक रीयतियाँ होती हैं। कोई भी विवाद यकायक नहीं होता बल्कि उसके पीछे लम्बे समय से चला आ रहा मतभेद होता है। हम ग्रामतौर पर देखते हैं कि विवाद का प्रारम्भ छोटी छोटी बातों को लेकर होता है और समय आता है जब विवाद को 'यायालय' में प्रस्तुत करना पड़ता है। जैसे महाजन सम्बन्धी विवाद का प्रारम्भ गलत हिसाब या लेन देन में भेरे होने या इन्कार करने से होता है। पारिवारिक एवं विवाह सम्बन्धी विवाद का प्रारम्भ तो अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर ही होता है। लोकअदालत के अवलोकन से इस बात की पुष्टि हुई कि पारिवारिक विवादों का प्रारम्भ पति पत्नी के बीच मारपीट, भोजन न देना, मसुगल न घा पाना, धीन सम्बन्ध में विषमता आदि से होना पाया गया है और यह सब एकाएक न होकर धीरे धीरे होता है। पारिवारिक विवाद मामा-यतया दो से चार वर्षों में इस स्थिति में पहुँचता पाया गया कि वह अदालत में जाय। कौन सा विवाद कितने समय में अदालत में जाता है, यह पारिवारिक सम्बन्ध एवं सहिष्णुता पर निर्भर करता है।¹

लोकअदालत में आने की प्रेरणा

किसी व्यक्ति को लोकअदालत में आने की प्रेरणा क्यों होती है इस सम्बन्ध में सर्वेक्षित गाँवों से आये विवादों के बारे में जानकारी प्राप्त करन लोगों से बातचीत एवं लोकअदालत की बैठक का अवलोकन करने के बाद निम्न तथ्य सामने आये हैं

- (क) स्वयं की जानकारी—इस क्षेत्र के करीब एक सौ गाँवों में लोक-अदालत का प्रभाव है। इन गाँवों के बहुसंख्यक निवासियों को ग्रामतौर पर यह जानकारी है कि लोकअदालत में विवादों को सुलझाया जाता है और यही जानकारी लोगों को लोकअदालत में आने की प्रेरणा देती है।
- (ख) जानकारी के साथ विश्वास जुड़ने से लोकअदालत में आने की प्रेरणा मजबूत होती है। जिन लोगों का लोकअदालत के नेतृत्व एवं 'याय' देने की क्षमता में विश्वास है, वे सहज ही विवादों को

मुलभूत के लिये यहाँ आता है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लोकन्यायालय की जानकारी तो है परन्तु जो विश्वास की वृद्धि के कारण यहाँ आने से कतराते हैं। ऐसे उदाहरण भी देखने में आये हैं कि लोग न जानकारी हान हुए भी लोकन्यायालय में आने में देरी की ओर विवाद को बढ़ाते रहे। यह स्थिति विवाह एवं पारिवारिक विवादों में अधिक पायी गई है। विश्वास का प्रश्न एक आम बात से भी जुड़ा हुआ है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आया है कि एक पक्ष लोकन्यायालय में नहीं आना चाहता या आने में देर करता है। आमतौर पर लोग लोकन्यायालय में आने से इंकार नहीं करते पर निष्पक्ष नहीं हैं। ऐसा करने के पीछे सत्य से बचने का प्रयास करने की भावना जुड़ी होती है। कुल मिलाकर जानकारी एवं विवेकायुक्त के कारण लोग लोकन्यायालय में विवाद लाते हैं।

- (ग) किसी के द्वारा जानकारी दिया जाना—जिन लोगों को लोकन्यायालय की जानकारी नहीं है व किसी व्यक्ति द्वारा जानकारी देने पर यहाँ आते हैं। इस प्रकार की जानकारी देने वालों में मुख्य ये हैं —
- (i) नात रिश्ते के लोग जिनका विवाद लोकन्यायालय में मुलभूत होता है।
- (ii) ऐसे लोग जिन्होंने लोकन्यायालय की बैठक में भाग लिया हो या उसके अधिवेशन देखे हों।
- (iii) लोकन्यायालय के कार्यकर्त्ताओं द्वारा जिनका क्षेत्र की जनता से अधिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों के कारण निकट का सम्पर्क है।
- (iv) कभी कभी महत्व के प्रश्न मुलभूत से भी लोकन्यायालय सम्बन्धी जानकारी का विस्तार होता है, यथा—किसी गाँव के भूमि सम्बन्धी मामलों के निपटारे में सरकारी अधिकारियों के पूर्व निष्पक्ष को बदलने के प्रयास आदि।

सर्वेक्षण के दौरान एक से अधिक विवाद ऐसे भी देखने में आये जिनमें विवाद प्रस्तुतकर्त्ताओं को लोकन्यायालय के बारे में पहले से जानकारी नहीं थी और किसी अन्य की सलाह पर वे यहाँ आये। ऐसे लोग आमतौर पर दूर होते हैं। सर्वेक्षण के दौरान गुजरात एवं मध्य प्रदेश की सीमा के ऐसे गाँवों से भी ऐसे लोग आते पाये गये जो लोकन्यायालय केन्द्रों की करीब पचास

भील दूर पड़ते थे। एक पक्ष के आन पर दूसरे पक्ष को बुलाने में थोड़ा अधिक प्रयास तो करना ही पड़ता है। इस प्रकार लोकन्यायन का कार्य क्षेत्र भी नमस्त व्यापक होता जाता है।

(घ) ग्रामसभा द्वारा भेजा जाना—लोकन्यायालय के सघन क्षेत्र में ग्राम सभाया द्वारा अनिर्णीत विवाद लोकन्यायालय में भेजे जान की प्रवृत्ति रही है। जिन गावा की ग्रामसभायें सक्रिय है वहा विवाद पहले ग्रामसभा के पास जाता है और ग्रामसभा उसे सुलझाने का प्रयास करती है। लेकिन ग्रामसभा में विवाद न सुलझने पर या ग्रामसभा द्वारा यह महसूस किया जाने पर कि विवाद को के द्रीय लोकन्यायालय में भेजना ठीक रहेगा उसे लोकन्यायालय के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाता है।

(ङ) ग्रामदानी गावों द्वारा गैर ग्रामदानी गावों की समस्या में हिलचल्यी ली जाती है और कई बार उन्होंने गैर ग्रामदानी गावा के निवासियों को अपनी समस्यायें लोकन्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने एवं उसके माध्यम से उन्हें हल कराने की प्रेरणा दी।

निर्णय प्रक्रिया

लोकन्यायालय में आये विवादों की कार्यवाही एवं निर्णय प्रक्रिया की अनेक स्थितिया होती हैं। विवाद के लोकन्यायालय में आने एवं निर्णय होने के बीच होने वाली प्रक्रिया को प्रो० उपेन्द्र बक्षी ने तीन मुख्य भागों में विभाजित किया है

- (क) विवाद सुलझाने की दृष्टि से की जाने वाली प्रारम्भिक कार्यवाही।
- (ख) ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से विवाद को अच्छी तरह समझा जा सके और उसकी गहराई में जाया जा सके।
- (ग) निर्णय प्रक्रिया जिसके द्वारा याय प्राप्त होता है।

चूँकि लोकन्यायालय की कार्य पद्धति का विकास स्वाभाविक रूप से और क्रमिक ढंग से हुआ है, इसलिए इसमें तन्नीकी कमिया हा सकती हैं। यह स्वीकार करना चाहिये कि यहा मौजूदा यायपद्धति की निर्णय प्रक्रिया का अनुकरण नहीं किया जाता। यहा की निर्णय प्रक्रिया अपने ढंग की है और इस अपने ढंग का विकास स्वभावतः अनुभव तथा आवश्यकता के आधार पर हुआ है। इसमें कोई बने बनाये नियमों या सिद्धांतों का उपयोग नहीं

किया गया है। लोकप्रदालत के अध्ययन के बाद हम यह कहना चाहेंगे कि नियम के समय मोटे तौर पर नीचे लिखी बातों का ध्यान में रखा जाता है और नियम की प्रक्रिया भी इसी बातों के आधार पर विकसित हुई है

- (क) लोकप्रदालत में विवाद के प्रवेश (रजिस्ट्रेशन) में सरलता रहे और विवाद प्रस्तुतकर्ता का रजिस्ट्रेशन में कम से कम उलझाव हो।
- (ख) विवाद निपटान में स्थानीय लोगों का प्रमुख स्थान रहे।
- (ग) निर्णय प्रक्रिया सरल हो।
- (घ) किसी पक्ष का किसी प्रकार का भय न हो।
- (ङ) विनियम आर्थिक या अन्य विवादग्रस्त पक्षों पर न पड़े।
- (च) तथ्यों के आधार पर जाय दिया जाय और नियम देने में तत्परता बरती जाये।

लोकप्रदालत की बैठकों का अवलोकन करने से इसकी निर्णय पद्धति की जानकारी मिलती है। लोकप्रदालत की प्रक्रिया का नीचे लिखी स्थितियों (stages) में दस मंच हैं।

(1) विवाद का प्रस्तुतीकरण एवं पंजीयन

सामान्यतया विवाद प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति लोकप्रदालत के मंत्री (secretary) से विवाद के बारे में खर्चा करता है लेकिन यदि अभ्यक्ष उपस्थित होते हैं, तो वे स्वयं विवाद को सुनते हैं। अभ्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकप्रदालत का मंत्री विवाद को सुनकर उसका रजिस्ट्रेशन कर लेता है। विवाद के रजिस्ट्रेशन में नीचे लिखी जानकारी रजिस्टर में नोट की जाती है

- (अ) दिनांक।
- (आ) बादी का नाम एवं गांव।
- (इ) प्रतिवादी का नाम एवं गांव।
- (ई) विवाद का प्रकार।
- (उ) अन्य विनियम नोट।

प्रस्तुत विवाद का रजिस्टर में नाट करने की व्यवस्था पहले नहीं थी। प्रारम्भिक जानकारी एवं स्थान पर मिल जाय, इस दृष्टि से उपरोक्त जानकारी

कारो 1970 स रखी जान लगी है लकिन अभी भी यह व्यवस्था व्यवस्थित नही मानी जा सक्ती । रजिस्ट्रेशन की कायवाही को दस्त हुए यह कहना चाहने कि काय नोकरशाही के ढग का न हा कर आपसी मदभाव के रूप म होता है । इस बात की पुष्टि यहां के काम का ढग देखकर की जा सक्ती है । उदाहरण के लिए विवाद कभी भी प्रस्तुत किया जा सक्ता है और कई बार रात्रि मे भी विवाद का रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है । जिस समय विवाद प्रस्तुत हाता है, प्राय रजिस्ट्रेशन का काम भी उसी समय हाता है ।

विवाद का पजीयन (रजिस्ट्रेशन) सुनवाई के क्रम की प्रथम कायवाही है । इसके करीब 15 से 30 दिनों के बीच लोकअदालत की बठक म विवाद की सुनवाई प्राय हो जाती है । प्रथम सुनवाई म लगभग इतना समय तो लगता ही है । यदि एक पक्ष बिही कारणों से उपस्थित न हो सका तो उसके लिये दूसरी तारीख दी जाती है । यदि लोक अदालत की अगली बैठक की तारीख निश्चित नही होती तो विवाद प्रस्तुतकर्ता को तारीख लेने के लिए पुन खुला लिया जाता है और उसी तारीख पर उपस्थित होने के लिए प्रतिवादी को आमत्रण पत्र भेज दिया जाता है । इस बात की जानकारी भी प्राप्त की जाती है कि दूसरा पक्ष क्या नही उपस्थित हुआ । यह प्रयास किया जाता है कि अगली बैठक मे दोनों पक्ष उपस्थित हो । इन काय मे सम्बंधित गाव के लोग मदद करन है ।

(2) सुनवाई की सूचना

विवाद का पजीयन होने के बाद उसकी सुनवाई की प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है । यदि उस समय लोक अदालत की बैठक की तारीख निश्चित हो गयी रहती है तो सुनवाई की तारीख निश्चित कर दी जाती है । विवाद प्रस्तुत करन वाले को नीचे लिखे नमूने का पजीयन पत्रक दिया जाता है

‘ लोकअदालत ’

आनंद निवेदन आश्रम,
पो० रंगपुर (कवाट)
जिला बडोदा

तारीख

केस नम्बर

वादी

प्रतिवादी

सुनवाई की तारीख

दिन

(3) सुनवाई की प्रक्रिया

विवाद की सुनवाई के समय काफी सख्या में लोग उपस्थित होते हैं। सुनवाई के समय ग्रामतौर पर ग्रामस्थ के सदस्य भी उपस्थित होते हैं। उपस्थिति कई बातों पर निर्भर रहती है। सामान्यतया नीचे लिखी बातों के अनुसार बैठक में उपस्थिति की सख्या निर्भर करती है।

- (क) उस दिन की बैठक में सुनवाई होने वाले विवादों की सख्या। जिस दिन विवादों की अधिक सख्या होती है उस दिन उपस्थिति अधिक होना स्वाभाविक है।
- (ख) विवाद का प्रकार—एक गांव के बीच, कई गांवों से सम्बंधित, पुलिस या अन्य कमचारियों से सम्बंध विवाद आदि होने पर अधिक उपस्थिति रहती है।
- (ग) विवाद की प्रकृति—जमीन सम्बंधी, बज के लन-पेन, विवाह एवं परिवार सम्बंधी तलाक भूत प्रेत मारपीट आदि।
- (घ) साक्षियों की सख्या।
- (ङ) विवाद से सम्बंध पक्ष के लोगों का ग्रामस्थ से दूर या समीप होना।
- (च) विवाद में रुचि की स्थिति।
- (छ) ग्रामस्थ में उपस्थिति—देश के या विदेशी मित्रों का उपस्थित रहना।

विवादों के अध्ययन के दौरान विभिन्न विवादों के निणय के समय जो उपस्थित रही उसकी जानकारी नीचे की तालिका से प्राप्त हो सकती है।

तालिका सख्या-15

निणय के समय उपस्थिति

क्र०	निणय के समय उपस्थिति	विवाद सख्या	प्रतिशत
(1)	50 त 100	20	25
(2)	101 से 150	37	46—25
(3)	151 से 200	14	17—50
(4)	200 से अधिक	9	11—25
योग		80	100—00

ग्रामतौर पर सौ व्यक्तियों की उपस्थिति देखी जा सकती है।

सुनवाई की कार्यवाही आमनीर पर दापहर म दा बजे प्रारम्भ होनी है । पास के गावा के साग भाजन करके आत हैं जबकि दूर गावा के लोग भोजन साथ में लाते हैं । सभी लोग आश्रम के मध्य स्थित महुषा के वृक्ष के नीचे बन चरुतर पर बैठन हैं ।

विवाद की सुनवाई की एक परम्परा यह भी देखने में आयी कि किसी भी बैठक में पहल उन विवादों का हाथ में लिया जाता है जो पिछली बैठक में अधूरे रह गये थे । सुनवाई के समय यह भी ध्यान रखा जाता है कि दूर गाव से आने वाले विवादों पर पहल विचार हा जाय ताकि वहाँ के लोग आमानी में अपने गाव उसी दिन वापस जा सकें । इन मामलों सुविधा का ध्यान रखा जाना बह सबन हैं ।

वादी-प्रतिवादी का नाम पुकारने पर दोनों पक्ष आगे आकर आमन-मामने बैठत हैं । आमनीर पर अध्यक्ष विवाद के बारे में प्रश्न पूछना प्रारम्भ करता है । प्रश्नोत्तर काल में विवाद के सभी पक्षों पर खुलकर विचार विमर्श होता है । उपस्थित व्यक्तियों का भी प्रश्न पूछने का अधिकार है । इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है, कि एक पक्ष अपनी पूरी बात कह ले, तभी दूसरा पक्ष अपनी बात कह । बीच में दूसरे पक्ष का हस्तक्षेप टाला जाता है ।

इस प्रकार के प्रश्नोत्तर में सभी प्रकार के तथ्य सामने आ जाते हैं । सुनवाई के दौरान नीचे लिखी बातें देखने में आयी ।

- (क) व्यापक प्रश्नोत्तर के दौरान उपस्थित लोगों को गलती का अंदाज लग जाता है ।
- (ख) दोषी व्यक्ति अपना दोष जनसमूह के सामने नहीं छिपा पाता है ।
- (ग) विवाद के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है ।
- (घ) दोषी व्यक्ति द्वारा अपना दोष स्वीकार किय जाने की मन स्थिति का निर्माण हा जाता है ।

इस प्रकार की सामूहिक सुनवाई की प्रक्रिया परम्परागत 'याय व्यवस्था' में एक नया प्रयोग है । परम्परागत 'याय व्यवस्था' में ग्राम मुखिया के स्थान पर महत्व को देखते हुए सामूहिक सुनवाई (collective hearing) का स्थान नाम मात्र का ही रहता था । डा० उपेन्द्र बन्शी³ न भी स्वीकार किया है कि लोक अदालत में तुलनात्मक दृष्टि से सामूहिक सुनवाई अधिक व्यवस्थित ढंग से होती है ।

(4) विवाद की चर्चा को समेटना

प्रस्तुत विवाद के सम्बन्ध में दोनों पक्षों का पूरी बात सुनने एवं उपस्थित समुदाय की राय जानने के बाद लोक अदालत के अध्यक्ष प्रस्तुत विवाद का समेटत है। वे दोनों पक्षों की बातों को संक्षेप में अभिव्यक्त करते हैं और उपस्थित लोगों का मतभेद भी जान लेते हैं। अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य मान विवाद को स्पष्ट करना ही नहीं है बल्कि इससे विवाद को एक दिशा भी मिलती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत अध्यक्ष विवाद के विभिन्न मुद्दों के सन्दर्भ में सामाजिक एवं व्यक्तिगत व्यवहार की कमियाँ को दूर करने की बात भी बताते रहते हैं। जैसे यदि तलाक़ का विवाद है तो उसकी सामाजिक अच्छाईयों और बुराईयों को स्पष्ट किया जाता है। साथ ही साथ उसमें कानूनी पक्ष की भी जानकारी दे दी जाती है।

(5) पक्षकारों की नियुक्ति

इसके बाद अ पक्ष के निर्देश से विवाद के बारे में निर्णय देने के लिए दोनों पक्षों की ओर से दो दो प्रतिनिधियों के नाम सुझाये जाते हैं। प्रतिनिधियों की नामजदगी में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि (1) वे प्रत्यक्ष रूप से विवाद से सम्बद्ध न हों। (2) किसी पक्ष के रिश्तेदार न हों। उपस्थित व्यक्तियों में से कोई भी पक्षकार ज़ूरी के रूप में चुना जा सकता है। सामान्यतया आश्रम का कार्यकर्ता एवं बाहर के दशक पक्षकार नहीं बनते हैं।

विवाद को सुलझाने के लिये पक्षकारों की नियुक्ति परम्परागत पाप व्यवस्था के सन्दर्भ में नहीं चीज है। उपस्थित जन समुदाय में से कोई भी व्यक्ति (उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए) पक्षकार बन सकता है यह इस पाप व्यवस्था की मुख्य बात है। यह एक व्यक्ति के स्थान पर सामूहिक पाप पद्धति का स्वीकार करने की दिशा में प्रयास है। श्री हरिवल्लभ परीस का यह मानना है कि लोक अदालत व्यक्तिपरक न रहे। इसी बात को ध्यान में रखकर 1966 से पक्षकारों की नियुक्ति की जाने लगी। पक्षकारों की नियुक्ति में उन सामान्य बातों का भी ख्याल रखा जाता है जो विवाद को समझने के लिये आवश्यक होती है जैसे पक्षकार सामान्यतया बुद्धियुक्त हों, समझदार हों वगैरह आदि आदि।

(6) पक्षकारों को पंच के रूप में घोषित किया जाना

दोनों पक्षों के पक्षकार अध्यक्ष के सामने उपस्थित होते हैं। अध्यक्ष यह घोषणा करता है कि ये पक्षकार अब पंच के रूप में विवाद के बारे में निर्णय

देंगे। उह यह भी बताया जाता है कि अब व (पक्षकार) किसी पक्ष से सम्बन्धित न होकर पक्ष परमेश्वर की भूमिका में विवाद पर विचार करेंगे। अब वे लोकप्रदालत में सम्बद्ध हैं और प्रदालत उनसे यह अपेक्षा रखती है कि वे निष्पक्ष होकर कार्य करेंगे। इस प्रकार के निर्देश के माध्यम से वह एक नए रूप में कार्य करने को कहा जाता है। अब उन्हें (पक्षकारों को) पक्ष या जुरी के नाम से सम्बोधित किया जाता है। अलग अलग विवादों के लिये अलग-अलग पक्ष नियुक्त किये जाते हैं।

निर्णय की पक्ष प्रक्रिया लोकप्रदालत की नियम प्रक्रिया का आसान बनाती है। यहाँ एक बात यह सामने आती है कि दोनों पक्षों द्वारा पक्षकारों का चयन पक्षों में नतिवृत्ता की अपेक्षा का बड़ा देता है। यह पक्षकार अपने पक्ष द्वारा मनानीत होते हैं, इस कारण पूर्ण तटस्थता की बठिनाई यदा बदा सामने आ सकती है। परन्तु यह बात दाना पक्षों पर ही लागू होती है। सामान्यतः पक्षगण विचार विमर्श से ऐसे निष्कर्ष पर ही पहुँचते हैं जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। यह सही है कि ऐसे अवसर भी आते हैं जब पक्ष अपनी उचित भूमिका नहीं निभा पाता और उससे नियम में बठिनाई आ जाती है। एक विवाद की सुनवाई के समय हमने स्वयं देखा कि एक पक्ष अपने को निष्पक्ष न रख सका और एकपक्षीय निर्णय लिये जान के लिए अड़न लग गया। इस स्थिति में पक्षों द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा सका और विवाद पुनः प्रदालत के सम्मुख आ गया। पक्षों की बात प्रदालत में सुनी। बातचीत के दौरान यह सिद्ध हो गया कि वह पक्ष एक पक्षीय बात कह रहा है। उस समय सभा में करीब 200 व्यक्ति उपस्थित थे। उस पक्ष की एक पक्षीय बात का सभा ने अस्वीकार किया और महत्वपूर्ण बात तो यह रही कि उक्त पक्ष ने भी अपनी भूल स्वीकार कर ली और कह दिया कि उसने पक्ष की भूमिका उचित ढंग से नहीं निभाई है और इसलिए उसे पक्ष के दायित्व से अलग कर दिया जाये। इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्णय प्रक्रिया में निष्पक्ष रह कर निर्णय देना लोकप्रदालत की एक विशेषता है।

(7) पक्ष निर्णय की घोषणा

पक्षों द्वारा विचार विमर्श के बाद, उनके निर्णय की जानकारी सभा को दी जाती है। आमतौर पर पक्ष निर्णय सर्वानुमति से किया जाता है। यदि पक्ष किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पाता और मतभेद बना रहता है तो उस मतभेद की जानकारी सभा को दे दी जाती है। इस स्थिति में प्रायः तीन बातें होती पायीं गयीं (1) निर्णय को अगली बैठक के लिये रोक दिया गया। (2) सभा के साथ विचार विमर्श कर निर्णय पर पहुँचा गया।

(3) अध्यक्ष के ऊपर निर्णय का भार सौंपा गया।

जिस समय एक विवाद पर पंच निर्णय की प्रक्रिया चलती है, उस समय दूसरे विवाद की अन्य प्रारम्भिक प्रक्रियाएँ भी चलती रहती हैं। इस प्रकार एक समय में एक से अधिक विवादों की निणय प्रक्रिया चलती रहती है।

पंच निणय में कितना समय लगता है इसकी सही जानकारी देना संभव नहीं है। हमने यह पाया कि एक विवाद पर विचार करने में पंचों को प्रायः आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक का समय लग जाता है।

पंच निणय में मत स्वातंत्र्य की बात साफ़तौर पर देखने में आयी। हर व्यक्ति अपनी बात को खूबकर रखता है। सभी पंच अपनी बात निर्भीकता से प्रस्तुत करते पाये गये। इस स्थिति में निणय पर पहुँचने के लिए यदा कदा पहल करने की भी आवश्यकता होती है। सामान्यतया ऐसे अवसरों पर भाई सभी की बातों को सुनते हैं एवं निणय पर पहुँचने में मदद करते हैं। इस परिस्थिति का देखते हुए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो प्रभावशाली हो और आवश्यकता पड़ने पर सामूहिक निर्णय प्रक्रिया को सही दिशा प्रदान करता रहे।

किसी भी विवाद का समाधान खोजते समय पंचों की दृष्टि तथ्या एवं मामले की वास्तविकता पर केन्द्रित रहती है। सामुदायिक निर्णय प्रक्रिया से स्वभावतः ही विवाद की असलियत सामने आ जाती है और इसलिए विवाद का निणय तथ्यात्मक (rational) आधार पर किया जाता है किसी भावनात्मक आधार पर नहीं।

तथ्या का पता लगाने में निम्न प्रक्रियाएँ सहायक होती हैं

- (क) सम्बंधित पक्षों द्वारा अपने पक्ष समर्थन के लिये प्रस्तुत तथ्य।
- (ख) प्रश्नोत्तर द्वारा तथ्यों की खोज का प्रयास।
- (ग) सभा में उपस्थित लोगों की निजी जानकारी।
- (घ) वादी प्रतिवादी के समक्षों से प्राप्त जानकारी।
- (ङ) यदा कदा तथ्य प्राप्त करने के लिये अपनाये गये भावनात्मक उपाय—यथा गपथ दिलाकर तथ्यों की जानकारी हासिल करना आदि।

लोक अदालत में निणय में निम्न मानदंडों का ध्यान रखा जाता है

- (क) नैतिकता का रक्षण एवं पोषण।
- (ख) राज्य के कानूनों का अवलम्बन एवं अनुपालन।

(६) विवाद म सम्बन्धित पक्षा की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति की दृष्टिगत गम्त हुए दण्ड या जुर्मान का निर्धारण ।

(8) निणय की पुष्टि

पच निणय के बाद गभा की निर्णय की जानकारी दी जाती है । विवाद म निणय का जानकारी सभा को दन व बाद गभा । इसकी पुष्टि भी करा सी जाती है । सभा स पूछा जाता है कि क्या पचा के निणय मे आप सब सन्तुष्ट हैं ? यदि आवश्यकता हाती है तो अध्यक्ष द्वारा निणय का स्पष्टी करण भी किया जाता है । जंगा कि ऊपर कहा गया है सभा स विचार विमग इस निर्णय प्रक्रिया का प्रमुख अंग है ।

निर्णय की स्वीकृति की अंतिम रूप दन के लिय महात्मा गांधी की जय ' का उदघाप किया जाता है ।

(9) करारखत का लेखाबद्ध किया जाना एवं उस पर हस्ताक्षर

निर्णय को लिखित रूप देन के लिय करारखत तैयार किया जाता है । करारखत मे निर्णय का लिखित रूप प्रदान करन के साथ जिस पक्ष को दोषी पाया जाता है उनका भी संक्षेप म उल्लेख किया जाता है । इसमे निणय दंड, समझौता आदि का उल्लेख भी होता है । कई विवादों म तो करारखत एवं प्रचार के समझौता पत्र के रूप म रहता है । जस तलाव सम्बन्धी विवादो म यदि आपसी मेलजोल हो गया या किसी प्रकार का दंड नहीं दिया गया और दोनो ने भविष्य म प्रेम से रहन का निणय किया तो ऐसे विवाद म करारखत म समझौता की शर्तें भी लिखी जाती है ।

इस करारखत पर वादी प्रतिवादी दोनो के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान होता है । इसके अतिरिक्त पचो एवं अध्यक्ष के हस्ताक्षर भी होत है ।

(10) गुड-वितरण

करारखत लिखा जान के बाद विवाद के निणय की अंतिम प्रक्रिया गुड वितरण की होती है । सभा म उपस्थित सभी व्यक्तियों को गुड वितरित किया जाता है । गुड वितरण स निर्णय की पुष्टि अंतिम रूप स होती है । गुड की रकम आमतौर पर दोनो पक्षा द्वारा बराबर दी जाती है ।

गुड की रकम कितनी होगी, यह कई बातों पर निर्भर हाता है जैसे व्यक्ति की सामर्थ्य विवाद की स्थिति दण्ड की मात्रा आदि । गुड का वितरण कौन करेगा, इसका भी कोई निश्चित नियम नहीं है । आश्रम का सदस्य या कोई भी अ य व्यक्ति गुड वितरण करता हुआ पाया गया ।

गुड वितरण प्रतीकात्मक क्रिया है। सामूदायिक व्यवस्था में इस प्रकार की परम्परा का खास महत्व होता है। समस्या का समाधान होने पर पूरा समाज खुशी व्यक्त करता है और इस उपलक्ष में मुह मोठा करना एक अच्छी परम्परा है। परम्परागत आदिवासी समाज में इसी परम्परा का एक रूप शराब पीना पाया जाता है। आदिवासी समाज में, खासकर भीलो में विवाह के निपटारे के बाद शराब पीने की परम्परा का जितना प्रोटी की नायक ने भी किया है। उनके अनुसार भील समाज में मुखिया द्वारा शराब पीने पिलाने के बाद यह घोषणा की जाती है कि अब किसी प्रकार का झगडा शेष नहीं रहा है और भविष्य में आप झगडा नहीं करेंगे और भिन्न के रूप में रहेंगे।¹⁴ लोक अदालत ने गुड वितरण की परम्परा विकसित करके पुरानी परम्परा को शुद्ध बनाया है। इसमें पुरानी परम्परा में शुद्धता आने के माध्यम निर्णय की स्वीकृति की भावना स्थापित रहती है। गुड वितरण के प्रश्न पर किसी प्रकार का मतभेद देखने में नहीं आया। गुजरात में पूरा शराब बंदी होने तथा आश्रम द्वारा शराबबंदी के पक्ष में जातिवरण बनाने के कारण शराब के स्थान पर गुड वितरण की परम्परा का स्वागत भी किया गया है।¹⁵

लोक अदालत तुलनात्मक दृष्टि से कम खर्चीली है। गुड वितरण का नाममात्र का खर्च प्रायः सभी विवादों में होता है। गुड के अतिरिक्त जो अन्य खर्च होता है उसका विवरण देना संभव नहीं है और एक दृष्टि से यह ठीक भी है क्योंकि इसके अतिरिक्त विवाद पर प्रायः अन्य प्रकार का नुकसान व्यय होता नहीं पाया गया। नजदीक के गाँव के सभी लोग भोजन करने आते हैं या शाम का घर जाकर भोजन कर लेते हैं। पास पड़ोस के लोग पैदल ही आते जाते हैं। अतः यहाँ के लोगों की दृष्टि में लोक अदालत में कोई खर्च नहीं होता है।

कुछ विवादों में दण्ड अवश्य दिया जाता है। दण्ड की मात्रा लोक अदालत के निर्णय के दौरान निश्चित की जाती है। विभिन्न प्रकार के विवादों में दण्ड की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। तलाक सम्बन्धी विवादों में धाम तोर पर किसी एक पक्ष को ही दण्ड देते हुए पाया गया। इसी प्रकार मारपीट, जेन देन सम्बन्धी विवादों में भी एक ही पक्ष को दण्ड देते हुए पाया गया।

,विभिन्न विवादों में दिये गए दण्ड एवं गुड वितरण में हुए खर्च के तथ्यात्मक आकड़े निम्न प्रकार हैं

तालिका सख्या-16

लोकप्रदात मे सच एव दण्ड

सह्या-४०

क्र०	गुट्ट पर खच (रुपये में)	संख्या	वादी प्रतिवादी दण्ड की मात्रा (रुपये में)					योग से अधिक
			51 100	101 150	151 200	201 250	300	
(1)	1 स 10	48	1	3	00	2	6	12
(2)	11 से 20	13						
(3)	21 से 30	14						
(4)	31 स 40	00						
(5)	41 स 50	3						

कुल सर्वोदित 80 वादी प्रतिवादिया में से केवल 12 वादी प्रतिवादियों को ही दण्ड दिया गया है। तीन सौ से अधिक रुपये के दण्ड वाले विवादों की संख्या अधिक है। उक्त अंका का देखने से यह बात स्पष्ट होती है कि उन विवादों की संख्या कम है जिनमें दण्ड दिया गया है। आमतौर पर समझौता किया जाता है। इससे यह भी साफ होता है कि लोकप्रदात अधिक अधिक दण्ड दिये जाने के पक्ष में भी नहीं है। ऐसा एक भी उदाहरण देखने में नहीं आया जिसमें शारीरिक दण्ड दिया गया हो। गुड वितरण पर हुमा खर्च भी कम है। सामान्यतया अधिकतर मामलों में 5 से 15 रुपये तक का खर्च होता पाया गया। दो विवाद ऐसे भी पाये गये जिसमें गुड वितरण नहीं किया गया। ये विवाद प्रारम्भिक वर्षों के थे।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लोक अदालत की कार्य पद्धति वैधानिक न्यायालया की कार्य पद्धति की तुलना में अपेक्षाकृत कम खर्चीली, सहज एवं सरल प्रतीत होती है। यदि वैधानिक न्यायालया की कार्य पद्धति में भी उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कुछ सुधार किये जा सकें तो जन साधारण को शीघ्र एवं सस्ता न्याय प्राप्त करने में सहूलियत हो सकती है।

सारंश

(1) 'याय प्राप्ति' की प्रक्रिया इस प्रकार की हो जिसमें विवाद से सम्बद्ध

में आयीं। लोकन्यायालय का संस्थात्मक ढांचा मजबूत न होने के कारण दूर गांव के लोग का विवाद सुलझाने के लिए केन्द्रीय लोक-न्यायालय में आना पड़ता है क्योंकि ग्राम स्तर पर इसका संगठन अभी भी कमजोर है। यही कारण है कि कभी-कभी लोकन्यायालय की बैठक की तारीख प्राप्त करने में बाड़ी प्रतिवादी को कठिनाई होती है। यह कठिनाई अध्यक्ष की व्यस्तता के कारण भी हो सकती है। यह स्थिति एक व्यक्ति के लोकन्यायालय पर अधिक प्रभाव के कारण भी उत्पन्न हुई मानी जा सकती है।

(4) लोकन्यायालय की प्रक्रिया में अध्यक्ष, मंत्री पंच एवं सभा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उक्त संगठनात्मक इकाइयों द्वारा 'राय काय' किया जाता है। अध्यक्ष इस बात का प्रयास करता है कि निर्णय पंच द्वारा सभा की सहमति से किया जाय। पंचों को इस बात की छूट रहती है कि वे भी खुलकर अपनी राय व्यक्त करें। अभिव्यक्ति की इस स्वतंत्रता का प्रभाव यह भी पड़ता देखा गया कि यदाकदा विवाद के निर्णय में कठिनाई होती है और मामले की सुनवाई अगली बैठक के लिए स्थगित हो जाती है। यह भी देखने में आया कि कई बार पंचों की राय में काफी भिन्नता रही या कभी-कभी पंच तटस्थता की भूमिका का निर्वाह न कर सके।

(5) सामान्यतः पर कार्य-पद्धति में दो प्रकार की कमियाँ और देखने में आयीं (1) संगठनात्मक, (2) प्रक्रियात्मक। संगठन में अध्यक्ष के प्रभाव एवं महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इसकी छाय इकाइयाँ (मंत्री पंच सभा) की भूमिका कभी-कभी गाय हो जाती है। यह प्रश्न लोक-न्यायालय के संस्थात्मक स्वरूप से भी जुड़ा हुआ है जो इसके स्थायित्व के प्रति शका प्रकट करता है। प्रक्रिया सम्बन्धी कमियों में मुख्य बात सामुदायिक निर्णय की प्रक्रिया के स्पष्ट चित्र का अभाव है। अभी तक लोकन्यायालय वह स्वरूप विकसित नहीं कर पायी है जिससे सामुदायिक निर्णय की प्रक्रिया सहज में चल सके। पंचों को एक राय होने की कठिनाई व्यक्तिगत स्वार्थ से मुक्ति सभा द्वारा विवाद के बारे में सीधे निर्णय पर पहुँचने की कठिनाई आदि भी यदा कदा सामने आती रहती है।

सदभ

- 1 श्री हरिवल्लभ परीख ने साथ चर्चा व आचार पर ।
- 2 प्रो० उपेन्द्र बख्शी एव डा० एल०एम० सिपवी सोन अदालत एट रणपुर ए प्रीतिमिनरी स्टडी दिल्ली विश्वविद्याय दिल्ली 1974 ।
- 3 The element of public participation in the traditional system of informal dispute handling was thus comparatively minimal Dr Upendra Baxi (*ibid*) page 20, Delhi University, Delhi 1974
- 4 देखें टी०बी० नायक उपरोक्त पृष्ठ 230 ।
- 5 The drinking ceremony follows the headman's address
Now you need not quarrel any further You will now
drink together and from now you are friends

निर्णय की पूर्ति

पूर्ति की समस्या

लोक अदालत की निणय प्रक्रिया पूरी होने के बाद निणय की पूर्ति का प्रश्न आता है। जैसा कि हमने देखा है लोकअदालत में स्वेच्छा से निणय स्वीकार किया जाता है। इस कारण निणय की पूर्ति में खास कठिनाई नहीं आती। सामान्यतया लोग निणय के बाद इस पर अमल करते ही हैं। हा, कई कारणों से एक मानवीय गुण-दोष सीमा को स्वीकार करते हुए निर्णय की पूर्ति में यदाकदा कठिनाइयाँ भी आ जाती हैं।

साक्षात्कार के दौरान लोकअदालत के निणय के बाद उसकी पूर्ति की दृष्टि ॥ कुछ बातें इस रूप में देखने में आयी—

- (1) किसी विवाद में दोनों पक्षों की पूर्ण सतुष्टि न होने पर या किसी एक पक्ष के मन में शका रहने पर निर्णय की पूर्ति में कठिनाई आती है।
- (2) कई ऐसे विवाद होते हैं जो व्यक्ति के स्वभाव, पारिवारिक राग द्वेष एवं स्वाध से प्रेरित होते हैं जैसे, प्रेम सम्बंध, तलाक की उलझी हुई परिस्थिति आदि। इस स्थिति में निणय होने पर भी दोनों पक्षों का मन साफ नहीं हो पाता है।
- (3) एक पक्ष का मन बलने या किसी के बहकावे में आकर सरकारी न्यायालय में जाने के कारण भी निणय की पूर्ति नहीं हो पाती है।
- (4) ऐसे मौके भी देखने में आये जिनमें निणय की पूर्ति के लिये कुछ समय दिया जाता है। इस दौरान पैसा न जुटा पाने या मशा बदल जाने पर भी निणय पूर्ति में बाधा आती है।

उपरोक्त परिस्थितियों में लोकअदालत के सम्मुख निणय की पूर्ति की

समस्या आती है। लोकन्यायालय के पास दण्ड शक्ति का अभाव है। इस कारण उसका निर्णय पूर्ति का तरीका भिन्न है। सरकारी न्यायालयों के निर्णय की पूर्ति में पुलिस मददगार होती है और निर्णय पूर्ति (यदि भागे अपील नहीं की तो) में कोर्ट के आदेश का प्रमुख स्थान होता है। इस आदेश के पालन में पुलिस के सहयोग से याचार्जीशमन स्वयं भी निर्णय की पूर्ति के लिए निर्णय न मानने वाले को जेल भेज देते हैं अथवा उसकी सम्पत्ति नीलाम करने की आज्ञा जारी कर देते हैं जबकि लोकन्यायालय के पास ऐसी कोई शक्ति एवं व्यवस्था नहीं है। साथ ही लोकन्यायालय इस प्रकार की व्यवस्था में विश्वास भी नहीं रखती।

लोकन्यायालय में विभिन्न प्रकार के विवादों में जा निणय दिये हैं उन्हें समेट कर देखें तो स्थिति अधिक साफ होगी। विभिन्न विवादों में जिस प्रकार के निर्णय दिये गये, उन्हें संक्षेप में नीचे लिखे रूप में विभाजित कर सकते हैं

- (क) नकद दण्ड दिया जाना।
- (ख) लेन देन के मामलों में हिसाब को समझ कर उसे स्पष्ट करना और जो भी लेना देना हो, उसकी पूर्ति कराना।
- (ग) जमीन के प्रश्न पर जमीन वापस दिलाना और इस मद में यदि कोई लेन देन जुड़ा हुआ हो तो उसकी पूर्ति करना।
- (घ) तलाक सम्बन्धी ऐसे विवादों में जिनमें किसी के पूर्व सम्बन्ध पहले से कायम हुये पाये जायें, पुनर्विवाह की औपचारिक रस्म पूरी किये जाने की अनुमति।
- (ङ) तलाक सम्बन्धी विवाद में तलाक दिलाना।
- (च) पारिवारिक कलह में समझौता एवं प्रेम का वातावरण कायम करने का प्रयास करना।
- (छ) ऐसे निर्णय जिनमें स्थायी नुस्खान की पूर्ति की व्यवस्था की गई हो। जैसे शारीरिक क्षति के एक विवाद में इस प्रकार निर्णय की पूर्ति होती पायी गयी कि दोषी व्यक्ति द्वारा उस समय तक पीड़ित परिवार की खेती की व्यवस्था की जायेगी जब तक कि पीड़ित व्यक्ति का लड़का खेती करने लायक न हो जाय।

पूर्ति की प्रक्रिया

निर्णय के उद्देश्य प्रकारी की पूर्ति मामा यतया स्वेच्छा से होती पायी गयी। यह बात भी देखने में आयी कि वादी प्रतिवादी दाना ही प्रायः निर्णय की पूर्ति के लिये तत्पर रहते हैं। विवाह तलाक़ पारिवारिक कलह आदि के मामला में तो निर्णय की पूर्ति तुरंत भी होती पायी गयी। प्रत्यक्ष प्रवक्तृव्य एवं माध्यात्मिक व दोरान प्राप्त जानकारी के आधार पर निर्णय की पूर्ति की नीचे लिखी स्थितियाँ देखने में आयी

- (1) नकद दण्ड की स्थिति में दंडित व्यक्ति उम्मी समय अपने पास से दण्ड की रकम का भुगतान कर देता है।
- (2) कुछ लोग उम्मी समय किसी मध्य व्यक्ति से लेकर भी दण्ड की राशि का भुगतान कर देते हैं।
- (3) कई निर्णयों में करारगत में दण्ड देने की तारीख नियत कर दी जाती है और उस तारीख तक वह दण्ड की रकम दे देता है। नकद दण्ड न दिया जान पर भय जा भी निर्देश दिया गये हों उनकी पूर्ति कर देता है।
- (4) करारवता में इस बात का उल्लेख भी पाया गया है कि निर्णय की पूर्ति न होने पर आगे क्या बायबाई होगी या कितना अतिरिक्त दण्ड दिया जायगा।
- (5) ऐसे विवादों की संख्या अधिक है जिनमें समझौते के रूप में निर्णय दिया गया है। समझौता प्रदान विवादों में तलाक़ वैवाहिक उलझनों पारिवारिक कलह आदि मुख्य हैं। व्यक्तिगत वाद विवाद या मामा य मारपीट सम्बन्धी झगड़े भी इसी श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार के विवादों से सम्बन्धित निर्णय की पूर्ति तत्काल होती पायी गयी यथा—
 - (क) तलाक़ की घोषणा एवं सम्बन्ध विच्छेद की बात दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार कर अलग हो जाना। महिला आमतौर पर अपने परिवार द्वारा लिया गया कड़ा खोल कर पिता के घर चली जाती है।
 - (ख) यदि किसी से प्रेम सम्बन्ध है और तैयारी है तो तलाक़ के साथ साथ विवाह की रकम भी पूरी कर दी जाती है।
 - (ग) पारिवारिक कलह एवं यय विवादों में इस घोषणा के साथ

निणय की पूर्ति मान ली जाती है कि "अब दोनों पक्ष प्रेम से रहेंगे।"

निणय से सन्तुष्टि

निणय की पूर्ति के साथ इस बात पर विचार करना भी उपयोगी होगा कि विवाद से संकटो पक्षों को निणय से किस सीमा तक सन्तुष्टि हुई है। वादी प्रतिवादी से साक्षात्कार के दौरान जा तथ्य सामने आये हैं उसके आधार पर निणय से सन्तुष्टि एवं विवाद की मौजूदा स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है —

तालिका सरया-17

निणय से सन्तुष्टि एवं विवादों की मौजूदा स्थिति

क्र०	विवाद की मौजूदा स्थिति	सतोप की स्थिति			योग	
		पूर्ण सतोप	सामान्य सतोप	कम सतोप		
				उत्तर न देने वाले		
1	विवाद सुलझ गया	47	21	6	6	80
2	कुछ तनाव है	50	24	6	0	80
3	सामान्य स्थिति	47	19	6	8	80

वादी प्रतिवादी से साक्षात्कार के आधार पर हम यह कहने की स्थिति में हैं कि 47 उत्तरदाताओं की राय में उन्हें लोकअदालत के निणय से पूर्ण सतोप है और उनका विवाद सुलझ गया है एवं आज भी सुलझा हुआ है। ऐसे उत्तरदाता जो यह जानते हैं कि विवाद सुलझ गया है उनमें से 21 की सन्तुष्टि की स्थिति सामान्य है जबकि 6 लोग कम सन्तुष्टि रहे हैं परंतु वे भी यह स्वीकार करते हैं कि उनका विवाद सुलझा हुआ है। उत्तरदाताओं में से 50 ने माना है कि कुछ तनाव शेष रह गया है परंतु फिर भी वे निणय से सन्तुष्ट हैं। तनाव की बात कहने वालों में से 24 को सामान्य सतोप है जबकि 5 को कम सतोप। विवाद की मौजूदा स्थिति में सामान्य स्थिति प्रकट करने वालों में 47 को निर्णय से पूर्ण सतोप है 19 को सामान्य सतोप और 6 को कम सतोप। निणय से सन्तुष्टि का स्तर

एक विवाद की मौजूदा स्थिति से लोकप्रदात के निर्णय की पूर्ति का एक चित्र स्पष्ट होता है।

निर्णय से पूर्ण सन्तोष एक सामान्य सन्तोष व्यक्त करने वाला की सख्या ज्यादा है जबकि कम सन्तोष व्यक्त करने वालों की सख्या बहुत कम है। इसमें हम बात की भी पुष्टि होती है कि लोकप्रदात के निर्णय से प्रायः दोनों पक्षों को सन्तोष होता है। यदि किन्हीं कारणों से आज कुछ तनाव पैदा है तो भी उससे लोकप्रदात की 'व्यापकता' में कमी नहीं आती है। लोक प्रदात में जो 'व्यापक' दिया वह अपने ध्यान पर ठीक है और उससे बहुसंख्यक लोग का पूर्ण तथा सामान्य सन्तोष है। निर्णय के बाद नयी घटनाओं के कारण तनाव पुनः पैदा हो सकता है। यह भी संभव नहीं है कि दोनों पक्षों को पूर्ण सन्तोष मिले ही या भविष्य में तनाव नहीं आयेगा, इसकी गारंटी लोकप्रदात दे। यह तो व्यक्ति के भावी व्यवहार एवं सद्भाव पर भी निर्भर करता है।

जैसा कि हमने ऊपर देखा आमतौर पर लोकप्रदात के निर्णय की पूर्ति स्वेच्छा से होती है। इस बात की पुष्टि उक्त तालिका से भी होती है। यदि निर्णय से सन्तोष है तो उस पर प्रतिक्रिया करना आसान हो जाता है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि सभी निर्णयों की पूर्ति सहज में हो जाती है। कई ऐसे अवसर भी देखने में आये जिनमें निर्णय की पूर्ति में कठिनाई आती है। जिन कारणों से निर्णय की पूर्ति में कठिनाई आती देखी गयी उसे हम रूप में गिना सकते हैं

(क) एक पक्ष को असन्तोष होना।

(ख) दोनों पक्षों को पूर्ण सन्तोष नहीं होना।

(ग) निर्णय के समय कुछ बातों की अस्पष्टता रह जाना या दोनों पक्षों का मन साफ न होना।

(घ) स्वाध।

(ङ) किसी के बहुवादे में आ जाना।

लोकप्रदात के निर्णय की पूर्ति न होने पर लोकप्रदात क्या करती है? जैसा कि ऊपर कहा गया है, लोकप्रदात के निर्णय की पूर्ति विभिन्न प्रकार के विवादों में अलग-अलग ढंग से होती है। यदि किसी विवाद में एक पक्ष निर्णय की पूर्ति नहीं करता है, तो सामान्यतया तीन स्थितियाँ होती हैं

- (1) करारखत में उल्लिखित दण्ड दिया जाता है। अधिकांश करारखतों में इस बात का उल्लेख होता है कि निर्णय की पूर्ति न होने पर क्या किया जाय ?
- (2) निणय की पूर्ति न होने पर विवाद पुनः लोकअदालत में आता है और उस पर विचार किया जाता है।
- (3) निणय में शामिल पक्ष (जुरी) निणय की पूर्ति के लिये प्रयास करते हैं।

सारांश

(1) वादी-प्रतिवादी द्वारा लोकअदालत का निर्णय स्वेच्छा से स्वीकार किये जाने के कारण उस निणय की पूर्ति में विशेष कठिनाई देखने में नहीं आयी। फिर भी मानवीय स्वभाव की भिन्नता एवं खास परिस्थितिवश यदाकदा निणय की पूर्ति में कठिनाई आती है। विवाद के निणय में जो दण्ड का प्रावधान रहता है उसे मूलरूप देने की प्रक्रिया में ही निणय की पूर्ति न होने पर की जाने वाली कार्यवाही का उल्लेख करारखत में रहता है। अतः यदि किसी निणय की पूर्ति नहीं होती है तो करारखत में उल्लिखित कार्यवाही की जाती है या विवाद पुनः लोकअदालत में आया जाता है।

(2) यह बात साफ़तीर पर देखने में आयी कि निणय की पूर्ति कराने के लिए पक्षगण भी सक्रिय रहते हैं। पक्ष इस बात का प्रयास करते पाये गये कि जो निणय हुआ है उसका पालन हो। यह भी देखने में आया कि विवाद से सम्बद्ध पक्ष स्वयं भी विवाद सुलझाने को उत्सुक रहते हैं इस कारण एक बार निणय स्वीकार करने के बाद उसे क्रियाविन करने का ध्यान रहता है।

(3) स्वैच्छिक स्वीकृति के कारण आमतौर पर निणय के प्रति वादी-प्रतिवादी को सामान्यतः सन्तोष रहता है। लोकअदालत में जिस प्रक्रिया से निर्णय होता है उसमें अधिकतम सन्तुष्टि की गुंजाइश रहती है। फिर भी यह संभव नहीं कि सभी विवादों में दोनों पक्षों का समान या पूर्ण सन्तुष्टि प्राप्त हो। सन्तुष्टि की तीन स्थितियाँ देखने में आयीं (क) पूर्ण सन्तोष (ख) सामान्य सन्तोष और (ग) कम सन्तोष। इसका माप माप विवाद सुलझने की स्थिति भी सभी विवादों में एक ही नहीं पायी गयी। विवाद के निणय के बाद उसकी मौजूदा स्थिति (सुलभाव की स्थिति) के तीन स्वरूप सामने आये—(अ) कुछ लाभा का विवाद पूर्णतया मुक्त

जाता है। (पा) कुछ लोग निर्णय के बाद भी आपसी सम्बन्धों में तनाव महसूस करते हैं और इस प्रकार उनमें मन में गांठ बनी रहती है। (२) ऐसे लोग भी हैं जो यह मानते हैं कि सामान्य स्थिति कायम तो हो गई है फिर भी कतिपय कारणों से कुछ उलझनें बनी हुई हैं। पर साथ ही वे यह विचार भी व्यक्त करते हैं कि फिलहाल कोई समस्या नहीं है।

(4) निर्णय की पूर्ति न होने की स्थिति में लाकड़वालत के पास ऐसी एजेंसी नहीं है जिससे निर्णय पूर्ति में आगे बढ़ने की जगह बहिष्कार की दूर किया जाय। जब एक सीमा तक यह प्रयास करते हैं कि निर्णय की पूर्ति हो लेकिन निर्णय की पूर्ति करना काफी हद तक दोनों पक्षों की इच्छा पर ही निर्भर करता है। ऐसी व्यवस्था विकसित कर जान की आवश्यकता है जो निर्णय की पूर्ति की स्थिति को दृष्टि से और निर्णय पूर्ति न होने पर पूर्ति हेतु आगे कार्यवाही करे। ऐसी मामलों में दृष्टि में आये जिसमें बराबर पर हस्तक्षेप के बावजूद एक पक्ष के मन बदलने या अन्य कारणों से उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में विवाद उस समय तक उत्पन्न रह जाता है जब तक कि वह पुनः लाकड़वालत में नहीं आये और पुनः निर्णय होकर उसकी पूर्ति न हो जाय।

निर्णय की प्रतिक्रिया और आस्था

लोकप्रदात के निर्णय का समाज के जिन वर्गों पर प्रभाव पड़ता है, उनकी प्रतिक्रिया जानने पर जो तथ्य सामने आये, उन पर इस अध्याय में विचार किया गया है। यहाँ लोकप्रदात से प्रभावित नीचे लिखे पक्षों की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया गया है

- 1 वादी एवं प्रतिवादी की प्रतिक्रिया।
- 2 विवाद से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए लोगों यथा वादी प्रतिवादी के निकटस्थ मित्रों एवं सम्बन्धियों की प्रतिक्रिया।
- 3 सामान्य लोगों की प्रतिक्रिया।

जो लोग लोकप्रदात में आकर अपना विवाद सुलझाने का प्रयास करते हैं, लोकप्रदात के निर्णय के बारे में उनकी प्रतिक्रिया का एक विशिष्ट विच्छेद अध्याय में भी देखने को मिल सकता है। बातचीत के दौरान प्रायः सभी लोगों ने यह राय व्यक्त की कि लोकप्रदात में न्याय मिलता है इस कारण वहाँ विवाद से जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि विवाद का निर्णय हमारे पक्ष में ही आये। तथ्या के आधार पर न्याय देने की दिशा में प्रयत्नशील लोकप्रदात यहाँ के लोगों को सस्ता, सरल एवं सुलभ न्याय प्रस्तुत करती है और दोनों पक्षों की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसा समाधान खोजती है जिससे दोनों पक्षों को अधिकतम संतोष हो और जनसाधारण के हृदय में नतिकता सच्चाई एवं मानवीयता और सहृदयता के गुणों का गचार हो।

विवाद खान में आने वाली कठिनाइयाँ जानने का भी प्रयास किया गया।

जो दानें सामने आयी वे कठिनाइयाँ को स्पष्ट करने में मददगार हो सकती हैं। उत्तरदाताओं में तीन प्रश्न किये गये थे

- (1) क्या लोकसभालय में काम पद्धति की कठिनाई महसूस होती है ?
- (2) क्या लोकसभालय में ध्यान या नियम तन में आर्थिक कठिनाई सामने आती है ?
- (3) क्या एक व्यक्ति के नेतृत्व के कारण कोई कठिनाई दृष्टिगोचर होती है ?

उक्त प्रश्नों के उत्तर में वादी प्रतिक्रिया दिया न जा बात कही उसे इस तालिका में देना संभव है

तालिका सख्या-18

विवाद से सम्बन्धित पक्षों की कठिनाइयाँ

सख्या-80

क्र०	क्या नीचे लिखी कठिनाइयाँ हैं ?	उत्तरदाता सख्या	प्रतिशत
1	काम पद्धति का) हा	2	2—50
))		
) नहा	78	97—50
))		
2	आर्थिक) हा	00	0—00
))		
) नहा	80	100—00
3	एक व्यक्ति के नेतृत्व) हा	1	1—25
))		
) नहीं	79	98—75

इससे स्पष्ट हो जाता है कि कठिनाइयों से सहमति व्यक्त करने वालों की संख्या प्रायः नगण्य है और जहाँ तक आर्थिक कठिनाई का तात्पर्य है लोकसभालय में आने वालों के समक्ष कोई आर्थिक कठिनाई नहीं आती। इन बातों की पुष्टि लोकसभालय के निर्णयों में हुए व्यय की जानकारी से भी मिलती है। यहाँ की कार्यपद्धति सरल एवं सबके समझने लायक है। निर्णय की स्वीकृति के पक्ष में एक कारण यह भी रहा है कि अधिकांश लोगों का लोकसभालय के अध्यक्ष के नेतृत्व में विश्वास है और प्रायः सभी उत्तर-

दाताओं ने उनके प्रति आस्था व्यक्त की है। अध्यक्ष विवाद को मुलभूतने में भेद भाव नहीं करता और दोनों पक्षों को सही राय देता है, यह बात भी प्रायः सभी ने स्वीकार की है। केवल एक उत्तरदाता ने ही उनके नेतृत्व में शका व्यक्त की है लेकिन वह भी लोकअदालत की उपादयता के प्रति शकालु नहीं है।

लोकअदालत के निर्णय की प्रतिक्रिया जानने के लिये सामान्य साक्षात्कार वाले उत्तरदाताओं के माध्यम से जो तथ्य सामने आये हैं, उनसे इस बारे में यथार्थ जानकारी प्राप्त होती है। लोकअदालत की बैठक में गांव का सामान्य व्यक्ति शामिल होता है और जिस व्यक्ति का विवाद होता है उसके नात रिश्तेदार एवं मित्रगण भी बैठक में शामिल होते हैं।¹ लोकअदालत की बैठक में भाग लेने वालों को चार श्रेणियों में विभाजित किया है (I) दशक (II) वादी प्रतिवादी (III) पक्ष-विपक्ष में गवाही देने वाले और (IV) जूरी (पंच)। उत्तरदाताओं में से कितने व्यक्तियों ने किस रूप में भाग लिया इसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद निर्णय की प्रतिक्रिया के बारे में इन उत्तरदाताओं की राय जानना अधिक उपयुक्त रहेगा। (तालिका सख्या 19 पृष्ठ 95)।

लोकअदालत से प्रभावित गांवों में किये गये साक्षात्कार (सामान्य साक्षात्कार) में यह पाया गया कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने किसी न किसी रूप में लोकअदालत की कार्यवाही में भाग लिया है। जबकि ऐसे गांव या कस्बों के लोग ने (विशेष साक्षात्कार) जहां लोकअदालत का प्रभाव कम है लोकअदालत की कार्यवाही में बहुत कम भाग लिया है। कार्यवाही में भाग लेने वालों और भाग न लेने वालों की प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न है। सामान्य साक्षात्कार वाले 99 54 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि उन्होंने दशक के रूप में भाग लिया है लेकिन विशेष साक्षात्कारियों में से एक भी उत्तरदाता न वाद विवाद, पक्ष-विपक्ष या जूरी के रूप में भाग नहीं लिया। इससे यह कह सकते हैं कि विशेष साक्षात्कारियों का (जो कि सामान्यतया बुद्धिजीवी एवं बाजार, कस्बों के निवासी हैं) लोकअदालत से निकट का सम्बन्ध नहीं है ये लोग लोक अदालत के निर्णयों एवं कार्यों से भी विशेष परिचित नहीं हैं और इसी लिए इनकी प्रतिक्रिया भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आयी है।

लोकअदालत के बारे में प्रतिक्रिया जानने की दृष्टि से पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में जो बातें सामने आयीं, उसे लोकअदालत में आस्था के कारणों के रूप में तालिका सख्या-20, पृष्ठ 97 में देखा जा सकता है।

सामान्य और विशेष साक्षात्कार के उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया में

भिनता माफ़ीर पर देगी जा सकती है। विनय के बारे में अपनी राय जाहिर करत हुए सामान्य उत्तरदाताओं में 91 25 प्रतिशत ने यह मत व्यक्त किया कि लोकप्रदासत के विनय में 'याय भिनता है और 'याय भिनने' के कारण ही वह लोकप्रदासत के प्रति धारणा भी है। विनय उत्तरदाताओं में 64 52 प्रतिशत ने 'याय भिनने' की बात स्वीकार की और 6 45 प्रतिशत ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनमें मतभेद में यह जाहिर होता है कि विशेष उत्तरदाताओं का लोकप्रदासत से सीधा सम्बन्ध एवं अनुभव नहीं होने पर भी उनका यह मानना है कि यहाँ 'याय भिनता है। लेकिन इनमें से कुछ (29 03) ने यह बात स्वीकार नहीं की कि वहाँ 'याय भिनता है। विशेष साक्षात्कार के उत्तरदाताओं में प्रश्न प्रश्न के मर्म में भी अपनी असहमति व्यक्त की है। काय पद्धति का सरलता, आश्रम का काय और ग्राम-दान-विचार का प्रभाव आदि प्रश्नों के उत्तर में इन्होंने सामान्य साक्षात्कार के उत्तरदाताओं से भिन्न मत व्यक्त किया है। कुछ लोगों ने सामान्य मत भी व्यक्त किया है। भिन्न मत व्यक्त करने वालों से प्रतिप्रश्न करने पर स्पष्ट उत्तर नहीं प्राप्त हो सका। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि ये विशेष उत्तरदाता ऐसे हैं जिनका लोकप्रदासत से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। इनमें से कुछ लोग स्थानीय पूर्वाग्रह से ग्रस्त भी हो सकते हैं यथा वकील सरकारी कर्मचारी आदि। ये लोकप्रदासत के बारे में स्पष्ट राय नहीं रखते। इन लोगों से असहमति के कारण जानने का भी प्रयास किया गया लेकिन खास जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। बातचीत के दौरान जो बातें सामने आयी उस पर से कुछ बातें इस रूप में त्रुटि की जा सकती हैं

- (1) विनय उत्तरदाताओं की राय में लोकप्रदासत आदिवासी, प्रशिक्षित एवं पिछड़े क्षेत्र में ही एवं हद तक सफल हो सकती है। उनकी धारणा है कि ऐसी समस्या विकसित समाज की गुंथियाँ एवं मानसिक उलझाव को हल करने में सक्षम नहीं हो सकती।
- (2) इनमें से कुछ लोग किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से भी लोकप्रदासत के बारे में अनुकूल राय नहीं रखते।
- (3) लोकप्रदासत की सरल व्यवस्था मौजूदा पेचीदा कानूनी मुद्दों के साथ कैसे मेल खा सकती है, यह उनके मन में स्पष्ट नहीं है।
- (4) लोकप्रदासत की सरल सीधी सुलभ एवं खुली 'याय पद्धति का कोर्ट के नियमों, कानूनों एवं वकील आदि व्यवस्था आदि के साथ कैसे मेल बैठे, यह उनके दिमाग में साफ नहीं है और कानून

तालिका सत्या-20

लोक अवास्त में आस्था के कारण

क्र०	आस्था के कारण	सामान्य साक्षात्कार सत्या 435				विचार साक्षात्कार सत्या 31					
		सहमति	असहमति	सहमति	असहमति	सहमति	असहमति	उत्तर महा न्या	सत्या प्रतिफल		
1	चाय मिलना	400	91 15	35	805	20	6452	9	2903	2	645
2	बाप पढ़ति की सरसता	339	77 93	96	2207	8	2581	21	6774	2	645
3	आध्याम का बाप	16	368	419	9632	16	5161	13	4194	2	645
4	आमदान विचार	225	51 72	210	4828	1	322	28	9033	2	645
5	जाति संगठन	6	138	429	9862	2	645	27	8710	2	645

एक व्यवस्था का प्रश्न सामने आने पर लोकअदालत जैसी व्यवस्था में अधिकार एवं कार्य क्षेत्र जैसे प्रश्न भी इनके दिमाग को उलझन में डाल देते हैं।

उक्त कारणों से बुद्धि एवं कानून की उलझनों में उलझा व्यक्ति लोकअदालत के बारे में स्पष्ट राय रखने में कठिनाई महसूस करता हुआ ही पाया जाता है। फिर भी विशेष उत्तरदाताओं ने जो उत्तर दिए हैं उनमें लोकअदालत के अस्तित्व एवं उपादेयता को एक सीमा तक तो स्वीकार किया ही है।

संक्षेप में, उत्तरदाताओं द्वारा व्यक्त भाव निम्न प्रकार क्रम बद्ध किये जा सकते हैं—

- (1) निर्णय के बारे में वादी प्रतिवादों की सामान्य प्रतिक्रिया यह देखने में आयी कि दोनों पक्ष यह स्वीकार करते हैं कि यहाँ 'याय मिलता' है। याय मिल ही उनके पक्ष में नहीं जाये पर याय मिलता है यह विश्वास मौजूद है।
- (2) वादी प्रतिवादों का निकटस्थ लागू, नाते रिश्तदार भी यह स्वीकार करते हैं कि लोकअदालत के निर्णय में सही 'याय' निहित रहता है। यद्यपि कई ऐसे उदाहरण भी देखते में आये हैं जिसमें कोई पक्ष जूरी की नियुक्ति में इस बात का ध्यान रखता है कि वह उसका पक्ष ले। परन्तु खुली निर्णय प्रक्रिया के कारण इस प्रकार की स्वार्थ वृत्ति चलने की गुंजाइश बहुत कम रहती है।
- (3) सामान्य उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि लोकअदालत की निर्णय प्रक्रिया का देखते हुए तथ्यों के आधार पर सही 'याय' मिलने का विश्वास मजबूत होता है। इन लोगों (सामान्य साक्षात्कार) में से अधिकांश न लोकअदालत की कार्यवाही में किसी न किसी रूप में भाग लिया है।
- (4) विशेष साक्षात्कार वाले उत्तरदाताओं ने लोकअदालत के निर्णय के प्रति एक सीमा तक शका व्यक्त की है। उनका लोकअदालत के माध्य प्रत्यक्ष या निकट का सम्बन्ध न होने के कारण उसके निर्णय के बारे में शक्यों है। उन शकाओं के होत हुए भी उनके द्वारा लोकअदालत की स्वीकृति एवं उसकी उपादेयता को स्वीकार किया गया है।

- (5) लोकअदालत का कार्य क्षेत्र आदिवासी समाज तक सीमित होने के कारण गर आदिवासी क्षेत्र के लागू के मन मे इसकी सफलता के प्रति शका है । उनवे मन मे यह बात भी है कि शायद गर आदिवासी समाज मे ऐसी व्यवस्था उत्तनी सफल न हो सवे जितनी आदिवासी समाज मे हो रही है । गर आदिवासी समाज मे वह कितनी सफल होगी उसकी क्या प्रक्रिया होगी यह प्रश्न अभी अनुत्तरित है ।
- (6) लोकअदालत द्वारा दिय गये निणय के बारे म वादी प्रतिवादी किस सीमा तक स तुष्ट होत हैं, उसका एक प्रमाण यह है कि हमने जिन विवादों एव उन पर लोकअदालत द्वारा दिय गये निणयों का अध्ययन किया है, उनमे एक भी ऐसा निणय सामने नहीं आया जिसको उन्होंने अगोकार नहीं किया हो और जिससे अस-तुष्ट होकर निणय के विरुद्ध सरकारी यायालय की शरण ली हो । उसका दूसरा प्रमाण यह है कि हमने जिन 80 वादी प्रतिवादिया के मामलों का (67 विवाद का) वारीकी से अध्ययन किया है उनम 9 ऐसे विवाद भी सामने आये हैं जो पहले वैधानिक यायालयों के समक्ष याय-प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किये गये थे और जिन पर वादी प्रतिवादी का काफी रुपया और साल-दो साल का समय बरबाद हो गया था कि तु फिर भी जिन पर वैधानिक यायालय स निणय नहीं मिल सका और जिनका लोकअदालत न एक दो पेणियों के बाद ही दोनों पक्षा का स-तोपप्रद निर्णय देकर समाधान कर दिया और पारस्परिक कटुता एव तनाव से मुक्ति दिलाकर दोनों पक्षा को एक दूसरे का शुभेच्छु और हितचिंतक बना दिया लेकिन लोकअदालत के निणय के विरुद्ध सरकारी अदालत का द्वार खटखटाये जाने से सम्बंधित विवाद इनम से एक भी देखने म नहीं आया ।

संदर्भ

लोक अदालत और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन

सामाजिक परिस्थिति

जसा कि प्रारम्भ में कहा गया है लोकअदालत मात्र 'यायिक' मस्या नहीं है बल्कि यह याय के साथ-साथ-साथ समाज के अन्य अवयवों को प्रभावित करने वाली समाजसेवी संस्था भी है। समाज रचना में आयी गलत रुढ़ियों, परम्पराओं और असामाजिक व्यवहार को परिष्कृत करने का प्रयास करना भी लोकअदालत का एक प्रमुख कार्य है। विवाद के निणय की प्रक्रिया के दौरान अध्यक्ष द्वारा किया गया मार्ग दर्शन इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विभिन्न चर्चाओं के दौरान एवं लोकअदालत की कार्यवाही देखने से जो जानकारी मिली है, उसके आधार पर कहना चाहेंगे कि लोक-अदालत सामाजिक परिवर्तन में मददगार है और इससे समाज को एक नयी दिशा मिली है एवं नये मूल्य प्रतिष्ठापित हुए हैं। सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया पिछले कई दशकों से सम्पूर्ण समाज में चल रही है, उसका प्रभाव इस क्षेत्र में भी पड़ा है। इस परिवर्तन में शहरीकरण, यातायात की सुविधा, संचार साधनों का विकास चल-चित्र, शिक्षा आदि सामाजिक परिवर्तन से प्रभावी तौर पर इस क्षेत्र में भी समान रूप से प्रभावी हैं। लेकिन लोकअदालत एवं आश्रम की प्रवृत्तियों में परिवर्तन की प्रक्रिया को अधिक सजीव एवं गतिशील पाया गया। प्रस्तुत अध्याय में यह विचार करने का प्रयास किया गया है कि लोकअदालत 'याय' कार्य के अलावा इस क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक जीवन को किस सीमा तक प्रभावित करती है। साथ ही साथ यह देखने का

प्रयास भी किया गया है कि इस क्षेत्र के लोग इस बात को किस सीमा तक स्वीकार करते हैं कि लोकअदालत सस्ता एवं सरल याय उपलब्ध करने के साथ साथ उनके जीवन के सामाजिक-आर्थिक पक्ष को भी प्रभावित करती है।

आदिवासी समाज में परम्परागत रूढ़ियाँ अथवा समाज से अधिक पायी जाती हैं।¹ इनके सामाजिक जीवन का बड़ा भाग जातीय धर्म पर आधारित होता है। रोज के जीवन में इसका प्रभाव सहज में देख सकते हैं। विभिन्न आदिवासी समाजों में एक ही रूढ़ियाँ एवं परम्परा न होते हुए भी सामाजिक जीवन में इनकी जकड़न प्रायः समान रूप से देख सकते हैं। भूत-प्रेत डायन गति का मेला विवाह मृत्यु की परम्पराएँ इनके जीवन को कठारता से प्रभावित किया करती हैं।

आदिवासी-प्रधान क्षेत्र को, अनेक अच्छी सांस्कृतिक परम्पराओं के बावजूद एक सीमा तक कई गलत एवं अमानुषिक परम्पराएँ एवं आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार मान सकते हैं। जैसे भूत-प्रेत की मायता यहाँ इतनी गहरी जड़ें जमाये हुये हैं कि कठिन से कठिन बीमारी में भी ओम्भा एवं भगत को बुलाकर उसे ठीक कराने का असफल प्रयास करते हुए बहु-मूल्यक आदिवासियों को देखा जा सकता है। अथ विश्वास इस सीमा तक पाया गया है कि किसी महिला को डायन करार देने पर गांव के लोगो ने बिना सोचे समझे अमानुषिक अत्याचार करके उनका जीना दूभर कर दिया और कुछ मामलों में तो गांव के लोगो ने उस महिला की इस सीमा तक पीटाई की कि वह एक प्रकार से मृत्यु की स्थिति तक ही पहुँच गयी। ओम्भा के कहन पर गांव के लोगो ने यह मान लिया था कि उक्त महिला डायन हो गयी है और गांव के लोगो को या जाती है। इसी प्रकार के अनेक अथ प्रकार के अथ विश्वास भी देखे जा सकते हैं।

विवाह एक परिवार की अस्थिरता इस क्षेत्र में आम बात है। अथ आदिवासी क्षेत्रों की भाँति यहाँ भी विवाह एक तलाक में सहजता पायी जाती है। इससे महिलाओं की सुदृढ़ स्थिति का भी अदृज लगता है।² कई स्थितियों में तलाक व्यक्ति की गलत आदतों एवं गैर व्यक्ति के साथ सम्बंध के कारण भी होते पाये गये हैं। गरासिया आदिवासी समाज में तो तलाक इतना आसान पाया गया कि नाम मात्र की रकम देखकर तलाक स्वीकार कर लिया जाता है।³ लोकअदालत में आये विवादों की मर्यादा से भी इस बात की पुष्टि होती है कि इस क्षेत्र में तलाक एवं विवाह सम्बन्धी विवादों की संख्या सबसे अधिक है। भील राठवा तथा नायका में तलाक सम्बन्धी परम्पराएँ प्रायः एक-सी पायी गयी हैं। लोकअदालत के अध्यक्ष एवं अथ लोगो ने स्वीकार

किया कि करीब दो दशक पूर्व इस क्षेत्र में तलाक की जो स्थिति थी और पारिवारिक ढांचा जितना अस्थिर था, उतना अब नहीं है। अब तलाक की सरया कम हुई है और पारिवारिक स्थिरता आयी है। पहले तलाक की प्रवृत्ति इतनी अधिक बढ़ी हुई थी छोट छोट प्रश्नों पर विवाह विच्छेद हो जाया करता था। लोकअदालत की भावना है कि पारिवारिक अस्थिरता अयस्कर नहीं है और जहाँ तक सम्भव हो, इसे रोका जाना चाहिये। लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं है कि वह तलाक को बढ़ कराने की नीति की पोषक है। वह सामान्यतया ठोस कारण होने पर ही तलाक स्वीकार करती है। आदिवासी समाज की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए पारिवारिक अस्थिरता के कारण कई कठिनाइयाँ होती पायी गयीं जैसे (1) बच्चों की देखभाल की (2) तलाक होने पर लेन देन के कारण पड़ने वाला आर्थिक भार और (3) सम्पत्ति का बंटवारा आदि।

सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के क्षेत्र में लोकअदालत ने जीवन के कई पक्षों को प्रभावित किया है। परिवर्तन के इन पक्षों को इस रूप में विभाजित करना चाहेंगे—

- (1) सस्यात्मक—विवाह, जाति, परिवार आदि मर्यादों के बारे में विचार परिवर्तन।
- (2) मूल्यात्मक—स्त्रियों एवं सामाजिक आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के सम्बन्ध में नये मूल्यों की स्थापना अपराध की स्वैच्छिक स्वीकृति प्रायश्चित्त, हृदय परिवर्तन आदि भावनात्मक मूल्यों का विकास और नैतिकता सम्बन्धी मूल्यों की प्रतिष्ठा।
- (3) आचरणात्मक—स्त्रियों के प्रति व्यवहार में सुधार, आदिवासी एवं गर आदिवासी के आपसी व्यवहार के नये मानदण्ड और महाजन के साथ व्यवहार आदि में परिवर्तन।
- (5) सांस्कृतिक—परम्परागत सांस्कृतिक मूल्यों में जैसे भूत प्रेत डायन, भगत आदि सम्बन्धी धारणाओं में परिवर्तन।
- (4) आर्थिक परिवर्तन—उन्नत कृषि तरीकों का प्रचलन, सिंचाई-साधनों का विस्तार आर्थिक विवादों का निपटारा और आर्थिक शोषण की समाप्ति।

सामाजिक प्रभाव

लोकअदालत से प्रभावित गांवों के उत्तरदाताओं में से क्षत प्रतिगत की

राय है कि तलाक सम्बन्धी विवादों की जो स्थिति पहले थी, उसमें परिवर्तन आया है और विवादों की संख्या कम हुई है। यह भी स्वीकार किया गया कि लोकअदालत से सम्पर्क बढ़ने के साथ-साथ यह धारणा भी मजबूत हुई है कि क्षणिक आवेश में आकर बिना किसी खास कारण के तलाक देना ठीक नहीं है और स्थायी पारिवारिक जीवन बिताने का प्रयास किया जाना चाहिये।

आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन का भी सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ता पाया गया। बेरोजगारी का क्षेत्र बढ़ने और अधिक मात्रा में काम मिलने आदि के कारण पारिवारिक स्थायित्व में बढातरी हुई है। यहाँ यह भी स्वीकार करना चाहिये कि गैर आदिवासी हिंदू समाज में पारिवारिक स्थायित्व सम्बन्धी जो स्थिति है, उसका प्रभाव भी इन पर पड़ा है और गैर आदिवासी समाज से सम्पर्क बढ़ने से उनकी व्यवस्था की अच्छा मानने की भावना भी मजबूत हुई है। विशेष साक्षात्कार वाले उत्तरदाताओं में से भी 83/87 प्रतिशत यह मानते हैं कि तलाक एवं विवाह सम्बन्धी विवादों में कमी लाने में लोकअदालत मददगार हुयी है।

पारिवारिक तनाव सम्बन्धी विवादों में भी कमी होने में लोकअदालत का प्रभाव एक कारण है। उसका यह अनवरत प्रयास रहा है कि विवादों की संख्या घट और विवाद उन्हें भी तो उन्हीं स्थानीय स्तर पर ही सुलझा लिया जाय। पारिवारिक तनाव की कमी के बारे में भी सामान्य एवं विशेष दोनों प्रकार के उत्तरदाता प्रायः वही राय रखते हैं जो तलाक एवं विवाह के सम्बन्ध में है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है पहले आदिवासी समाज में हर सकट भगत ओम्मा को याद करना आम बात थी लेकिन लोकअदालत से सम्पर्क के बाद के समय में इसमें अर्थ प्रभावों का भी कुछ कारण हो सकता है। अनेक गलत मान्यताओं पर से उनकी विश्वास हटा है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि यहाँ के लोग ने भूत प्रेत पर विश्वास करना छोड़ दिया है पर हा विश्वास पहले से कम अवश्य हुआ है। भूत प्रेत में विश्वास का प्रश्न व्यक्ति की भावना के साथ जुड़ा होने के कारण इस बारे में निश्चित आकड़ प्रस्तुत करना सम्भव नहीं। इतना ही कहना उचित होगा कि भगत एवं ओम्मा आदि का जो प्रभाव पहले था, वह अब नहीं रहा है।

इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न अर्थ अथवा विश्वास का भी है। अर्थ विश्वास काफी कम हुय है यह सहज में देखा जा सकता है। अध्ययन के दौरान एक विवाद ऐसा भी आया जिसमें एक महिला को डायन करार दिया गया था।

तालिका सख्या—21

उत्तरदाताओं की राय में लोकभदालत का सामाजिक प्रभाव

क्र०	प्रभाव का प्रकार	सामान्य साक्षात्कार सख्या 435				विशेष साक्षात्कार सख्या 31			
		सहमति		व्यसहमति		सहमति		व्यसहमति	
		सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1	विवाह एवं तनाव सम्बन्धी विवाद में कमी	435	100—00	00	00—00	26	83—87	5	16—13
2	पारिवारिक तनाव में कमी	435	100—00	00	00—00	25	80—65	6	19—35
3	भूल प्रत में विस्वास में कमी	398	91—49	37	8—51	15	48—39	16	51—61
4	सच विस्वास में कमी	433	99—34	2	0—66	31	100—00	0	0—00
5	जातिगत एकता भावी है	74	17—01	361	82—99	29	93—55	2	6—45
6	छायाछल में कमी भावी है	434	99—77	1	0—33	31	100—00	0	0—00

डायन करार देने वाले व्यक्ति का कहना था कि उक्त महिला न उसके पिता को खा लिया अर्थात् मार दिया है। उस व्यक्ति के साथ कुछ अन्य लोगो न भी उसे डायन बनाया। महिला न ग्राम सभा में शिकायत की। ग्राम सभा ने निणय दिया कि डायन कहने वाला पुरुष दापी है और डायन कहना ठीक नहीं है क्योंकि कोई महिला किसी को कस खा सकती है? कुछ दिन चुप रहने के बाद उन व्यक्ति ने उस महिला का पुन डायन कहना प्रारम्भ कर दिया। विवाद फिर लोकअदालत में आया। उस पर विचार किया गया और सबने उस व्यक्ति का दोषी करार दिया एवं उसे अपनी मायताये बदलने की सलाह दी। उस व्यक्ति न भी अपनी गलती स्वीकार करली। शायद उसके मन में भी यह बात बैठ गयी कि कोई महिला डायन नहीं हो सकती।⁵ ऊपर दी गई तालिका से भी यह तथ्य सामने आता है कि ग्राम विश्वासो में कमी आयी है।

आपसी सदभाव बढ़ाने के लिये आवश्यक है कि गाव में रहने वाली विविध जातियाँ के बीच जाति-भेद के कारण भेद भाव न हो। विविध जातीय ग्राम में राजनैतिक चेतना में वृद्धि होने के कारण जाति स्तर पर पारस्परिक सम्बन्धों में अक्सर कटुता पायी जाती है। यह क्षेत्र भी हमका अपवाद नहीं है। आदिवासी प्रधान गावों में भी गैर आदिवासी पाये जाते हैं और यदि केवल आदिवासी भी हैं तो भी आदिवासी उपजातियाँ पायी जाती हैं। उत्तर-दाताग्रा का मानना है कि गाव की विभिन्न जातियों में एकता का भाव बढ़ाने में लोकअदालत मददगार हुई है। लोकअदालत का कार्य एवं प्रभाव-क्षेत्र का प्रकार का देखने में आया। एक तो ऐसे ग्रामदानी गाव हैं जहाँ ग्राम सभा है और जहाँ के लोग लोकअदालत के कार्य एवं आश्रम के साथ सक्रिय रूप में जुड़े हैं। इस प्रकार के गावों में आश्रम की ओर से आर्थिक कार्यक्रम भी चलते पाये गये। इन गावों के लोगो ने स्वीकार किया कि लोकअदालत एवं आश्रम के कारण जातीय सदभाव बढ़ा है। दूर के गावों या कम प्रभावित गावों का लोकअदालत या आश्रम से इतना सम्पर्क नहीं जुड़ सका है कि वह विभिन्न जातियों के बीच एकता लाने में मददगार हो सके। इन गावों का विवाद लोकअदालत में कम जाते हैं फिर भी जो विवाद आते हैं, उन्हें सुनभान का काम लोकअदालत करती है और उन गावों में भी जातिगत एकता के दगन होने लगे हैं। विशेष साप्ताहिक वाले उत्तरदाताग्रा का भी विश्वास है कि लोकअदालत के कारण जातीय एकता बढ़ी है।

छुआछूत के सम्बन्ध में सामान्य एवं विशेष दोनों प्रकार के उत्तरदाताग्रा की राय प्रायः एकही है कि लोकअदालत के कारण छुआछूत में कमी आयी

आश्रम में चल रहे अनन्यरूपि व प्रणामों को देने का मोक्ष मिला। उसमें उसका कई प्रकार का अधिकार लाभ उठाया व नियम प्रारम्भ हुआ मिला जस भूमि सुधार द्वारा, रूपि की सुधरी पद्धति व प्रयोग द्वारा और नयी तकनीक अपनाया व द्वारा। राजगार में वृद्धि को दो सत्रों में देखा जा सकता है। एक तो गांव में ही निवास की सुविधा बढ़ा आधुनिक रूपि पद्धति अपनाया एवं भूमि-सुधार व कारण पहल में अधिक लोग को राजगार मिला। दूसरे आश्रम में सम्भव बढन व कारण गांव में या गांव से बाहर भी काम का क्षेत्र बढ़ा। जीवन-गतांता व जरिय आश्रम में नित्य जान वाल तकनीकी ज्ञान व कारण भी एक क्षण में राजगार बढ़ा है। इन प्रकार अप्रत्याशित रूप से इस लोकप्रदासत का आर्थिक प्रभाव माना जा सकता है। यहां यह स्वीकार करना चाहिये कि धूमि आश्रम और इस प्रकार लोकप्रदासत का भी गहन वायदाय आन्विवासी प्रधान गावा तक ही फैला हुआ है इसलिए गैर आन्विवासी गावा में अपेक्षाकृत कम काम हुआ है। यही कारण है कि लोकप्रदासत का आर्थिक प्रभाव उन गावा के निवासियों पर उतनी सीमा तक नहीं पड़ा है। इसे आश्रम एवं लोकप्रदासत के कार्य की सीमा भी मान सकते हैं।

आर्थिक प्रभाव क्षेत्र को बाढ़ा गहराई में देखने पर जो तथ्य सामने आये हैं उस पर से यह कहा जा सकता है कि लोकप्रदासत का तीन अर्थ रूपों में भी आर्थिक प्रभाव पड़ा है—यथा (1) महाजन के गोपण में वसी। (2) महाजन द्वारा पहल से अधिक सही हिसाब रखा जाना। (3) जंगल के अधिकारियों द्वारा शोषण में वसी।

यहां भी सामान्य एवं विशेष उत्तरदाताओं के उत्तर में भिन्नता है। भिन्नता का एक बड़ा कारण संभवतः यह है कि विशेष उत्तरदाता इस प्रकार के गोपण के स्वयं भुक्तभोगी नहीं रहे हैं। शायद इसी कारण उन्हें यह प्रभाव सामान्य उत्तरदाताओं (जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हों) से कम स्पष्ट दिखलाई देता है। लेकिन फिर भी यह तो किसी भी हद तक नहीं कह सकते कि विशेष उत्तरदाताओं ने इन प्रभावों को अस्वीकार किया है।

आदिवासी समाज महाजन व क्षाण से बुरी तरह पीड़ित था। एक सीमा तक वह आज भी इस शोषण से पीड़ित है। लेकिन लोकप्रदासत एवं आश्रम के कार्यों ने इस पीड़ा को कम किया है और ऐसा वातावरण बनाया है जिससे एक ओर तो महाजनो का साथ उनका सदभाव बढ़ा है और महाजनो ने पहले से अधिक सही हिसाब रखना शुरू कर दिया है और दूसरी ओर लेन देन सम्बन्धी विवादों का फैसला लोकप्रदासत में होने के कारण महाजन

वर्ग के मन में भय कायम हुआ है। भय इस बात का कि गलत काम करने गलत हिसाब रखने और परेशान करने पर उन्हें लोकअदालत में जाना पड़ेगा और वहाँ उनके विपक्ष में निर्णय होगा।¹⁵ संदभाव इस कारण बढ़ा कि लोकअदालत एवं आश्रम दोनों ही सम्पूर्ण समाज में संदभाव कायम करने के लिए प्रयत्नशील हैं और दोनों ही महाजन एवं आदिवासी सभी को मेहनत की कमाई एवं इज्जत की रोटी खान की प्रेरणा देते रहते हैं। लोकअदालत में आन-जाने और अध्यक्ष की शिक्षा प्रधान बातें सुन सुन कर महाजन वर्ग भी प्रभावित हुआ है। यही कारण है कि अनक महाजनो ने लोकअदालत के समक्ष अपनी गलती स्वीकार की है और सही हिसाब रखने एवं आदिवासियों को परेशान न करने का निर्णय भी किया है। कवाट, नसवाडी, कोसिन्दा आदि बाजारों के अनेक महाजनो ने अपना व्यवहार एक सीमा तक बदला है और विशेष उत्तरदाताओं तक के बड़े भाग ने यह बात स्वीकार की है।

इस क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों खासकर जंगल के कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की शिकायतें बराबर देखने में आयीं। जंगल में रहना वाला का जीवन जंगल में प्राप्त होने वाली वस्तुओं पर काफी हद तक निर्भर रहता है। लोगो से बातचीत के दौरान सुनने में आया कि आश्रम की स्थापना के पूर्व इस क्षेत्र में या जिन क्षेत्रों में आश्रम का प्रभाव नहीं है, वहाँ जंगल के कर्मचारियों द्वारा आदिवासियों को परेशान किये जाने की घटनायें अधिक होती थीं लेकिन अब जागति एवं आत्मविश्वास बढ़ने के कारण यहाँ के लोगो में हिम्मत आयी है और सरकारी कर्मचारियों द्वारा परेशान किये जाने की प्रवृत्ति भी कम हुई है इसमें लोकअदालत का महत्वपूर्ण योगदान है। लोकअदालत ने ऐसे कई विवादों को सुलझाया है जिसमें जंगल के अधिकारियों द्वारा आदिवासियों के साथ अत्याचार किये जाने की शिकायत थी।¹⁶ इन विवादों में कर्मचारियों ने अपनी गलती स्वीकार करली और एक विद्वान् में ली गयी रकम भी वापस करदी। यही स्थिति पुलिस के साथ क्षेत्र के लोगो के आपसी सम्बन्ध के बारे में भी है। पुलिस द्वारा परेशान किये जाने की घटनायें पहले यहाँ आम बात थीं लेकिन लोकअदालत के कारण अब उस स्थिति में सुधार हुआ है एवं कर्मचारियों का अत्याचार कम हान के साथ साथ आपसी संदभाव भी बढ़ा है।

कमजोर वर्ग और लोकअदालत

यह प्रश्न सहज में सामने आता है कि समाज के कमजोर वर्ग को लोकअदालत किस सीमा तक प्रभावित करती है? इस प्रश्न के उत्तर में यही

कहा जाना चाहिये कि लोकभदालत की पूरी कार्य प्रक्रिया ही ऐसी है जिससे समाज का कमजोर वर्ग प्रभावित होता है। 'यायिक' या अय कार्यों का प्रभाव समाज के कमजोर वर्ग पर ही अधिक देखने में आया। इस क्षेत्र में कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति के लोगों का अधिक होने के कारण यह स्वाभाविक भी है। आश्रम एवं लोकभदालत के कार्य की दृष्टि भी यही रही है कि समाज के कमजोर वर्ग को मदद मिले।

क्या तलाक एवं विवाह सम्बन्धी विवादों का अधिक मस्या में आना समाज में स्त्रियों के स्थान का दिग्दर्शक है? और क्या भूमि या लेन-देन सम्बन्धी विवादों की सरया भूमि व्यवस्था की सामियों का परिणाम है? इन प्रश्नों का उत्तर एक अर्थ में ऊपर के अध्ययन से प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में समाज में स्त्रियों का स्थान महत्वपूर्ण है। तलाक, पुनर्विवाह आदि के विवादों का अधिक मस्या में आना स्त्रियों की मजबूत स्थिति का परिचायक है। यह देखने में आया है कि स्त्रियाँ लोकभदालत की बैठकों में खुलकर भाग लेती हैं और अपनी बात निःसंकोच भाव से सभा के सामने रखती हैं। ऐसा भी देखने में आया जब स्त्रियाँ स्वयं पुरखों शब्दों में तलाक की मांग करती हैं। पारिवारिक तनाव की स्थिति में स्त्री अपने पिता के घर जाती हैं और स्वयं माता पिता या अन्य किसी नाते रिश्तेदार के साथ लोकभदालत में आकर अपनी बात कहती हैं और 'याय' प्राप्त करती हैं। ये बातें समाज में स्त्रियों की सुदृढ़ स्थिति को व्यक्त करती हैं। लेकिन कई परिस्थितियों में स्त्रियाँ कमजोर भी पायी गयीं यथा अनेक घटनाओं में स्त्रियों को सताय जाने और मारे-पीटे जाने के तथ्य सामने आये हैं। अथ विश्वासों के कारण किसी स्त्री को डायन घोषित करना, उसको हीन समझे जाने का मजबूत प्रमाण है। अनेक परिस्थितियों में स्त्रियों को परिवार एवं समाज में अपमान सहना पड़ता है। इन सारी बातों को देखते हुए कहना चाहेंगे कि आदिवासी समाज में भी स्त्रियों की एक सीमा तक ही सुदृढ़ स्थिति है और वे एक सीमा तक ही पुरुष की बराबरी करती हैं। लेकिन कई प्रकार के व्यवहारों में उन्हें भी उपेक्षित रहना पड़ता है। कुल मिलाकर स्त्रियों को कमजोर वर्ग में शामिल करना उचित है। लोकभदालत उनकी स्थिति मजबूत करने एवं उन्हें समान दर्जा देने के प्रयास में विश्वास करता है। यह प्रयास लोकभदालत की कार्यवाही के दौरान देखा जा सकता है। हम देख सकते हैं कि लोकभदालत की कार्यवाही के समय स्त्रियों की समान स्तर पर रखा जाता है। उन्हें अपनी बात कहने की पूरी छूट होती है और पूरी बात कहने की प्रेरणा दी जाती है। इसके साथ साथ पर्दा प्रथा समाप्त करने और शिक्षा में

रवि लेन की प्रेरणा भी उह दी जाती है।

जमीन एवं लन-देन सम्बन्धी विवादों का अधिक सख्या में आना यहा की परम्परागत व्यवस्था में आयी गिनितता एवं बाहरी हस्तक्षेप का परिणाम है। जैसा कि पहले कहा गया है और आदिवासी समाज यहा के मूल निवासियों की जमीन हथियाने एवं उनका शोषण करने का भरसक प्रयास करता रहा है। लोकअदालत इस प्रयास को रोकने का प्रयत्न कर रही है। अतः यह स्वाभाविक है कि लोकअदालत में इस प्रकार के विवाद जाये। जमीन सम्बन्धी विवाद दो प्रकार के आते हैं—(1) आदिवासी एवं गैर आदिवासी के बीच का विवाद (2) आदिवासियों के आपसी विवाद। सरकार ने आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा के लिये जा कानून बनाया है उमसे गैर आदिवासियों में सम्बन्धित विवादों की मख्या में कमी आई है। परन्तु आदिवासियों में आपसी विवाद तो आज भी होते ही हैं। गांव में भूमि ही मुख्य सम्पत्ति होने के कारण इससे सम्बद्ध विवादों की मख्या अधिक होना स्वाभाविक है। यहा हम स्वीकार करना चाहिए कि लोकअदालत समाज के सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि में कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा करके उसे न्याय देने का प्रयास करती है।

सारांश

- (1) सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया मंदत चलती रहनी है। किसी विशेष क्षेत्रीय समाज पर सम्पूर्ण समाज के परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रभाव पड़ता है। आधुनिक युग में शहरीकरण यातायात के साधनों का विकास संचार साधनों का विकास शिक्षा का प्रसार आदि सामाजिक परिवर्तन के ऐसे कारक हैं जिन्हें सब जगह देखा जा सकता है। इस आदिवासी क्षेत्र में जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है उसमें इन कारणों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है पर इतना अवश्य है कि लोकअदालत ने इन कारणों के प्रभाव को अधिक तीव्र किया है।
- (2) आदिवासी समाज में रूढ़ियों एवं अंध विश्वासों का अधिक प्रभाव है। भूत प्रेत डायन भगत ओम्हा आदि में विश्वास के कारण यहा के लोगों को अनन्त प्रकार के कष्ट सहते देखा जा सकता है। लोकअदालत के माध्यम से इन अंधविश्वासों में कमी आयी है। वस इस कमी में अर्थ कारणों का योगदान भी स्वीकार किया जाना चाहिए। पारिवारिक अस्थिरता, तलाक एवं पुनर्विवाह इस क्षेत्र में

आम बात है। लोकअदानत ने पारिवारिक स्थिरता स्तान म मदद पहुचायो है।

- (3) सर्वोक्षण म प्राप्त तथ्यो पर से यह कहन की स्थिति है कि लोक-अदानत ने सामाजिक आर्थिक क्षेत्र म नय विचार एव नये मूल्यो का स्वीकार करने के अनुकूल वातावरण बनाया है एव शिक्षा म रुचि पैदा करन म भी लोकअदानत का योगदान रहा है। सांस्कृतिक परम्पराओ एव मूल्य भावनाओ के स्थान पर नई मान्यताय स्थापित करने की दिशा म भी प्रगति हुई है। एक सीमा तक जाति, परम्परा विवाह आदि क्षेत्रो म नये मूल्यो का स्वीकार किया जा रहा है।
- (4) समाज परिवर्तन की इस प्रक्रिया पर अय सामाजिक आर्थिक कारको का प्रभाव भी पड़ता देखा जा सकता है। लोकअदानत सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के अनेक कारणो म एक कारक है। लेकिन यह कारक अय कारको से अधिक प्रभावी है। आवश्यकता हम बात की है कि समाज परिवर्तन की प्रक्रिया मे लोकअदानत द्वारा स्थापित स्वदासन के मूल्यो की अधिक व्यापक स्वीकृति दी जाय।
- (5) लोकअदानत की कायवाही क अवलोकन, ग्रामदानी गावा की प्रगति की स्थिति एव लोकअदानत ओर समाज-परिवर्तन की प्रक्रिया सम्बन्धी बातो पर विचार करने पर यह दपने म आया कि लोक-अदानत की प्रक्रिया एव काय पद्धति म समाज-परिवर्तन के तत्वो पर अधिक बल दिया जाता है।

सदभ

- 1 देखें हरिश्चन्द्र उप्रती उपरोक्त।
- 2 देख मकन है म्पन पूव पूव अनिखित पुस्तक।
- 3 देखें, हरिश्चन्द्र उप्रती उपरोक्त।
- 4 देखें हरिश्चन्द्र उप्रती उपरोक्त।
- 5 देखें श्री हरिश्चन्द्र परीक्ष जालि का धरणीय, एक प्रो० उपद्र कपी, पूव उल्लिखित।
- 6 देखें श्री हरिश्चन्द्र परीक्ष, जालि का धरणीय।

न्यायालय और लोक अदालत

लोकअदालत में निर्णित विवादों के अध्ययन के दौरान जिन 67 विवादों का गहराई से अध्ययन किया गया, उनमें 9 विवाद ऐसे थे जो लोकअदालत में लाये जाने के पूर्व निणयार्थ सरकारी न्यायालयों में प्रस्तुत किये जा चुके थे और काफी पसा और समय बरबाद हो जाने के पश्चात् भी जिन पर निणय नहीं मिल पाया था। इन 9 पक्षकारों से लोकअदालत के निर्णय से सम्बन्धित जो उत्तर प्राप्त हुए हैं उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें से एक भी पक्षकार ऐसा नहीं था जिसे लोकअदालत के निणय से असन्तोष रहा हो। पाँच पक्षकारों ने अपनी सम्पूर्ण तृप्ति यक्ष की और बाकी चार ने सामान्य मनुष्य।

ऐसे 23 विवादों का अध्ययन भी किया गया जो लोकअदालत में निणयार्थ नहीं आये और जिनका निपटारा केवल सरकारी न्यायालयों में ही हुआ। विवाद प्रस्तुत कर्त्ता सभी आदिवासी हैं और उनमें भी अधिकांश अशिक्षित हैं। इसके लिए तालिका 23 इनकी जाति एवं शैक्षणिक स्तर की जानकारी की दृष्टि से प्रस्तुत की जा रही है।

समय एवं खर्च

तालिका 24 सर्वशिक्षित मुरुदमों में हुए व्यय एवं समय के बारे में हमारा मागदर्शन कर सकती है।

तालिका मख्या 23

सरकारी न्यायालय में जाने वालों की जाति एवं शैक्षणिक स्तर

क्र०	जाति	शैक्षणिक स्तर			कुल सं०
		मध्यमज्ञान	कक्षा I से 14	अशिक्षित	
1	राठवा सख्या) प्रतिशत)	4 (17 39)	1 (4 35)	10 (43 48)	15 (65 22)
2	भील सख्या) प्रतिशत)	1 (4 35)	00 (0 0)	3 (13 04)	4 (17 39)
3	नायका सख्या) प्रतिशत)	00 (0 0)	00 (0 0)	4 (17 31)	4 (17 39)
	योग सख्या प्रतिशत	5 21 74	1 4 35	17 73 91	23 100

तालिका मख्या-24

सरकारी न्यायालय में लगा समय एवं खच

क्र०	कुल खच (रुपये में)	निणय में लगने वाला समय (माह)							31 से योग अधिक
		1 6	7 12	13 18	19 24	25 30			
1	100/—से 200/	1	00	00	00	00	00	1	
2	201/—से 400/	1	1	00	1	00	00	3	
3	401/—से 600/	00	2	1	1	00	1	5	
4	601/—से 800/	00	00	00	00	1	00	1	
5	801/—से 1000/	00	1	00	00	00	1	2	
6	1001/—से 1200/	00	1	00	00	00	1	2	
7	1201 से अधिक	00	2	00	00	1	6	9	
योग		2	7	1	2	2	9	23	

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 23 म से 9 अर्थात् 39 12 प्रतिशत विवादों में 1200 रुपये से अधिक पसा और 31 महीन से अधिक समय लगा

जबकि लोकप्रदालत म इस प्रकार के विवादो के निपटारे मे किसी भी परिस्थिति म दो महीन से अधिक समय नही लगता । इसी प्रकार केवल 1 प्रार्थित 4 35 प्रतिशत विवाद ही ऐसा है जिसमे 6 महीने से कम समय और 200 रुपये तक धन व्यय हुआ जबकि लोकप्रदालत मे वादी प्रतिवादी के रूप मे विवाद ले जाने वाल 80 उत्तरदाताओ मे से 60 को लाख प्रदालत म केवल 10 रुपये तक का गुडवितरण का खर्चा हुआ है और केवल मात्र 12 उत्तर दाताओ से ही दण्ड वसूल किया है ।

लोक प्रदालत मे दिये गये दण्ड की स्थिति इस प्रकार है

तालिका सख्या-25

लोकप्रदालत द्वारा दिया गया दण्ड

क्र०	दण्ड की मात्रा (रुपये म)	सख्या	प्रतिशत
1	दण्ड नही	68	85 00
2	51/—से 100/—	1	1 25
3	101/—से 150/—	3	3 75
4	201/—से 250/—	2	2 50
5	301/—से अधिक	6	7 50
योग		80	100 00

जिन 12 वादी प्रतिवादियो को प्रस्तुत विवादो के स'दम म लोक-प्रदालत द्वारा दण्ड दिया गया है वे विवाद, तलाक' भरण-पोषण एव सम्पत्ति विषयक ऐसे विवाद थे जो सरकारी यायालया म प्रस्तुत होत तो हजारों रुपये तक हान पर भी कई वर्षों तक नही सुलभ पात और यायालया के खर्चों काटने रहने म वादी प्रतिवादीगण एव उनके गवाहा पक्षकारा एव मित्रो सम्बन्धिया का धन एव समय बरबाद हाता वह प्रलय स ।

उपयुक्त तालिका से हम इस निष्कर्ष पर पहुचत ह कि लोकप्रदालत न जिन 60 विवादो म 10 रुपये तक के गुड वितरण का खर्चा कराया है, उनम केवल 6 ही ऐसे विवाद थे जिनम 300 रुपये स अधिक दण्ड दिया गया है । गेप लोगो म 1 को 51 रु० से 100 रुपये तक 3 व्यक्तिया को 100 रुपये स 250 रुपये तक और 2 का 200 स 250 रुपये तक दण्ड देने का निर्णय लिया गया है और 20 वादी प्रतिवादिया पर प्रार्थित 25 प्रतिशत लागो पर कुछ नो

दण्ड नहीं लगाया है। मात्र गुड विवरण का ही मंच कराकर उनका विवाद निपटा दिया गया है।

सुविधा असुविधा

जहां तक लोकप्रदास में विवाद प्रस्तुत करने वाला की सुविधा असुविधा का तात्पर्य है उत्तरदाताओं की यह राय रही कि लोकप्रदास में समक्ष निर्णायक विवाद प्रस्तुत करने में उन्हें अधिक सुविधा रहती है।

लोकप्रदास में विवाद प्रस्तुत करने वाले 80 वाणी प्रतिवादी उत्तरदाताओं में इस प्रश्न के उत्तर में लोकप्रदास में समक्ष विवाद प्रस्तुत करने वाले के समक्ष कि काय प्रक्रिया सम्बन्धी अथवा अन्य प्रकार की कोई कठिनाई तो नहीं आती जो उत्तर दिये उनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि सरकारी यायालयों की तुलना में उनके लिये लोकप्रदास अधिक अनुकूल एवं सुविधाजनक यायालय सिद्ध हुआ है।

80 में से केवल 2 उत्तरदाताओं (1.5 प्रतिशत) ने लोक प्रदास में प्रयुक्त काय पद्धति के प्रति असंतोष व्यक्त किया है जबकि 78 (97.5 प्रतिशत) को लोक प्रदास द्वारा अपनायी गयी काय प्रक्रिया से पूर्ण संतोष है। इसी प्रकार शत प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि लोकप्रदास में बहुत कम पर्स में याच मिल जाता है जबकि सरकारी यायालयों में जान वाले अधिकांश वादी प्रतिवादी खर्च की अधिकता से पीड़ित व परेशान रहते हैं। वे इस एक राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त समितियाँ ही नहीं स्वयं यायाधीशगण एवं विद्वान वकील भी इस सत्य का महसूस करते हैं और इस सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं।¹

80 उत्तरदाताओं में 79 अर्थात् 98.75 प्रतिशत ने यह स्वीकार किया है कि लोकप्रदास की याच प्रक्रिया लोकतन्त्रवादी पद्धति है जबकि सरकारी यायालयों में यायाधीशों की निजी भावनाओं ही एक सीमा तक उनके द्वारा दिये गये निर्णयों में प्रभावगामी ढंग से कार्य करती रहती है।

लोकप्रदास द्वारा दिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की जिसमें 44 वादी और 36 प्रतिवादी शामिल हैं, जब राय मांगी गयी तो उनमें 90 प्रतिशत का उत्तर एक ही था और वह यह कि विवाद संतोषजनक ढंग से सुलभ गया और सामान्य स्थिति कायम हो गयी। किसी भी उत्तरदाता ने यह नहीं बताया कि लोकप्रदास के निर्णय के बाद किसी प्रकार का तनाव का वातावरण पैदा रहा है अथवा निर्णय से किसी प्रकार का तनाव पूर्ण वातावरण बन गया है।

न्यायदान्त व वायव्य म स्थित जिन गावा का लोकअदालत द्वारा दिये गये निणया के परिपश्य म सर्वेक्षण किया है उन निणया के विरुद्ध किसी भी प्रभावित वादी प्रतिवादी न मरचारी यायालया का द्वार नहीं खट पटाया । हा एस विवाद जम्हू हमारी जानकारी म नाय गये जिनम लोक-अदानत व वायव्य कतिपय विवादास्पद मामल स्वय ही सरकारी याया लया के समक्ष न गये और मरचारी यायालया न लोकअदालत व वायव्य कतिपय के तत्विपश्य निणया व प्रति सहमति व्यक्त करन हुए लोकअदानत विरोधी पक्षा को सलाह दी कि व लोकअदानत व निर्णया का स्वीकार करके विवाद का निपटारें ।

न्यायालय और सामाजिक परिवर्तन

वैधानिक न्यायालयों की कार्यशैली एवं व्यवस्था का आदिवासी समाज का विकासो मुख करन की दिशा मे कोई उत्पत्तनीय प्रभाव नहीं पड़ा है । अभी भी आदिवासियों म जाति पचा की व्यवस्था कायम है और बहुमहक आदिवासी अपन सामाजिक विवाद उहाँ के माध्यम मे हन करते हैं । जाति पच उनके सामाजिक व्यवहारो का निपटारा करत है । हर गाव म नायक, तहवी भगत, ओझा कारभारी और प्रत्येक फलिया पच के सम्यो स बना हुआ जाति पच होता है । नायक को मान दिया जाता है परन्तु अधिकतर भगडे सामाजिक प्रसंगा पर इकट्ठी हुई समस्त जाति के सामने रखे जाते हैं और वह उनका निपटारा करती है ।¹ हि दू वैधानिक अधिनियम 1955 क प्रावधान भी आदिवासियों पर लागू नहीं है । वैधानिक यायालया के समक्ष उनका अधिकार मामले मुकदम पेन नहीं होते और वे एक हद तक उनके व्यापक प्रभाव से अलग रहते हैं ।

हा, पिछन कुछ दशका स कतिपय निवानी और फौजदारी विवादा के निपटारे के लिये आदिवासियों म भी वैधानिक यायालयों का आश्रय लेने की प्रवृत्ति बढ़ी है । लकिन जो भी आदिवासी यायानया म अपन विवाद ल गये हैं वे उनकी लम्बी कार्यविधि खर्चीली व्यवस्था और दीर्घ सूत्रता के कारण परेशान रह ह और यह महसूस करने लगे हैं कि यदि कोई कल्पिक याय व्यवस्था उपनय हा जाय जा उनके विवादा का सही ढंग स शीघ्र निपटारा कर द तो वे अपनी पुरानी सामाजिक व्यवस्था अक्षुण्ण रखते हुए नयी समाज व्यवस्था से लाभ उठाने म समर्थ हो सकत हैं ।

यह नहीं है कि वैधानिक यायालयों के सम्पर्क म आन स उनकी निष्पक्षता सरलता एवं सत्यप्रियता पर आच आने लग गई है और छन कपट,

तिकड़म एवं मिथ्यात्व का महारा सत्कर अपने पक्ष में फैंगला प्राप्त करने की वृत्ति उनमें भी बढी है। फिर भी समाज के अल्प वर्गों की तुलना में वे 'यायालयों की मौजूदा बाय शैली से होने वाले दुष्टपरिणामों से अधिक प्रभावित नहीं हो पाये हैं।

तुलनात्मक पक्ष

लोकप्रदानत के अस्तित्व का आधार इसका नतिक धरातल एवं सच्चाई साजने और जनता की बढिनाइया का सरलता से समाधान करने की क्षमता ही है जबकि सरकारी 'यायालयों का आधार विधान बानूनी व्यवस्था और शासन सत्ता का बल है। लोकप्रदानत प्रतिवादी को जो आम-यण भेजती है, उसे स्वीकार करने के लिये वह बाध्य नहीं है और यदि बाध्य है तो केवल अपनी नीति निष्ठा या क्षेत्र अथवा गांव के निवासियों के नतिक दबाव के कारण ही है लेकिन हर प्रतिवादी को अदालत के सम्मन को बानूनन मानना पडता है और न मान तो उस बानून द्वारा निर्दिष्ट दण्ड भुगतने के लिये तैयार रहना पडता है।

लोकप्रदानत के निर्णय की अपील नहीं होती जबकि सरकारी यायालयों के निर्णय के विरुद्ध नमन उच्च 'यायालयों में अपील करने का नागरिकों को अधिकार प्राप्त है। 'यायालयों की अंतिम सीडी सर्वोच्च 'यायालय है और मध्यदण्ड प्राप्त व्यक्ति को रहम के लिये राष्ट्रपति के समक्ष दया-याचिका पेश करने का भी अधिकार है। जबकि लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध किसी का शिकायत हो तो वह अपना मामला साधारण 'यायालय में नये सिरे से ल जा सकता है। लोक अदालत के निर्णय को सरकारी यायालय किसी प्रकार का महत्व द तो वह उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है उसका वैधानिक आधार नहीं है। हा लोक-अदालत की निर्णय प्रक्रिया में यह व्यवस्था शामिल है कि वह अपनी नीचे की इकाई, जो धीरे धीरे विकसित हो रही है—ग्राम-सभा द्वारा किया गया निर्णयों पर विचार कर लत है लेकिन ऐसा मामला भी लोकप्रदानत में अपने ढंग से नये सिरे से ही पैदा होता है अपील के रूप में नहीं।

'यायालयों के अधिकार क्षेत्र और सुनवाई की शक्तियां विधान द्वारा प्रति बंधित व सीमित हैं जबकि लोक अदालत के अधिकार क्षेत्र के बारे में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उसको बानून से कोई अधिकार प्राप्त नहीं है जिससे अंतगत वह किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के एक अमुक सीमा तक की घन राशि या दण्ड जुर्माना अथवा सजा के प्रावधान युक्त विवाद सुन सके। उसकी अधिकार-सीमा दोनों पक्षों की सहमति एवं सदभावना में और क्षेत्र के

निवायिया द्वारा नाकप्रदानत का प्राप्त प्रतिष्ठा म निहित है जिसम फोज-
नानी मामला म हत्या का प्रयास करन तक के मामला म लकर दीवानी
मामला म किमी भी मूल्य की विवादग्रस्त सम्पत्ति तक के मामला शामिल हैं ।
लोक प्रदानत द्वारा दिय गय दण्ड म एसा दण्ड भी शामिल है जिसम एक
परिवार क भुवियष का गरीबीक क्षति पटुवाने क आरोप म गुनहगार का
20 साल तक अथवा उसक लडके क बालिग होन तक की अवधि के लिये
पीडित परिवार का गेन जोतन और उसका भरण पोषण करन का दण्ड दिया
गया और दस दण्ड को सम्प्रिप्त व्यक्ति न अपन प्रायश्चित के रूप म ईमान
दारी म स्वीकार किया । फनस्वरूप दोनो परिवारा के सम्प्रथ सदभावना-
पूर्ण बने और यह सदभावना आज तक कायम है । निणय देने का उसका डग
और उम निणय की त्रिदात्रित के निय लोजे गये उपाय यायालय की
प्रचलित आचार एव दण्ड महिता स किमी भी प्रकार भन नही खात ।

लोकप्रदालत एव न्यायालय म भान बान कुछ विवादा म एक सीमा तक
ही साम्य है लकिन यायानया के समक्ष जहा सत्र तरह के विवाद बानूनी
तौर पर निर्णायक प्रस्तुत होत है वहा नाकप्रदालत के कार्य क्षेत्र के निवा-
मिया की अपने डग की अलग अलग समस्याये होने के कारण लोकप्रदालत
के समक्ष सभी प्रकार क विवाा आत ह । मोटे तौर पर लोक प्रदालत के
समक्ष निम्नलिखित प्रकार क विवाा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुए हैं

- 1 हत्या का इगदा ।
- 2 पति पत्नी सम्बन्धी—जिनम तलाक भरण पोषण, सहवास का अधिकार,
गृह आदि के विवाद शामिल है ।
- 3 भूमि सम्बन्धी—जिनमे भूमि की सीमा बंदी सम्पत्ति के बटवारे और
पूरा का पूरा खेत लीटाये जाने के विवाद भा शामिल हैं ।
- 4 लेन देन सम्बन्धी—जिन म खेत या सम्पत्ति रहन रखन म सम्प्रिप्त
विवाद भी शामिल है ।
- 5 मारपीट ।
- 6 चोरी आदि ।

उक्त प्रकार के सभी विवाद एक ही प्रकार के सरकारी यायालय म
निणयार्थ प्रस्तुत नही किय जा सकते । वहा दीवानी एव फौजदारी विवानो
की सुनवाई मु सिफ मजिस्ट्रेट करत है तो राजस्व सम्बन्धी विवादो
की सुनवाई राजस्व अधिकारियो द्वारा की जाती है । दीवानी एव फौजदारी

क छोटे रिश्वत याप पचाया गया था याप पता द्वारा मुन जात का पानुनी प्रावधान भी कुछ अर्थ से चावू है नति हए रिश्वत का अधिवाश भन एव मूलानुसार अधिवाश मजा की मानानुसार गुनवाई की धविता मर्यान्ति है । उसा प्रकार विभिन्न प्रकार क राजस्व अधिवाशिया क गुनवाई मम्मी अधिवाश एव कायक्षण भी मर्यादिता एव मोमिता है । सरकारी यापालया द्वारा दिय गये निणया म कउल मात्र गानून क रक्षण की प्रवृत्ति अधिवाश रहती है । सच्चाई की ग्राज का प्रयाग कम धोर पारस्परिक तनाव दूर करने की दृष्टि ता धोर भी कम रहता है । अपनी बुद्धि एव गान क अनुसार निणय दन की प्रवृत्ति अधिवाश समाज पर पडन या न दूरगामी प्रभाव का दृष्टिगत रगने की या समाज म प्रगतिशीलता सात की प्रवृत्ति कम हानी है, तात्कालिक प्रभाव का दृष्टिवाण अधिवाश । जबकि तात्कालिक न क निणय इस उद्देश्य से किय जात है कि उभय पक्ष उम निणय की गभीरता को महसूस करके पारस्परिक पटुता एव तनाव क वातावरण से मुक्त होकर अपने पर जायें क्षत्र म आपसी सहाई भगडे एव बिबाद न हा धोर नाग अधिवाश अच्छे पडोसी एव रिस्तदार बनकर अपना जीवन व्यतीत करें । यही कारण है कि लोकप्रदालत क्षेत्र म भगडा एव बिबादा की मर्या घटी है जबकि सरकारी यापालया की कार्य प्रणाली स बिबादा एव भगडा की मर्या म कमी का कोई लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता । उनके समक्ष प्रस्तुत हान वाल बिबादा एव मामलो की सख्या तजी स बढ़ती ही जा रही है ।

सरकारी यापालया मे बिबाद म सम्बन्धित तथ्या की जानकारी प्राप्त करने म यायाधीन को कई साल लग जाते हैं धोर अधिकांश बिबादो म पसना हान तक प्राय एव स अधिवाश बार यायाधीन बदल जात हैं । बिबाद की सुनवाई का मिलसिना अबाध गति से नहीं चल पाता । उसकी एकमूर्तता टूटती रहती है धोर यापालय प्रस्तुत गवाही एव तथ्या क आधार पर निणय दे देता है । जरूरी नहीं कि जिम यायाधीन के सम्मुख वादी प्रतिवादी न अपन बिबाद सम्बन्धी तथ्य गवाह के रूप मे पेश किय हा धोर वकीला ने जिरह करके ऐसे गवाहो से वाई तथ्य प्राप्त करने का प्रयास किया हो वही यायाधीन उस बिबाद के बारे म निणय भी दे । इस प्रक्रिया म हर यायाधीन के लिये वादी प्रतिवादी के मुह स बिबाद सम्बन्धी तथ्य सुनना आवश्यक नहीं है ।

सरकारी यापालयो मे प्रस्तुत अधिकांश बिबादो की सुनवाई जूरियो क सहयोग क बिना ही किये जान की व्यवस्था है । जुरी की नियुक्ति बहुत कम मामलो मे होती है जबकि नौकप्रदानत का वाई भी निणय एक व्यक्ति द्वारा

‘याय’ दिलाना भी उसके कार्यक्रम का अनिवार्य अंग है। इसीलिए उसने ‘याय’ दिलाने के लिये सरकारी अधिकारियों से मध्य किया है, सत्याग्रह का सहारा लिया है गिरफ्तारियाँ दी हैं, जमानतें करवाई हैं पुलिस थान में यातनाये नहीं है और समाचार पत्रों राजनतिक कार्यक्रमों तथा सावजनिक नेताओं का सहारा लेकर तक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखा है। लोक जागृति द्वारा जनसाधारण को अ याय के विरुद्ध संगठित होने की प्रेरणा उसकी अपनी विशेषता है जबकि सरकारी ‘यायालय’ इस प्रकार के किसी भी उपाय का अवलम्बन नहीं कर सकत चाहे अपराधी को दण्ड मिल या न मिल।

लोक अदालत एवं ग्रामदानी गावों की ग्राम सभाएँ

अब लोक अदालत एवं ग्रामसभाओं के पारस्परिक सम्बन्धों को लें। ग्रामदानी गावों लोक अदालत के संस्थापक एवं उसके संचालकों की वृत्ति है और इसीलिए ग्रामदानी गावों के समस्त बालिग लोगों से निर्मित ग्रामसभा लोक अदालत का अपना अभिन्न अंग है। अपने क्षेत्र के विवादात्मक तथे के निपटान का प्रयास करती ही है लेकिन पड़ोस के गैर ग्रामदानी गावों के लोगों के साथ भी यदि कोई झगड़ा हो रहा होगा तो उससे प्रतिकार के लिये भी वे प्रत्यक्षशील रहती हैं।

ग्रामसभाओं के निणय का स्वीकार नहीं किये जाने की स्थिति में ग्रामसभाएं एक पक्षवार बन कर स्वयं भी ऐसे विवादों का अदालत के समक्ष ले जाती हैं और लोक अदालत के निणय को शिरोधार्य करती हैं। कई मामले देखने में आये हैं जिसमें लोक अदालत ने ‘याय’ के लिये सामूहिक नेतृत्व प्रदान करके ग्रामसभा या उस क्षेत्र के शोषण एवं अत्याचार के शिकार निवासियों को ‘याय’ दिलाने का प्रयास किया है। इस प्रकार वह कबल स्वयं ही क्षेत्र की जनता को सही ‘याय’ उपलब्ध नहीं कराती अपितु सही याय प्राप्त कराने में उनकी मद्दगार भी बनती है।

लोक अदालत एवं ‘याय’ पचायत

लोक अदालत का ‘याय’ पचायतों से भी वैधानिक सम्बन्ध नहीं है। प्रकारान्तर से सम्बन्ध बनता भी है तो केवल यही कि ‘याय’ पचायत अपने क्षेत्र में कानून के जरिये सौंपे गये अधिकारियों के भीतर छोटे छोटे दीवानी व फौजदारी मामलों का निपटारा करती हैं जबकि लोक अदालत अधिक विस्तृत क्षेत्र में और अधिक पेचीदा एवं गम्भीर प्रकार के दीवानी फौजदारी विवादों का निपटारा करती है। ‘याय’ पचायत में सर्वानुमति की जगह निणय प्रक्रिया में बहुमत का प्राधान्य रहता है, जबकि लोक अदालत में यथा

शक्ति विवादा का निपटारा सर्वानुमति से किया जाता है। लोकअदालत में वादी-प्रतिवादी दोनों की भावनाओं की रक्षा करते हुए उन्हें संतुष्ट रखने का भरसक प्रयास भी किया जाता है ताकि उभय पक्षों में पारस्परिक कटुता समाप्त हो और तनाव की स्थिति दूर हो।

लोक अदालत—विवादों की सुनवाई सम्बन्धी स्थिति

जहाँ तक सुनवाई का अधिकार क्षेत्र का सम्बन्ध है सरकारी न्यायालयों की मूल्यानुसार विवाद सुनने का अधिकार है यथा मु सिफ 5 हजार रुपये मूल्य तक की सम्पत्ति या सन देन के दावे सुन सकते हैं और सिविल जज 5 से 10 हजार रुपये मूल्य तक के नन देन अथवा सम्पत्ति के दावे सुन सकते हैं पर लोकअदालत किसी भी मूल्य के दावे सुन सकती है। इसी प्रकार प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट का तीन साल तक की अवधि की जेल और 5 हजार रुपये तक के जुर्माने की सजा देने का और द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट की 1 साल तक की कैद और 1 हजार रुपये तक के जुर्माने की अधिकतम सजा देने का अधिकार है जबकि लोकअदालत किसी का सजा देना ही नहीं चाहती है। लेकिन यह सही है कि वह कैद से कहीं अधिक प्रभरकारी ढंग की सजा भले ही दे दें जिसमें जीवन पर्यंत या बीस साल की अवधि तक अपराधी को पीड़ित परिवार की स्वेच्छिक आधार पर मदद देने का प्रावधान रहा है। इसी प्रकार वह किसी भी सीमा तक जुर्माने की सजा दे सकती है। लेकिन उस सजा को भोगने की जवाबदेही दोषी व्यक्ति स्वयं अपने सिर पर लेता है उस पर किसी प्रकार का कानूनी बंधन नहीं रहता। इस प्रकार लोक अदालत एक से अधिक मजिस्ट्रेट की कोर्टों के कार्यक्षेत्र के उपयुक्त विवादों का निपटा सकती है जबकि सरकारी न्यायालयों के मजिस्ट्रेट अपनी सीमा रेखा में आगे नहीं बढ़ सकते।

जहाँ तक यायपचायता का सम्बन्ध है उनकी कार्य सीमा ता प्रत्यक्ष मकुचित एवं मर्यादित है। दोषी की मामला में वह अधिक से अधिक 250 रुपये तक के मूल्य के विवादों की सुनवाई कर सकती हैं। फौजदारी मामलों में वे जिन मामलों की सुनवाई कर सकती हैं उनमें 50 रुपये में अधिक दण्ड दोषी व्यक्ति को नहीं दे सकती। उन पर यह भी प्रतिबंध है कि वे ऐसे मामलों में विचार ही नहीं कर सकती जिनमें अपराधी को पहले किसी मामले में तीन साल या अधिक का कारावास का दण्ड दिया जा चुका हो अथवा दोषी व्यक्ति अभ्यस्त अपराधी हो अथवा दोषी व्यक्ति का पहला भी चोरी करने अथवा चोरी के माल का जानबूझकर रखने के अपराध में

पचायत या 'याय' पचायत द्वारा स्पष्ट दिया जा चुका है। प्रथम उस दायी व्यक्ति में स्पष्ट प्रक्रिया गहिता की धारा 109 और 110 के अधीन नवचलनी का मुचलना लिया जा चुका है।

साक्षरप्रदायत तथा सरकारी यायालय में विवाह ल जान एव उसकी निजय प्रक्रिया में पर्याप्त अंतर है और यही अंतर इस क्षेत्र के ग्रामीणजन का विवाद सुलभान के लिए साक्षरप्रदानत में ध्यान की प्रेरणा प्रदान करता है। सरकारी यायालय की कानूनी उलभनें अधिक व्यय एवं अधिक समय लगन वाली प्रक्रिया गांव के लोगों के लिए बड़ाता है। इसके अतिरिक्त लोक-प्रदायत में समाज परिचयन साक्षरप्रदायत और नैतिक मूल्य की स्थापना का जो प्रयास रहता है वह सरकारी यायालय में दायन का नहीं मिलता है। तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर यह कहने की स्थिति है कि साक्षर प्रदानत की समग्रता ग्रामीण 'याय-यवस्था' को नयी दिशा प्रदान कर सकती है और मौजूदा यायव्यवस्था की कठिनाइयों को कम करने में मददगार हो सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि लोकप्रदायत की अधिक व्यवस्थित किया जाए एवं उस राज्य के कानून के साथ संबद्ध करने के साथ साथ उन कमियां को दूर किया जाय जिनके बारे में अतिम अध्याय में उल्लेख किया गया है।

संदर्भ

- 1 भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डा. राजद्र प्रसाद ने डा. अमन जमाने के छोटी के वकील के नाम इंडिया के 6 अक्टूबर 1920 के अमन में लिखा था भारत में भूकदमे बाजी बहुत महंगा मामला है। 'यायालयों की सम्पूर्ण व्यवस्था और 'याय प्रदान करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया बहुत खर्चीली एवं व्ययसाध्य है। 'यायप्राप्ति और निजय की पूर्ति होने तक कभी-कभी बागी की विवादप्रस्त सम्पत्ति के मूल्य से भी अधिक धन राशि खर्च करनी पड़ जाता है।

दूसरे छोटी के वकील श्री भोतीलाल नहू ने लिखा था 'याय प्रक्रिया में लग हुए लोगों के नसिब घरालत में ऊपर से नीचे तब गिरावट घाती जा रही है। देश में चल रही भूकदमेबाजी की कार्यशाली ही उन अधिकार पापों के लिए जबाबदेह है जिनसे हम पीड़ित हैं—यंग इंडिया 13 अक्टूबर 1920।

भारत सरकार द्वारा याय पचायतों के लिये गठित अध्ययन दल की रिपोर्ट में जो अप्रैल 1962 में प्रकाशन हुई थी पृष्ठ 35 पर उल्लिखित वाक्य का अर्थलोकन कीजिय—एक गांव में उत्पन्न छोट से विवाद के निपटारे के लिये सम्बन्धित तहसील जिला है नवान्तर अधिकांश अथ कितनी दूरस्थ स्थान की अनागत में अपने प्रमाण में

कागजाना, गवाहों और कानूनी सलाहकारों के साथ अनिवाय उपस्थिति और कई कई दिन तक तारीखें पेशिया बदलने के कारण वहाँ ठहरने की मजबूरी जितने मूल्य की धनराशि का विवाद नहीं उससे अनुपात में नहीं अधिक खर्चा (याय को यह व्यवस्था निम्नेह आदश नहीं कही जा सकती) हमारी अदालतें सस्ती नहीं हैं।

- 2 उदाहरण के लिए देखें परिशिष्ट 5।
- 3 गुजरात के आन्निवासी प्रकाशक मजरात विद्यापीठ अहमदाबाद पृष्ठ 28।
- 4 देखें सम्बन्धित सारणी।
- 5 देखें श्री हरिबल्लभ परीख कान्ति का अक्षरणीय पृष्ठ 1 सबसेवा सभ प्रकाशन, 1973।
- 6 देखें सप्तम सारणी।

लोक जागृति और न्याय में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना

लोक अदालत लोक जागृति

प्रस्तुत अध्याय में हम निम्न बातों पर विचार करने का प्रयास करेंगे (क) लोकअदालत का कारण नाम जागृति की स्थिति (ग) लोकअदालत में लोकतांत्रिक मूल्यों का स्थान ।

लोकअदालत का कार्य और उसकी याव प्रक्रिया के सामाजिक प्रभाव की जो स्थिति है उसे देखते हुए यह कहना चाहेंगे कि लोकअदालत ने निश्चित तौर पर समाज में जागृति लाने में मदद की है । परम्परागत आदिवासी समाज में अन्यायकार महान की जो प्रवृत्ति रही है, उसमें ये लोग स्वभावतः ही बूढ़ों की भेनने के आदी बन गये ^१ । यहाँ के लोगी ^२ जो जड़ता थी उस काम करने का प्रयास लोकअदालत ने किया है । साक्षात्कार के दौरान जो तथ्य सामने आये हैं, उसके आधार पर इस बारे में कुछ निश्चिन्त बातें कही जा सकती हैं ।

इस सदन में तीन बातें उत्तरदाताओं ने स्वीकार की हैं—^३

- 1 सगठित होकर अध्याय का विरोध करते हैं ।
- 2 दोषी को दण्ड देने का प्रयास करते हैं ।
- 3 लोक अदालत में विवाद ले जाते हैं ।

यदि गांव में किसी प्रकार का अध्याय होता है तो इसका विरोध किया जाना चाहिये, यह विचार मजबूत हुआ है और उस अध्याय का विरोध करने की

अमता भी पदा हुई है। अ-याय कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे सरकारी कर्मचारियों का अ-याय पुलिस का अत्याचार, महाजना, किसानों या अ-य-य-र आदिवासियों द्वारा शापण आदि। अ-याय की दो श्रेणियाँ और भी मान सके हैं यथा—

- 1 उस प्रकार का अ-याय जिसका प्रभाव केवल व्यक्ति या परिवार पर पड़े, और
- 2 ऐसा अ-याय जिसका प्रभाव कई लोगों पर या पूरे ग्रामसमाज पर पड़े। सम्पूर्ण प्रभाव क्षेत्र में दाना प्रकार का अ-याय का विरोध करने की क्षमता विकसित हुई है। व्यक्तिगत स्तर पर ग्रामस्थों पर विवाद की ग्रामसभा या लोकप्रदात में ले जाया जाना पाया गया और ऐसे विवाद या अ-याय का जिसका सम्बन्ध पूरे ग्रामसमाज से होता है या जिस व्यक्तिगत प्रश्न को पूरे ग्राम का प्रश्न मान लिया जाता है, पूरा ग्राम विरोध करता पाया गया। इस प्रकार के अ-याय का विरोध पुलिस जंगल के कर्मचारी आदि के मदद में भी दृष्टिगोचर हुआ है। जहाँ सामान्य उत्तरदाताओं में से अधिकांश (97.24 प्रतिशत) ने स्वीकार किया कि अ-याय का विरोध करने की क्षमता प्राप्ति है, वही विशेष उत्तरदाताओं ने इस बारे में कम सहमति (29.03 प्रतिशत) प्रदान की है।

यह बात भी सामने आयी कि गांव के लोग दोषी व्यक्ति को दण्ड देने दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं। सहमति-असहमति की दृष्टि से यहाँ भी सामान्य एवं विशेष उत्तरदाताओं की स्थिति पूर्वोक्त जैसी ही है। जहाँ सामान्य उत्तरदाताओं में से अधिकांश ने इस बात में सहमति प्रकट की है कि दोषी व्यक्ति को दण्ड देने का प्रयास पहले से अधिक किया जाता है वहाँ विशेष उत्तरदाताओं ने उस सीमा तक इस तथ्य का स्वीकार नहीं किया है, यद्यपि इस बात की पुष्टि लोकप्रदात में होने वाली उपस्थिति कायवाही में भाग लेने की अभिरुचि एवं उसके निणय की स्वोच्छति के बारे में प्राप्ति तथ्यात्मक आँकड़ों से होती है। इस प्रकार इस बारे में भी ग्राम सहमति देखने में आयी कि अ-याय का विरोध करने में लोकप्रदात की प्रमुख भूमिका रही है।

जिस गांव के लोग अधिक जागरूक हैं (जैसे गजलावा), वहाँ ग्रामस्तर पर भी इस प्रकार के विवादों को सुलभान का प्रयास किया जाता है। यह भी देखने में आया है कि पड़ोसी गांव के लोग न पान के गांव में हुए

गान्धिया मर्या-26
 लोहपवात और मर्या के विरोध की गति

क्र.सं.	विवरण	गान्धिया या लोहपवात मर्या 435		विपक्ष लोहपवात मर्या 31		
		मर्या	प्रतिपक्ष	मर्या	प्रतिपक्ष	प्रतिपक्ष
1	लोक प्रगति के विरोध	423	9724	12	276	9
2	लोक प्रगति के विरोध	421	9678	14	122	9
3	लोहपवात के विरोध	429	9862	6	138	24
						7
						22
						70
						97
						22
						70
						97
						22
						7
						22
						58

आयाय के विरुद्ध आवाज उठाइए अब दोषी व्यक्ति को दण्ड देने का प्रयास किया।¹ सामान्यतः आयाय के विरुद्ध उठाये गये प्रत्येक मामले में लोक अदालत एवं आश्रम का सहयोग लिया गया।

आयाय का विरोध किए जाने के कारण आयाय में किस सीमा तक कमी हुई है इसकी माप अन्वेषण करना सम्भव नहीं है। फिर भी जो प्रश्न पूछे गये, उनके उत्तर से यह स्पष्ट है कि पुलिस के हस्तक्षेप में कमी कोर्ट में जाने की प्रवृत्ति में कमी जगल के अधिकारियों द्वारा परेशान किये जाने की घटनाओं में कमी—इनके सबब में राज्य की अभिवृत्ति यह सिद्ध करती है कि उनकी परेशानी कम हुई है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अब यहां के लोग अत्याचार करने वाले सरकारी कर्मचारियों से पहले जितने भयभीत नहीं हैं।

नीचे लिखी चार बातों के बारे में सहमति या असहमति बांटी गई थी—²

- 1 पुलिस के हस्तक्षेप में कमी आयी है।
- 2 कोर्ट जाने की प्रवृत्ति में कमी आयी है।
- 3 जगल के कर्मचारियों की परेशानी पहल से कम हुई है।
- 4 सरकारी अधिकारियों के सहयोग में वृद्धि हुई है।

मन्युस्क्रिप्ट तालिका (संख्या 27) से जो तथ्य सामने आये हैं, उस पर से यह स्पष्ट चित्र उभरता है कि वहां के लोग पर बाहरी दबाव कम हुआ है। सामान्य उत्तरदाताओं में से सभी ने उत्तर चारों बातों से अपनी सहमति व्यक्त की है लेकिन विशेष उत्तरदाताओं की स्थिति बाकी भिन्न है। उनमें से आमतौर पर 74 से 77 प्रतिशत द्वारा ही इन तथ्यों में सहमति व्यक्त की गयी है। कुछ लोग—19-35 प्रतिशत—ने इस बार में किसी भी प्रकार की राय जाहिर नहीं की है पर केवल गिन-चुन लोगों ने इस बात में असहमति व्यक्त की है कि गांधी में पहल की स्थिति में परिवर्तन आया है। लेकिन असहमति व्यक्त करने वाला न भी अपने मत के बारे में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं दिया है। ऐसा मान सकते हैं कि अधिक निबट मर्यादित हान के कारण उन्हें परिवर्तन नहीं दिखाई दिया है। पूरी तालिका के विश्लेषण पर से यह कहने की स्थिति है कि ऊपर बताई चार बातों का यहां के उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है। यह स्थिति दो बातों का ध्यान जाहिर करती है

तालिका सरया-27

लोकप्रदालत और अन्याय मुक्ति की दिशा

क्र०	प्रभाव	सामान्य साक्षात्कार सरया-435			विशेष साक्षात्कार सरया 31		
		सह्यति सख्या प्रतिगत	प्रसह्यति सख्या प्रतिगत	सह्यति प्रतिगत	प्रसह्यति सख्या प्रतिगत	उत्तर नहीं देने वाले सख्या प्रतिगत	प्रतिगत
1	मुक्ति हातपाय में कमी	435	100 00	00 00 00	24	77 43	1 3 22 6 19 35
2	कोट जाने की प्रवृत्ति में कमी	435	100 00	00 00 00	24	77 43	1 3 22 6 19 35
3	असलाह के अधिकारियों को पहले से कम परेशानी	435	100 00	00 00 00	24	77 43	1 3 22 6 19 35
4	सरकारी अधिकारियों के सहयोग में वृद्धि	435	100 00	00 00 00	23	74 20	2 6 45 6 19 35

- 1 लोकअदालत के कारण जिस प्रकार की जागृति एवं अध्याय का प्रति-
कार करने की क्षमता का विकास हुआ है, वह लोकशक्ति के विकास
एवं जन जागृति का प्रतीक है और इससे यहाँ के लोग में 'स्व शक्ति'
का भी विकास हुआ है।
- 2 गांव में सम्बन्ध रखने वाले कर्मचारियों एवं गैर आदिवासियों के द्वारा
शोषण एवं अध्याय कम हुआ है। इसे अध्याय मुक्ति का एक सफल
प्रयास कह सकते हैं।

याय में भागीदारी

लोकअदालत की वाय पद्धति से सम्बंधित अध्याय में हमने देखा कि लोक
अदालत की बैठक में काफी सग्या में लोग उपस्थित होते हैं और किसी न
किसी रूप में भाग भी लेते हैं। इसलिए याय व्यवस्था का लोकतांत्रिक दिशा
प्रदान करने का इसे एक सफल प्रयास कह सकते हैं। याय काय में लोक-
तांत्रिक मूल्य स्थापित करने का जो प्रयास लोक अदालत में किया जाता है,
उत्तम मुक्त प्रभावी तत्त्व निम्न है—

- 1 वादी-प्रतिवादी द्वारा निःसंकोच होकर निणय प्रक्रिया में भाग लेना।
- 2 दोनों पक्षों के गवाहों द्वारा लोक अदालत के सम्मुख सध्यात्मक जान-
कारी स्वयं रचना।
- 3 उपस्थित लोग को अपना मत व्यक्त करने की छूट होना।
- 4 मध्यस्थ (वकील) का अभाव।
- 5 जूरी द्वारा निणय।
- 6 स्वेच्छा से निणय की पुष्टि एवं स्वीकृति।
- 7 निणय की पूर्ति में जनमत का दबाव।

उक्त बातों के कारण लोकअदालत की याय प्रक्रिया में जिस प्रकार के
लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश हो गया है उसे मूल्य सरकारी यायालयों में
प्रतिष्ठापित नहीं हो पाया है। वहाँ दोनों पक्षों के गवाहों के प्रतिरिक्त प्रत्येक
लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ नहीं चलती और न इस प्रकार का खुलापन एवं
निःसंकोच होकर बात कहने की स्थिति रहती है। सरकारी यायालयों में प्रायः
सभी काय वकील द्वारा किए जाते हैं। यह सही है कि पंचायतीराज यन्त्रणा
के अंतर्गत गठित याय पंचायतों में एक सीमा तक लोकतांत्रिक मूल्यों का

स्वीकार किया गया है लेकिन याय पचायत का अधिकार क्षेत्र सीमित होने के कारण उसकी व्यापक स्वीकृति नहीं पायी जाती। सर्वोक्षित क्षेत्र में याय पचायतो द्वारा एक सीमा तक ही लोकतांत्रिक मूल्यों को स्वीकार किया गया है।

लोक-अदालत का स्थायित्व

सवाल उठता है कि ऐसे कौन से प्रभावी तत्त्व दृष्टिगोचर हुए हैं जिनके कारण यह समझा जाए कि लोकअदालत को स्थायित्व प्राप्त होगा? इस सम्बन्ध में सामान्य एवं विशेष दोनों प्रकार के उत्तरदाताओं से जो प्रश्न पूछे गये थे, उनसे लोकअदालत के स्थायित्व के सम्बन्ध में निम्न तथ्य सामने आये हैं—

- 1 हममें यहाँ लोगो का विश्वास है।
- 2 मंत्री एवं सस्ता याय प्राप्त होता है।
- 3 नीध्र याय मिलता है।
- 4 लोकअदालत के नाम एवं प्रक्रिया को ग्राम सभाधा ने अपना लिया है।
- 5 इसमें बानूनी भावना एवं दबाव का प्रभाव है।
- 6 इसे एक सेवाभावी व्यक्ति का नेतृत्व तो प्राप्त है लेकिन इसमें निरंकुशता नहीं है।
- 7 लोकअदालत की ठोस व्यवस्था का धीरे धीरे विकास होता जा रहा है।

ऊपर दी गई तानिका से उक्त बातों के बारे में सहमति या असहमति की स्थिति की जानकारी मिलती है। लोकअदालत से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित मामलों में उत्तरदाता उपरोक्त तथ्यों से सहमत हैं और इस कारण यह माना व्यक्त की जानी चाहिए कि लोकअदालत को स्थायित्व प्राप्त हो सकेगा।

लोकअदालत में श्री हरिवल्लभ परीय व प्रभावशाली नेतृत्व का हाथ हुआ भी यहाँ का सागा का विश्राम है कि यह कार्य उनकी अनुपस्थिति में भी चल पाता है। तानिका सारअदालत का अधिकांश बैठका में यह स्वयं उपस्थित रहते हैं और अधिक भाग लेते हैं फिर भी सागा में यह धारणा विश्राम जागृत हो रहा है कि वे उनकी अनुपस्थिति में भी सारअदालत का कार्य का

सफलतापूर्वक संचालन कर सकत है। लोकप्रदासत में किस सीमा तक स्थायित्व आया है, यह कहना अभी संभव नहीं है क्योंकि अभी तो अध्ययन की उपस्थिति का सर्वत्र पूरा प्रभाव पड़ता दिखाई देता है और केवल उत्तर दाताओं के आत्मविश्वास में ही भविष्य की स्थिति का सही अंदाज नहीं लगा सकते। जैसे तालिका में उल्लिखित कारण संख्या 1 2 3 ता वास्तव में लोकप्रदासत के प्रति लोगों की आस्था का प्रमाण हैं। स्थायित्व के प्रमुख कारण तो संख्या 4 5 और 7 का मानना चाहिए। यदि ग्रामसभाओं इस काम की प्रपना लेती है तो स्थायित्व की आशा की जानी चाहिए। परंतु प्राप्त जानकारी के अनुसार हमें दिशा में अभी तक आभाजनक सफलता नहीं मिल सकी है। सामान्यतया लोग केन्द्रीय लोकप्रदासत में विवाद सुलभान के लिए आतं दिखाई दिए। यदि ग्रामस्तर पर लोकप्रदासत की व्यापक रूप से स्वीकार किया जा सके तो यह इसके स्थायित्व की दिशा में निश्चय ही एक मजबूत कदम होगा।

उत्तरदाताओं ने हमके स्थायित्व के बारे में एक बात यह भी बतायी है कि इसमें कानून का स्वाद नहीं है और इसीलिए इसके स्थायित्व प्राप्त करने की अधिक संभावनाएँ हैं। उनका तात्पर्य यह है कि इसे जनस्वीकृति प्राप्त है और यह स्वेच्छा पर आधारित है और यदि यहाँ के लोगों को इसमें विश्वास है तो इसके स्थायित्व के बारे में आशा की जा सकती है। कानून एक दण्ड शक्ति के स्थान पर स्वेच्छा निर्णय स्वीकार किये जाने की प्रवृत्ति भी इसका संकेत है। यदि लोकप्रदासत में काय प्रक्रिया सन्ध की ओर व्यवस्था का विकास हो सके तो हमसे भी इसके स्थायित्व में मदद मिलेगी। यदि विविध प्रकार के विवादों में निणय के मुद्दे, निणय प्रक्रिया, निणय की पूर्ति की व्यवस्था आदि के संबंध में मजबूत ढाँचा बन सके तो लोकप्रदासत अधिक कारगर ढंग से काम कर सकेगी। हम यह स्वीकार करना चाहिए कि पिछले एक दशक से लोकप्रदासत के काय को प्रवर्धन करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके निणय की प्रक्रिया का विकास हुआ है साथ ही साथ माय एवं पूर्ति का भी स्वरूप निम्न रहा है। यहाँ यह भी स्वीकार करना चाहिए कि विशेष उत्तरदाताओं ने लोकप्रदासत की स्थायित्व की संभावना अपेक्षाकृत कम स्वीकार की है जबकि सामान्य उत्तर दाताओं का विश्वास है कि यह उसका स्थायित्व प्राप्त करेगी।

सारांश

लोकप्रदासत न माय काय के माय साथ ही क्षेत्र के लोगों में आत्मविश्वास को बढ़ाया है जिससे उनमें शोषण एवं भ्रष्टाचार का प्रतिकार

स्वीकार किया कि अध्यक्ष (श्री हरिवल्लभ परोष) का अनुपस्थिति में लोक अदालत चलती रहेगी। लेकिन प्रत्यक्ष अवलोकन एवं बातचीत के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि स्थायित्व का जो स्वरूप विकसित होना चाहिए था, उसका अभी अभाव दिखाई देता है। एक व्यक्ति के नेतृत्व की स्थिति एवं ग्राम स्तर पर इसका विस्तार की कमी के कारण इसका स्थायित्व के लिए अधिक प्रयत्नशील एवं जागरूक रहने की आवश्यकता है।

संदर्भ

1. नवें सम्बिधन सारिका।
2. दशैं श्री हरिवल्लभ परोष प्राति का अध्यापन पण्ड [, सब सेवा मय प्रकाश, 1973।
3. नवें श्री हरिवल्लभ परोष प्राति का अध्यापन।
4. दशैं मल्ल सारिका।

12

उपसंहार

मानव समाज के विकास के साथ-साथ उनके सामाजिक जीवन को संगठित एवं नियंत्रित करने वाली अनक सस्यामो एवं व्यवस्थाओं का भी विकास हुआ । इन सस्यामो में मुख्य है—विवाह, परिवार, धर्म, राज्य, आदि । ये सस्यामें सावभौमिक रही हैं चाहे देश एवं काल के अनुसार उनके स्वरूप में 'यूनान-धिक' भिन्नताएँ दणिगोचर होती हैं । सामुदायिक जीवन में व्यक्ति के पारस्परिक सम्बन्धों के आचरणों को नियमबद्ध करने वाली व्यवस्थाओं में 'यायिक' सस्या का मुख्य स्थान रहा है और इसकी सावभौमिकता भी सबविदित है । याय व्यवस्था के गचानन के लिए आदिकाल में ही मानव समाज ने 'याय' के कुछ नियमों का सहारा लिया है । विभिन्न देशों की भौगोलिक परिस्थितियाँ और उनके फलस्वरूप विकसित सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की भिन्नताओं के कारण नियमों में अंतर भन ही रहा हो लकिन आधारभूत नियमों का सभी जगह सादृश्य म्ना जा सकता है । इन आधारभूत नियमों में मुख्य य माने जा सकते हैं । जैन—(क) अपराधी को दण्ड मिले, (ख) ऐसे व्यक्ति को दण्ड न मिले जा निर्दोष हो (ग) 'यायालय' के सम्मुख सब समान हैं आदि । कानून एवं याय सामाजिक जीवन के अभिन्न अंग हैं । समाज में कानून का निर्माण नतिक्ता के पोषण के लिए होता है और इस प्रकार दोनों का निकट का सम्बन्ध है । जिस समाज में जितनी अधिक नतिक्ता होगी वहाँ कानून का पालन उतना ही अधिक होगा । यह देने में आया है कि सामाजिकता परम्परागत नियम नतिक्ता की भित्ति पर आधारित रह हैं ।

किमी भी देश की 'यायिक' सस्या के विकास को सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में दखा जाना चाहिए क्योंकि उसका विकास उसी परिप्रेक्ष्य में होता है । यायिक सस्या की मरचना 'याय' प्रक्रिया 'यायिक' मूल्य एवं दण्ड

आदि में सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता के कारण अंतर पाया जाता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय परम्परा एवं सामाजिक संरचना का ध्यान में रखते हुए ग्राम एवं ग्राम पंचायतों का कानूनी रूप देने का भी प्रयास किया गया है। गांधीजी ने भारतीय समाज में स्मृति एवं जन स्वभाव का ध्यान में रखते हुए पंचायतीराज का एक विचार रखा था। कुछ समाज सेवकों ने जिनके ऊपर गांधी विचार का प्रभाव था, ग्रामसेवा का कार्य प्रारम्भ किया। परन्तु यह कार्य पूर्णतया समाज सेवा से सम्बंधित था और इसमें राज्य या कानून के हस्तक्षेप का प्रभाव जनसहयोग विज्ञान एवं जन स्वीकृति की भावना विद्यमान थी। समाज सेवा के काम प्रयास में कुछ लोगोंने ग्राम पंचायतों को भी स्पर्श किया और मौजूदा ग्रामपद्धति की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर गांधी विचार के अनुरूप ग्रामपद्धति विकसित करने का प्रयास प्रारम्भ किया। इस प्रयास में यह ध्यान रखा गया कि यह भारतीय समाज के अनुकूल हो, समाज की समस्याओं को सुलझाने में मददगार हो और ग्रामीण समाज को मौजूदा ग्रामपद्धति की कठिनाइयों से मुक्ति दिला सकें। इसी परिप्रेक्ष्य में गांधीजी से प्रभावित होकर गांधी विचार के प्रति निष्ठा रखने वाले युवक श्री हरिवल्लभ परीस सन 1949-50 में समाज सेवा के काम में अग्रसर हुए और उन्होंने बड़ोदा जिला (गुजरात) स्थित छोटा उदयपुर तहसील के गगनपुर गांव में ग्राम सेवा का कार्य प्रारम्भ किया। ग्रामीण समस्याओं का मुनना एवं ग्रामस्वराज्य की स्थापना के प्रयास के दौरान बड़ा लोकप्रदालत समस्या का स्वतंत्र विकास होता गया। इस लोकप्रदालत ने अब तक हजारों छोटे-बड़े विवादों को सुलझाया है। इसका सघन कार्यक्षेत्र बड़ोदा जिला की दस तहसीलों में है—(1) छोटा उदयपुर और (2) नसवाडी। लोकप्रदालत एक ऐसी संस्था है जहाँ विभिन्न विवादों एवं समस्याओं का लाक्षणिक मूल्यों के अनुसार स्वेच्छा एवं पक्ष निर्णय से सुलझाया जाता है। लोकप्रदालत राज्य के कानून से प्रतिबंधित नहीं है।

लोकप्रदालत के लिये उद्देश्य दिखाई देते हैं

- 1 गांव के लोगों में स्वशासन की भावना का विकास एवं उसका अभ्यास कराना।
- 2 समाज के सभी वर्गों के लिए ऐसी सब सुलभ एवं सरल ग्रामपद्धति का विकास करना जिससे उन्हें सस्ता एवं शीघ्र ग्राम मिले।

लोकप्रदालत की नीचे लिखी विशेषताओं मान सकते हैं—

(क) इसकी सभी कार्यवाही खुले रूप में होती है। इसीलिए इसे घोषण

काट (open court) भी बहा गया है।

- (ग) विवेचन स्वल्प—यह सामान्य पर फल रहा है यद्यपि मीजुदा व्यवस्था में मुख्य बंदर सब स्थान पर है।
- (ग) पाय प्रक्रिया में लोकतांत्रिकता।
- (घ) निजय को स्वच्छता में स्वीकार करना।
- (ङ) राज्य व वानुजी बंधन का अभ्यास।
- (च) नीति एवं सत्ता पाय।
- (छ) स्वशासन का अभ्यास।
- (ज) पाय प्रक्रिया की सरलता एवं सहजता।
- (झ) मध्य की भाषा की पूरी गुंजायमान।
- (ञ) समानता एवं सामाजिक पाय।

2 लोकप्रदानत के बाय का फैलाव जिम क्षेत्र में है वह प्रादिवामी-प्रधान है इगतिम आन्विवासी संस्कृति की विवेकताओं ने भी लोकप्रदानत का प्रभावित किया है। इस क्षेत्र की गिरी हुई आर्थिक स्थिति सामाजिक उपस्था एवं शासन यहा के जन जीवन को दूभर बनात है। पाय के लिए आन्विवासी पचायत इह विरामत में मिनी है जिसमें लोकप्रदानत के लिए स्वत ही अनुकूल वातावरण उपलब्ध है। सामाजिक जीवन की विकट समस्याओं, प्रादिवामी समाज में व्याप्त अथ विद्वान और गलत एवं अमानवीय परम्पराओं में जहा लोकप्रदानत के बाय क्षेत्र की आवश्यकता को बढ़ाया है वहा यहा की आन्विवासी संस्कृति में दसवीं मायता एवं प्रतिष्ठापन के अनुकूल वातावरण प्रदान किया है। क्षेत्र की भौगोलिक संरचना, प्रादिवामी समाज की सामाजिक अवस्था और परम्परायें लोकप्रदानत के विकास में मददगार हुई हैं।

3 लोकप्रदानत के संगठन का किसी प्रकार का बना बनाया ढांचा नहीं है। आवश्यकतानुसार प्राप्त अनुभवों के आधार पर संगठन का विकास नमन स्वत ही हुआ है। इसके संगठन को ताल क्रम के अनुसार तीन वर्गों में बांट सकते हैं

- (क) चल लोकप्रदानत का संगठन।
- (ख) केन्द्रीय लोकप्रदानत का विकास एवं संगठन।

- (9) जूरी व निणय पर सभा द्वारा विचार और समाधान की घोषणा ।
- (10) करारखत का लिखा जाना ।
- (11) करारखत पर वादी प्रतिवादी, जूरी एवं अध्यक्ष के हस्ताक्षर ।
- (12) गुड वितरण ।

5 लोकप्रदालत के निणय को स्वेच्छा से स्वीकार किया जाता है । यही कारण है कि निणय की पूर्ति में ज्यादा कठिनाई नहीं होती । आमतौर पर लोकप्रदालत के निणय को तुरन्त ही त्रिया वित्त कर दिया जाता है । फिर भी कभी-कभी निणय की पूर्ति में कठिनाई आ जाती है । यह कठिनाई एक पक्ष के असताप, निणय के समय कुछ मुद्दों के छूट जान, व्यक्तिगत राग-द्वेष, किसी के बहुवाक्त्रे में आ जान आदि कारणों से होती है । इस कठिनाई को दूर करने में पचा की प्रमुख भूमिका होती है । पच इस बात का प्रयास करते हैं कि निणय की धाराओं की पूर्ति हो । करारखत में निणय की पूर्ति न की जाने पर की जाने वाली कार्यवाही का भी उल्लेख होता है । यदि निणय की पूर्ति नहीं होती तो वह विवाद दुबारा भी लोकप्रदालत में आ जाता है । लोकप्रदालत की कोई उच्च इकाई न हान के कारण उसके निणय के विरुद्ध अपील नहीं होती । हा, आमतौर के निणय के विरुद्ध के द्वीय लोकप्रदालत में सुनवाई अवश्य होती है । निणय की पूर्ति की दृष्टि से लोकप्रदालत के प्रति विश्वास और सामाजिक दबाव का विशेष महत्व होता है । यह प्रश्न निणय के पक्षस्वरूप प्रतिवादी को प्राप्त सतोंप की स्थिति से भी जुड़ा हुआ है । निणय के प्रति व्यापक सतुष्टि दखन को मिलती है । इस कारण उनकी पूर्ति सम्बन्धी समस्या नहीं देखी गयी ।

6 लोकप्रदालत के निणय की विभिन्न लोगों पर होने वाली प्रतिक्रिया के विषय में दा स्थितियां देखने में आयी । जो लोग लोकप्रदालत के साथ निवृत्त सम्पर्क में हैं और विवाद एवं हान वाले निणयों में मग्न है उनकी प्रतिक्रिया एक प्रकार की है—ये लोग लोकप्रदालत की सफलता का तुलनात्मक दृष्टि में अधिक मूल्यांकन करते हैं जबकि बिना उत्तरदाता जिनका लोकप्रदालत से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, इसकी सफलता एवं उपयोगिता का उतना महत्व नहीं देते ।

माटे तीर पर लोकप्रदालत के निर्णय के प्रति विभिन्न प्रकार के लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में ये बातें कही जा सकती हैं

- (क) निम्न के बारे में वादी-प्रतिवादी की सामाज्य प्रतिक्रिया यह देखने में आयी कि लोकप्रदालन में वाय मिलता है। संभव है कि संसदा उनका पक्ष में नहीं हुआ है। परन्तु वाय मिलता है उनका मन में भी यह विश्वास है।
- (ग) वादी प्रतिवादी के निकटवर्ती नात रिश्ते के लोग भी यह स्वीकार करते हैं कि यहाँ वाय मिलता है और खुली प्रदालन के कारण जूरी पक्षपात नहीं कर पाता—हो जूरीगण की राय में यथावदा मतभेद होता है लेकिन उस स्थिति में अतिम निर्णय सभा या अध्यक्ष करता है और विवाद का समाधान हो जाता है।
- (ग) सामाज्य उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि लोकप्रदालन की निम्न प्रक्रिया का अन्त में वाय मिलने का विश्वास मजबूत होता है।
- (घ) विधि साक्षात्कार वाले उत्तरदाताओं ने लोकप्रदालन के निम्न के प्रति एक सीमा तक गंभीर व्यक्त की है। लेकिन गंभीर वायजूद लोकप्रदालन की उपादयता उसके महत्त्व एवं उसका प्राप्ति सम्मान एवं मान्यता का उद्धान भी स्वीकार किया है।

7 लोकप्रदालन के कार्य का एक मुख्य पक्ष सामाजिक परिवर्तन का पारा का सही दिशा में भी रहा है। लोकप्रदालन का सामाजिक प्रभाव उगरी महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। आदिवासी समाज के सामाजिक पिछड़पन, उसमें व्याप्त अज्ञानता और प्रचलित गलत परम्पराओं एवं अंधविश्वास आदि का सही दिशा में एक समाप्ति करने की दिशा में लोकप्रदालन का प्रमुख भूमिका है। लोकप्रदालन की काम प्रक्रिया के द्वारा भी लोग को प्रत्यक्ष प्रशिक्षण मिलता है। इस लोक शिक्षण का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में देखने को मिलता है। शिक्षा एवं आर्थिक समृद्धि के क्षेत्र में भी कई उपलब्धियाँ देख सकते हैं। अंधविश्वासों में बड़ी प्रगति है यह गंभीर स्वीकार किया है। दूसरे साथ-साथ आदिवासी वाय व्यवस्था में जनभागीदारी की भूमिका भी बनी है।

8 विवादों की संख्या में कमी

प्रमुख परम्परा के आधार पर हम यह कहने की स्थिति में भी हैं कि लोकप्रदालन में वाय मिलने की संख्या में कमी को प्रदर्शित है। तालिका संख्या 29 में हम विवादों की तुलना हम कर सकते हैं।

तालिका सरया-30

विवादो की सरया मे कमी

वष	पजीवृत विवाद सरया
1972	577
1973	574
1974	340
1975	324
(नवम्बर तक)	

उपरोक्त दोनऱ तालिकाओ के आघार पर हूँ यह कहते की स्थिति मे है कि लोकअदालत मे आने वाले विवादो की सरया तो कम हुई ही है, साथ ही साथ लोकअदालत मे आने वाले कुल विवादो की सरया मे भी पिछले चार वषों मे कमी हुई है। वैसे उक्त आंकडो के आघार पर यह तो नहीं कहना चाहेंगे कि यह सरया बहुत उत्साहवधक है लेकिन विवादो की सरया मे कमी की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर अवश्य हाती है। विवादो की सरया मे कमी के निम्न मुख्य कारण देखने मे आये

- (क) आर्थिक विकास खासकर कृषि के विस्तार के कारण रोज के जीवन मे व्यस्तता बढी है।
- (ख) विवाह मे स्थायित्व के कारण तलाक सम्बन्धी विवादा मे कमी आयी है।
- (ग) भूत प्रेत डायन तथा अथ अथ विश्वासो मे कमी जातीय सदभाव मे वृद्धि शिक्षा मे विकास एवं सामाजिक जागृति के कारण भी इस प्रकार के विवादा मे कमी आयी है।
- (घ) ग्राम स्तर पर विवादो का सुलझान की प्रवृत्ति बढने के कारण भी विवादो की सरया मे कमी आई है।

के द्रीय लोकअदालत मे कम विवादो के आने का एक सूक्ष्म कारण यह भी दत्तन मे आया कि अध्यक्षा श्री हरिवल्लभ परीख के व्यस्त रहने के कारण लोकअदालत की बैठकें कम हो पाती है और कभी कभी दो बैठको के बीच

(3) सामाजिक परिवर्तन और लोक शिक्षण

समाज में परिवर्तन की सतत प्रक्रिया चलती रहती है। सामाजिक मस्याओं में परिवर्तन की इस प्रक्रिया को सही दिशा देने का प्रयास लोक शिक्षण के माध्यम से लोकअदालत करती रही है। 'याय' ऐसी संस्था है जहाँ सामाजिक व्याधियाँ से सम्बद्ध समस्याएँ विवाद के रूप में आती हैं। मौजूदा व्यवस्था में 'यायालय' इन विवादों को मात्र कानूनी एवं तकनीकी दृष्टि से सुलझाता है। लेकिन लोकअदालत विवाद के निणय में इस बात का ध्यान रखती है कि सामाजिक व्याधि समाप्त हो और सामाजिक परिवर्तन को सही दिशा मिले। जैसे पारिवारिक विघटन समाज में महिलाओं का स्थान, धर्म विश्वास शिक्षा आदि का सही दिशा देने का प्रयास।

(4) जनशक्ति का विकास

स्थानीय स्तर पर जनता की शक्ति का विकास हो, इसका प्रयास लोकअदालत द्वारा बराबर किया जाता रहा है। समाज में व्याप्त शोषण एवं गलत परम्पराओं का दूर करने के लिए जनशक्ति का विकास 'याय' व्यवस्था में लोकअदालत का महत्वपूर्ण योगदान है। 'यायालय' नागरिक चेतना की प्रक्रिया मजबूत करने में मददगार हो सकता है यह लोकअदालत ने सत्याग्रहों एवं घरनों के माध्यम से प्रमाणित करने का प्रयास किया है। इस सम्बन्ध में अधिक अध्ययन एवं अनुसंधान किये जान की आवश्यकता है।

(5) शारीरिक दण्ड से मुक्ति

अपराधी का दण्ड मिले, इस बात का स्वीकार करते हुए भी लोक अदालत शारीरिक दण्ड में आस्था नहीं रखती। बस मैदातिन रूप से भी 'दण्डशास्त्री' शारीरिक दण्ड के बारे में एक मत नहीं हैं। लोक अदालत अपराधी को 'शारीरिक' दण्ड न देने के साथ साथ इस प्रकार का वातावरण निर्माण करती है जिसमें अपराधी अपना अपराध स्वेच्छा से स्वीकार कर और अपनी भूल के लिए पश्चाताप अनुभव करे। पश्चाताप की इस उदात्त भावना से अपराधी का सुधार होता ही है यह लोकअदालत की मान्यता है। यह दण्डशास्त्र के क्षेत्र में लोकअदालत का महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है।

लोकअदालत की सीमा

- (1) लोकअदालत याय न क्षेत्र म एक प्रयोग है। इस बात को स्वीकार करत हुए भी इसकी कुछ सीमाए है। इन सीमाओं को दूर करने का प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि उसका क्षेत्र और व्यापक हो सके। लोकअदालत की जो सीमाए देखने म आइ, उन्हें दूर करने पर उसे अ य क्षेत्रो म भी विस्तृत किया जा सकता है और यह मौजूदा सरकारी यायव्यवस्था की बठिनाईया का दूर करने मे बड़ी सीमा तक मददगार हो सकती है।
- (2) इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विशेषता लोकअदालत के बाय की एक सीमा निर्धारित करती पायी गयी। लोकअदालत का सघन कायक्षेत्र अब तक आदिवासी मस्कृति तक ही विनोप रूप से सीमित रहा है। गैर आदिवासी समाज एव मस्कृति म इसका फनाव कम रहा है। मत गरआदिवासी समाज एव मस्कृति बाने क्षेत्र मे भी इस प्रकार के परीक्षण की आवश्यकता है। गरआदिवासी समाज एव मस्कृति आदिवासी समाज एव मस्कृति से काफी हद तक भिन्न है इस कारण वहा लोकअदालत का स्वरूप कुछ भि न भी हो सकता है।
- (3) परिस्थिति शास्त्रीय (Ecological) दष्टि से भी यह क्षेत्र सामान्य से भिन्न है। यहा की भौगोलिक परिस्थितिया जिस प्रकार की है उसम आर्थिक शोषण गरीबी एव पाश्चात्य सभ्यता स अप्रभावित जीवन पद्धति दखने की मिलती है जबकि गैरआदिवासी एव शहरी जीवन से प्रभावित क्षेत्र का जीवन भि न प्रकार है। ऐसे क्षेत्रो की सामाजिक, आर्थिक नतिक एव राजनतिक समस्यायें भी भि न है। इस परिस्थिति भिन्नता से लोकअदालत की एक सीमा बनती है और भि न परिस्थितियों म इसके प्रयोग को आग बढ़ाय जान की आवश्यकता भी सामने आती है।
- (4) जीवन की उलभनो की भिन्नता भी इसकी सीमा निर्धारित करती है। जीवन की जिस प्रकार की उलभन सवेंक्षित क्षेत्र म पायी जाती है वे अ य क्षेत्रो पास कर गरआदिवासी क्षेत्र म, नहीं है। यहा का पुन जीवन तलाक पुननिवाह स्थितो का स्थान, सहज एव सरल मान वीय स्वभाव इ ह अ य समाजो स भि न करता है।
- (5) ऐसा समाज जहा बहुत अधिक वानुनी उलभन है और जीवन मत्प त गतिशील है एव जहा व्यक्तिगत स्वाध का बोन-बाला रहता है यहा

लोकप्रदालन जिस सीमा तक सफल होगी, यह प्रश्न अभी तक अनुत्तरित है। यहाँ शिक्षा की कमी के कारण कानून की कम जानकारी है इसलिए अधिकांश लोग परम्परागत जीवन को स्वीकार करते हैं। शिक्षा के प्रसार से यह परिस्थिति बदल सकती है। शहर, धार्मिक संस्कृति एवं ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों की जीवन की उत्सर्गों एवं कानूनी दावों पेचों को ध्यान में रखकर भी बाय किये जान की आवश्यकता है। लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई खास प्रयास नहीं किया गया है। यही कारण है कि कस्बा, शहर एवं कानूनदा लोगों के मन में इस बारे में स्पष्टता नहीं है। यह स्पष्टता प्रयोग अभ्यास एवं क्षेत्र के विस्तार से आ सकेगी।

- (6) लोकप्रदालन की मौजूदा अवस्था भी इसकी सीमा दर्शाती है। इस समय लोकप्रदालन को विशेष व्यक्तित्व का नेतृत्व प्राप्त है जिसके कार्य के प्रति क्षेत्र के लोगों का विश्वास है और उसके प्रति भक्ति भी है। ऐसा विश्वास एवं भक्ति लोकप्रदालन के कार्य की एक सीमा मानी जा सकती है। हाँ वैसे यह प्रयास अवश्य चला है कि एक व्यक्ति के प्रति भक्ति लोकप्रदालन का आधार न बने और इसको एक याव्यवस्था के रूप में स्वीकार किया जाय लेकिन हम स्वीकार करना चाहिये कि अभी एक व्यक्ति के नेतृत्व का पूरा प्रभाव लोकप्रदालन पर दृष्टिगोचर होता है। एक व्यक्ति के नेतृत्व के प्रभाव के कारण इसके सस्थात्मक विकास की कमी देखने में आती है। इस कमी को दूर किये बिना लोकप्रदालन स्थायित्व नहीं प्राप्त कर सकेगा साथ ही साथ इसका सस्थात्मक ढांचा भी मजबूत नहीं हो सकेगा।

सुझाव

- (1) प्रस्तुत अध्ययन में जो बातें सामने आयी हैं, उसके आधार पर कुछ सुझाव दिये जा सकते हैं जो (क) लोकप्रदालन और (ख) सरकारी याव्यवस्था दोनों के लिये उपयोगी हैं। हमारा यह मानना है कि लोकप्रदालन के व्यापक प्रसार के लिये इसके प्रयोग क्षेत्र को विस्तृत किया जाय। लोकप्रदानत जैसी व्यवस्था के लिये आवश्यक है कि ग्राम क्षेत्रों में काम कर रहे ग्राम निष्ठावान समाज सबके भी अपने अपने क्षेत्रों में इस प्रकार के प्रयोग में लगे।
- (2) लोकप्रदालन की याव्यवस्था को अधिक विकसित एवं व्यवस्थित किया जाने की जरूरत है। इस दिशा में एक प्रयास तो यह किया जा

सबता है कि निणय प्रक्रिया में सामूहिक निणय को और बढ़ावा दिया जाय। इस कार्य में मदद के लिये यदि सम्भव हो तो, एक निणय संहिता का भी निमाण किया जाय जिसको आधार मानकर ग्राम सभाओं द्वारा अपने अपने क्षेत्र में विविध प्रकार के विवादों का निणय दिया जा सके। इससे स्थानीय नेतृत्व की मदद मिलने के साथ साथ जूरीगण को भी निणय लेने में मदद मिलेगी। यह निणय संहिता स्थानीय समाज व्यवस्था परम्परा, कानून एवं नैतिकता के आधार पर बनाई जा सकती है और इसमें कानूनविद एवं समाजशास्त्रियों की भी मदद ली जा सकती है।

- (3) लोकप्रदात के केन्द्रीय एवं ग्रामस्तरीय दाना कार्यालयों को अधिक व्यवस्थित किया जाय ताकि विवादों और उनके निणयों के बारे में और अधिक जानकारी रखी जा सके। अभी जो रकॉर्ड रखे जाते हैं वे भी पूर तौर पर नहीं रखे जाते, ऐसा हम महसूस हुआ है।
- (4) लोकप्रदात की व्यवस्था को स्थायित्व देने की दृष्टि से आवश्यक है कि इसे ग्रामस्तर पर विवेचित किया जाय और यह एक माय व्यवस्था के रूप में ग्रामस्तर पर स्वीकृति कर ली जाय। इस दिशा में अभी काफी प्रयास की आवश्यकता है ताकि इसका सस्यात्मक ढाँचा मजबूत हो सके।
- (5) इस दृष्टि से लोकप्रदात के कार्य एवं प्रक्रिया के अनुकूल सबल स्थानीय नेतृत्व विकसित किये जाने की भी आवश्यकता है। जैसे ता इस बात को सब स्वीकार करते हैं कि स्थानीय नेतृत्व विकसित हुआ है फिर भी गाँव गाँव में इस कार्य के अनुरूप नेतृत्व विकसित करने की आवश्यकता कम प्रतीत नहीं होती। लोकप्रदात का बैठक के दौरान स्वाभाविक रूप से इसकी कार्य प्रक्रिया सम्बन्धी प्रशिक्षण तो मिलता है लेकिन यदि समय-समय पर स्थानीय नेतृत्व को इस काम में प्रशिक्षित करने के लिये निविरो का आयोजन किया जाय तो वह और भी अधिक उपयोगी हो सकता है।
- (6) लोकप्रदात की व्यापक स्वीकृति की स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक लगता है कि इस काम में ऐसे लोगों का भी सहयोग लेना चाहिये जो न केवल कानून के जानकार हों बल्कि जो लोकप्रदात की भावना को भी भली भाँति समझते हों। इससे इसका क्षेत्र विस्तृत

किय जाने में मदद मिलेगी ।

- (7) लोकन्यायालय ने दण्ड का जिस ढंग से मानवीकरण किया है वह अपराध एवं दण्ड शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान है । इसका लाभ मौजूदा यायव्यवस्था को भी मिलना चाहिये । यह दो प्रकार से हो सकता है —

(क) याय एवं व्यवस्था में लग सकने वाले लोकन्यायालय की कार्य प्रक्रिया एवं व्यवस्था में समझने के लिए यहाँ आना चाहिये । इस दृष्टि से याय व्यवस्था में लगे लोगों के लिए यहाँ शिबिर एवं सेमिनार भी आयोजित किये जा सकते हैं और उनमें वकील यायाधीश जेल के अधिकारी कमचारी एवं पुलिस अधिकारियों को आमंत्रित किया जा सकता है ।

(ख) लोकन्यायालय क्षेत्र को जेल की सजा भुगत रहे लोगों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र बनाया जा सकता है । जिन कैदियों के लिए खुली जेल की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया है, उन्हें यहाँ भेजा जाना चाहिये और खुली जेल का एक प्रयोगात्मक केंद्र यहाँ चलाया जाना चाहिये, ताकि लोकन्यायालय द्वारा जिस ढंग से विवादग्रस्त पक्षों के मानस को बदल कर आपसी तनाव घटाने एवं पारस्परिक सहानुभूति बढ़ाने के प्रयास किये गये हैं, उनकी जानकारी उन कैदियों को भी मिल सके और वे अपना भावी जीवन अधिक मधुरता एवं सहज भाव से बिता सकें ।

- (8) लोकन्यायालय द्वारा दिये गये दण्ड दोषी व्यक्ति के साथ किये जाने वाले व्यवहार याय में मानवीय एवं सामाजिक मूल्यों का स्थान आदि बातों को सरकारी याय एवं दण्ड व्यवस्था किस रूप में और किस सीमा तक स्वीकार कर सकती है, यह भी एक विचारणीय विषय होना चाहिये । सरकारी न्यायालय विवाद के सामाजिक पक्ष को किस रूप में स्वीकार करें यह भी विचारणीय विषय है ।

- (9) सरकारी न्यायालयों की मुख्य कठिनाई याय कार्य में देरी एवं अधिक खर्चा है । लोकन्यायालय इन दोनों कठिनाईयों से मुक्त है । यही लोकन्यायालय का मुख्य आकर्षण भी है । सरकारी न्यायालय इन दोनों कठिनाईयों से मुक्त हो इस दिशा में प्रयास किये जाने जरूरी

है। लोकअदालत इसमें कई दृष्टियों से सहयोगी बन सकती है।
जैसे —

(क) अधिक से अधिक विवाद स्थानीय स्तर पर सुलझाये जायें, ताकि सरकारी न्यायालयों में ले जाये जाने वाले विवादों की संख्या घटे।

(ख) स्थानीय न्याय संस्थाओं को अधिक ॥ अधिक न्यायिक अधिकार दिये जायें और लोकअदालत की विशेषताओं को ग्रहण करके चलने वाली स्थानीय न्याय व्यवस्था सुदृढ़ एवं विकसित की जाये। इससे भोजपुरी न्यायालयों में विवादों की संख्या कम होने के साथ-साथ जन साधारण में स्वशासन की भावना भी विकसित हो सकती है।

(10) स्थानीय स्तर पर स्वशासन मजबूत बनाया जाना चाहिये इस बात का स्वीकार किया जाना चाहिये। गांधीजी के ग्रामस्वराज्य की कल्पना को नीचे की दृष्टि में स्वशासन हो और ऊपर की दृष्टि का विकास समुद्र की लहरों की भाँति है," मूल रूप देने का प्रयास किया जाना चाहिये।

(11) स्थानीय नवतृत्व के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे उनमें स्वशासन की योग्यता आये। पंचायतीराज के अन्तर्गत न्याय पंचायत की व्यवस्था है। प्रयागात्मक रूप में बड़ोदा जिले की न्याय पंचायतों का लोकअदालत के साथ जोड़ना चाहिये और इस न्यायिक दृष्टि से प्रयाग क्षेत्र बनाना चाहिये।

(12) सरकारी न्यायालयों की कठिनाइयाँ एवं समस्याएँ कम हों। इसके लिये प्रयागात्मक प्रयास किया जाय। इस प्रयाग के प्रथम चरण के रूप में ऊपर के सुझाव (सं० 11) के अनुसार लोकअदालत न्याय पंचायत एवं अन्य सरकारी न्यायालयों में तात्कालिक बैठकर विचारों व नीति निर्धारण के लिए जिना स्तर पर एक प्रयोगात्मक योजना बनाई जानी चाहिये। प्रयागात्मक योजनाओं को न्याय का विविध समस्याओं के साथ जोड़ा जाना चाहिये। हमारी राय में लोकअदालत के अध्यक्ष एवं इस काम में नये लोगों का इसमें पूरा महत्वाग लेना चाहिये। इससे लोकअदालत न्याय पंचायत एवं सरकारी न्याय व्यवस्था तीनों को नयी दिशा मिलेगी।

- (13) इस प्रयोग पर विचार करने के लिए सरकारी 'ग्रामालया' या पंचायत (पंचायती राज) लोकप्रदात के प्रतिनिधियाँ समाज शास्त्रियों एवं उच्चस्तरीय प्रतिनिधियों की बैठक बुनाया जानी चाहिये।
- (14) लोकप्रदात का जो स्वरूप विकसित हुआ है वह समाज सेवा कार्य में लगे लोगों के कार्यरिम्भ के लिए उपयोगी है। देश भर में ग्राम लोग ग्रामसेवा कार्य में लगे हैं और सुदूर गाँवों में समस्याओं के समाधान का प्रयास भी कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में विवाद सुलझाने का काम भी छोटे माट पैमाने पर चलता है। लेकिन यह कार्य लोकप्रदात की भाँति व्यवस्थित नहीं है। ग्राम प्रदाता में भी ग्रामजनों क्षेत्रों में विवादों का स्थानीय स्तर पर सुलझाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ के कार्यकर्त्ता यहाँ के प्रयाग एवं अनुभव का लाभ ले सकते हैं और अपने क्षेत्र में इस प्रकार की 'ग्राम पद्धति' को विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं।
- (15) लोकप्रदात की व्यवस्था आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों में विशेष रूप में उपयोगी हो सकती है। इससे क्षाण्य एवं सामाजिक अंधविश्वास में कमी आने के साथ-साथ उनमें स्वायत्तता की क्षमता का विकास भी होगा और आर्थिक विकास का भी गति मिलेगी। जिन आदिवासी क्षेत्रों में समाज सेवा में लगे हुए निष्ठावान कार्यकर्त्ता हैं, वहाँ इसका विकास सहज हो सकता है। निःस्वार्थ सेवा की भावना, प्रभावशाली नेतृत्व एवं ठोस कार्य में विश्वास इस प्रकार के कार्य को बढ़ाने के लिए आवश्यक है।

परिशिष्ट

परिशिष्ट में लोकप्रदालत के निणय समस्याया के समाधान के लिये किये गये प्रयास एवं करार खत के नमूने नीचे लिखे क्रम में दिये गये हैं

परिशिष्ट (क)

इसमें अध्ययन दल की मौजूदगी में लोकप्रदालत में जो विविध प्रकार के विवाद आय उनके नमूने दिये गये हैं। साथ ही कुछ अन्य विवादा की स्थिति एवं लोकप्रदालत द्वारा दिये गये निणय सम्बन्धी जानकारी भी संक्षेप में दी गई है।

परिशिष्ट (ख)

इसमें सरकारी मायालय में गये कुछ विवादा के संक्षिप्त नमूने दिये गये हैं।

परिशिष्ट (ग)

लोकप्रदालत द्वारा किये गये सामाजिक कार्य, क्षेत्र में अत्याय के ग्रहितात्मक प्रतिकार सम्बन्धी समस्याएं एवं उसके समाधान के लिये किये गये प्रयास एवं सत्याग्रह के कुछ नमूने दिये गये हैं।

परिशिष्ट (घ)

इसमें लोकप्रदालत के निणय (करार खत) के कुछ नमूने दिये गये हैं।

परिशिष्ट 'क'

लोकअदालत में निर्णित विवादों के नमूने

1 'क' न शिकायत पत्र की कि उसका पति 'ख' उसे खाना नहीं देता उसके साथ मारपीट करता है और बातचीत भी नहीं करता। लड़की पति के पास रहना चाहती है। उसके तीन साल का एक बच्चा भी है। 'ख' चुप रहता है। सभी उपस्थित लोग उसे समझाते हैं। समाधान सुझाते हैं कि तलाक की स्थिति में 'ख' 'क' को पेंसा देगा लेकिन बच्चा 'ख' के पास रहेगा। 'क' के दिमाग पर बच्चे के बिछुड़ने का डर है। आखिरकार लोकअदालत ने सारे विवाद पर विचार करके उसी दिन निर्णय दिया कि 'ख' पत्नी का साथ रहे। उसे खाना दू मगहा न करे और उससे दूर चले। बरार-खत लिखा गया जिस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हुए।

इस पूरी कायदाही से हम निम्न निष्कर्ष पर पहुँचे —

- (क) 'क' और 'ख' दोनों की बात बड़ी गति से सुनी गयी और दोनों न निडर होकर अपने विवाद की मुख्य बातें लोकअदालत के समक्ष पेश कर दी।
- (ख) दोनों के माता पिता का विवाद के बारे में अपनी अपनी बातें कहने का पूरा मौका मिला।
- (ग) उपस्थित लोगों ने जिनमें अधिकांश पड़ोसी एवं गाँव के रिश्तेदार थे, 'ख' को समझाया।
- (घ) दोनों पक्षों की ओर से नियुक्त चारों जूरियाँ ने सबसे श्रेष्ठ निर्णय दिया कि 'ख' 'क' को तलाक देना ही जरूरी माने तो उसे 'क' को रकम देने पर तैयारी लेकिन सर्वोत्तम बात यह रहे कि 'ख' 'क' का अपने प्रेम से रहे।

इस निर्णय में वही भी आपसी तनाव बहानों की स्थिति नहीं दिखाई दी। निर्णय देने में उनकी दृष्टि इस तथ्य की ओर केंद्रित रही कि 'क' और

ख' दोना छोटी सी बात को लेकर सम्बन्ध विच्छेद न करे अपितु एक दूसरे की कठिनाई को समझें और आपसी तारनम्य बठाकर सुख के साथ जीवन बिताना सीखें ।

इस सुनवाई की दूसरी विशेषता यह थी कि 'क' और 'ख' दोना ने अपनी गलती स्वीकार की । 'क' ने कहा कि उसने पति द्वारा धक्का मारे जाने की बात गलत रिपोर्ट की थी ता 'ख' न पत्नी के साथ किय गये दुर्व्यवहार के लिये क्षमा मांगी । अध्यक्ष ने निणय सुनाने के बाद उपमहाराज प्रेरणादायी भाषण देकर महिला जाति का सम्मान करने की और पारिवारिक जीवन को तनाव रहित व प्रेम पूर्ण बनाय रखने की अपील की और बताया कि जरा-जरा सी बात पर तनाक लेकर जीवन बिगाड़ना उचित नहीं है ।

इस विवाद का एक और पहलू भी था । वह यह कि विवाद का ग्रामदानी गावो से सम्बन्धित था— 'क' और 'ख' दोना के परिवारजन मलग मलग गावा के थे लेकिन ग्रामदानी गावो की ग्रामसभाभागा न मामल पर स्वयं निणय न देकर लोकअदालत के समक्ष इस विवाद को निणयाय प्रस्तुत किया था ।

(2)

दूसरे विवाद का निर्णय लोकअदालत उसी दिन नहीं कर पायी । विवाद यह था कि 'क' को अपनी पत्नी व' धाचरण के बारे में ठोस एवं प्रामाणिक शका थी और एक बार उसकी पत्नी अपने जेठ व' साथ दुष्कर्म में लीन पकड़ी भी गई थी और ग्रामसभा ने बड़े भाई पर 400 रुपये दंड निर्धारित करके वह घनराशि 'क' को दिलवाई थी । 'क' को शिकायत थी कि इस घटना के बाद भी पत्नी का धाचरण ठीक नहीं रहा है और उसके विवाह को पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी बाल बच्चे नहीं हुए हैं । पत्नी न शिकायत की कि पति ने दवा खिलाकर दो तीन बार गर्भपात कराया था । उसने यह भी कहा कि वह पति के पास रहना चाहती है लेकिन पति नहीं रखता है ।

लोकअदालत की बैठक में उपस्थित लोगो ने पत्नी की गलती मानी लेकिन साथ ही 'क' को भी समझाया कि वह पत्नी को सुधार का एक मौका और दे ।

जुरी की नियुक्ति की गई । जुरी ने त्वा खितावर गर्भपात कराने की पत्नी की शिकायत गलत मानी लेकिन फिर भी जुरी दोना पक्षों में पारम्परिक समाधान कराने में असफल रहे । 'क' के मन में पत्नी के धाचारे के प्रति अविश्वास बना ही रहा और पत्नी का मानस भी जुरीगण को माफ नजर नहीं आया । जुरी भी एकमत नहीं हो सके । एक जुरी न 'क' का पक्ष

घोर 40—50 रुपये पत्नी को देकर उस तलाक देने का आग्रह रखा। घ य तीन जूरियो की राय उससे भिन्न थी। बाद में उस जूरी ने स्वीकार किया कि वह एक पक्षीय भूमिका निभा रहा है जो जूरी के सिद्धांत एवं व्यवहार के विरुद्ध है इसलिये उसे जूरी से अलग किया जाय और भूल के लिये उसे क्षमा किया जाये। लेकिन फिर भी विवाद नहीं निपट पाया क्योंकि क' ने लोकप्रदालत से कुछ समय दिये जाने की मांग की। उधर पत्नी तत्कालिक निणय किये जान पर जोर देती रही। अध्यक्ष ने समाधान खोजने के लिये अगली सारीख दे दी।

(3)

दो पक्षों में इजिन की खरीद-बिक्री की रकम के लेन-देन के प्रश्न पर विवाद उठ खड़ा हुआ। लोकप्रदालत ने हिमाचल कृषि का निरीक्षण किया और इजिन खरीदने वाले को बाकी रकम कितनी में भुगतान करने का निणय देकर विवाद का निपटारा कर दिया।

(4)

क ने ग्राम सभा में गिकायत की कि ख ने उसे डायन कहा है। ग्रामसभा ने ख पर 80 रुपये का जुर्माना किया और भविष्य में क को डायन न कहने का निर्देश दिया। लेकिन ख ने क को न केवल डायन कहकर परेशान करना जारी रखा बल्कि उसे मारा पीटा भी और उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कर दी। क ने लोकप्रदालत के समक्ष अपनी गिकायत रखी। लोकप्रदालत ने पुलिस को पत्र भेजा कि वह क' को इस सम्बन्ध में परेशान न करे और लोकप्रदालत को इस विवाद के निपटारे में सहयोग दे। उस बैठक में मामला अनिणित रहा। अगली बैठक में समझौता हो गया और क' ने अपनी गलती स्वीकार कर आगे से ऐसा न करने की प्रतिज्ञा ली।

(5)

क की शादी 'ख' के साथ 1970 में हुई थी। पत्नी को गिकायत थी कि पति की सूरत शक्ल एवं व्यवहार उसे पसन्द नहीं है इसलिये वह तलाक चाहती है। फलतः ग्रामसभा ने तलाक स्वीकार कर दिया, लेकिन पति को सतोष नहीं हुआ। इसलिये क' ने लोकप्रदालत के समक्ष मामला प्रस्तुत किया। लोकप्रदालत दोना पक्षा की बातें सुनकर समाधान किया कि क आज से 15 दिन के भीतर भीतर ख' को 525 रुपये दे और

ख' उसको तलाक दे दे। 'ख' ने भा इस निणय को स्वीकार कर लिया।

क' ने उसी दिन य' को दण्ड की रकम द दी और पड़ोसी गांव के एक युवक से गान्धी करके उसके साथ चली गई।

(6)

क' अपनी पत्नी ख' के साथ दुर्व्यवहार करना था इसलिये ख' अक्सर अपने पीहर चली जाया करती थी। पारस्परिक तनाव बढ़ रहा था और लोकप्रदात क समझ मामला पक्ष हुआ तो पक्षी ने निणय दिया क 'ख' को परेशान करना बंद करे और अच्छी तरह रखे। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो 'ख' की तलाक की प्रार्थना स्वीकार कर ली जायेगी। पक्षी के निणयानुसार ख' ने भी यह इकरार किया कि वह भविष्य में अपने पति से बिना अनुमति प्राप्त किये पीहर नहीं जायेगी और अगर गई तो दण्ड देने की जिम्मेदार होगी।

(7)

क (पति) और 'ख' (पत्नी) में अक्सर मारपीट होती रहती थी। लोकप्रदात ने निर्णय दिया कि क' भविष्य में 'ख' के साथ मारपीट नहीं करे और उसे परेशान करना बंद करे। यदि वह ऐसा न करेगा तो उसे दण्ड देना होगा। ख' ने निर्णय स्वीकार करके करारखत पर यह लिख दिया कि आज के बाद वह क' को दवा खाकर मर जान को नहीं बहूगी और यदि वह ऐसा बहेगी तो पक्षी द्वारा दिया गया दण्ड उस स्वीकार होगा।

(8)

रगपुर गांव की एक महिला ने पिता की जमीन में हिस्सा प्राप्त करने के लिये सरकारी न्यायालय में आवेदन किया। 18 महीने का लम्बा प्रसंग बीत जाने पर भी उसे सरकारी न्यायालय से किसी प्रकार का निर्णय प्राप्त नहीं हुआ तो उसने लोकप्रदात की शरण ली। लोकप्रदात ने उसका भाई को, जो दूसरा पक्ष था, बुलाकर सबसम्मत निणय दिया कि महिला को पिता की जमीन में हिस्सा दिया जाय। उस महिला के समुदाय में उसने पति की भी जमीन है। अब वह दाना जगह खेती करती है और पीहर बान गाय रगपुर में स्थायी तौर पर रहती है। लोकप्रदात का निर्णय गीघ्र ता हुआ ही लेकिन सरकारी न्यायालय में जान के पत्रस्वरूप बहिन एवं भाई का कटुता एवं तनाव का वातावरण पैदा हो गया था। लोकप्रदात ने स्थान पर दोनों पक्षों में सौहार्द एवं स्नेह का भाव भी सुदृढ़ कर दिया।

(9)

एक व्यक्ति 'क' ने अपना खेत ख के पास रहन रख दिया। चार साल बाद उसने ख की रहन की रकम देकर अपना खेत वापस लेना चाहा तो 'ख' ने इकार कर दिया। क न सरकारी यायालय की शरण ली। काफी समय बीत जान के बाद भी सरकारी यायालय से धाय नहीं मिला तो वह लोकअदालत में आया। लोकअदालत ने निर्णय दिया कि ख 'क' से रहन की रकम लेकर उसका खेत वापस कर दे। 'ख' न खेत वापस कर दिया। अब 'क' उस खेत में धाराम से खेती कर रहा है। लोकअदालत के नैतिक प्रभाव और सामाजिक धाय-भावना के कारण ही ख न क की जमीन आसानी से वापस कर ले। अथवा सरकारी यायालय के माध्यम से क का जमीन वापस पाने में पता नहीं कितना धन एवं समय बरबाद करना पड़ता और फिर भी निणय उमक पक्ष में होता या बिपक्ष में इसकी कोई गारण्टी नहीं थी।

(10)

रगपुर ग्राम में जमीन के मामले को लेकर क की ख से मारपीट हो गई। मारपीट की रिपोर्ट पाने में दज बरा दी गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अतः मामला लोकअदालत के समक्ष प्रस्तुत हुआ। 150 व्यक्ति उपस्थित थे। अदालत ने निणय दिया कि वाली जमीन प्रतिवादी के सुपुद कर दे क्योंकि उभका हक है और प्रतिवादी वादी को 120 रुपये भरे।

(11)

रगपुर के क का जमीन के मामले को लेकर ख से विवाद हो गया। एक साल तक यायालय में विवाद चला लेकिन फसला नहीं हो सका। लोक अदालत ने एक ही पेशी में निणय दे दिया जिसके अनुसार वादी को उसकी जमीन वापस मिल गयी एवं प्रतिवादी को 2850 रुपये मिल गये।

(12)

मोटावाटा के 'क' का जमीन के मामले में ख से विवाद हो गया। मामला सरकारी यायालय में प्रस्तुत किया गया लेकिन निणय नहीं मिल सका। लोकअदालत ने दो पेशियां में मामले की सुनवाई करके जमीन प्रतिवादी को दिलवा दी और वादी का उसका पैसा मिल गया।

(13)

मोटावाटा के 'क' ने अपनी जमीन 'ख' के पास गिरवी रखी थी लेकिन

उमन 'ग' का उम मेन म बुझाई नहीं करन दी । तारमदानन न निणय दिया कि क' 'ग' को 2029 काय न्या तब जमीन उम वारन मिल जायगी ।

(14)

मेरवा की क' ने अपन पति की मृत्यु र पाश्चात उसकी जमीन पर धरना हुन प्रस्तुत किया । दो बार सारीग्रे पढी । पति क' ध य रिश्तदारा क मुकाबल म पत्नी का जमीन सम्बन्धी हुन स्वीकार किया गया । 150 व्यक्तियों की उपस्थिति म लाकमदानन र जमीन मन्त्र की पत्नी का निवेदन थी ।

(15)

जाफ़ा क' का भाइया—'क' और ग' म जमीन क बटवार क मवान को नकर निवात उपस्थित हो गया । तारमदानन न 150 व्यक्तियों की उपस्थिति म दाता भाइया म विवातग्रस्त जमीन का बराबर बराबर बटवारा करा दिया ।

(16)

जाफ़ा का क' सरकारी सत की जमीन लेना चाहता था । उसी भूमि का भूमिहीन किमान भी लेना चाहत था । इन्ही क' हुन की जमीन थी । 150 व्यक्तियों की उपस्थिति म लाकमदानन र निणय दिया कि क' सरकारी जमीन न ले । बरार मन पर क' ने हुस्ताक्षर कर न्यि और भूमि हाना क पक्ष म अपना हुन छाड़ दिया ।

(17)

क' अपनी पत्नी को शराब पीकर पीटता था । तीनअनलत क समक्ष मामला प्रस्तुत हुआ तो उसन निणय दिया कि क' अपनी पत्नी को नहीं पीटगा और यदि पाटगा तो उसकी पत्नी को उसका घर छोडकर दूसरा घर बसान का अधिकार मिल जायगा । उमन लोकअदालत के समक्ष बरार-खत पर हुस्ताक्षर कर न्यिे तकिन बाट म पत्नी के साथ पुन मारपीट की । उसकी पत्नी घर छोडकर चली गई और दूसरा विवाह कर लिया ।

(18)

क' ने अपनी पुत्रवधू के साथ शारीरिक सम्पर्क स्थापित कर लिया । मामला लोकअदालत के समक्ष प्रस्तुत हुआ और उस स्त्री का तलाक हो गया ।

बाप म 'ब' ने उस पुत्रवधू से बिवाह कर लिया और उस दूसरी पत्नी बना लिया ।

साकप्रदासत के निणय की उम्मा करने ब कारण आज समाज उस गिरी हुई नजर ॥ देसता है और उमरा जग माधारण मे बाई मात नहीं है । उमर माय सम्पत् करत हुए पढीमिया एवं ग्रामवासिया का नाम धानी है और सगात होता है । दोना ही ब एवं उसकी दूसरी पत्नी समाज मे उमेगा एवं सम्मानना का जीवन बिता रह है ।

(19)

'ब' गाव की एक लड़की का विवाह 'ब' गाव ब एक लड़के के साथ हुआ था । दोना परिवार म गहन एवं दहेज की संकर 3 4 मान तक भनयन एवं विवाद चलता रहा । लड़की के पिता न विवाद हुन बिय जाने का काफी प्रयास लेकिन बाई नतीजा नहीं निकला । साकप्रदासत के समक्ष प्रस्तुत किया । प्रतिवादी को साकप्रदासत द्वारा पत्नी के दिन उपस्थित होने म नियम आमत्रण भेजा गया लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ पुन आमत्रण भेजा गया । लड़की का स्वसुर उपस्थित हुआ लेकिन वह को घर ल जान के लिय महमति व्यक्त नहीं की । इस पर लोक प्रदासत ने निर्णय दिया कि लड़की का पिता लड़की के स्वसुर की चादी के ताकतें धान वाली कमल के पहन लीटा देगा । स्वसुर वह को घर लिया स गया । बरमा का विवाद महीने भर के भीतर निपटा दिया गया ।

(20)

'ब' पारिवारिक कसह के कारण अपने पति 'ब' के साथ नहीं रहना चाहती थी । मामला सरकारी न्यायालय मे 1½ सान तक चला लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ । हार कर लड़की वाली ने लोकप्रदासत के समक्ष मामला प्रस्तुत किया । दूसरी पेशी पर ही जो बिवाद प्रस्तुत बिय जाने के 15 दिन के भीतर ही रखी गई थी, लड़की को तलाक मिल गया और दोना परिवारों का पारस्परिक तनाव समाप्त हो गया ।

(21)

'ब' को उसने पति ने पारस्परिक तनाव की वजह से घर से निकाल दिया यद्यपि 'ब' ने उसको नो बच्चे हो चुके थे । लोकप्रदासत के समक्ष मामला निणयाय प्रस्तुत हुआ । लोकप्रदासत ने निणय दिया कि पति पत्नी को

900 रुपये ज़ुर्माना भ्रदा करे। क को तनाव मिन गया और उसने दूसरा विवाह कर लिया।

(22)

क' ने पुलिस थान म अपने पति 'ख' के विरुद्ध मारपीट का मामला दज कर दिया था लेकिन नतीजा नहीं निकला ता लोकभ्रदालत के समक्ष वह विवाद निणयाय आया। लोकभ्रदालत ने निणय दिया कि पति पत्नी को तनाव दे द। इस प्रकार गीछ ही निणय हो गया और तनाव भी समाप्त हो गया।

(23)

क' ने पत्नी को पीटा इसलिय पत्नी अपने पीहर चली गयी। सरकारी न्यायालय म विवाद चला लेकिन एक वर्ष बीत जान पर भी निणय नहीं हुआ। काफी खचा भी हुआ था। आखिर मामला लोकभ्रदालत के समक्ष पेश हुआ और 'क' की पत्नी का तनाव स्वीकार हो गया।

(24)

'क' को उसके देवर ने पीटा। उसके सिंग म ऐसी चोट लगी कि खून बहने लग गया। वह पीहर चली गयी। बाप ने 'क' के दवर के विरुद्ध सरकारी न्यायालय म फरयाद की लेकिन नतीजा नहीं निकला। आखिरकार उसने लोकभ्रदालत की शरण ली। देवर ने पत्नी के सामने माफी मागी। लोकभ्रदालत ने निर्णय दिया कि प्रतिवादी भविष्य म ऐसा नहीं करेगा और करेगा तो न्यायभ्रदालत 500 रुपये तक ज़ुर्माना ले सकती है।

(25)

गोयावाट गाव की एक लडकी 'क' का विवाह सात सान पहले हरिपुरा गाव के एक लडके 'ख' के साथ सम्पन्न हुआ था लेकिन 'क' सम्म भर्से से 'ख' से अलग रह रही थी।

लोकभ्रदालत के समक्ष विवाद प्रस्तुत हुआ। क' ने बताया कि 'ख' के साथ उसका कोई झगडा नहीं है लेकिन 'ख' का पिता (बसुर) उसे घुरी नजर से देखता है। दूसरे लोग की उपस्थिति म वह उस साडी म मुह ढका हुआ रखने के निये कहता है और मुह न ढकन पर भ्रमना भी करता है। लेकिन जब वह भ्रमना होता है तो वह मुह ढका रखने पर उसे डांटता रहता है इसी कारण वह पति के साथ नहीं रहती क्योंकि पति अपने पिता के साथ

है। यदि उसका पति अनग रहने लग जाये तो वह उसके साथ खुशी में रह सकती है।

'ख' के पिता ने लोकप्रदालन द्वारा सुनझाया गया समाधान स्वीकार कर लिया। समाधान के करारखन में लिखा गया कि यदि स्वसुर भविष्य में बहू पर कुदृष्टि रहता हुआ पाया गया और लोकप्रदालन के समक्ष इसका प्रमाण प्रस्तुत हो गया तो उसे 500 रुपये का दण्ड भरना पड़ेगा और अपनी पुत्रवधू पर उसके समस्त अधिकार सार्व हो जायेंगे।

'क' 'ख' के साथ स्वसुर से अलग मकान में रहने के लिए चली गयी।

(26)

'क' अघेड उन्न की महिला थी जिसके पांच बच्चे थे। वह बीमार पड़ी तो उसके पति 'ख' ने उसके इलाज के लिये एक साधू 'ग' की सेवायें प्राप्त की और 'ग' द्वारा ही गई जहा बूटियों के इलाज से वह कुछ भर्त्त बाद ठीक हो गयी। इलाज के दौरान 'ग' के मकान में रही और इस भर्त्त में 'क' और 'ग' में पारस्परिक प्रेम सम्बंध कायम हो गया। 'क' स्वस्थ होते ही अपने बपड़े लत्ते लेकर 'ग' के साथ रहने के लिये चली गयी। कुछ दिन बात किसी ने 'ग' की पिटाई कर दी तो 'क' ने लोकप्रदालन के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की।

लोकप्रदालन की बैठक में 'क' ने बताया कि जब 'ग' उसका इलाज करने के लिये उनके घर पर ठहरा हुआ था तो 'ग' की सहमति से उसके भवना द्वारा भेंट किये गये अनाज और पैसे से उनका घर का खर्च चलता था। उस स्वयं भी अक्सर 'ग' से रुपये उधार ले लिया करता था। एक दिन 'ख' ने 'क' से कहा कि वह जहा चाहे चली जाय लेकिन घर में कोई कार्य नहीं कर सकती। 'क' ने 'ख' से क्षमा भी मायी लेकिन उसने कुछ भी नहीं सुना और घर से धक्का देकर निकाल दिया। निकालने के साथ साथ वह भी कह दिया कि वह अपने पीहर नहीं जाये। उस स्थिति में 'क' के पास 'ग' के घर चली जाने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। वह 'ग' का कार्य करती थी और 'ग' उसका भरण पोषण करता था। इस बीच 'ख' दो बार बार 'ग' के घर पर भी आया और 'ग' से कुछ रुपया उधार लेकर चला गया। इस पर 'क' ने 'ग' से कहा भी कि वह 'ख' को पसा उधार न दे क्योंकि पैसा उधार से लेकर खान से वह सुस्त हो जायेगा। 'ग' ने 'ख' से यह भी कहा कि तुम 'क' को क्यों पीटा करते हो? उस ने जाग्रो और प्रेम से रन्नी लेकिन 'ख' ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस बीच 'क' की बहुत विषवा हा गयी। उसने तीन बार

बच्चे भी थे। 'ख' उसे अपने घर ले आया और अब वह उसके साथ रह रहा है। इसके बावजूद उसने 'ग' की पिटाई करवाई है और अब उससे दवाई के और उसके बदले में रुपये माग रहा है।

ख ने बताया कि उसने 'क' को नहीं निकाला। वह तो स्वयं 'ग' के पास चली गयी थी। यह सही है कि 'क' की विधवा बहन उसके साथ रह रही है और उसका और अपने बच्चों की देखभाल कर रही है और वह अब 'क' को साथ भी रखना नहीं चाहता। लेकिन उसने 'क' के पिता की दी गयी बहुज की धनराशि 'ग' से उसे दिखाये जाने की माग की।

'ग' ने कहा कि उसकी कोई गलती नहीं है। वह कबीरपथी साधू है और 'क' को अपनी स्वयं की मरजी से नहीं रखना चाहता है। 'क' स्वयं उसके पाम आई है। 'क' ने भी इस बात का समर्थन किया लेकिन ब्रठक में उपस्थित एक दो कबीरपथी 'ग' का मारने के लिये उद्यत हो गये। बड़ी मुश्किल से स्थिति शांत हुई।

जुरी की नियुक्ति की गई। सर्वसम्मति निर्णय हुआ कि 'ग' को 250 रुपये दण्ड राशि 'ख' को दनी पड़ेगी। 'क' चाहे तो 'ग' के साथ रह सकती है। 'ख' को 'क' की विधवा बहन के साथ रहने की अनुमति मिल गयी।

अध्यक्ष के अनुरोध पर दण्ड राशि 250 रुपये से घटाकर 200 रुपये कर दी गयी। 'क' की इस प्रार्थना पर कि जब वह अपने बच्चा को देखने 'ख' के घर आय तो वह उसे नहीं पीटे ख ने उत्तेजित होकर कहा कि वह उसे गांव में पैर नहीं रखने देगा।

इस पर लोकप्रदात न 'ख' को समझाया कि अब 'क' पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा है। इसलिये अब यदि वह बच्चों का देखने के लिये घर पर आय तो 'ख' उसका साथ प्रतिधि जैसा व्यवहार करे।

हसी के ठहारा के बीच लोकप्रदातन का समाधान स्वीकार कर लिया गया।

(27)

'क' ने अपने पति 'ग' के साथ रहना अस्वीकार कर दिया। उन कई बार समझाया गया लेकिन वह पति के पाम नहीं गयी। लोकप्रदातन में मामला पन हुआ तो 'क' ने बताया कि 'ख' के बड़े भाई की पत्नी ने उसके खाने में बाल डाल दिये थे और उस आंगना है कि वह किसी रोज उसको जहर भी दे सकती है। इसलिये वह इस घर में कभी नहीं जायेगी।

लोकप्रदातन में महमूम किया कि गलती 'क' की है। पत्नी की राय रही कि 'क' का पिता 350 रुपये धनराशि दे जिससे 'ख' को 325 रुपये दिये

जायें और 25 रुपये का मुद्द वितरण किया जाये ।

अततो गत्वा 300 रुपया 'ख' को दहेज के वापस लौटाये गये और 50 रुपये जुमले के रूप में लिये गये । 'व' ने अपने पैर में से 'ख' द्वारा दिया गया कड़ा निकाल दिया और तलाक सम्पन्न हो गया ।

परिशिष्ट 'ख'

सरकारी न्यायालयों में प्रस्तुत विवादों के नमूने

(1) 'क' का 'ख' से झगडा हो गया। गांव वाला ने 'क' को मामला लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने की राय दी। 'क' नहीं माना। मामला सरकारी न्यायालय में गया। मामले का फैसला होने में तीन साल निकल गए। 1100 रुपये से अधिक खर्च हो गये और दोनों ही पक्षों को अन्य असुविधायें भी भोगनी पड़ी। फैसला हो जान पर भी आपसी कटुता एवं तनाव बरकरार है।

(2) 'क' की पत्नी ने विवाह के पांच महीने बाद ही एक बच्चे का जन्म दे दिया। 'क' ने अपनी पत्नी के साथ डाट-डपट की और कहा कि यह बच्चा किसी और मर्द से हुआ है। पत्नी तान सुनत सुनत परेशान हो गयी। उसने बच्चे को नाले में फेंक दिया। सुबह चरवाहा ने बच्चे का शव देखा और गांव वालों को बताया तो गांव वालों ने पुलिस में खबर कर दी। पुलिस ने 'क' की पत्नी को गिरफ्तार करके उसका चालान न्यायालय में कर दिया। मुकदमें में 1000 रुपये खर्च हो गये लेकिन मामले का समाधान नहीं हुआ है।

(3) 22 साल के एक नौजवान ने दो भाइयों के खेत में घान की चोरी करली। दोनों भाइयों ने गुस्से में आकर चोरी करने वाले लड़के को मार डाला। सरकारी न्यायालय में मुकदमा चला। दोनों भाई न्यायालय में बिना दण्ड पाये बरी हो गए। खर्चा ज़रूर 6200 रुपये हो गया। मृत लड़के के बाप ने अपराधियों को सजा दिलाने के लिये 250 रुपये खर्च किये लेकिन रुपये के बल पर छाठ महीने के भीतर ही अपराधी बरी हो गये। गांव के लोग सच्चाई जानते हैं लेकिन अदालत के निर्णय के कारण चुप रहने के लिए बाध्य हैं।

(4) 'क' ने 'ख' के खेत से लकड़ी चुरा ली। सरकारी न्यायालय में मामला गया। 2 महीने तक केस चला। 'क' को 25 दिन की जेल

भुगतनी पडो और 200 रुपये खच हो गये ।

(5) दो भाइयो की जमीन गाव के दो व्यक्तियो न वनिय की मदद से अपने बन्जे मे करती । मामला तीन साल से सरकारी यामालय न चल रहा है । 2000 रुपये खच हो चुके है लेकिन अभी तक दाना भाइया को अपनी जमीन नहीं मिल पायी है ।

परिशिष्ट 'ग'

लोकप्रदालत और समस्याओं के समाधान का प्रयास

(1)

सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन

रतनपुर गांव की एक बहन नन्दा के पति मगाभाई गौहाई तीन वय पहले चल बस। नन्दा और तीन लड़कियां रह गयी। लड़का नहीं था। मगाभाई की 9 एकड़ जमीन थी जो परिवार के गुजारे भर के लिये काफी थी। मगाभाई के कोई भाई नहीं था, केवल एक बहन थी जिसकी बहुत पहले शादी हो चुकी थी। इस इलाके के आदिवासियों में अब तक ऐसी प्रथा रही है कि विधवा औरत अपने देवर या पति के छोटे भाई के साथ जीवन बिता सकती है। छोटा भाई न हो तो बड़े भाई के साथ दूसरी पत्नी के रूप में रह सकती है। इस रिवाज का उद्देश्य यह है कि परिवार की जमीन परिवार में ही रहे। अगर मत भाई की पत्नी इस प्रकार का व्यवहार पसंद नहीं कर तो उस परिवार से निकाल दिया जाता था।

नन्दा के पति की बहन शांति और बहनोई की नीयत नन्दा बहन की जमीन पर गई। उन्होंने नन्दा के घर में रहना शुरू कर दिया और खेत में भी काम करने लगे। उनके माथ लड़ाई-झगडा किया और पटवारी से मित्रकर शांति के पति न मगाभाई की जमीन पर अपना नाम दर्ज करवा दिया। मामला ग्रामनभा के मामल आया लेकिन ग्रामसभा इस प्रश्न पर बंटी हुई थी। एक दल परिवार की जमान परिवार में हो रहने के नाम पर शांति का जमीन का मालिक स्वीकार करने के पक्ष में था तो दूसरा इसे सामाजिक अनाय मानकर यह चाहता था कि मतक की पत्नी, चाहे उसके बच्चे हों या न हों अपने पति की जायदाद की मालिक बनी रहनी चाहिये।

ग्राम में गारदीया भाई ने बीच का माग सुझाया 'मृतक की पत्नी चाहे तो अपने बच्चों के साथ जमीन पर रह चाहें तो किसी से शादी करले, शर्त इतनी ही रहे कि वह शादी करके नये पति के घर

या गांव न जाये किन्तु पति इसके घर पर रह कर भतीबाड़ी कर। जमीन पत्नी के नाम पर हो रहे। अगर बच्चे हो तो वे उस जमीन के उत्तराधिकारी माने जायें, पति उस परिवार का पालक जरूर रहे कि तु मालिक नहीं रहगा। गांधीवादी परिभाषा में वह उस परिवार की सम्पत्ति का ट्रस्टी बनकर उपयोग करे।”

प्रस्ताव सर्वानुमति से स्वीकार हो गया। मामलामा ने प्रस्ताव कर पटवारी से जो कच्ची एंट्री उसने क्षाति के पति के नाम दर्ज की थी, उसे रद्द कराया।

इस प्रकार लोकअदालत के माध्यम से नयी सामाजिक मान्यता स्थापित हुई और वपों से चली आ रही सामाजिक दूषण की एक प्रथा का अंत हुआ।

(2)

अंधविश्वास से मुक्ति

वाटडा गांव की रावली बहन के बारे में मुष्ठा (घोभा) ने यह कतवा दे दिया कि वह डाकिन है और वही गांव के पशु और मनुष्यों को खा रही है। मुष्ठा का बोल उनके लिये भगवान का बोल था। मुष्ठा के इस कथन से उत्तेजित होकर गांव के लोगो ने रावली पर हथियारों से हमला बोल दिया और उसके परिवारजनों की उपस्थिति में ही जो मुष्ठा के हुक्म और पूरे गांव में उसके कथन की मिलन वाले समर्थन से भग्याक्रांत होकर चुपचाप खड़े रहे उसकी खूब मार पिटाई कर दी। उसके शरीर पर घाव ही घाव हो गये और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। मारने वाले यह सोच कर चले गये कि वह मर चुकी है लेकिन उसके परिवारजनों को उसकी सास चलती हुई दिखाई दी। वे उसे घाट पर लिटाकर अस्पताल ले गये और उसका इलाज कराया। डाक्टर के बुलाने पर पुलिस आई। पहले तो उसने रावली के परिवारजनों के प्रति सहानुभूति प्रकट की किन्तु दूसरे दिन गांव के पटल और अन्य कुछ लोग थाने पर गये और पुलिस का व्यवहार बदल गया। उसके पति का गांव जाना मंजूर हो गया। उसकी सेती बाड़ी खराब हो गयी। वह किसी तरह लुक छिपकर रात को गांव आता था लेकिन सवेरा होत ही गांव छोड़ देता था।

इस परिस्थिति में मामला लोकअदालत के समक्ष पेश हुआ। गांव वालों को निमंत्रण भेजा गया। पुलिस को भी नोटिस दिया गया। रावली और उसका पति दरिया लोकअदालत का नोटिस और उनको नय तिर पर दो गयी निवापत लेकर पुलिस थाने पहुँचा। पहुँचे तो पुलिस अधिवारी काफी

क्षुब्ध हुये लेकिन बाद में उ होने कहा कि तुम लाग इस प्रकार की फरियाद देना चाहत हो तो मैं ले लूंगा कि तु याद रखो, पुलिस काई 24 घण्टे आपके साथ नहीं रहेगी। पूरा गांव एक तरफ है। मुआ का उनका आदेश है। अत वे तुम्हें छाड़ेंगे नहीं। तुम जान बचाना चाहते हो तो गांव छाड़कर वहीं भाग जाओ। वे हतोत्साह हाकर यान से वापस लौट आये।

उधर पुलिस का भेजी गयी लाकअदालत की सूचना पूरी तफसील के साथ अखबारी में छपी। इसका पुलिस पर भी असर पड़ा। लोकअदालत की बैठक में अच्छी उपस्थिति थी। सारा गांव आया था। पहले तो गांव के अगुआआ ने इस बात को माना ही नहीं कि उ होने रावली को पीटा है। लेकिन बाद में उ हान सच सच बयान कर दिया।

लोकअदालत के अध्यक्ष ने मिथ्या बहसों और झूठी मायताआ के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए लाकअदालत के सदस्यों से पूछा, 'आप में कितने ऐसे लोग हैं जो अब भी यह मानते हैं कि डाइन बन कर कोई औरत किसी को खा सकती है?' जवाब में एक भी हाथ नहीं उठा। लेकिन बाटडा के लोगो ने कहा 'मुआ के आदेश को हमने देवी का आदेश माना है।

मुआ को बुलाया गया। लाकअदालत की ओर से मुआ से सवाल किया गया 'आपके शरीर में जब देवी आती है तब सब कुछ कह देते हैं और जो चाह सो कर लत है। हम आपके सामने एक पाना का पिलास भरकर रख रहे हैं। आप इसको खून में बदल दें। अगर आप पानी को खून में बदल सके तो हम एक प्याले में कोई भी चीज भरकर रख देंगे। आप बताइये इसमें क्या है? अगर आप किसी के शरीर में घुस कर यह बता सकते हैं कि उसने क्या खाया है तो यह बताना आपके लिय बहुत ही मामूली बात होगी चाहिये। गांव के लोग लोकअदालत के इस तक़युबन सवाल में प्रभावित हुए और उ होने भी लोकअदालत के सवाल का समयन कर दिया। मुआ बगलें झुकने लग गया। लागी की मौजूदगी में उसके गान और देवीपन का दिवाला निकल गया।

तुरत गांव के कुछ लोग बोल पड़े — हमने इस मुआ ने चक्कर में आकर बहुत बड़ा पाप किया है। लोकअदालत हम चाह जो सजा दे।'

लोकअदालत ने दोनों पक्षा से दो-दो जूरी नियुक्त करने का कहा। करीब घण्टे भर बाद जूरी ने अपना सबसेममत फैसला सुनाया। हमने दस मामलों पर काफी सोचा, गुनाह बहुत गंभीर प्रकार का है। एक तरह से लोगो ने रावली बहन का क़त्ल ही कर दिया था। गयोग की बात है कि वह किसी तरह बच गयी। लोग ने यह कार्य अनानाया किया है। जांच

से पता चला है कि गांव वाले अब तक पुलिस को 700 रुपये और वकील को 500 रुपये दे चुके हैं। अब इन लोगों पर ज्यादा दण्ड डालना मुनासिब नहीं। रावली बहन की दवा आदि पर जा खर्च हुआ है, उसके लिये गांव के लोगों से 125 रुपये दिलाये जाय।”

उपस्थित लोगों ने इस फैसले को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। रावली बहन ने 25 रुपये का गुड मगवाकर लोकअदालत की बठक में उपस्थित लोगों को बांटा। स्नेह व सदभाव के वातावरण में लोकअदालत उठ गई। अज्ञान का अधकार साफ जो हा चुका था।

(3)

आर्थिक शोषण की समाप्ति

खायगिया गांव की ग्रामसभा ने प्रस्ताव करके तणखला कस्बे के साहूकारों को नोटिस दिया कि वे अपना हिसाब करके ग्रामवासियों की जमीनें वापस कर दें। कुछ व्यापारियों ने ग्रामसभा के समक्ष उपस्थित होकर हिसाब कर दिया और जमीन भी लौटा गये लेकिन कुछ व्यापारियों ने संगठन करके ग्रामसभा के प्रस्ताव का बहिष्कार किया।

ग्रामसभा ने इन व्यापारियों का बहिष्कार करने और उनकी दुकानों व मकानों पर धरना देने का कार्यक्रम बनाया। व्यापारी आ दोलनकारियों के प्रदर्शन के सामने स्वतः झुक गये। उसी दिन शाम को उन्होंने समझौता कर लिया।

यहां यह उल्लेख करना अप्रत्याशित नहीं होगा कि जैसे ही इस ग्राम ने ग्रामदान का स्वरूप पत्र भरा या पुलिस कमचारी गांव में पहुंच गये थे और लोगों को दानपत्र वापस लौटाने के लिये न केवल डराया धमकाया बल्कि गांव के 8 अनुग्रामों को पकड़कर पुलिस थाने में बंद कर दिया। गांव वालों ने मुकाबला किया। गांव में सभा हुई और कई गांव के लोग एकत्रित होकर पुलिस थाने पहुंचे। उनके द्वारा उद्धोषित नारों से पुलिस वाले घबरा उठे। उधर कुछ लाग खायरिया और जीतनगर के अनुग्रामों को लेकर राजपौपला स्थित डिप्टी इन्स्पेक्टर पुलिस के कार्यालय तक गये और उनसे पूछा कि ग्रामदान करना किस धारा के अंतर्गत जुर्म बनता है और गाठ लोगों को क्या हिरासत में रखा है? डिप्टी साहब यह सुनकर शर्मिदा हुये। थाने के पुलिस कमचारी को ग्रामवासियों की उपस्थिति में डाटा पटकारा, चाय पिलाई और क्षमा मांगते हुए विदा किया।

लोकअदालत द्वारा जागत अहिंसात्मक प्रतिकार एवं निश्चयता की भावना

न मर्दिया से चनी घा रही आर्थिक शोषण की भीषण प्रक्रिया पर तीव्र प्रहार किया ।

(4)

चोरी की कपास की खरीददारी बन्द

नलवाट (ग्रामदानी) गाव की ग्रामसभा न गाव के उन व्यापारियों का, जो चोरी की कपास खरीद कर गाव की बुरी तरह लूटत थे, नोटिस दिया कि वे अगर चीजों का ठीक ठीक मूल्य नहीं लेंगे और खेती की चोरी का माल—कपास इत्यादि खरीदेंगे तो गाव उनका बहिष्कार करेगा । ग्रामसभा के नोटिस का कुछ असर तो हुआ—चीजों के दाम कुछ सुधरे और मापतोल भी ठीक होने लगी लेकिन चोरी का माल छोड़ना मुश्किल था क्योंकि चोरी का माल इन्हें आधे से भी कम कीमत में मिल जाता था और व्यापारी इतना बड़ा लालच आसानी से कैसे छोड़ सकते थे ।

ग्रामसभा की दुबारा नोटिस देना पड़ा । ग्रामसभा ने चोरी का माल खरीदने वाले दूकानदारों की दूकानों के सामने 24 घण्टे की पिकेटिंग शुरू कर दी । नतीजा अच्छा निकला । चोरी का माल लेना बंद हुआ, लेकिन व्यापारियों ने ग्रामसभा के लागे से बदला लेने का पक्का निश्चय कर लिया ।

एक दिन नजदीक के गाव के एक धनी किसान के पम्प हाउस के कुछ पुर्जों की चोरी हो गई । व्यापारियों ने पुलिस वाला को बताया कि आपस-पास में केवल गजलावाट के ग्रामदानी गाव में ही इजन पम्प है । हा न हो, यह चोरी का काम गजलावाट के किसानों ने ही किया होगा ।

पुलिस अधिकारी गजलावाट गाव के मुखिया श्री छोटाभाई के घर पहुंच गये । जब छोटाभाई ने तलाशी लिय जाने का विरोध किया तो पुलिस अफसर काफी नाराज हुआ और बोला 'कौन होती है तुम्हारी ग्रामसभा हमारे काम का रोकने वाली ।' वे छोटाभाई को पकड़कर नलवाट के एक धनी किसान के घर ले गये । गाव के दूसरे लोग को इसका पता चला तो वे सब तुरन्त वहां पहुंच गये और पुलिस अफसर को बताया कि 'जिस किसान के इजन के पुर्जों की चोरी हुई है, वह इजन 5 हाम पावर का है जबकि हमारा इजन 20 हार्स पावर का है, आप ही बताइये, क्या इनके पुर्जे बदल बदल विप्रे जा सकते हैं ?'

छोटाभाई के लड़के मोती ने कहा, 'चोरी का माल खरीदने वाले चोर व्यापारियों ने हमारे खिलाफ कोई पक्ष-त्र रचकर आपको भूठे चक्कर में

खरीद लिया जाये और दूसरी जमीन की तरह यह क्षेत्र इस प्रकार पर वेहलाभाई को सुपुर्द कर दिया जाये कि व कर्जों की रकम चुकाने तक इस क्षेत्र के उत्पादन में से 50 प्रतिशत अन्न हर साल ग्रामसभा को देते रहेंगे।

ग्रामसभा के इस प्रस्ताव के कुछ दिन बाद वेहलाभाई ने ग्रामसभा के समक्ष निवेदन किया कि ग्रामसभा से कर्जा लेने की वजाय वे अपने स्वसुर नकलाभाई से बिना ब्याज व कर्जा ले लेंगे और यह जमीन श्री चिमनभाई से खरीद लेंगे लेकिन खरीददारी सीधी ग्रामस्वराज्य समिति के नाम से ही की जायेगी ताकि अगले लोगों के क्षेत्रों की तरह जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत मालिकी ग्रामस्वराज्य समिति के नाम कर दी है यह क्षेत्र भी ग्रामस्वराज्य समिति की मालिकी का अंग बन जाये।

ग्रामसभा ने कहा कि चूंकि वेहलाभाई के स्वसुर नकलाभाई ग्रामदान के बाय में गरीब नहीं हुए हैं और एक घनी किसान होने के नाते वे पहले भी कुछ लोगों की जमीनें हड़प चुके हैं इसलिये ग्रामसभा वेहलाभाई के प्रस्ताव का इसी बात पर स्वीकार कर सकती है कि वे ग्रामसभा को इस बात का लिखित वचन दें कि वे किसी भी सूरत में यह क्षेत्र अपने स्वसुर को नहीं सौंपेंगे। वेहलाभाई ने ग्रामसभा को लिखित वचन दे दिया और उनके स्वसुर ने भी लिखित निवेदन कर दिया कि वे यह जमीन वेहलाभाई के पास ही रहने देंगे और अपना रुपया उत्पादन में से ग्राहिस्ता ग्राहिस्ता वसूल करेंगे।

जमीन खरीद ली गयी और वेहलाभाई ने भी एक साल तक इस जमीन को जोता भी लेकिन दूसरे वर्ष उनके स्वसुर नकलाभाई ने इस जमीन को जोता। ग्रामसभा ने बराबर वेहलाभाई को इस प्रकार वचन भंग न करने के लिये समझाया लेकिन वेहलाभाई ने ग्रामसभा के निर्णय की अवहेलना की। इस पर ग्रामसभा ने उसको ऐसा न करने के लिये नोटिस दिया और बाद में पूरी ग्रामसभा ने मिनर क्षेत्र जोत लिया और कपास बो दी।

वेहलाभाई ने अपने स्वसुर के दवाब में आकर पूरी ग्रामसभा के विरुद्ध इंडियन पतल कोड की दफा 420 416 और 438 के अंतर्गत निश्वासघात का केस दाखिल कर दिया। ग्रामसभा की बैठक हुई और इस घड़यंत्र के मुकाबले के लिये ग्रामसभा ने लोकप्रदानत के अध्यक्ष को ही मूनिया नामजद कर दिया।

पुलिस की चार्ज लिस्ट में केस इस प्रकार दर्ज था 'वेहलाभाई ने ग्रामसभा को अपने स्वयं के लिये साहूकार से जमीन खरीदने का उद्देश्य से फर्षा दिया था और ग्रामसभा ने विश्वासघात करने जमीन उनके नाम खरीदने की वजाय अपने (ग्रामसभा के) नाम में खरीदली। ग्रामसभा के सदस्या ने

पुलिस के सामने बयान दिये और ग्रामसभा के प्रस्ताव एवं बेहलाभाई व नक्लाभाई के अपना हाथों से दिये गये निवेदन एवं यचन भग्न प्राप्ति की बातें पुलिस में समक्ष पेश की। लेकिन पुलिस ने लोकप्रदानत के अध्यक्ष का ग्रामसभा के मुखिया की हैमियत से एवं ग्रामसभा के कुछ सन्ध्या को गिरफ्तार कर लिया। बाट न तत्काल सबका जमानत पर रिहा कर दिया। ग्रामसभा के गावों वाले इस मामले से काफी दुःखी हुये। उन्होंने बेहलाभाई और नक्लाभाई का समझाने और पुलिस की मित्रभगत से उन्हें बर्तन कराने की कोशिशें भी की लेकिन मामले का सुरत निपटारा नहीं हो सका।

छ महीने तक ग्रामसभा का और लोकप्रमाण के अध्यक्ष को अपनी निजी हैमियत में प्रदानत जाना पड़ा। लेकिन हर बार पुलिस ने बेहला बनाकर तारीखें बदलवाने का तरीका अपनाया। मजिस्ट्रेट के ध्यान में यह बात आ गई इसलिये उसने आग्रिकार पुलिस का चेतावनी दे दी कि अगली तारीख के पहले पुलिस सारे बागजात पेश कर दे। उस दिन मुनवाई अवश्य होगी। इस पर इसपक्तर कुछ चबराय। उपर बेहलाभाई व नक्लाभाई भी पूरे समाज से बर्तन हो गये थे। वे भी किसी तरह अपनी गलती सुधारना चाहते थे। अतः मजिस्ट्रेट के चम्बर में सब इकट्ठे हुए। ग्रामसभा की ओर से यह मांग पुनः दोहराई गयी कि जमीन बेहलाभाई को मिलनी चाहिये। ग्रामसभा जमीन बेहलाभाई को जोतने के लिये देने की तैयार है किन्तु उससे दबसुर नक्लाभाई को इस जमीन पर भाव नहीं समझनी चाहिये। अगर वे (बेहलाभाई) जमीन जातना न चाहें तो ग्रामसभा उसका 3600 रुपये मय व्याज लौटाने की तैयार है। प्रारम्भ में पुलिस वालों ने कई चालें चली ताकि मुनदमा जल्दी न उठे लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने ग्रामसभा द्वारा सुझाया गया समाधान स्वीकार कर लिया। उन्हीं दिन मजिस्ट्रेट साहब के चम्बर में ही छाटा उदयपुर के लोगो ने लाकर रुपया जमा करा दिया। मजिस्ट्रेट साहब इससे बहुत प्रभावित हुये।

विवाद तो समाप्त हो गया लेकिन बाद में मालूम हुआ कि पुलिस ने इससे काफी रुपया ले लिया था। बेहलाभाई बहुत परेशान थे। दबसुर और दामाद दोनों में रुपये के प्रश्न पर मुनमुटाव हो गया था।

लोकप्रदानत ने दोनों को अपनी गलती पर पश्चाताप करने की सलाह दी और दोनों में पुनः मेलमिलाप करवा दिया।

(6)

व्याय प्राप्ति के लिये सफल सघर्ष

श्रवतेश्वर गाव की लगभग 300 एकड़ जमीन तत्काल और तिलकवाडा

- (1) रेवे यू ट्रिब्यूनल ने पुन जाच का जो आग्रह किया था, उसपर मात्र साल तक वीर अमल नहीं किया।
- (2) मन् 1962 में जो जमीनें बिना चुकी थी और जिसके रुपये मेजर धीरेन्द्र सिंह ले चुके थे तथा जिन जमीनों के खाते हमारे किसानों के नाम चढ़ चुके थे वह जमीनें 1966 में बने डिफेंस पमनल एक्ट के द्वारा बेचने वाले को वैसे लौटायी जा सकती थी ?

सामाजिक एवं मानवीय दृष्टि से किये जा रह इस अध्याय के विरुद्ध सत्याग्रह किये जाने का संकल्प किया गया। इसपर किसानों का सरकारी नोटिस मिले कि वे उस जमीन का राजा मेजर वीरेंद्र सिंह को मौप दें और उधर अकतेश्वर की ग्रामसभा ने मिलकर तय किया कि किसान स्वयं अपनी धार से जमीन का राजा नहीं छोड़ेंगे। फेंनाई प्रदश ग्रामस्वराज्य मंडल ने अकतेश्वर ग्रामसभा के प्रस्ताव का समर्थन किया और गुजरात सर्वोदय मंडल ने भी इस मामले पर विचार किया लेकिन इसी दौरान रेवे यू विभाग के अधिकारी पुलिस दल के साथ अकतेश्वर पहुंच गये और गांव वालों को डांटना शुरू कर दिया। ग्रामसभा के मुखिया ने कहा कि ऐसी डांट फटकार की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सरकार के इस हुक्म के खिलाफ हैं। हम अपने हाथों अपनी जमीन नहीं सोपेंगे। इस पर गांव के 48 लोग को, जिनमें दो दो बच्ची वाली बहन भी शामिल थीं, गिरफ्तार कर लिया गया और तहसीलदार के सम्मुख राजपीपला ले जाया गया। यहां सरकारी कर्मचारियों ने एक साजिश की। तहसीलदार ने लोगों के सामने तो पुलिस को डाटा कि एतने सारे लोगों को क्या गिरफ्तार किया गया और ग्रामजनों से कहा 'मैं आप सब लोगों को व्यक्तिगत जमानत पर छोड़ देता हूँ' फिर तथाकथित जमानत के कागजों पर किसानों के हस्ताक्षर लिए गये। लेकिन असल में वे कागज जमानत के कागज नहीं थे वे कोरे कागज थे। उनमें अपनी खुशी से जमीनों के कच्चे मेजर वीरेंद्र सिंह के सुपुत्र बनने की बात वाद में लिख दी गयी थी। इस प्रकार सरकारी कर्मचारियों ने लोगों के साथ धोखा किया और पुलिस की मदद में वीरेंद्र सिंह की पत्नी ने सेतो में बुवाई करवा दी।

ग्रामसभा ने मुख्यमंत्री तथा सारी जानकारी भिजवाई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इस पर 18 अप्रैल यानी भूमि प्राप्ति दिवस पर अकतेश्वर में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया जिसमें सचिव श्री इंदुलाल यादव श्री सनत मेहता (जो बाद में गुजरात के थम एवं पूर्वार्थ मंत्री बने) और गुजरात किसान सभा के अध्यक्ष श्री चंदूलाल पटेल

भी उपस्थित थे। श्री याज्ञिक ने कहा कि 200 ग्रामजनों के साथ किये गये इस अध्याय के प्रतिकार के लिये सरकार से मुकाबला करना होगा। श्री सनत मेहता ने जोरदार शब्दों में सत्याग्रह का समर्थन करने की घोषणा की और श्री चद्रभाई पटेल ने कहा कि सरकार गांव के गरीबों के मुंह से रोटी का कोर छीनने को सहायता दे रही है। इसका मुकाबला उग्र आंदोलन के जरिये किया जाना चाहिये।

लोकप्रदात के नेतृत्व में समस्या के समाधान के लिये सघट करने का निश्चय किया गया और एक ऐक्शन कमेटी की स्थापना की गयी जिसमें अक्वेश्वर के आसपास के गांवों के लोगों को भी लिया गया।

सभा द्वारा लिये निर्णय की सूचना सरकार को दे दी गयी। अगवाओं ने भी इस समस्या के सम्बंध में अच्छा प्रकाशन किया। अंतिम प्रयत्न के रूप में लोग राज्यपाल श्री श्रीमन्नारायण से भी मिल लेकिन सरकार की ओर से कोई कदम न उठा। 22 मई को अक्वेश्वर में बड़ी सभा हुई। 250 से ज्यादा व्यक्तियों ने सत्याग्रह में भाग लेने के लिये इस मकरूप पत्र पर हस्ताक्षर किये। 'सरकार या किसी ओर की तरफ से हिंसक प्रहार हो, फिर भी हम अहिंसक रहेंगे। कष्ट खुद सहन करेंगे किंतु अध्यायपूर्ण कानून को ताड़कर छीनी गयी जमीन को वापस प्राप्त होने तक, हर तरह की कुर्बानी के लिये तैयार रहेंगे।' सभा जलूस के रूप में बदल गयी। जलूस के आगे डोंग वगैरह बज रहे थे। बिल्ल सगाये हुए सत्याग्रही भाई बहन सबसे आगे चल रहे थे। अगल बगल पुलिस चल रही थी—खेता के किनारे पुलिस कतार बाधकर मोर्चा लेने को तयार खड़ी थी। लेकिन पांच सत्याग्रहियों की टोली ने खेत में प्रवेश किया नारियल फोड़ा और खेत की मिट्टी मिर पर चढ़ायी। पुलिस सत्याग्रहियों को लेकर चली गयी। उस दिन पांच खेतों पर इस प्रकार सत्याग्रह हुआ। सत्याग्रहियों की प्रथम टोली को दो सप्ताह जेल में रहना पड़ा। गुजरात के तथा देश के अन्य अगवाओं ने आदिवासियों द्वारा किये गये इस अनुशासन बद्ध सत्याग्रह की काफी मराजना की।

तीन सप्ताह के बाद फिर सत्याग्रह हुआ। 58 सत्याग्रही कानून भंग करने गिरफ्तार हुए। विधान सभा में भी मामला उठाया गया। मदम्या ने राज्य सरकार को काफी आड़े हाथों लिया।

तीसरी टोली में 122 भाई बहन गिरफ्तार हुए। सत्याग्रहियों को उसी दिन शाम को छाड़ दिया गया।

सत्याग्रह का चौथा चरण अगस्त 70 में शुरू हुआ। बहुत बड़ी तादा-

म जलूम सेता म प्रगिट्ट हुमा । पुलिस दा मोटर वाहन भरकर सत्याग्रहिया को घात पर ले गयो । पुलिस की एक पूरी गाड़ी बच्चा वाली बहना से भी भरी थी । जब पुलिस ने बहना को मोटर से उतारना चाहा तो ब नहा उतरी । उन्होंने कहा “पुलिस ने हम गिरफ्तार किया है ता किसी न किसी गुनाह के आरोप म ही किया हागा । अब हम बंधो छोड रह हैं । हम तो उन सेतो म जरूर जायेंगी और सेती बरेंगी ।”

अध्याय के प्रतिवार की हवा यहा तक फैली कि पुलिस प्रक्रमरा का कहना पडा, ‘पहले पुलिस के नाम से यहा के आदिवासी लोग डरते थे, याने और जेल की बात सुनते ही धबका जात थे । लेकिन इस सत्याग्रह ने आदिवासी पुरपो के ही दिल से नही, स्त्रिया के दिन से भी याने और जेल का डर निबाल दिया है ।’

अक्तेश्वर के इस बार के सत्याग्रह न पूरे गुजरात का ध्यान आकर्षित कर लिया था । अर्गन 71 म फिर सत्याग्रह शुरू करने की भ्पति आयी । सत्याग्रह के मंचालको—लोकअदालत के कायकर्त्ताओं ने सरकार को स्पष्ट तौर पर बता दिया कि अब सत्याग्रह सिर्फ सेता तक ही सीमित नही रहगा बल्कि सरकारी यानो और सरकार के उस इलाके के समस्त विभागो क सामने होगा” अर्थात् इस क्षेत्र म सारा सरकारी काम ठप्प कर दिया जायगा ।

ऐकशन कमेटी के सदस्य राज्यपाल से भी मिले । उन्होंने सब कागजात दते । उन्हें लगा कि कानूनी दृष्टि से सरकार द्वारा की गयी गलती के विरुद्ध कुछ कार्यवाही हाईकोर्ट म ही की जा सकती थी लेकिन गरीबो के लिये अदालत से क्षीघ्र न्याय प्राप्त करना न तो आमान था और न मभव । इसलिये उन्होंने बीरेन्द्र सिंह को बुलाकर आपसी बातचीत द्वारा ही समाधान खोजने का प्रयास किया । याममभा के सदस्या और मेजर साहब म बातचीत शुरू हुई लेकिन मेजर साहब की पत्नी ने तुरंत समाधान नहीं होने दिया । उन्होंने एक महीने के समय की माग की । समय दे दिया गया, लेकिन दा महीने बीत जान पर भी आगे कायवाही नही हुई । इस पर लोकअदालत के अध्यक्ष ने अवतेश्वर का प्रश्न—मेरी अन्तर्वेदना शौर्य से एक खुलापत्र गुजरात के सब राजनतिक एवं सामाजिक कायकर्त्ताओं के पास भेजा जिसमे सम्पूर्ण परिस्थिति की जानकारी देते हुए तीन माग बताये गये

- 1 बडे पैमाने पर सामूहिक सत्याग्रह करके सरकारी तन को राब देना ।
- 2 लोकअदालत के कायकर्त्तागण एवं अक्तेश्वर के आमजन सामूहिक आमरण अनशन करें ।

3 हाथ में हाथ धर कर बैठे रहें और नक्सलवादी तुलान जैसे हिंस्रक आन्दोलन के आने का इन्तजार करें।

अब मैं उस पक्ष में निम्न बातें कि यदि 11 सितम्बर 71 तक गुजरात सरकार ने समस्या का समाधान नहीं किया तो कार्यकर्त्ता अपने बलिदान को सुझाव कर देंगे।

उन्होंने सचदेवा नथ के मंत्री के नाथ राजपूत से पुनः भेंट की। उनके अनुरोध पर बीरेंद्रसिंह के साथ 8 सितम्बर को ऐकान कमेटी के सदस्या की तीन घंटे बातचीत चली, जिसमें निम्न समाधान लाया गया —

1 सरकार ने मेजर बीरेंद्रसिंह का जा जमीन विमान से छुड़ाकर दिखाई है उसमें से अपनी जमीन व सरकार का लौटा दें।

2 किसानों ने और मेजर ने जा आधी आधी जमीनें छाड़ी हैं उन दोनों को सरकार अपनी ओर से सरकारी जमीन देकर पूर्ति कर दें ताकि किसानों को और मेजर का पूरी मात्रा में जमीन मिल जाय।

3 दोनों पक्ष पार्टी में चल रही केस वापस ले लें और इन बय की फमत निकलने ही इस समस्या का समाधान होगा।

4 गांव के लोगों की जा आधी जमीन छूटेगी उन्हें अपनी ही जमीन सरकार वहीं भी दूमरी जगह देगी किन्तु किसी किसान को बदखल करके नहीं।

5 जिन किसानों का काफी समय तक तकनीफें उठानी पड़ी और जिन्हें नयी जमीन को ताड़ने के नियम भी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी वह सरकार अपनी ओर से कम ब्याज पर या बिना ब्याज के ऋण देंगी।

इस प्रकार इस समाधान के जरिये सरकार ने अपनी गलती को दुरुस्त कर दिया और उसने ही इस गलती की कीमत भी चुका दी। आदिवासियों के अधिकार सत्याग्रह ने पहली बार ही सरकार का अपनी भूत सुधारने को बाध्य किया। सत्याग्रह की इस विजय ने लोकप्रशासित के कार्यकर्त्ताओं की प्रतिष्ठा तो बढ़ाई ही साथ ही आदिवासियों में आगा एव माहम का संचार करके उनमें नई जान भी फूँक दी।

(8)

अत्याचार का प्रतिकार

जमा कि अध्ययन में बताया गया है लोकप्रदानत न न केवल दोनों पक्षों के आपसी विवाद का ग्राह्य एव समा समाधान खोज कर न्याय की प्रक्रिया में मदद दे है बल्कि जन-साधारण को सरकार की गलत नीतियाँ एवं

सरकारी कर्मचारियों के अत्याचार और उत्पीड़न एवं व्यापारियों के शोषण से मुक्ति मिल अर्थात् जन साधारण को व्यापक रूप से विभिन्न प्रणामनिक, आर्थिक एवं सामाजिक मामलों में सत्ताष्ट लोकोत्त प्रयास प्राप्त हो मक, इसने लिये भी उसने प्रयास किया और ऐसे प्रयासों में एक प्रकार से स्वयं पक्षधर बन कर अहिंसात्मक संघर्ष एवं प्रतिहार के द्वारा सरकार एवं जन साधारण को न्याय की सही दिशा बताया है और लोक जागरण का सफल प्रयास किया है। नीचे दी जा रही घटनाएँ एवं लाक्षणिकता द्वारा तत्विषयक अपनायी गई कार्य प्रक्रिया उक्त कथन की पुष्टि के लिये यथेष्ट सामग्री प्रदान करती हैं।

ताडकाछना गांव में जगलात के कर्मचारियों ने गांव के लोगों पर अत्याचार किया। वे न केवल रोज किसी न किसी ग्रामवासी को पीटत थे और उनसे मुर्गियाँ एवं दूध मागत रहते थे, बल्कि एक दिन तो उन्होंने वहाँ के लोगों के जो उनके लिये दूध घी नहीं ला सके उन गांवों की 22 के करीब जवान लड़कियों को एक कतार में खोपायो की तरह दो टांगा और दो हाथों के बल मुर्गी बना दिया और जगलात विभाग के एक चीट गाड़ भीखानान को जो बहुत भारी वजन का है उस लड़कियों की पीठ पर चढ़ाया और उस उनकी पीठ पर चलने का आदेश दिया। मानो वह जिन्दा लड़कियाँ की बनायी गयी पुलिया हो। उनके पीछे फारेस्टर हटर नेकर चल रहा था और जो लड़की बोझ के कारण जरा सी झुकती उसको परा पर हटर मारता जाता था। जब एक ग्रामवासी इस दयनीय दृश्य को बर्णन नहीं कर सका और उसने फारेस्टर से नाकभोक की तो उसकी बुरी तरह पिटाई की गयी और जगलात के तीन अधिकारियों ने ग्रामवासियों की तरफ बंदूकें तान ली। गांव वालों डर के भारे भाग गये। जब ग्रामस्वराज्य समिति जगलावाट के मंत्री तजलाभाई और ग्राम सभा के मुखिया श्री भगत ने ताडकाछना गांव के लोगों पर किये गये इस अत्याचार का विस्तृत विवरण सुना तो उन्होंने एक जाच समिति नियुक्त की। जाच समिति एवं ग्राम सभा के सदस्य जगलात के कर्मचारियों से मिलने के लिये घटना स्थल पर पहुँचे लेकिन जगलात के कर्मचारियों ने उनकी कोई परवाह नहीं की—उनकी आपस में मोकभोक भी हो गया। उन्होंने गांव वालों से भेंट करके उनके ऊपर किये गये अत्याचार एवं अमानवीय जगली कृत्यों की जानकारी प्राप्त की और इस अत्याचार का मुकाबला करने के लिये लोकअग्रज के सस्थापक के नेतृत्व में समस्त ग्राम दानी गांवों के लोगों का आवाहन किया। सभा बुलाई गयी और उसमें निम्न प्रस्ताव पारित करके इन कृत्यों की भर्त्सना करते हुए सरकार में माग

घात बटाई व निरा दूमर दिा मे जाा बा यह निर्णय शमसभा व मुनियों की सहमति स हुमा था । जब जांच अधिकारी श्री बारजा ने कहा कि "प्रगर बल आपन माग नाम पर लगा को तयार है ता मैं नय प्राप्ती ताडवाछला भेजन का हुक्म दता हूँ" ता प्रगत नि दोषावली का त्योहार होने के बावजूद ग्राम मुनियोगा न उनकी धुनोती स्वीकार करती । और राता रात एक गाव से दूमर गाव तक इस धुनोती की जानकारी घाम बटाई पर आने वाले मादूरा तक पहुँचा दी । गाव गाव म यह आवाज गूज उठी— "सरकार न हमारी बात मानली है । अयायी अधिकारिया व बजाय नय अधिकारिया को निगुन किया है । यद्यपि आज दोषावली का त्योहार है, फिर भी हम अपना बायदा पूरा करत के लिय घात काटन ताडवाछला चनता होगा । चलो जल्दी ही तैयार हारर ताडवाछला चलें ।"

लोक-शक्ति के जागरण की इस महान प्रक्रिया की दायवर जांच अधिकारी श्री बारजा को कहना पडा —

"मैं आप लोगो से क्षमा चाहता हूँ । आप लोगो के प्रति हमारे कमचाचारियों ने जा दुर्ब्यवहार किया उसके लिय मैं क्षमादा हूँ, उन सब अधिकारियों को आज से ही नौकरी पर स हटा देन का मैं एलान करता हूँ । आप लोगो ने दोषावली जैम बडे त्योहार के अवसर पर भी काम पर लगने का जो सबल साधार किया है, इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूँ और अपनी ओर ल आप लोगो की त्योहार मनान की दो दिन की छटिया दता हूँ । आप लोग दो नि के बाद काम पर आ जाइये । नय अधिकारी आप की सेवा म उपस्थित रहेंगे । मैं बायदा करता हूँ कि अब ऐसी कोई घारशत नही होगी जिससे आपको कोई बच्ट हो । एक बार फिर स मैं आपसे क्षमा मागता हूँ ।"

यह की सत्याग्रह की अयाय का अहिंसात्मक प्रतिकार करन की विजय कहानी । आदिवासियों ने ऐसे बडे अधिकारी के मुह से क्षमा याचना के बोल अपने जीवन म पहली ही दफा सुने थे । यह पहला ही अवसर था, जब अत्याचारी अधिकारियों की मुह की खानी पड़ी—उ ह नौकरी से हटने की मजबूर होना पडा और जनसाधारण के मन म हिम्मत एवं आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ एवं अयाय और अत्याचार का मुकाबला करने के लिये लोकप्रगल्भ से उन्हें नयी दिशा मिली ।

(9)

शोधन का मुकाबला

चलामली गाव के एक धनी जमींदार श्री चुनीलाल भाई पटेल का गाव की लगभग आधी जमीन पर कब्जा था। भारत भाई कंसलाभाई को 9 एकड़ जमीन उ होन सिफ 300 रुपये म ले ली थी। यह जमीन इतनी उपजाऊ है कि एक एकड़ में बिना सिंचाई के भी 400 रुपये की उपज हो जाती है। इस प्रकार करीब 4 हजार रुपये सालाना की उपज पांच साल तक तो उहोन ले ही ली। लेकिन साथ ही साथ 300 रुपये के बज की रकम को 900 रुपये भी बना दिया।

जब ग्रामसभा ने उह रुपये वापस देकर जमीन प्राप्त करनी चाही तो उहोन ग्रामसभा के ग्रामपञ्चो की कोई परवाह नहीं की। आखिर मामला लोकप्रदालत में प्रस्तुत किया गया। श्री चुनीलाल की रजामंदी से ही सुनवाई की तारीख भी तय की गई लेकिन तारीख के दिन हम बीमार है ऐसा कहकर श्री चुनीलाल ने अपना लड़के कालीदास को लोकप्रदालत की बैठक में भेज दिया और स्वयं नहीं पहुंचे। हिसाब किताब की जांच पड़ताल हुई और कालीदास की सहमति से ही लोकप्रदालत ने यह निणय दिया कि भारत भाई ने अपनी पुत्री की शादी के लिये इस खेत पर जो 951 रुपये श्री चुनीलाल भाई से कर्ज लिया है, वह कर्जा श्री चुनीलाल भाई को बिना मूल के लौटाने का दायित्व ग्रामसभा ले ले और चुनीलाल भाई इस वष खेत छाड़ दें। चुनीलाल का गेय दावा (जो 300 रुपये की रकम चन्द्रवृद्धि ब्याज लगाकर उहोने 900 रुपये कर दी थी) इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि गत पांच साल में खर्च वगैरह काटकर उस खेत से चुनीलाल जी ने 8000 रुपये का मुनाफा कमाया है इसलिये अब उस बर्जे की राशि वापस मागना उचित नहीं है। लेकिन इस करारखत पर कालीदास ने यह कहकर दस्तावेज करने से इन्कार कर दिया पिताजी ही उस पर हस्ताक्षर कर सकत है।'

जब लोकप्रदालत में यह कार्यवाही चल रही थी तब चलामली में चुनीलाल भाई अपना भ्रमण पड़यत्र रच रहे थे। गाव वाता की अनुरस्थिति का लाभ उठाकर उहोन दस जाड़ी हल बन लिये और बुवाई करन के लिय खड़ा किया जहा खेत स्थित है पहुंच गये। लेकिन जीजीराई के नेतृत्व में गाव की महिलाओं ने चुनीलाल जी के इस पड़यत्र और जोर जबरदस्ती का मुकाबला किया और वे इस बला के सामने एकतार में हाथ में हाथ डालकर

किल बंदी करने मही हो गयी। चुनीलाल जी न गानी मनीज किया और नौरंगे स भी बहा इन राडा पर बैन चना दा।' नमिन नौरंगे की हिम्मत नही हुई तब तब स्वय चुनीलाल जी ने एक महिला का हाथ पकड़ कर दूसरी महिला स उस झलग करवा चाहा। इस पर उस बहिन ने फटकारा देकर चुनीलाल जी से अपना हाथ छुड़ा दिया और मारी बहिन चुनीलाल जी पर टूट पड़ी। नौरंग हन बेल छोड़कर भाग गय और चुनीलाल जी भी अपने घर सोट गय।

कुछ दिन बाद बोरियाद के पुलिस अधिकारी की रिश्तत दकर उ होत गाव क घाट तस व्यक्तिता को गिरफ्तार कराया लकिन जब मजिस्ट्रेट क सामने ग्रामसभा क मुगिया न पुलिस का भडा फोड दिया तब मजिस्ट्रेट न पुलिस का उलाहना देकर गाव के सब लोग का बिना जमानत बरी कर दिया।

उपर लालमदालत की प्रयहेलना और गलत कृत्य करने क कारण चुनीलाल जी के प्रति क्षेत्र के लोग म जो प्रतिक्रम भावनायें फैली, उससे के शमि दा हुए और पछताये, ग्रामसभा से भाकर मिन और लोकमदालत के फैसन को कबूल करने का सदेशा भिजयाया। निश्चित तारीख को समाधान के मसविदे पर चुनीलाल जी ने हस्ताक्षर कर दिये और गाव के साथ उ हाने जो घोषा किया था और बहना के साथ जो ज्यादाती की थी, उसके प्रामश्चित स्वरूप 15। रुपये का दण्ड भी स्वीकार किया।

इस प्रकार शापण के मुकाबले के लिये किए गये इस अहिमात्मक प्रतिकार स भारतभाई की जमीन मुक्त हुई और ग्रामसभा को विजय प्राप्त हुई। लोकमदालत के कार्यकर्ताओं की सच्चाई स प्रभावित हाकर मजिस्ट्रेट न पुलिस वालो द्वारा लगाये गये झूठे आरोपो को अस्वीकार किया और उनको झूठे पक्ष का समर्थन लिए उह उलाहना दिया। चुनीलाल भाई भी समझ गये कि गाव वाला की संगठित शक्ति के मुकाबले के अधिक दिन टिक नही सकते और इसलिये उनके लिये यही श्रेयस्कर माग है कि के लोकमदालत का नियम स्वीकार करके क्षेत्र मे हो रही अपनी अप्रतिष्ठा को रोकें।

(10)

सगठन एव बहिष्कार के बल पर न्याय-प्राप्ति

मातोरा के किसानो पर सखेडा के साहूकार जमनादास का कुछ ऋण था। ग्रामसभा ने साहूकार को अपना हिसाब लेकर ग्रामसभा के समक्ष उपस्थित

हाने के लिये कई बार नाटिम भेजे लेकिन वे हिसाब बिताव साफ करके अपना चाजिब बकाया रकम लेने के लिये ग्राम सभा के समक्ष नहीं आय और सखेडा की अदालत में मुबदमा दायर करके अदालत के जरिये रुपया जमा कराने का नाटिम ग्रामजनों के पास भिजवा दिया ताकि ग्रामवासी धवरा जायें और साहूकार को मनचाही धनराशि मिल जाये। इस ग्रामदानी गांव के ग्रामजनों ने सखेडा की अदालत के अमीन की धमकी की परवाह नहीं की और अमीन को सारी स्थिति से अवगत कराया और कहा कि साहूकार पैसे के बल पर हम काट को धमकिया दे रह हैं लेकिन अब हमने अपने गांव में ग्रामस्वराज्य स्थापित कर लिया है। इसलिए किसी से डरत, धवराते नहीं और अगर उनका रुपया हक का और सच्चा है तो वे जायें और हमारी ग्राम सभा के सामने अपना हिसाब रखें और अपना पैसा ले जायें। अमीन उनकी बातों से प्रभावित हुआ। वह वापस चला गया लेकिन महीने भर बाद फिर वह गांव में पहुंच गया और लोगों से कोट का हुक्म लेने का आग्रह किया। लेकिन लोगों ने फिर भी नोटिस लेने से इनकार कर दिया। अमीन घर घर घूमकर घरो पर यह नोटिस चिपकाता रहा कि "5 मई 62 के दिन 12 परिवारों की जमीन नीलाम होगी।"

ग्रामवालों ने ग्रामसभा की एक तात्कालिक बैठक बुलायी और यह तय किया कि गांव का कोई भी परिवार नीलामी में बिकती नहीं लगायेगा। ग्राम सभा ने अड़ोस-पड़ोस के 10-15 गांवों के लोगों के पास भी निम्न मजमून का पर्चा लिखकर भिजवाया—

"आपसे न्याय चाहते हैं"

हमारे प्यारे ग्रामीण भाई-बहन,

हम मातोरा गांव के लोग आप ही की तरह किसान परिवार हैं। आप सब भली भांति जानते हैं और अनुभव कर चुके हैं कि हमारे इलाके के साहूकारों ने लेन देन में हम गरीबों की सैकड़ों एकड़ कीमती जमीन हड़पली है। सेठ साहूकार अफसरों को रिश्वत देकर मनमानी करवा लेते हैं। शायद ही कोई गांव बचा हो जहां उन्होंने अपना हाथ न दिखाया हो। गांव गांव में साहूकारों की जमीनें हैं। मेहनत हमारी और उत्पादन उनका। मीज मजा वे लूटें और हमारे बाल बच्चे भूखे मरें। ठीक ऐसी ही एक आफत हमारे मातोरा गांव पर आयी है। 5 मई को हमारे 12 परिवारों की जमीन नीलाम होने वाली है। अगर यह जमीन उन परिवारों के हाथ से चली गयी तो 12 परिवारों के करीब 100 लोग भूखी मरेंगे। मजदूरी तो

राज नहीं मिलती नहीं। सिजा खोरी के और कोई चारा नहा रह जायगा।

आप जानते हैं कि हमारा गांव न और ग्राम पास के कुछ गांवों न ग्राम स्वराज्य का संवत्स किया है। अब एक मगठन सडा हुआ है जिसके बन पर हम ऐसे ग्राम का मुनाबला करने की हिम्मत कर रहे हैं। आप सबका सहयोग हम इस काम में चाहते हैं। चाह आपन ग्रामस्वराज्य का संवत्स न किया हो, पर तु आप नीलामी के रोज हाजिर न रह और अगर हाजिर रहें भी तो खोली न बोलें। आपका इतना सहयोग ग्राम का करने वालों की हिम्मत तोड़ देगा और हमारे जैसे अनैक गरीबों को अपनी भूमि माता से बिछुड़ने से रोकने में मदद करेगा। हम सब आपके सहयोग की प्राप्ति करते हैं।

‘हम नैक बनें एक बनें।’

‘गांव की परती गांव का राज’

‘हर गांव में हो ग्रामस्वराज्य।’

विनीत

ग्रामस्वराज्य सभा मातारा के
सब भाइयों के राम राम
द दलाभाई जीता भाई भील,
मुखिया, ग्रामसभा, मातारा

लोकअदालत के कार्यकर्ताओं के सहयोग से यह पत्रक साइकलोस्टाइल करवा कर पचास गांवों में पहुंचा दी गयी। उधर निश्चिन्त दिन प्रमीन, सेठ जमनादास और पुलिस कमबारिया के साथ मातारा पहुंच गया। गांव वालों ने इनका बहिष्कार किया। वे लोग दिन भर बैठे रहे। न कोई उस गांव का आदमी उनके पास फटका न कोई दूसरे गांव का बोली बोलने वाला ही आया। हा, मुखिया के निर्देश पर उनके बैठने के लिये रात जल्द बिछा दी गयी थी और पीने के लिये पानी के घड़े रखवा दिये गये थे। दो बार गांव की लड़कियां उन्हें चाय भी पिला आयी थी। यह नाटक तीन बार चला। आखिरकार श्री जमनादास समझ गये कि गांव के मगठन को छिन भिन करके अपना उल्लू सीधा करना उनके लिये किसी भी प्रकार संभव नहीं है। उन्होंने ग्रामसभा की शरण ली। अदालत ने 15000 रुपये जमा कराने का जो निणय दे रखा था, उसके मुकाबले केवल 1500 रुपये में ही मामला निपटा और वह रुपया अगले मास में लौटाने का ग्रामसभा ने लिखित

वादा किया। गुड बाटा गया। बन्ले म सेठ ने उठ यह लिख दिया कि पूरा रुपया लोमो से मिल गया है, अतः उनके सारे केस कोर्ट से उठा लिये जाय। लिखित निवेदन पर सेठ ने अपने दस्तखत कर दिये और वह निवेदन कोर्ट में भेज दिया गया।

इस प्रकार 'संगठन एवं अनुचित कायवाही का बहिष्कार' की नीति के बल पर ग्रामवालों ने अपनी समस्या के समाधान का अचूक रास्ता खोज निकाला। गाववालों की इस विजय से आसपास के अनेक गावों का ग्राम स्वराज्य का स्वरूप लेने की प्रेरणा मिली। व्यापक पैमाने पर हुई लोक जागृति और उसके फलस्वरूप लोकप्रदानत को मिली मायता एवं प्रतिष्ठा इसका ज्वलंत प्रमाण है।

(11)

लोकप्रदानत के संस्थापकों के प्रयास से ग्रामदान की जा लहर चली, उससे व्यापक पैमाने पर लोकजागरण तो हुआ ही साथ ही उन क्षेत्रों में अफमरो और साहूकारों का प्रभाव भी क्षीण हुआ और भूतपूर राजाओं के जो पुराने कानून चलते थे, वे भी समाप्त हो गये और ग्रामदानी गावों ने नाजायज कर देने से इनकार भी कर दिया।

ग्रामदानी गाव गुटिया ग्राम्बा के फतुभाई ने इस दिशा में नेतृत्व किया। ठाकुर वीरियाद ने गुटिया ग्राम्बा के लोगों को डराना घमकाना चाहा लेकिन उनकी कागिसे नाकामयाब रही। अतः ठाकुर ने एक दफा फतुभाई को दूसरे गाव बुलाया और वहाँ उसकी काफी पिटाई की। उस समय पुलिस के दो कर्मचारी भी वहाँ मौजूद थे लेकिन ठाकुर से मिलीभगत हान के कारण वे कुछ नहीं बोले। पिटाई बिना वजह की गयी थी और सम्पूर्णतया गैर कानूनी थी।

ठाकुर भय के और पर टकस वसूल करना चाहत थे। गाव के लोगो को पता चला तो पूरा गाव ठाकुर से लोहा लेने के लिये तैयार हो गया। ठाकुर जीप लेकर भाग गया। आसपास की ग्रामसभाया ने मिलकर जमूस निकाला और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। तब से ठाकुर ने किसी ग्रामदानी गाव से पैसा वसूल नहीं किया है।

इसी प्रकार साहूकारों द्वारा 'झडप' के नाम पर की जाने वाली स्वच्छा-चारिता का भी अन्त हुआ है। लेन देन की प्रथा का नाम 'झडप' है। इस प्रथा के अनुसार जो किसान साहूकारों से खान व बोने के नियम अनाज सात पं वह उनके खाते में अनाज की जगह कपाम लिखता था और जनवरी

फरवरी में वषाम निवृत्ति पर सबसे पहले वषाम पर हक उस भंडप वाल साहूकार का होता था। इस प्रकार वह भंडप की प्रथा के द्वारा ग्राम की प्रपक्षा दुगुन मूल्य का मान (वषाम) प्राप्त कर लेता था और व्याज अलग से ले लेता था। लोकप्रचलित व प्रयासा से स्थापित ग्राम स्वराज्य मगठों में किसानों को भंडप से मुक्ति दिला दी है क्योंकि ग्रामदानी गांव मगठ के बल पर साहूकार व चुगन में मुक्त हो गये हैं और उनकी जरूरत का वर्जा ग्राम स्वराज्य साहूकारी समिति ने माध्यम से उन्हें सस्ते व्याज दर पर उपलब्ध हो जाता है।

(12)

अफसरी की अनुचित हरकतों का पर्दापाश

ग्रामस्वराज्य में शामिल होने वाले ग्रामीणों ने लोकप्रचलित के संस्थापक के नेतृत्व में अफसरी द्वारा की जाने वाली घाघली एवं साजिशों का भी सफलतापूर्वक प्रतिवार करने की क्षमता प्राप्त करली है। इसका नमूना है वसु दर के ठाकुर वाला मामला। उन ठाकुर ने स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात् अपना शासनाधिकार सरकार को सभालात समय राजस्व रेवाइज में फेरबदल करवा दिया और अम्बालिया गांव के 16 किसानों की 180 एकड़ जमीन अपनी खुदकाश्त में बंटा दी। यह जमीन वह थी जो पीढ़ियों से किसानों के अधिकार में थी और जिस पर वे बराबर काश्त करते आ रहे थे लेकिन ठाकुर इस बड़िया जमीन को सरकारी कानून की मदद से किसानों से ले लेना चाहते थे। वर्षों तक तहसीलदार के यहां मामले की पैरवी चलती रही लेकिन फसला नहीं हो पाया। संयोग के ठाकुर के सम्बन्धी गुजरात सरकार के डिप्टी रेवेन्यू सेक्रेटरी बन गये। उनके द्वारा भड़ोच के बलकटर डिप्टी बलकटर और राजपीपला के तहसीलदार पर प्रभाव डलवाया गया। किसानों की जमीन ठाकुर की सोप जान के आदेश भी हा गये। लेकिन ग्राम सभा इस अन्याय को, चाहे वह कानून के द्वारा समर्थित ही क्यों न रहा हो सहन नहीं कर पायी। उसने दो साल तक सरकार के हुक्म का पालन नहीं होने दिया लेकिन 1966 में पुलिस अधिकारियों के सहयोग से ठाकुर ने जमीन पर बर्जा कर लिया।

ग्रामसभा ने फसला किया कि 'चाहे जो नतीजा निकले वे अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेंगे।' सत्याग्रह शुरू कर दिया गया। रोज आठ दम किसानों की टोली प्रतिवधित खेतों में जुताई के लिए जाती और पुलिस को गिरफ्तारी देती। सत्याग्रह में दूसरे गांव के लोग भी हिस्सा लेते थे। 12 दिन के

सत्याग्रह में अम्बालिया गांव के सब बालिग जेन चले गये। तब बहिनी ने सत्याग्रह में सहयोग देना शुरू कर दिया और वे भी जेल जाने लग गयी।

इधर सत्याग्रह चलता रहा, उधर लोकप्रदात के कायकत्ता न केवल सत्याग्रह की सम्पूर्ण जानकारी इलाके के अन्य गांवों तक पहुंचात रह बल्कि राजपीपना भडोच और अहमदाबाद जा जाकर अधिकारियों से भेंट कर के अम्बालिया गांव के नये पुराने समस्त रेकार्ड भी इकट्ठा करत रहे और उह सही तथ्यों की जानकारी कराने का प्रयास भी करत रहे। नतीजा यह हुआ कि सरकार ने भूल महसूस करली। पुराना हुकम बदल दिया गया और दूसरा हुकम किसानों के हक में जारी किया गया। 12 दिन के बाद सत्याग्रही जेल से रिहा किये गये। सत्याग्रहियों का लौटने पर शानदार स्वागत किया गया।

संगठित होकर अग्रयण का मुकाबला करने के इस प्रयास ने क्षेत्र की जनता में जान फूक दी।

जब क्लक्टर के पास प्रतिनिधि यह जमीन फिर से किसानों को लौटाने के लिये पहुंचे तो सत्याग्रहियों ने उन्हें बताया कि किस प्रकार बच्चा को भूखा रखकर किसानों ने बीज बचाकर बोया था और किस प्रकार चार बार ठाकुर ने उगे हुए बीज को हल चला कर नष्ट कर दिया था। फलस्वरूप कई घरों में आज बोनो के लिये दाना भी नहीं बचा है।

उसी समय पड़ोसी गांव के एक भाई ने उठकर अम्बालिया ग्रामवासियों को विश्वास दिलाया कि उनका गांव न केवल उनके लिये बीज की व्यवस्था करेगा बल्कि पूरे गांव के लोग हल बल लेकर वहां पहुंचेंगे और खेतों की बीआई जुताई में मदद करेंगे।

क्लक्टर के प्रतिनिधि इस भावना से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने सुझाव दिया कि सब लोग अपने अपने गांव या परिवार की ओर से सहायता का अनाज लिये दें और आज या कल तब तक सक्लिप्त अनाज अम्बालिया पहुंचा दिया जाय। रात भर में अनाज अम्बालिया पहुंच गया और दूसरे दिन ठाकुर वाले खेता की 150 हज्र बैला की सहायता से जोत कर किसानों ने चिर प्रतिक्षित सही धान प्राप्त कर लिया।

(13)

सरकारी कमचारियों ने रिश्कत लौटायी

यस क्षेत्र में नाबराचिमली और वाडवा नामक गैर ग्रामस्थानी गांव हैं। कुछ समय पहले जंगल विभाग के अधिकारियों ने इन गांव से सरकारी जुरमान

की वसूली की भी, किंतु जितना रपया लिया, उससे घाघे की भी रसीदें नहीं दी। उदाहरण के लिए जिससे 300 रुपये वसूल किये, उसे 125 रुपये की रसीद दी और जिस पर 500 रुपये जुर्माना किया, उसे 200 रुपये की रसीद दी। कुल मिलाकर 3900 रुपये कम की रसीदें बांटी।

ग्रामसभा के समक्ष शिकायत आयी तो उसने जाच कराई। शिकायत सही निकली। मामला लोकप्रदात के समक्ष पेन किया गया। लोकप्रदात के कार्यकर्ता द्वारा भी पुन जाच करके सही तथ्या का पता लगाया गया। लोकप्रदात की ओर से सम्बन्धित अधिकारियों को भी स्पष्टीकरण हेतु पत्र लिखे गये। उन्हें लिखा गया कि वे लोकप्रदात में घाबर घपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं अन्यथा दूसरे कदम उठान पड़ेंगे। एक अधिकारी ने घाबर अपनी भूल स्वीकार करली, रुपया वापस लौटा दिया और भविष्य में ऐसी भूल न करने का लिखित आश्वासन दे दिया, लेकिन दूसरे दो अधिकारियों ने लोकप्रदात के निर्देश की अवहलना की। ऊपर के अधिकारियों को भी मामले से अवगत कराया गया लेकिन उनकी ओर से निश्चित कदम नहीं उठाया गया।

अंत में लोकप्रदात को भ्रष्टाचार का सहारा लेना पड़ा। सारी जानकारी प्रकाशित कराई गयी और सम्बन्धित अधिकारियों के दफ्तर पर सत्याग्रह करने की घोषणा की गयी। तब उच्च अधिकारियों की प्राप्ति जुली। वे दल दल सहित लोकप्रदात के सामने पहुंचे। उनके आने की सूचना मिलते ही घासपास के गांवों के करीब 2000 लोग जमा हो गये। अधिकारियों ने लोकप्रदात के चबूतरे पर जाने से पहले सारी जानकारी प्राप्त करली। लेकिन फिर भी इस बात से इनकार करते रहे कि रुपया उनके लोगो ने लिया होगा। वे यही कहते रहे कि हमारे किसी कर्मचारी से किसी प्रसंग में गलती हो गयी होगी कि तु इतने मामली में तथा इतनी बड़ी रकम की गलती होना संभव नहीं है।

जब लोकप्रदात के मंत्री ने माफी मागने वाले जंगलात अधिकारी का दस्ताखती करारखत मुख्य वन-संरक्षक के हाथों में रख दिया तो वे बगलें झांकने लग गये। उन्होंने संबंधित अधिकारी को बुलाकर वह करारखत उसके समक्ष रख दिया। उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि मैंने ही यह माफी नामा लिखा है। मैं इस गलती के लिए क्षमादा हूँ। आप चाहे मुझे नौकरी में रखें या निकाल दें मेरी गलती हुई है। मैं भविष्य में ऐसी भूल नहीं करूंगा।

वन संरक्षक उसके पश्चाताप भाव से गद्गद हो गये और उ हे लोकप्रदात

न अध्यापक के समक्ष यह हादिस उदगार प्रकट करना पड़ा "कि आपकी लोक अदालत ने हमारे एक कर्मचारी का जीवन बदल दिया है। मैं आपका बड़ा आभारी हूँ।"

मुख्य वन सरक्षक ने बाकी दोनों अधिकारियों को भी बुलाया। निसानो न हिम्मत और विश्वास के साथ, जितने रुपये अधिकारियों को दिये थे सब ठीक-ठीक बता दिये। वन सरक्षक ने अपने अधिकारियों को घमकाया। फरवरी एक न अपनी भूल स्वीकार करली और लिखित रूप में माफी मांगी, एक रुपया भी लौटा दिया, लेकिन तीसरा अधिकारी अपनी गलती फिर भी स्वीकार नहीं कर रहा था इसलिए मुख्य वन सरक्षक को उसके विरुद्ध कार्यवाही करना पड़ी।

लोकअदालत की खुली बैठक में मुख्य वन सरक्षक ने अपने अधिकारियों के आचरण के लिये क्षमा मांगी, भविष्य में ऐसा न होगा, इस बात का विश्वास दिलाया और अपने सब कर्मचारियों को जाहिराती पर चेतावनी दी कि प्रायः दा के ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे।

उन्होंने गांव की जागत ग्रामसभा की भी तारीफ की और अगले ग्राम वासियों से अनुरोध किया कि वे भी ऐसा ही संगठन बनायें।

(14)

लोक शक्ति से अत्याचार का मुकाबला लोकअदालत और लोक कूच

नवालजा गांव के एक युवक का खून हो गया था और उसकी लाश रणधी गांव के एक खेत में मिली। पुलिस कर्मचारियों ने अकारण ही ग्रामवासियों के साथ मारपीट की। गांव भर के पुरुषों को तीन दिन तक पशु की तरह हाथों पीरो पर उनटा किया गया और उनकी इसी तरह खड़ा रखा गया। रात को वही झिटा दिया जाता था। तीसरे दिन गांव की एक कुंवारी लड़की रेमती को इस क्षण में कि उसकी मरने वाले युवक से मुहब्बत थी बुलाया और एक कमर में ले जाकर पीटना शुरू कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने रेमती के वक्षस्थल पर हाथ डाला और बुरी गाली दकर उसको नीचे गिराना चाहा तो उसकी बुआ दशरी बहिन, जो गांव की उप मुखिया भी थी और दरवाजे से मार पीटाई का दृश्य देख रही थी पुलिस के सिपाहियों पर गैरनी की तरह कूद पड़ी और पुलिस वालों के आचरण की तीव्र शब्दा में भत्सना करत हुए चेतावनी दी 'यदि तुम एक भी कदम आगे बढ़े और लड़की को हाथ लगाया तो मैं जान दे दूंगी।'

दशरी बहिन की दहाड़ ने पुलिस कमचारियाँ क होसले पस्त कर दिय। कुछ घंटों बाद पुलिस के बड़े अधिकारी आये। उन्होंने रेमती को अपने डेरे पर ले जाकर उसके साथ डाट डपट की और गालियाँ दकर छोड़ दिया। फिर रात्रि में पुलिस वाले रेमती को उसकी इच्छा के विरुद्ध घर से खींच कर बाहर ले गये और उसने मुँह में रुमाल ठूस कर उसके साथ बलात्कार किया एवं उसके सारे शरीर को क्षतविक्षित कर दिया एवं उसके गुह्या में लकड़ी डालकर उसे रोता-चीखता छोड़कर गायब हो गये। नजदीक के घर वाली औरतो ने हो हल्ला मचाकर गांव की औरतो की इकट्ठा किया। अघेरी रात में रेमती की बुआ दशरी बहिन पहले कवाट (कांग्रेसी विधायक के घर) और बाद में छोटा उदयपुर (विरोधी पक्ष के विधायक के घर) गई और उहाँ सारी घटना बताई।

विधायक श्री भट्ट (छोटा उदयपुर) ने अपनी गाड़ी से रेमती को छोटा उदयपुर अस्पताल पहुँचाया। पुलिस वाले भी वहाँ पहुँच गये और उस लड़की को यह कह कर अपने कब्जे में ले लिया कि वे बड़ीदा के अस्पताल में उसे ले जायेंगे। वहाँ उन्होंने बात का डठल लगने की मनगढ़त बात कह कर उसका उपचार कराया और उसे रिहा कर दिया।

इसपर यह बात लोकअदालत में पहुँची। तत्काल बैठक बुलाई गयी। दशरी बहिन ने अत्याचार का लोमहर्षक विवरण प्रस्तुत किया। रेमती तो अदालत के पूछने पर रो ही पड़ी मुश्किल के सभल पाई। वातावरण बड़ा तनावपूर्ण हो गया। कुछ लोगो ने जोश में जाकर यहाँ तक कह डाला कवाट घाने को जला देंगे और इस पाप की सजा हम पुलिस वालों को पूरी तरह देंगे।”

लोकअदालत में पुलिस वाला के अत्याचार की कड़ी आलोचना करते हुए एक प्रस्ताव स्वीकार किया। पांच आदमियों की जांच कमटी घनी जिसने मेहनत करके 68 प्रत्यक्षदर्शी व्यक्तियों के बयान लिये। बाद में लोकअदालत के कार्यकर्ता कवाट पुलिस घाने के सब इ सपेक्टर से मिले। उन्होंने स्वीकार किया कि डिप्टी पुलिस इ सपेक्टर के ड्राइवर और घान के दा अ य कम चारिया ने बलात्कार का पाप किया है लेकिन इस मन्ब व म कायवाही बड़े अधिकारी ही कर सकन है। मैं तीना कमचारियों के खिलाफ अपनी रिपोर्ट बड़े साहब को अवश्य भेज दूँगा। दूसरे दिन सब इ सपेक्टर पुलिस कांग्रेसी विधायक के माध्यम लोकअदालत में आये लेकिन इस उद्देश्य कि लोकअदालत सरकार और अगबारा के पास सही जानकारी न भेज और न सय इ सपेक्टर द्वारा दी गयी रिपोर्ट की नकल मागने का आग्रह करें। लेकिन

लोकप्रदानत उनका यह अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकती थी। भूतबारो को सारे घटनाक्रम की जानकारी भेज दी गयी और सरकार से अनुरोध किया गया कि वह इस मामले में तुरंत कायदाही करे। अथवा अदाम के प्रति कार के लिये जनता को सत्याग्रह का रास्ता अपनाना पड़ेगा क्योंकि पुलिस द्वारा जिस तरह पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया गया है वह बरदाश्त के बाहर है और इस मामले को 12 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक सरकार के पट का पानी भी नहीं हिला है।

भूतबारो ने इस घटनाक्रम पर गहरा रोष व्यक्त किया और गुजरात के और भी कई नेताओं ने आदिवासियों पर हुए इस अत्याचार के सम्बंध में लोकप्रदानत की बात मानने का सरकार से अनुरोध किया।

लोकप्रदानत के नोटिस का सरकार पर काफी प्रभाव पड़ा। तीनों छोटे पुलिस कमचारियों को तुरंत हटा देने का हुक्म हुआ लेकिन तीनों जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध—जिनकी मौजूदगी में तीन दिन तक लोगों की पिटाई हुई थी तथा उनके साथ पशु से भी बदतर व्यवहार और यह बलात्कार हुआ था—कार्यवाही नहीं की गयी।

15 दिन बाद लोकप्रदानत फिर बैठी। तय किया गया कि सरकार पर प्रभाव डालने के लिये तीन दिन बाद एक 'लोक कूच' का आयोजन किया जाये। इस 41 मील लम्बे लोक कूच में भाग लेने के लिये लगभग 1500 स्त्री पुरुष निर्धारित तिथि और समय पर एकत्रित हो गये। धूप की परवाह न करके लोक कूच में भाग लेने वाले स्त्री पुरुष छोटा उदयपुर पहुँचे और निमग्न होकर किसी बात की परवाह किये बगैर अहिंसक लोकशक्ति का प्रचण्ड प्रदर्शन किया। छोटा उदयपुर के इतिहास में आदिवासियों की संगठित शक्ति का इस प्रकार का यह पहला प्रदर्शन था जिसे देखने के लिये छोटा उदयपुर के लोग उमड़ पड़े। नचहरी के लोग भी सारा कामकाज छोड़कर अहाते से इसे देखने लगे।

उसी दिन लोक कूच छोटा उदयपुर से रवाना होकर पुलिस सब इंसपेक्टर के कार्यालय कवाट पहुँचा। इस प्रदर्शन का तत्कालिक फल निकला। समाचार पत्रों ने बड़ी बड़ी सुखिया देकर इस प्रदर्शन का प्रकाशन किया। रेडियो ने स्थानीय समाचार बुलेटिन में इसे प्रसारित किया। आखिरकार सरकार ने कवाट के सब इंसपेक्टर को हटाने और उसकी निलंबित करने की घोषणा की। हमारे दो उच्च पुलिस अधिकारियों के भी तबादले कर दिये गये।

परिशिष्ट 'घ'

करारखत के नमूने

लोकप्रदात द्वारा दिये गये निणयो को करारखत के रूप में लिपिबद्ध किया जाता है। फाइल अध्ययन से यह बात सामने आयी कि प्रारम्भिक वर्षों में करारखत की सम्यक् व्यवस्था नहीं थी। लोकप्रदात के करारखतो का नमूना इस परिशिष्ट में दिया गया है। इन करारखतो की देखने से ऐसा लगता है कि उनके लिखन में मुख्य दृष्टि समझाने की रही है। करारखत सामान्यतः अध्यक्ष द्वारा लिखा जाता है। करारखतो की भाषा में एक-रूपता का अभाव खटकना है। करारखत पक्षों को साम्प्रदायिक वादी-प्रतिवादी की ओर से लिखा जाता है। इसकी व्यवस्था, नियम आदि भी अत्यंत सरल हैं।

करारखतो के विकास के क्रम को देखते हुए उसे मुख्यतः दो वर्गों में बांट सकते हैं। (1) प्रारम्भिक करारखत इसे समयानुसार सन् 1965 तक मान सकते हैं। (2) करारखत का मौजूदा ढांचा, उक्त वर्ष के बाद करारखत के रूप का निखार हो रहा है।

विवादों के प्रकार के अनुसार करारखतो का नमूना इस प्रकार है

1961 से 1965 तक लिखे जाने वाले करारखतो का नमूना

(1) पति-पत्नी का झगडा

लडकी तेरसिह डूमडा ग्राम बिपानी ने पक्षों के सामने स्वीकार किया। तुम्हारी लडकी को नहीं मारूंगा। अगर मारूंगा तो पच 151 रुपये तक मुझ पर दण्ड कर सकत है। प्रतिवादी बाबा नाना ग्राम घोडा न पक्षों की जामनी (जमानत) पर लडकी को पति के सुपुर्द कर दिया।

(2) लडकी से छेड़छाड़

राजरसिह कनजी भाई, ग्राम घोडा ने डेवडा भाई थापडा भाई की लडकी देवली को, जिसका गांव खाटियावाटा या छेडा। खुली अदालत में लामा मागी। 45 रुपये लडकी के बाप को जुर्माना भरा।

(3) गुजर बसर

देवदत्ता के मूलजी जालमा ने अपनी नाकी बाईं भूरी बुटिया से करा किया कि मैं तुम्हें गुजर बसर के लिये निर्धारित अनाज और नकद मुकाल और दुक्काल दोनों में दूंगा क्योंकि मूलजी जालमा अपने काका की जमीन जोतता है।

(4) दहेज सम्बन्धी झगडा

लडकी के पिता मधुर छाडिया कोली, ग्राम मकोडी ने खरमडा ने नानजी सुमरा (लडकी के पति) को स्वीकार किया कि मैं 215 रुपये दहेज के लडक को दूंगा। पक्षों के सामने स्वीकार करता हूँ।

(5) मारपीट

प्रतिवादी कालिमा लालिया ग्राम गलेथा न स्वीकार किया कि गांव में झगडा मारपीट नहीं करूंगा। वरु तो मेरे पर पक्ष 500 रुपये तक दण्ड कर सकते हैं। वादी था गलेथा गांव का रजन यावरिया।

(6) जमीन का झगडा

मैं हरिया जानिया (ग्राम जाम्बा) तुम लोगो, गनिया जानिया, को निव देता हूँ कि मेरे पास 6 एकड़ जमीन है उसमें से आधा भाग तुमको देता हूँ। इसके सिवाय अनाज की पैदावार में मेरे दो भाग और तुम्हारा एक भाग होगा।

(7) जमीन का झगडा

मैं नाना भाई जायया कोली (मोटावाटा) तुम नारायण सीतू रगपुर को लिख देता हूँ कि पक्षों के सामने तुम्हारा खेत 4 एकड़ जो मेरे पास था, तुमको निम्न शर्त पर देता हूँ कि तुमको एक एकड़ के 600 रुपये के हिसाब से कुल 2450 रुपये देना पड़ेगा। ये सब रुपये इसी साल दे दोगे ता मैं जमीन का कब्जा इसी वर्ष छोड़ दूंगा।

(स) 1966 से 1975 तक

तलाक

(1) मैं मुन्दरिया राम रगपुर का तुम रणछोड तुलसी ग्राम अम्बाला को लिख देता हूँ कि आज मैं हमारे बीच तलाक नहीं है और तुम्हारी पुत्री को

मैंन त्याग दिया है। उसकी नहीं भी शादी कर सकते हो। उसमें हमको कोई एतराज नहीं है और वह जहा नहीं भी शादी करेगी वहा से हम 251 रुपय लेंगे।

(2) मैं केवजी बुधिया (ग्राम भाघा हूगरी), तुम बजली मगलिया ग्राम सामला को लिख देता हू कि आज के बाद मर और तुम्हारे बीच किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। तुम कही भी विवाह कर सकती हो। तुम्हारे पास जो बच्चा है, उस पर मेरा अधिकार नहीं है। कारण कि वह मेरा नहीं है। मैं बजली केवजी लिखती हू कि मैं राजी स तुम से तलाक लिया है। तुम नहीं भी विवाह कर सकते हो लिखावट हमने पढ़ लिखकर स्वीकार की है।

(3) मैं मानसिंह मालूतुम नायकडा बाबला को लिख दिया कि मैंने तुम्हारी पत्नी बाई जुवली को अपने घर में रखा है। इसके बदल में मैं 700 रुपया तुमको दूंगा और आज से हमारे बीच कोई झगडा नहीं है। मैं नायकडा तुम मानसिंह को लिख दिया कि हमारे तुम्हारे बीच कोई झगडा नहीं है। तुम बाई जुवली को घर में रख सकते हो या छोड़ सकते हो। उस पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं जुवली नायकडा को छोड़कर इसकी (मानसिंह की) पत्नी बन कर गई हू। यह मेरे लिये सब कुछ है। यह लिखावट हमने पढ़ सुनकर स्वीकार की है।

पारिवारिक झगडा

(1) मैं मयुरा डूमका तुम पचो के सामने मगिया भूरी नूरिया ग्राम कान खेडा को आज लिख देता हू कि आज के बाद तुम्हारी लडकी घनकी को मेरी मा नहीं सतायेगी और किसी प्रकार की हानी नहीं पहुचायेगी। मगर करेगी तो तुम तुम्हारी लडकी घनकी को अपने घर ले जा सकते हो और इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहेगा। आज से हम मा से भलग रहेंगे और उससे मा का काम नहीं कराऊंगा और घनकी बिना पति से पूछे पिता के घर नहीं जावेगी।

(2) मैं नागजी बुधिया तुम मयुर भगडा का पचो के सामने लिख देता हू कि आज के बाद तुम्हारी लडकी जस्सू को परेशान नहीं करूंगा, मारूंगा नहीं। अगर सताऊ तो पच 501 रुपये तक मेरे पर ज़ुर्माना कर सकते हैं और मेरा जस्सू पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। मैं मयुर तुम नागजी को लिख देता हू कि आज के बाद मेरी लडकी जस्सू तुम्हारी आजा के बिना मेरे

पर चली आई तो 501 रुपये देऊंगा। यह लिखावट पढ़ सुनकर स्वीकार की है।

(3) मैं गनिया बचना पचो के सामने लिख देता हूँ कि मैंने भूल से मेरी सानी मंगली को भूठी रीति से अपना घर में रखा और दो साल तक हमारे बीच सम्बन्ध रहे और मुझसे मंगली को एक लड़की है जिसकी आयु 15 दिन है। इस लिखित से स्वीकार करता हूँ कि मेरी गलती का कारण मंगली मेरे पास थी। मंगली और बच्ची पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। गलती के जुमाने का 150 रुपये दान की तयार हूँ। ऊपर की लिखावट पढ़ सुनकर स्वीकार की।

(4) मैं गोलिलाल हिरवत ग्राम जामली पचा के सामने लिख दिया कि झरोकी बाई टूटी के घर 11 बच स चर जवाई हूँ और मुझसे बाई टूटी को चार बच्चे हुए। मुझसे गलती से अपनी पत्नी की दा सड़कियों के साथ घर बानूनी सम्बन्ध हुए। इसके लिये दामा चाहता हूँ और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने के बचन से बंधा हूँ। ऐसा करूँ तो बाई टूटी पर मेरा पति का अधिकार समाप्त हो जायगा और पच 51 रुपये जुर्माना ले सकत है। अब घर में मैं अच्छी तरह से रहूँगा। यह लिखावट मैंने पढ़ सुनकर स्वीकार की है।

जमीन सम्बन्धी झगडा

(1) मैं सुन्दरियाराय (रंगपुर) पचो के सामने लिख देता हूँ कि मैं मेरी जमीन का बटवारा करने की तैयार हूँ। एक भाग मेरे पास रहेगा। दूसरा भाग रंगली सुन्दरिया की मिलेगा। एक एक भाग जमू भाई, करगन भाई और गमलभाई को मिलेगा। पच बटवारा करेंगे और उस पर भागीदार का क जा रहेगा। पर यह जमीन सरकारी कागजों, ग्राम-मुधार सस्था में सम्मिलित करनी पड़ेगी। ऊपर लिखा हमने पढाकर सुन लिया है और मेरे वारिसों को भी स्वीकार है।

(बाद में अगले पच कायवाही निम्न प्रकार लिखित में दर्ज हुई)।

इस लेख द्वारा हम रंगपुर के निवासी पक्षकार पचा के सामने लिखते हैं कि हमारी जायदाद का बटवारा निम्न प्रकार होगा

मैं सुन्दरियाराम जी मेरी पूरी जमीन को 5 भागों में बाँटता हूँ। पांचों भाग बराबर रहेंगे जो निम्न व्यक्तियों को मिलेंगे

प्रथम	सुन्दरियाराम जी
द्वितीय	रगली बहन सुन्दरिया
तीसरा	जमू भाई सुन्दरिया
चौथा	बरसनभाई सुन्दरिया
पाचवा	नटूभाई सुन्दरिया

मैं सुन्दरियाराम जी ने परिवार के निर्वाह के लिये तीन हजार का कर्जा लिया है जो प्रत्येक भागीदार (हिस्सेदार) को भरना पड़ेगा। लेकिन जमू सुन्दरिया गत दो वर्षों का कर्जा नहीं देगा। कारण वह स्वयं दो वर्ष से अलग रहकर काम रहा है। दो कमरे का मकान जमू, बरसन, नटू और उनकी या रगली के हिस्से में जावेगा और पुराना मकान सुन्दरिया भाई के हिस्से में जावेगा और सुन्दरिया भाई जब मकान को पक्का करेंगे तो सब भागीदारों को हिस्से में रुपये का भाग देना। यह लिखावट हमने पढ़कर-सुनकर स्वीकार की है।

(2) मैं कानजी घानका, ग्राम मिहड़ा मेरी भाभी बाई सादी को आज दिन पच्ची के सामने लिख देता हूँ कि मेरे जो भाई मर गये हैं उनकी पूरी जमीन और जायदाद भाभी सादी को दूंगा। इस समय हम सम्मिलित रहते हैं लेकिन जब भी भाभी अलग होगी, और वह लड़की के पति को घर जवाई रखेगी तब उनकी जमीन छाड़ दूंगा। साथ ही तब तक उसका और उसके बच्चों की सम्भाल करूंगा। लिखावट पढ़कर सुनकर स्वीकार की।

(3) मैं छाटा भाई बापू भाई (ग्राम गजलावाट) तुम रामा भाई हरियाभाई छगनभाई मोहन भाई मनसुख भाई कालू भाई रावला भाई, ग्राम बाटा का लिख दिया कि मेरे पास जो 3 एकड़ 5 गुजरी जमीन है इसकी एवज में मैं आपको 2027 रुपये देता हूँ और इस जमीन में आप लोग को 5 साल तक खेती करने का अधिकार देता हूँ यह अवधि खतम हान पर यह जमीन मुझे सौंपनी पड़ेगी। बीच में मैं किसी प्रकार तुम लोग को परेशान नहीं करूंगा। अगर इस दौरान आखा तीज के पहले पैसा लोटा दू तो यह जमान मुझे सौंपनी पड़ेगी। यह लिखावट मैंने पढ़ सुन कर स्वीकार की है।

(4) हमारे पिता लालसिंह जानमा के नाम पर जमीन सर्वे नं. 100 एकड़ और 38 गुछा है जो हमारे पिता लालसिंह, होरी, और भुमली के मध्य बराबर भागों में बटेंगे। बाकी सरका की पूरी जमीन हम साना भाईया को बराबर बटवारे के नियम पचा को सौंपते हैं। दापन का पंकर

लालसिंह न जा सचा किया है, वो कुल 500 रुपये है वो हमको स्वीकार है। इस रकम में से सात भाग होंगे। इसमें से चार भाईया बलसिंह, धनजी, मानसिंह और नरसिंह इन चारों को सबर न 300 रुपये दना है। यह हम चारों को मजूर है। इन आधार पर हमारे बीच जा झगडा है और जो मुकदमा बोट बचहरी में गया है वो वापस लेत हैं और भविष्य में नही झगडेंगे।

लेन देन सम्बन्धी

मैं बाई बीतली होदर की बहू तुम हरिजन पुनिया जीता पानबट को लिख देती हू कि मेरे पति ने तुम्हारे से जा बैल लिया था, उसने 600 रुपये बाकी थे। उसने बदले में मैं एक बछडा और बैल देती हू। भागे आपसे मेरी लेन देन सम्बन्धी तब्यार नही रहेगी। मैं पुनिया जीता बाई बीतली को लिख देता हू कि मुझे एक बैल और बछडा मिल गया है। अब हमारे बीच कोई झगडा नही है।

मारपीट

मैं भूरा भाई छदिया भाई कोली, गांव बनवा का रहने वाला हू। मेरी गलती के लिय क्षमा चाहता हू। पचा द्वारा दिया दण्ड खुशी से स्वीकार करता हू और पुलिस की रिपोर्ट वापिस ले लता हू। पचो का फैसला स्वीकार है। यह लिखावट पढ़ सुनकर स्वीकार की है।

चोरी

(1) मैं मंगा जादवा, ग्राम भोटावाटा पचा के सामन लिख देता हू कि आज मैंने चोरी का 217 रुपया का कपास मोल लिया था। उसके जुमाने के रूप में 50 रु देता हू। अगर फिर से चोरी का कपास लेते हुए पकडा जाऊ तो पच 1000 रुपये जुर्माना कर सकते हैं।

(2) मैं नायका रणछोड कोली (ग्राम आबालग) तुम पचो को लिख देता हू कि मैंने गलती से रणपुर के बेलिया छगन के बल को चुराया था। वो बैल मैं कवाट बेचने गया तब पकडा गया था। अब मैं पचो से क्षमा चाहता हू। भविष्य में ऐसा खराब काम नही करूंगा। मेरी गलती पर पच जो सजा देंगे, स्वीकार करूंगा। इस गलती के लिये 150 रुपया जुर्माना पचो को दे रहा हू। यह लिखावट पढ़ सुनकर स्वीकार की है।

(3) मैं रडतिपा भोल, ग्राम समिति को लिख देता हू कि सर्वे न 36,

57 की जमीन कुल 8089 रुपये 21 पैसे म मोल ली है । उसमें से 4000 रुपया मेरे को अप्रैल 71 के पहले देने है । इसके पश्चात अप्रैल 1972 में रुपये 2000 देने है और अप्रैल 1973 में रुपये 2089 तथा 21 पैसे तुमको देने है । इस प्रकार यह रकम भरूंगा । अगर मेरा प्रथम भाग 4000 रुपये इस वष न भर सकू तो प्रति एकड़ 100 रुपया जुर्माना दूंगा । इस प्रकार 5-5 एकड़ का 550 रुपया दूंगा और जमीन पर से अधिकार उठाना पड़ेगा और ग्राम समिति इस जमीन को किसी को भी दे सकती है ।

साक्षात्कार अनुसूची-1

कुमारप्पा ग्राम स्वराज्य संस्थान, जयपुर

लोकअदालत संगठन और काय पद्धति का अध्ययन

दिनांक

साक्षात्कार सख्या

नाम

आयु

ग्राम

शिक्षा

जाति

संयुक्त या एकाकी परिवार

सर्वेक्षण कर्ता

(1)

विवाद के वादी एवं प्रतिवादी से सम्बन्धित प्रश्न (दानो पक्षों से)

(1) परिवार तालिका

क्रम मुखिया से सम्बन्ध शिक्षा उम्र धर्म आय (मासिक/वार्षिक)

1

2

3

4

5

6

7

8

कौनसा विवाद लोकअदालत में गया

(2) विवाद कब और कैसे प्रारम्भ हुआ ?

(3) लोकअदालत में ध्यान से पूछ

(क) पचायत में गये हा तो वहा क्या हुआ ?

(ख) जाति पचायत में गये हा तो वहा क्या हुआ ?

(ग) आपसी बातचीत से क्या कुछ तय हुआ ?

(घ) लोकअदालत में क्या ल गये ?

(4) विवाद का स्वरूप (भावश्यकता हो तो अलग नाट करें)

(5) लोकअदालत में जान की तारीख - कितनी बार तारीखें लगी और प्रत्येक तारीख में क्या क्या हुआ ?

(6) फैसले की तारीख ।

(7) लोकअदालत की बैठक में कितने लोग उपस्थित थे ?

(8) क्या निर्णय हुआ ? विवरण दें ।

(9) क्या निर्णय आपके पक्ष में हुआ ? हा/नही ।

(10) क्या निर्णय से आप सन्तुष्ट हैं ? पूरा सन्तुष्ट/सामान्य सन्तुष्ट कम सन्तुष्ट/असन्तुष्ट ।

(11) निर्णय के बारे में आपकी क्या राय है ?

(क) 'याय मिला? यदि हा तो आपकी क्या कमोटी है ?

(ख) 'याय नहीं मिला इसकी कमोटी क्या है ?

(ग) विवाद बढ़ा, यदि हा तो किस प्रकार से ?

(घ) विवाद कम हुआ—यदि हा तो किस प्रकार से ?

(ङ) तनाव कम हुआ—यदि हा तो किस प्रकार से ?

(12) क्या लोकअदालत के निर्णय के बाद अन्य 'यायालय में धपोंन की है ? हा/नही । यदि हा तो वहा और क्या हुआ । (विवरण नाट करें) ।

(13) लोकअदालत में क्या परगानी होती है ?

- (घ) कार्य प्रक्रिया की
- (आ) आधिन
- (इ) एक व्यक्ति के नेतृत्व को ।

- (14) आज क्या स्थिति है ? विवाद सुलभ गया/कुछ तनाव है/सामान्य स्थिति ।
- (15) लोकअदालत में निर्णय हान तक कुल कितना खर्च हुआ ? विवरण दें ।

(II)

(गाव के मुखिया, सामान्य जन, अधिवारी, जूरी, वकील आदि से सम्बन्धित प्रश्न)

नाम	उम्र
गाव	आय मासिक
शिक्षा	जाति
धरा	

- (1) क्या आपने लोकअदालत की कार्यवाही में भाग लिया है ? हा/नहीं ।
- (2) लोकअदालत में किस रूप में भाग लिया ?
- (1) दल
 - (2) सामान्य—वादी/प्रतिवादी
 - (3) गवाह पक्ष में/विपक्ष में
 - (4) जूरी
 - (5) अन्य
- (3) आपकी राय में लोकअदालत से—
- (अ) क्या विवाद का हल आसानी से निकलता है ?
 - (आ) क्या आपसी तनाव कम होता है ?
 - (इ) क्या खर्च की बचत होती है ?
 - (ई) क्या न्याय शीघ्र मिलता है ?

(उ) यदि ग्राम कोई लाभ है तो क्या ?

(4) क्या लोकप्रदात में सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में स्थानिक आया है ?
जैसे—

(क) विवाह सम्बन्धी विवादों में कमी हुई है ।

(ख) पारिवारिक तनाव में कमी हुई है ।

(ग) भूमि सम्बन्धी विवादों में कमी आई है ।

(घ) भूत प्रेत में विश्वास कम हुआ है ।

(ङ) बेरोजगारी का क्षेत्र बढ़ा है ।

(5) क्या लोकप्रदात के कारण समाज में जागृति आयी है ? जैसे—

(प्र) क्या क्षेत्र के लोग विवादों को स्वयं सुलझाने का प्रयास करते हैं ? यदि हाँ तो कैसे ?

(प्रा) क्या महाजन का क्षोभ कम हुआ है ? हाँ/नहीं । हाँ तो किस प्रकार—

(क) क्या महाजन कम ध्याज लेने लगा है ?

(ख) क्या महाजन सही हिसाब रखता है ?

(ग) क्या महाजन पहल से अधिक सही हिसाब रखता है ?

(घ) ग्राम ?

(द्व) क्या जंगल के अधिकाधिक के द्वारा की जान वाली परेशानी कम हुई है ? हाँ/नहीं/यदि हाँ तो किस रूप में ।

(क) लकड़ी काटने से सम्बन्धित प्रश्नों पर अब परेशान नहीं करते/कम करते हैं ।

(ख) पशु चराने के प्रश्न पर परेशान नहीं करते या कम करते हैं ।

(ग) ग्राम ।

(6) क्या ग्राम याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत आयी है ? हाँ/नहीं ।
यदि हाँ, तो किस रूप में ?

(प्र) संगठित होकर ग्राम याय का विरोध करते हैं ।

(प्रा) लोकप्रदात में जाते हैं ।

(इ) अ यायी को समाज (ग्राम) दह देता है ।

(ई) अ-य ।

(7) लोकअदालत से क्या लाभ है ?

अ-(क) याय शीघ्र मिलता है ।

(ख) याय पर होने वाले व्यय में बचत होती है ।

(ग) याय काय में दोनों पक्ष खुल कर भाग लेते हैं ।

(घ) निष्पक्ष याय मिलता है ।

(ङ) लोकताम्रिष है ।

आ-लोकअदालत में आस्था के क्या कारण हैं ?

(क) अच्छा नेतृत्व ।

(ख) कार्य पद्धति ।

(ग) आनन्द निवेदन आश्रम का काम ।

(घ) ग्रामदान विचार का प्रसार ।

(ङ) जाति मगठन ।

(8) क्षेत्र में लोकअदालत के क्या प्रभाव पड़े हैं ?

(अ) राजनीतिक प्रभाव

(क) लोकअदालत के नेतृत्व की स्वीकार करते हैं ?

(ख) उसका भाग दशन मानते हैं ?

(ग) राजनीतिक दला की अपेक्षा लोकअदालत के नेता की बात की अधिक मानते हैं ?

(घ) लोकअदालत के कारण गांव में गुटबंदी है/नहीं है । है तो क्यों ?

(ङ) लोकअदालत के कारण एकात्मता है ?

(आ) सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव

(क) अ-घविश्वास कम हुआ/बसा ही है/समाप्त हुआ ।

(ग) जातिगत एकता आयी है/बढ़ी है/वसी ही है ।

(ग) झूठा छूत कम हुई है/समाप्त हुई है/पहले जसी है ।

(3) समग्र दृष्टि से लोकअदालत का कार्य कैसा है ?

- (क) अच्छा है ।
- (ख) बहुत उपयोगी है ।
- (ग) सामान्यतया ठीक है ।
- (घ) अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता ।

(9) लोकअदालत के अन्य प्रभाव

- (क) पुलिस का हस्तक्षेप कम हुआ ।
- (ख) कोर्ट में जान से मुक्ति मिली ।
- (ग) जंगल के अधिकारियों से परेशानी कम हुई है ।
- (घ) सरकारी अधिकारियों का सहयोग बढ़ा है ।

(10) सामान्य मायालय और लोकअदालत में क्या फर्क है ?

(11) आपके साथ आश्रम में कैसा व्यवहार होता है ?

- (क) हमारी बात सुनी जाती है ।
- (ख) कम रुचि लेते हैं ।
- (ग) निवास की समस्या रहती है ।
- (घ) भोजन की समस्या रहती है ।

(12) लोकअदालत के स्थायित्व के बारे में आपकी क्या राय है ?

- (क) इसमें विश्वास है ।
- (ख) ठीक एक सप्ताह याय मिलता है ।
- (ग) दोघ्न याय मिलता है ।
- (घ) ग्रामदानी ग्रामसभाओं ग्रामस्तर पर

इस काम को स्थायी रूप में करने लगी हैं ।

(ङ) ठोस व्यवस्था का विकास हो रहा है । लोकअदालत की/ग्रामसभा की ।

- (च) कानूनी मान्यता का प्रभाव ।
- (छ) एक व्यक्ति का नेतृत्व है ।
- (ज) विश्वास पर आधारित है ।

(13) निणय प्रक्रिया मे कौन कौन से तत्व प्रभावकारी होते हैं ?

- (क) सही न्याय की खोज ।
- (ख) व्यक्ति का नेतृत्व ।
- (ग) जाति का हित ।
- (घ) पैसा
- (ङ) नेताओं का प्रभाव ।
- (च) व्यक्ति का हित ।

(14) क्या छावनी-प्रतिवादी पक्ष मे निणय के लिये विशेष प्रयास भी करते हैं ? जैसे —

- (क) लोकअदालत में प्रभावी लोगों से बातचीत ।
- (ख) जूरी पर प्रभाव डालना ।
- (ग) पैसा देना ।
- (घ) शय ।

(15) क्या लोकअदालत के साथ किसी का टकराव है ? यदि हा, तो किस प्रकार का ?

- (क) न्यायालय के साथ ।
- (ख) पुलिस के साथ ।
- (ग) महाजन बग के साथ ।
- (घ) गांव के किसी विशिष्ट बग के साथ—कौन सा बग ?
- (ङ) पढे लिखे लोगों के साथ ।

(16) यदि टकराव है, तो उसका लोकअदालत पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

- (क) प्रतिष्ठा कम हुई ?
- (ख) विवाद से जाने में रुचि कम हुई ?
- (ग) विरोध में बातावरण बना ?

(17) लोकअदालत की प्रतिष्ठा कैसी है ?

- (क) इसे सभी स्वीकारत हैं ।

- (ख) खास वग व'म स्वीकारता/नही स्वीकारता—कौन सा वग ?
- (ग) प्रतिष्ठा का क्या कारण है ? सही 'याय/भाई (श्री हरिवल्लभ परोख) का व्यक्तित्व/कल्याणकारी वाय ?
- (घ) क्या लोकअदालत के लोग का अपना स्वाय है ? हो तो क्या और क्यों ?

कुमारप्पा ग्राम स्वराज्य संस्थान

लोकअदालत संगठन और काय पद्धति का अध्ययन
साक्षात्कार अनुसूची-2

परम्परागत कोर्ट में विवाद ले जाने वालों से साक्षात्कार

दिनांक	सरया
नाम	ग्राम
आयु	जाति
शिक्षा	

(1) किस प्रकार के 'यायालय' में विवाद ले गये? पंचायत/स्थानीय कोर्ट में/ग्राम कोर्ट में।

(2) लोकअदालत में विवाद क्यों नहीं ले जाते हैं?

(क) दूर पड़ता है।

(ख) जानकारी नहीं है।

(ग) वहाँ 'याय' नहीं मिलता। यदि हा तो क्या नहीं मिलता?

(घ) ज्यादा समय लगता है।

(ङ) लोकअदालत में विवाद ले जाने से मना करते हैं—गाव के नेता/जाति के नेता/राजनीतिक नेता।

(3) परम्परागत कोर्ट में क्या सुविधायें या असुविधायें हैं?

सुविधायें

असुविधायें

(क)

(ख)

(ग)

(4) लोकअदालत के साथ किसी प्रकार का तनाव है?

(क) स्थानीय राजनीति की दृष्टि से वहाँ (लोकअदालत) जाना ठीक नहीं मानत।

(ख) जाति समठन मना करता है ।

लोकप्रदासत या गान द-निकेतन आश्रम से ठीक सम्बन्ध नहीं है ।
यदि हा, तो ऐसा क्या ?

(5) आपकी लोकप्रदासत के बारे में क्या राय है ?

(6) परम्परागत कोट में याय प्राप्ति में कितना समय लगा ?

(7) परम्परागत कोट में याय में कितना लक्ष हुआ ? विवरण दें

(क) बकौल पर

(ख) गवाहों पर

(ग) कोट फीस

(घ) अन्य

कुमारप्पा ग्राम स्वराज्य संस्थान

लोकअदालत सगठन एवं काय पद्धति का अध्ययन
ग्राम-अनुसूची

सर्वेक्षण वर्ष 1975

नाम गाव

गाव से दूरी
(किलोमीटर में)

- (1) गाव
- (2) पचायत
- (3) पुलिस स्टेशन
- (4) तालुका
- (5) जिला
- (6) गाव का क्षेत्रफल (एकड़)
- (7) कुल परिवार संख्या ।

(क) 1971 की जनगणना के अनुसार—

(ख) वर्तमान समय में—

- (8) सुविधायें—

(1) स्कूल	प्राथमिक	मिडिल	माध्यमिक
(II) विद्यार्थियों की संख्या			
(III) बिजली	गाव में/गाव से		किलोमीटर दूर
(IV) सड़क	गाव में/गाव से		किलोमीटर दूर
(V) रेलवे स्टेशन	गाव में		किलोमीटर दूर
(VI) बस स्टैंड	गाव में/गाव से		किलोमीटर दूर
(VII) डाकघर	गाव में/गाव से		किलोमीटर दूर

- (VII) नार धर गाव म गाव मे किलामीटर दूर
 (IX) कुए बच्चे पक्के (गाव म सस्था)
 (X) तागाव (गाव म नस्था)
 (XI) बाजार गाव म गाव से किलामीटर दूर
 (XII) विक्लिम्बालय गाव म/गाव से किलोमीटर दूर
 (XIII) परिवार नियोजन केंद्र गाव म/गाव से किलोमीटर दूर
 (XIV) रंगपुर प्राथम की दूरी

तारीख

सर्वेक्षक

(नोट यह जानकारी सरकारी कार्यालय ग्राम पंचायत या ग्रामसभा से प्राप्त की जायगी) ।

(1) जाति विभाजन कुल सख्या परिवार सख्या

(i) घनमुद्रित जातिया

(क) (ख) (ग)

(ii) प्रादिवासी जातिया

(क) (ख) (ग)

(iii) सामान्य हिंदू जातिया

(क) (ख) (ग)

(iv) अन्य

(2) कुल जमीन

एकड़ म

(3) भूमि की किस्म

- (क) कृषि होती है
 (ख) कृषि हा सकती है
 (ग) भकान
 (घ) बजर
 (ङ) पहाड

(4) फसल एवं साधन

(अ) फसल की किस्म

(आ) आधुनिक साधन

(क) ट्रैक्टर

(ख) प्रोसेसर

(ग) पम्पिंग सेट

(घ) अथ

(5) भूमि का बटवारा—श्रेणी और परिवार संख्या

(अ) भूमिहीन

(आ) पांच एकड़ तक

(इ) दस एकड़ तक

(ई) बीस एकड़ तक

(उ) बीस एकड़ से अधिक

(6) राजगार की स्थिति परिवार संख्या जाति

(अ) मुख्यतः खेती पर निर्भर परिवार

(आ) मुख्यतः उद्योग पर निर्भर परिवार

(इ) मुख्यतः व्यापार पर निर्भर परिवार

(ई) मुख्यतः नौकरी पर निर्भर परिवार

(उ) गांव में नौकरी करने वाले लोग (मर्यादा) ।

(7) शिक्षित व्यक्ति (मर्यादा)

(क) एम ए

(ख) बी ए

(ग) टैक्नीकल

परीक्षा उत्तीर्ण

(घ) हाईस्कूल

(ङ) उससे नीचे

(च) अथ

(8) क्या गांव ग्रामदानी है ? यदि हा, तो निम्नलिखित जानकारी—(केवल ग्रामदानी एवं सक्रिय गांवों के लिए)

(क) ग्रामदान की घोषणा का वर्ष

(ख) ग्रामसभा की स्थापना

- (ग) ग्रामसभा के कार्यों का विवरण
(प्रत्येक मास पर)
- (घ) ग्रामसभा द्वारा लोकप्रदात (पाय) का कार्य अपनाया गया है। (प्रत्येक विवरण)।
- (ङ) किस किस प्रकार कितने विवादों को सुलझाया है ?
(पांच वर्षों में)

विवाद का प्रकार	ग्रामसभा ने सुलझाया	लोकप्रदात में गया	कोर्ट में गया
-----------------	---------------------	-------------------	---------------

(क)

(ख)

(ग)

विवाद का प्रकार	ग्रामसभा ने सुलझाया	लोकप्रदात में गया	कोर्ट में गया
-----------------	---------------------	-------------------	---------------

(घ)

(ङ)

(च) ग्रामस्तरीय लोकप्रदात की व्यवस्था का विवरण

(i) स्थान

(ii) कार्य पद्धति

(iii) अन्य जानकारी जो उपलब्ध हो।

(9) गांव में अधिक विकास का कार्य

कार्य का प्रकार	संख्या	(i) आश्रम के सहयोग से	(ii) सरकार के सहयोग से
-----------------	--------	-----------------------	------------------------

क

ख

ग

(10) गांव में अन्य कार्य जैसे—

(क) नई परम्पराओं का विकास

(ख) समाज सुधार के कार्य

(ग) संगठनों एवं संस्थाओं का विकास—इसका विवरण

सन्दर्भ ग्रन्थ

- डा. उपेन्द्र बन्नी लोकअदालत एट रंगपुर—ए प्रोलि
मिनरो स्टडी दिल्ली विश्वविद्यालय,
1974 ।
- हरिवल्लभ परीख क्रान्ति का अरुणोदय, सर्वसेवा सघ
प्रकाशन, वाराणसी, 1971 ।
- हरिवल्लभ परीख स्वप्न हुए साकार, सोसाइटी फॉर
डेवलपिंग ग्रामदान, 1972 ।
- गांधीजी हमारे गांवों का पुन निर्माण,
नवजीवन प्रकाशन, ग्रहमदावाद ।
- गांधीजी ग्राम स्वराज्य, नवजीवन प्रकाशन,
ग्रहमदावाद ।
- जनगणना रिपोर्ट बड़ोदा जिला
1961 ।
- एल एम श्रीवास्तव ट्राइबल सोवियनियर, भारतीय आदिम
जाति सेवक सघ नई दिल्ली ।
- ए आर देसाई एरल इन्डिया इन ट्राजिशन ।
गुजरात के आदिवासी गुजरात विद्या
पीठ, ग्रहमदावाद, 1968 ।
- हरिश्चन्द्र उप्रेती भारतीय जनजातियां राजस्थान
विश्वविद्यालय, जयपुर, 1970 ।
- स्टेफन फुच द एथनोरिजनल ट्राइब्स आफ इंडिया
मैमोरिल 1973 ।
- बी एन श्रीवास्तव एक्सप्लायटेशन इन ट्राइबल एरिया
भा आ जा सेवक सघ, नई दिल्ली,
1961 ।
- क्रान्तिवाद मेलिनाबेस्की वय समाज मे अपराध और प्रथा
(क्राइम एण्ड कस्टम इन सेवेज सासाइटी)
म प्र हिन्दी ग्रंथ प्रकाशनी, भोपाल,
सयाल्स आफ द सयाल परगना
1956 ।
- पी सी विश्वास

वाल्टर जो ग्रीफिथ्स	द कोल ट्राइवल ऑफ सेट्रल इंडिया द रायल एमियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल (कनकता) 1946 ।
अनिल कुमार दास	द अरन्स ऑफ सुन्दरवन 1963 ।
टी बी नायक	चारह भाई विभवार म प्र हिंदी ग्रंथ अकादमी 1971 ।
टी बी नायक	द भिल्स एक स्टडी भारतीय प्रादिम जाति सबक मध 1956 ।
जी एस घुरिय	द शिडियूल ट्राइव्स ।
ई डी रायन	एग्रोपलाजी खण्ड 2 थिक्म लाइवरी वाटम एण्ड क लन्डन 1946 ।
पी जी शाह	द दुवला ऑफ गुजरात भा प्रा जा सबक मध 1958 ।
मैक्स ग्लुक्मैन	आडर एण्ड रिवेलियन इन ट्राइवल्स ट्राइव्स ऑफ इंडिया भारतीय प्रा जा सबक मध, 1971 ।
पी सी माइकेल	आडर एण्ड रिवेलियन इन ट्राइवल अफ्रिका यूपाक ।
परिपूर्णानंद	प्राचीन भारत की शासन प्रणाली श्री राम मेहरा एण्ड कम्पनी, प्रागरा
प्रो एन वी पराजय	अपराध शास्त्र एन आपराधिक ग्याय प्रशासन म प्र हिंदी ग्रंथ अकादमी ।
मैकम मेरिमट	ग्रामीण भारत राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, 1973 ।
राबर्ट रेडफील्ड	कृषक समाज तथा कृषक संस्कृति राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, 1973 ।
हपदव भालवीय	विलेज पचायत इन इंडिया म भा का कमेटी नई दिल्ली 1956 ।
इंडियन पैन्शन कोड भारत सरकार	
सिविल प्रोसीजर कोड, भारत सरकार	
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भारत सरकार	
इंडियन एक्टिक्स एक्ट भारत सरकार	
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, भारत सरकार ।	

विषयानुक्रमिका

अध्ययन

- उद्योगिता, 8
- विषय 10
- सीमायें एवं समस्यायें, 16
- क्षेत्र एवं पद्धति, 11

अध्ययन के भाग

- आवागमन की सुविधा 46
- गांव और मुख्यालय, 44
- जाति और सामगम, 49
- भूमि और उगवा वितरण 46
- भूमि का प्रकार और उपयोग 48
- निगाह का स्तर 52

आदिवासी

सोपानदात

- आवास—सुविधा की दिशा 110
- आदिवासी समाज, 106
- आवास की प्रेरणा 68
- और साम सामान्य 53
- और सात जाति 126
- उद्देश्य एवं परिभाषा 6
- एवं सामान्यी गांव की साम
समायें 122
- एवं साम सामान्य 121
- बसन्त का 109
- बसन्त का सामान्य दिशा
जाना 79
- साम साम साम 91
- साम साम साम 70
- साम साम साम, 115

- लोकप्रदात से प्रेषित विवाद, 64
- विवाद का प्रस्तुतीकरण एवं
पजीवन, 71
- विवाद की चर्चा, 76
- विवादों की सुनवाई, 123
- संगठन 56
- संगठन का विकास 58
- समय एवं खर्च, 113
- सामाजिक परिस्थिति, 100
- सामाजिक प्रभाव, 102
- सुनवाई की सूचना, 72
- सुभाव, 148
- सुविधा असुविधा 116
- सैद्धांतिक यागदान, 145
- स्थापना की परिस्थिति, 4
- स्थायित्व, 132

Practical

डा. धनपदप्रसाद (1944) एम ए,
 पी एच डी (घरपान्त्र)। प्रारम्भिक शिक्षा
 मुनिपादी तालीम के माताद्वारा—श्रम
 भारती गान्धी ग्राम बिहार—में हुई।
 माध्यमिक शिक्षा मयाभारती महापुत्री,
 वाराणसी में और उच्च शिक्षा काशी विद्या
 पीठ वाराणसी में प्राप्त की। ग्रामीण
 समाज की समस्याएँ, तथा विकास की
 प्रक्रिया का समझन तथा उनके अध्ययन
 अनुसंधान में विनियोजित। काशी विद्या
 पीठ के घरपान्त्र विभाग में विद्वत्विद्यालय
 अनुदान आयोग के फेलोशिप में नवगणना
 क्षेत्र मुसहरा (बिहार) का अध्ययन।
 ग्रामीण हिमा' और गांधीजी और
 औद्योगिकरण" पुस्तक के लेखक। वर्तमान
 में कुमारपा ग्रामस्वरोज्ज्वल मस्थान, जयपुर
 में कार्यरत। मस्थान की धारा में व्यवसायी
 मस्थानों (कान्टरी एजेंसीज) द्वारा नियोजित
 रह सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्निर्माण के
 प्रयासों का समाजशास्त्रीय अध्ययन नियोजित
 जिनमें से करीब एक दर्जन अध्ययन प्रति-
 वेदन प्रकाशित हो चुके हैं। भारतीय
 सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद
 (ICSSR) की सहायता से दो अनु-
 संधान परियोजनाएँ पूरी की। गांधी विचार,
 ग्रामीण समाजशास्त्र तथा घरपान्त्र पर कई
 शोधपत्र प्रकाशित हो चुके हैं।